{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 10 अप्रैल 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मणिपुर पर प्रधानमंत्री का बड़ा दावा

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री का दावा है कि केंद्र सरकार के समय रहते दख़ल देने और राज्य सरकार की कोशिशों के कारण मणिपुर के हालात में सुधार आया है। द असम ट्रिब्यून नाम के अख़बार को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि – हमारा मानना है कि हालात से संवेदनशीलता के साथ निपटना सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। मैंने इस बारे में संसद में पहले भी कहा है। हमने अपने सबसे अच्छे संसाधनों, प्रशासन को इस संघर्ष को सुलझाने में लगाया हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में तब रुके, जब संघर्ष अपने चरम पर था। इस संघर्ष से जुड़े पक्षों के साथ शाह ने 15 से ज़्यादा बैठक की। राज्य सरकार को जो भी मदद चाहिए होती है, केंद्र सरकार मुहैया करवाती है।

गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसा और अशांति का एक लंबा दौर चला है। मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को अपने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर शीघ्रता से विचार करने को कहा था। इसके बाद मई 2023 की शुरुआत में मैतेई और कुकी लोगों के बीच हिंसक झड़पों की शुरुआत हुई, जो बढ़ते-बढ़ते पूरे राज्य में फैल गई। इस हिंसा में घोषित तौर पर अब तक क़रीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है। लगभग साल भर की अशांति के बाद फ़रवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया है जिसमें मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफ़ारिश का ज़िक्र था। लेकिन इसके बाद भी मणिपुर में हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। आलम ऐसा है कि हजारों मतदाता अब भी राहत शिविरों में हैं और चुनाव आयोग को वहीं से उनके मतदान का इंतजाम करना पड़ रहा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से ही हुई, ताकि इस राज्य की ओर शेष भारत का ध्यान खींचा जा सके और यहां हालात सामान्य करने का दबाव राज्य और केंद्र सरकार पर बनाया जा सके। यह हैरत की बात है कि राहुल गांधी ने हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया, उनके अलावा कई और विपक्ष के नेता मणिपुर चले गए, कई पत्रकारों ने मणिपुर जाकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए। बल्कि नवंबर-दिसंबर में जब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में प्रचार के लिए श्री मोदी नहीं गए, क्योंकि फिर उन पर मणिपुर जाने का दबाव भी बढ़ जाता। देश में कई बार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए गए कि वे सारे देश में घूम सकते हैं, विदेश जाने के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए।

प्रधानमंत्री से यह सवाल भी किया गया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में भाजपा की सरकार है, तो वहां के मुख्यमंत्री वीरेन सिंह से अब तक त्यागपत्र क्यों नहीं लिया गया। लेकिन इनमें से किसी सवाल का जवाब श्री मोदी ने नहीं दिया। और अब चुनावों के पहले वे मणिपुर का ज़िक्र कर भी रहे हैं, तो उसमें यह दावा कर रहे हैं कि मणिपुर में समय रहते केंद्र सरकार के दख़ल के कारण स्थितियां सुधरी हैं। जबकि संसद के 2023 के मानसून सत्र में विपक्ष के सांसदों ने जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, तब जाकर खूब मिनटों का बयान मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने दिया था। उसी दौरान मणिपुर में दो कुकी महिलाओं का वस्त्रहरण करके उनकी परेड करवाने का एक वीडियो भी सामने आया था, जिस पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए थे, और मजबूरन प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा था। अब एक तरफ नरेन्द्र मोदी दावा कर रहे हैं उनकी सरकार ने समय रहते हालात संभाले और वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अभी कहा है कि दो कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उनकी परेड करवाने का वीडियो विपक्ष ने वायरल किया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार को बदनाम किया जा सके। बीरेन सिंह ने दावा किया कि इस वीडियो के वायरल होने के कारण ये बात पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दी गई कि उन महिलाओं को मैतेई समुदाय की कुछ महिलाओं और युवाओं ने बचाया था।

बड़े दुख की बात है कि एक राज्य में फैली अशांति को केंद्र और राज्य की सत्तारुढ़ सरकारें राजनीति का विषय बना रही हैं, जबकि मणिपुर की जनता को इस वक्त हर तरह से सहारे और संवेदनशीलता की जरूरत है। विपक्ष अगर वहां की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिला रहा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें गंभीरता से सुने, न कि इसे विपक्ष की शिकायत के तौर पर ले। वहीं अगर यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं की मदद दूसरे समुदाय के लोगों ने की तो यह बात सराहनीय है, लेकिन इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती कि उन महिलाओं के साथ ऐसा दुव्यर्वहार हो सके, ऐसी नौबत ही क्यों आई।

मणिपुर में अभी स्थिति संभालने का श्रेय अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इस मामले की गूंज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठी। यूरोपीय संघ से लेकर अमेरिका तक कई जगह मणिपुर में हुए अत्याचारों की निंदा की गई। इस वक्त भी मणिपुर में हालात पूरी तरह से संभले नहीं हैं। हजारों लोग अगर अब भी विस्थापित हैं, तो फिर केंद्र सरकार खुद की पीठ कैसे थपथपा सकती है।

कैसी भाजपा छोड़ जायेंगे अपने पीछे मोदी और शाह?

18वीं

लोकसभा के लिये 7 चरणों में होने जा रहे मतदान का आगाज़ 19 अप्रैल से होने जा रहा है (समापन 1 जून) जिसमें यह तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एवं उसके गठबन्धन को इंडिया के अंतर्गत अपेक्षाकृत विलम्ब से एकजुट हुए प्रतिपक्षी दल तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। अपने तमाम प्रपंचों, संसाधनों और राजशक्ति के उपयोग के जरिये अपनी सफलता के चरम पर पहुंचने के बावजूद भाजपा आश्वस्त नहीं है कि आसन्न आम चुनावों में उसे वैसी कामयाबी मिलेगी जैसी कि उसे पिछली दफ़ा (2019 में) मिली थी; या जैसी वह अकेले 370 तथा संयुक्त रूप से 400 सीटें पाने का दावा कर रही है, उसे वह हासिल कर पायेगी। वैसे तो परिणाम बतायेंगे कि उसे अपेक्षित सफलता मिलती है या नहीं, लेकिन दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पार्टी को जिस स्वरूप में एवं मकाम पर ला खड़ा किया है, वह स्वयं भाजपाइयों के सोचने का विषय होगा कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि कभी उनका संगठन ऐसा हो जायेगा।

शुरुआत यहां से करें कि भाजपा अब तक अपनी मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निर्देशित व परिचालित होता रहा है। साम्यवादी पार्टियों की तरह इसमें भी संगठन का अपने राजनैतिक विंग या सत्ता पर अंकुश रहा है। शासन कोई भी सम्भाले, संघ की इजाज़त के बिना उसमें पत्ता भी नहीं खड़कता था। कारण है कि संघ की ही रणनीति के तहत पहले जनसंघ एवं बाद में भाजपा के रूप में उसकी राजनीतिक शाखाएं बनी थीं। भाजपा के अध्यक्ष पद पर अनेक कद्दावर नेता रहे परन्तु वे भी संघ के नियमों से बंधे होते थे, उनके आदेशों पर चलते थे तथा उसके आगे नतमस्तक रहा करते थे। यह पहली बार होते देखा गया है कि मोदी ने अपनी पार्टी को तो मुट्ठी में कैद कर ही रखा है, संघ भी उन्हीं के अधीन दिखाई पड़ता है। पहले के तमाम भाजपायी नेता, चाहे वे सत्ता के किसी भी पायदान तक क्यों न पहुंच जायें- नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में उन्हें हाजिरी लगानी ही पड़ती थी। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी तक यह काम नियमित अंतराल से करते थे। संघ इतना अशक्त कभी भी नहीं दिखा कि वह शासन के कामकाज में परामर्श तक न दे सके, जो कि उसका अधिकार व कर्तव्य दोनों ही कहे जाते रहे। फिर, भाजपा की सरकारों में पद सम्हालने वाले लोग एक ओर संघ के प्रति जवाबदेह तो होते ही थे, अपने संगठन के पदाधिकारियों के प्रति भी वे उत्तरदायी हुआ करते थे। ऐसा भी अब होता नहीं दिखता। यह हर कोई जानता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की स्थिति क्या है। यहां तक कि मंच पर उन्हें इस तरह से बिठाया जाता है कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फोटो फ्रेम में वे न आयें। निर्णय लेने की सारी ताकत मोदी व शाह के पास है। उन्हें केवल हस्ताक्षर करने और प्रेस बयान जारी करने होते हैं।

डॉ. दीपक पाचपोर

> **भाजपा अब तक अपनी मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निर्देशित व परिचालित होता रहा है। साम्यवादी पार्टियों की तरह इसमें भी संगठन का अपने राजनैतिक विंग या सत्ता पर अंकुश रहा है। शासन कोई भी सम्भाले, संघ की इजाज़त के बिना उसमें पत्ता भी नहीं खड़कता था। कारण है कि संघ की ही रणनीति के तहत पहले जनसंघ एवं बाद में भाजपा के रूप में उसकी राजनीतिक शाखाएं बनी थीं।**

अलबत्ता सरकार पर सम्पूर्ण कब्ज़ा करने की कला के चलते भाजपा का काडर, उसके समर्थक तथा वोटर मोदी-शाह की जोड़ी को फिलहाल पसंद करते हैं और चाहते होंगे कि उनकी ताकत यूं ही बढ़ती रहे लेकिन इस चुनाव के बाद- चाहे भाजपा-एनडीए जीते या हारे- दोनों का नये सिरे से मूल्यांकन होगा। जीतने पर तो वे स्वाभाविकत: इतने ताकतवर हो जायेंगे कि अपने ही संगठन पर भारी पड़ने लगेंगे; और यदि परास्त हुए तो उनका पहला व बड़ा विरोध संगठन के भीतर ही उठ खड़ा होगा। उनकी उन्हीं मुद्दों पर आलोचना होगी जिनके लिये आज तारीफ हो रही है। दोनों के जिन कामों के कारण उनकी आज वाह-वाही हो रही है, वे ही ऐसे मुद्दे बन जायेंगे जिनके आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं के सिर शर्म से झुक जायेंगे। शायद यही कारण है कि मोदी-शाह को खुद के लिये ये चुनाव जीतना उनकी पार्टी की जीत से भी अधिक ज़रूरी हो गया है। तभी तो दोनों ने सारी शक्ति सत्ता में तीसरी बार लौटने के लिये लगा दी है।

मोदी, शाह व भाजपा बार-बार कह रहे हैं कि 'बचे हुए कई महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिये तीसरा कार्यकाल ज़रूरी है।' समझा जाता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं तथा कट्टर हिंदुओं का ऐसा मानना है कि 400 सीटें जीतने पर भाजपा संविधान को बदलने या रद्द करने में समर्थ हो जायेगी। वे सम्भवत: यह नहीं जानते कि मोदी को इतना बड़ा बहुमत इसलिये चाहिये ताकि वे राजनीतिक शक्ति के साथ तमाम आर्थिक व सामाजिक शक्तियों को भी अपनी मुट्ठी में समेट लें। अपने दस साला कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार से पूंजी को अपने चुनिंदा मित्रों के हाथों पूरी तरह से सौंप दिया है, पूर्ण बहुमत मिलने पर वे सारे शासकीय उपक्रम, सभी कारोबार, हर प्रकार के उद्योग उन लोगों के हाथों में औने-पौने भाव से या मुफ्त में दे दिये जायेंगे जो अब तक नहीं दिये गये हैं। इसका कारण है कुछ दलों व नेताओं द्वारा उनका ऐसा करने का प्रखर विरोध। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के जीतने का अर्थ होगा विपक्षी बेंचें खाली होंगीं। पहले 'कांग्रेस मुक्त भारत' और अब 'विपक्ष मुक्त भारत' के नारे देने की मोदी की यही मंशा है कि उनके ये सारे काम बगैर किसी अवरोध के हो सकें। अपने इन उद्देश्यों को पाने के लिये जो-जो करना आवश्यक था, उनमें से अधिकतर तो मोदी कर चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वह सब करने के लिये तीसरी मर्तबा वे पीएम बनना चाहते हैं। पूछा जाये कि वे क्या-क्या कर चुके हैं, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं- नौकरशाही को पूरी तरह से पंगु करना, संवैधानिक संस्थाओं को शक्तिहीन करना, नागरिकों के अधिकारों तथा उनके नागरिक बोध को छीनना। बचा क्या है? तो वह है खुद को आजीवन शासक घोषित कराने की व्यवस्था करना। उसके लिये बेहद ज़रूरी है न्यायपालिका को अपने अधीन करना या उसकी इस प्रकार से पुनर्रचना करना कि सरकार के खिलाफ कोई भी फैसले न लिये जायें। ऐसा करना इसलिये मोदी के लिये ज़रूरी होगा क्योंकि फिलहाल उसके रास्ते में कोई अवरोध है तो वह देश की न्यायपालिका ही। हाल ही में कई फैसले भाजपा सरकार के विरोध में गये हैं। इनसे वे सबक ले चुके होंगे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे।

ऐसे वक्त में जब भाजपा हार की आशंका के साथ अपने एक दशक के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, मोदी-शाह का पूरा चरित्र तथा काम-काज का तौर-तरीका सामने आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनैतिक दल कही जाने वाली भाजपा का पूरा प्रचारतंत्र एक ही चेहरे के ईर्द-गिर्द बुना हुआ है- मोदी के। दो कार्यकाल के बावजूद मोदी के पास विमर्श के नाम पर विपक्षियों को भ्रष्ट व परिवारवादी कहने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मोदी ने खुद ही 'ऑपरेशन लोटस' के नाम पर कई दागी नेताओं व राजनीतिज्ञों के वारिसानों को अपने कुनबे में 'चाणक्यगिरी के नाम पर' शामिल कर लिया है। उनके लिये दरी बिछाने का काम आज वे निष्ठावान कार्यकर्ता कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों संघ-भाजपा की सेवा की है। दल में कंगना रनौत, हेमामालिनी, मनोज तिवारी जैसे लोगों को प्राथमिकता मिलती है ताकि कल को ऐसी पार्टी व संसद बने जहां हां में हां मिलाने वाले ही बैठे हों। जीत या हार दोनों ही सूरतों में मोदी-शाह निर्मित भाजपा कैसी होगी- यह खुद भाजपा तथा संघ समर्थकों को सोचना होगा। वे ऐसा ही चाहते हों तो कोई बात नहीं!

(लेखक देशबन्धु के राजनीतिक सम्पादक हैं)

2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता निभायेंगी अहम भूमिका

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कथा

■ कल्याणी शंकर

महिला मतदाता आगामी 2024 आम चुनाव का फैसला कर सकती हैं? उनके मतदाताओं की बढ़ती संख्या और अनुकूल कानून, जैसे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, उन्हें एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण वर्ग की महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए, वे विभिन्न लाभ की पेशकश कर रहे हैं।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला मतदाताओं का उच्च मतदान 2024 के चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2047 तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55फीसदी तक पहुंच सकता है, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत घटकर 45फीसदी हो सकता है।

गौरतलब है कि भारत के संविधान के निर्माता बी.आर.अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि – 'राजनीतिक शक्ति सभी सामाजिक प्रगति की कुंजी है।' यह कथन आज भी लागू है, क्योंकि महिलाएं तब तक न्याय पाने की उम्मीद नहीं कर सकतीं जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी न हो।

भारत में महिलाएं लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए और अधिक उपायों की मांग कर रही हैं। पिछले सितंबर में संसद ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। यह विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए 33फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने विधेयक के पारित होने का श्रेय लिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, 'यह हमारा विधेयक है।' 2008 में सोनिया गांधी ने इसे उच्च सदन में पारित किया लेकिन लोकसभा में ऐसा करने में विफल रहीं। पिछले सितंबर में पीएम मोदी ने बड़े गर्व के साथ इस विधेयक को पेश किया और पहली बार संसद में इस विधेयक के आने के 27 साल बाद यह लगभग सर्वसम्मति से पास हो गया। जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया में देरी के कारण यह विधेयक चार साल बाद ही लागू हो पायेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री और 15 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। हालांकि, 1950 के दशक के बाद से चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या सात गुना बढ़ गई है, और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5फीसदी से बढ़कर 15फीसदी हो गया है।

विश्व स्तर पर स्थिति समान है। अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 26फीसदी कानून निर्माता महिलाएं हैं। दूसरी ओर, रवांडा में 60फीसदी से अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। 2008 में, रवांडा महिला-बहुमत संसद वाला पहला देश बन गया।

भारत में केवल 14फीसदी संसदीय सीटें महिलाओं के पास हैं। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमश: 78 और 24 महिला सदस्य हैं। संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 193 देशों में 149वें स्थान पर है। इसके अलावा, भारत के प्रत्येक राज्य में 16फीसदी से कम विधायक महिलाएं हैं।

भारत में एक महत्वपूर्ण उपाय 1993 में किया गया तथा पंचायत की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थीं, जिसे अब अधिकांश राज्यों में 50प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। लगभग दस लाख महिलाएं जमीनी स्तर पर सरपंच के रूप में कार्य करती हैं। ये सरपंच अपने स्थूल अनुभव के बल पर उन्नति की सीढ़ियां चढ़ सकेंगी।

आगामी आम चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाता होंगे, जिनमें 47 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 2.63 करोड़ नये मतदाताओं में से 1.41 करोड़ महिलाएं हैं। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अधिक महिलाओं ने मतदान के लिए पंजीकरण कराया है।

महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि राजनीतिक दलों ने विधेयक का समर्थन किया, उन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को अपने टिकटों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत आवंटित किया, आमतौर पर 10-15प्रतिशत। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों में 421 उम्मीदवारों में से महिलाओं को केवल 67 टिकट दिये। हालांकि, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लाभों को पहचाना है।

लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, पार्टियों को महिला सशक्तीकरण के लिए अधिक महिला नेताओं और उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की जरूरत है। हालांकि, कुछ लोगों का तर्क है कि यदि महिलाएं ज्ञात राजनीतिक परिवारों से आती हैं तो वे जीतती हैं। कई नेता उम्मीदवारों को चुनने के लिए अपने परिवार से आगे नहीं देखते हैं। यह समझना जरूरी है कि सभी महिलाएं महिला उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगी।

> **राजनीतिक दलों को मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रोत्साहनों पर निर्भर रहने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई पार्टियां महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन तो देती हैं लेकिन अपनी उम्मीदवार सूची में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व नहीं देतीं। महिला आरक्षण कानून के अनुसार पार्टियों को अपने टिकटों का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए।**

राजनीतिक दलों को मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रोत्साहनों पर निर्भर रहने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई पार्टियां महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन तो देती हैं लेकिन अपनी उम्मीदवार सूची में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व नहीं देतीं। महिला आरक्षण कानून के अनुसार पार्टियों को अपने टिकटों का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पार्टियों को राजनीतिक राजवंशों को दिये जाने वाले तरजीही व्यवहार को हतोत्साहित करना चाहिए।

भारतीय राजनीतिक दल विभिन्न योजनाओं और लाभों के साथ महिला मतदाताओं को लक्षित कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और 2,000 रुपये नकद प्रोत्साहन राशि दिया है। हिमाचल प्रदेश में 18-60 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक दिया जाना है। दिल्ली की 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' भी 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने पारिश्रमिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। आप और कांग्रेस 1,000 रुपये मासिक भुगतान करने और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना भत्ता देने की घोषणा की है।

महिलाओं के प्रति राजनीतिक जवाबदेही निर्णय लेने में लिंग संतुलन हासिल करने, राजनीतिक दलों में महिलाओं की अधिक महत्वपूर्ण उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ावा देने और पार्टी नीतियों और प्लेटफार्मों में लैंगिक समानता के मुद्दों को आगे बढ़ाने से शुरू होती है। इन सबके लिए शिक्षा भी जरूरी है।

हमें ऐसे शासन सुधारों की आवश्यकता है जो लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों। इससे निर्वाचित अधिकारी अधिक प्रतिक्रियाशील हो सकेंगे।

पावन प्रसंग

सद्गुण का पुरस्कार है सम्मान

यश और सम्मान प्राप्त करने की अभिलाथा प्रत्येक मनुष्य को होती है, किंतु जिन कार्यों से सम्मान मिलना संभव होता है, उन्हें करने के लिए बहुत कम लोग राजी होते हैं। झूठे सम्मान के लोभी व्यक्तियों को बहुत प्रयास करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। जिस योग्यता पर यश मिलता है और सम्मान बढ़ता है, उसे बढ़ाया न जाए तो यह महत्वाकांक्षा अधूरी ही बनी ही रहेगी। उचित योग्यता के अभाव में भला किसी को सम्मान मिला भी है? मनुष्य की बड़ी इच्छा होती है कि वह प्रधानमंत्री बन जाए। सेनापति या कोई वरिष्ठ पद पाने की कामना तो बहुत लोग करते हैं,पर राज्य संचालन, सैन्य व्यवस्था की उचित योग्यता न हुई तो यह अधिकार कैसे मिल सकेंगे? संयोगवश यदि मिल भी जाए ता तो बंदर के हाथ में तलवार के समान आफतों को बुलावा देना ही होगा। इस तरह मिला सम्मान दुख-क्लेश और अशांति ही दे सकता है, उससे मनुष्य की आकांक्षा किसी भी तरह पूरी नहीं होती।

आप यदि यह चाहते हैं कि आप सम्मानित व्यक्ति ठहराए जाएं, आपकी प्रशंसा हो, सभी आपको आदर दें, तो आदरणीय पुरुषों की विशेषताओं का आपको अध्ययन करना होगा। जिन गुणों के आधार पर लोग आदर के पात्र गिने जाते हैं, उनका अनुसरण करेंगे तो आपका गौरव भी जाग्रत होगा और बड़प्पन मिलेगा किंतु आप यदि बाहरी ताम-झाम के द्वारा लोगों को भ्रम में डालकर सम्मान प्राप्त करने की कामना करेंगे, तो महंगा मोल चुका कर भी आपके हाथ कुछ न आएगा। गुणों का विकास करने में प्रयत्नशील हों तो संदेह नहीं आप सम्मान प्राप्त करेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। सच्चाई को सिर झुकाते हैं, बनावट को नहीं। टेसू का फूल देखने में बड़ा आकर्षक होता है, किंतु लोग गुलाब की सुवास को अधिक पसंद करते हैं। आप में स्‌द्‌गुण का विकास हो तो आप अवश्य ही प्रशंसा के पात्र हैं। गुणों की मात्रा उतनी बढ़ती है, जितनी मनुष्य की योग्यता विकसित होती है, उसी अनुपात में लोग उधर आकर्षित होते हैं। अच्छा काम करने वालों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। विद्वान सिसरो का कथन है- 'सम्मान सद्गुण का पुरस्कार है।' यह बात अक्षरश: सत्य है कि सच्चा सम्मान गुणवान को ही प्राप्त होता है।

आपके किसी एक गुण का विकास सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना अधिक होगा, उतना ही आपको अधिक यश मिलेगा। कर्ण के युग में दान देने की परम्परा सामान्य थी, किंतु यह प्रवृत्ति कर्ण में विलक्षणता लिए हुए थी। दान की परम्परा में वह श्रेष्ठतम प्रमाण बना इसलिए उसे 'दानवीर' कहलाने का सौभाग्य मिल सका। माता-पिता के प्रति आदर और सम्मान की भावनाएं अधिकांश लोगों में होती हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते हैं, किंतु श्रवण कुमार की पितृभक्ति पराकाष्ठा का स्पर्श करने लगी थी, इसलिए उसे सर्वोच्च ख्याति मिली। सद्गुणों के प्रति निष्ठावान होने से ही सर्वोपरि सम्मान मिलता है।

यों मानवता के प्रति उत्सर्ग की भावना कुछ न कुछ सभी में होती है। अपनी-अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार लोग इस आध्यात्मिक सद्गुण को अपनाते भी हैं, किंतु देवत्व की स्थापना में अपने आपको जीवित होम कर देने के कारण जो बड़प्पन, गौरव और उच्च पद महर्षि दधीचि को मिल गया, वह अन्य किसी को नहीं। यश की साधना में किसी एक सद्गुण पर पूर्ण रूप से निष्ठावान होना पड़ता है। आजीवन ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, परमभक्त हनुमान, महासती अनुसुइया, तपस्वी दुर्वासा, सत्यवादी हरिश्चन्द्र अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उच्चतम सम्मान पाने के अधिकारी बन सके थे। गुणों की विशिष्टता के कारण ही पूज्य पद प्राप्त होते आए हैं। .यह सनातन नियम आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए भी जीवन में सम्मान प्राप्त करने का एक सीधा सच्चा उपाय है और वह है- सबके प्रति शुभ अभिलाषा का भाव। किसी के प्रति बैर- भाव, ईर्ष्या-द्वेष और प्रतिशोध की भावना न रखना, सबके साथ मिलकर प्रेम, न्याय, दया, सहज ही में प्राप्त हो जाती है।

सम्मान प्राप्ति की आध्यात्मिक भूख को बुझाने के लिए हमें अपनी श्रेष्ठताएं और विशेषताएं निरंतर बढ़ानी चाहिए। अपना चरित्र अपेक्षाकृत अधिक उज्जवल बनाने के लिए और जनहित के लिए अधिक त्याग कारने का आवश्यक साहस संचय करना चाहिए। उत्कृष्टता के मूल्य पर ही कोई व्यक्ति जनसाधारण की श्रद्धा का पात्र बन सकता है।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

मानवीय शक्ति और प्राकृतिक संसाधन, विकास और प्रगति के पहिए

जब भी हम अपने विकास का इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का प्रकृति का अंधाधुंध दोहन होता रहा है। आजादी हमें मिली है यानी कि मानव को परंतु प्रकृति आजादी से अछूती रही है। अमूमन हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और जल की थी कि हमको उद्योग धंधे का विकास तीव्र गति से करना पड़ा। मशीनें जितनी बड़ी से बड़ी होती गई आदमी उतना ही बौना होता गया। कृषि में नई-नई तकनीक ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि बंजर होकर कराहने लगी। विकास का सही मायने माननीय शक्तियों के साथ ऊर्जा और उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य का सही उपयोग ही होगा। जब से हमने विकास के पथ पर उड़ान भरी है उद्योगों की चिमनियों को ऊपर उठाया मोबाइल क्रांति का बटन दबाया ई-मेल पर सवार होकर विश्व संदेश को सुना तब से हमारे झरनों का कल-कल स्वर और संगीत बंद हो गया, पक्षियों का कलरव बंद हो गया पक्षी अब चीत्कार कर रहे हैं।

नदी-नाले सूखकर मृतप्राय हो गए हैं। समुद्र की लहरों की झंकार विलुप्त हो गई है और पानी खारा और खारा हो गया है। अब हमें यह सोचना है कि विकास के नाम पर हमें ग्रीन इंडिया चाहिए या इंटरनेट की सवारी कर डिजिटल इंडिया चाहिए। बच्चों की झोली में इंटरनेट को डालकर डिजिटल जेनरेशन का सपना देखना चाहिए या प्रकृति की गोद में सुगंधित वायु की लहरों में खो जाना चाहिए। झरनों में बैठकर नौका विहार का आनंद लेना चाहिए या कंप्यूटर में बैठकर नेट खोल कर नन्हे-मुन्ने की आंखों पर जोर डालकर उन्हें चश्मा वाला बनाना चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान यानी कि ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया का सपना नदी के दो कभी ना मिलने वाले किनारे हैं। विकास के नाम पर असीमित उद्योग-धंधों की बाढ़ आ गई है। भूमि समाप्त हो रही है साथ ही हमारी वायु विषैली हो गई है। रात में शहरी मकानों मैं बिजली के झालरों के सामने आकाश में रात्रि के तारों की चमक फीकी पड़ गई है। जंगलों को हम ऐसे साफ करते गए जैसे सड़क पर रोड रोलर चला रहे हैं। नगर बने, महानगर बने, मकान बने किंतु अब घर गायब होते गए, हमें तब सुध आई जब चिड़िया चुग गई खेत, हमें विकास के नाम पर मानव सभ्यता से जुड़ी जमीन पानी, हरियाली, पक्षी, जानवर सब चाहिए केवल अंधाधुन्ध क्रांकीट का विकास या इंटरनेट की रफ्तार नहीं चाहिए। इसके लिए हमें संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश लगाना होगा। संसाधनों का इस्तेमाल अतिरेक में नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन है, किंतु मानव की लालच को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। हम प्राकृतिक परियोजना तथा परिस्थितिकी की परियोजनाओं का स्वागत करना होगा सम्मान करना होगा। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौर, पवन, बायोगैस, ज्वार तरंग लहरों को ऊर्जा का आधार बनाना होगा।

भारत में परिस्थितियां बड़ी विषम है एक तरफ सोडियम लाइट से नहाती दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की रंगीन सड़कें हैं, ऊंची-ऊंची इमारतें हैं, तेज गति की मेट्रो है,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लुफ्त उठाते हुए युवक-युवतियां है, दूसरी तरफ पसीने से भीगा हुआ किसान हैं। कैरोसिन की चिमनी में बच्चों को कहानी सुनाती माताएं हैं। यानी कि इतनी डिजिटल विषमताएं भारत के अलावा विश्व के किसी भी कोने में नहीं है। भारत में विकास के नाम पर डिजिटलाइजेशन करने की आवश्यकता जरूर है पर गांव जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों के निरस्तीकरण और विनाश की कीमत पर नहीं। हमें यह साबित करना होगा कि भारत के विकास की हरित क्रांति के साथ-साथ डिजिटल इंडिया भी विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत कि हरित क्रांति का विकास ही डिजिटल इंडिया का स्वप्न को भी पूरा करेगा। इसके लिए स्वच्छ साफ-सुथरे संसाधन जैसे जल, खनिज, यूरेनियम,थोरियम नहीं होगा तब तक नाभिकीय रिएक्टर की भट्टियां कैसे चलेंगी। किसी कवि ने कहा है-जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना। पंछी सारे उपवन के चहचहा उठेंगे।

विकास का जो भी रास्ता या नक्शा हम तैयार करेंगे निश्चित तौर पर वह मार्ग हरित क्रांति या हरित विकास से होकर गुजरेगा, जिससे हम अपनी 141 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे और एक नए भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे।

संजीव ठाकुर

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

संपादकीय

कांग्रेस का न्याय पत्र- कितना असरदार?

अखिल भारतीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र 'न्याय पत्र' के नाम से जारी कर दिया है। पार्टी की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इसे जारी किया। भाजपा ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने का आरोप लगाकर कांग्रेस को फिर कटघरे में खड़ा किया। बहरहाल, पार्टी का चुनाव घोषणापत्र 'पांच न्याय' या न्याय के पांच स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के साथ-साथ इसके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादों के तहत लोगों से की गई गारंटी भी शामिल है। पार्टी ने घोषणापत्र में कहा है कि पार्टी जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी और एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। पार्टी का दावा है कि यह न्याय पत्र राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श, ईमेल तथा 'आवाज़ भारत की' वेबसाइट के माध्यम से हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया। बेशक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया हो, लेकिन हकीकत में खुद पार्टी में लोगों को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है और लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर पार्टी नेतृत्व कांग्रेस छोड़कर जा रहे लोगो को रोक क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस या घोषणा पत्र कितना असरदार है। घोषणाओं को न्याय बताना शाब्दिक जादूगरी हो सकती है, लेकिन आम जनता को कितना अपील करेगी, कहना मुश्किल है। जानकारों का मानना है कि न्याय पत्र में शामिल अधिकांश योजनाएं मोदी सरकार की योजनाओं जैसी ही लग रही हैं। इसमें नया क्या है? वैसे भी भारत में चुनावी घोषणा पत्रों का इतिहास यह है कि जिस भी पार्टी को चुनाव में अपने सत्ता में लौटने का भरोसा नहीं होता, वह घोषणा पत्र में बड़े -बड़े और अव्यावहारिक वादे करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का न्याय भी शायद कुछ इसी श्रेणी का है। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके पूर्व कांग्रेस ने जिन राज्यों में चुनाव जीता और इस जीत के लिए जो गारंटियां दी थीं, वो ही ज्यादातर पूरी नहीं हुई हैं। इस न्याय पत्र में कुछ विरोधाभास भी हैं। मसलन पार्टी ईवीएम से चुनाव का पुरजोर तरीके से विरोध करती रही है, लेकिन न्याय पत्र में उसने चुनावी ईवीएम से कराने की ही पैरवी की है। केवल वीवीपैट पर्ची मिलान की बात कही है। रेंडम तौर पर पांच पर्चियों का मिलान तो अभी भी होता ही है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में जो वादे किए गए हैं, वो लगभग भाजपा के वादों के समान ही हैं। एक हद यह भाजपा की योजनाओं की नकल ही हैं, कहें तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया है कि कांग्रेस की ये योजनाएं केवल घोषणाएं नहीं हैं, उन्हें जमीन पर भी उतारा जाएगा। जमीन पर उतारने की बात तो छोड़िए, इन योजनाओं को आम मतदाता तक पहुंचाने की भी कोई कारगर मशीनरी आज कांग्रेस के पास बची नहीं है। ऐसे में भारी भरकम घोषणा पत्र देखने सुनने में अच्छा लग सकता है, उसकी व्यवहार्यता कितनी है, यह बड़ा सवाल है।

राज्य और व्यक्ति की धर्म आस्था का भेद

रघु ठाकुर

22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में, राम लला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्रधानमंत्री जी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वैसे यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस विशाल और व्यापक आयोजन से उनका जनाधार बढ़ा है तथा वे हिंदू मानस के सर्वप्रिय नेता बन गए हैं। यहां तक की हिंदू धर्म गुरु, शंकराचार्य और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के थोक बंद ठेकेदार डॉ. मोहन भागवत जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की आभा के समक्ष पीछे नजर आ रहे हैं।

4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी गुवाहाटी के दौरे पर थे। और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद सत्ता में रहे लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का चलन स्थापित किया। जबकि विकास और विरासत हमारी नीति है कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा तीर्थ मंदिर सभ्यता की यात्रा की निशानियां है। हमारे तीर्थ मंदिर सिर्फदर्शन करने की स्थली नहीं है यह हमारी सभ्यता की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे उसको अटल रखा है यह उसकी साक्षी है। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर या मिटाकर विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि पिछले 10 वर्षों में हालात बदल गये है '। उनकी आखिरी पंक्ति पर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में जो कुछ अच्छा हुआ है वह उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है और जो कुछ खराब हुआ है वह उनके आने के पूर्व का है,यह कहना उनके प्रारंभिक व स्थाई शगल है। एक प्रकार से वे अपने आपको श्शन भूतों न भविष्यती सिद्ध करते रहते हैं। उनकी आत्म प्रशंसा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। विशेषता जिन सज्जनों में योग्यता कम होती है वे दिखावे ज्यादा करते हैं। हमारी पुरानी कहावत है 'अध जल भरी' गगरिया छलकत जाएय। पर मूल प्रश्न जिस पर विचार जरूरी है कि संस्कृति पर शर्मिंदगी का चलन देश में कब था। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा को देवरूप मानने वाले थे, वे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते थे, पर देश में एक ऐसा भी हिंदू समाज या कहें तो हिंदू मानस के विचारकों व धर्म गुरुओं का हिमायती रहा है, जिसने मंदिर व पूजा की परंपरा को स्वीकार नहीं किया। चावार्क ने पाषाण पूजा को स्वीकार नहीं किया तो क्या चावार्क हिंदू नहीं थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि, पत्थर की प्रतिमा में शिव नहीं है तो क्या वे हिंदू नहीं थे? मंदिरों की पुर्नस्थापना तो पहले भी हुई है। क्या स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल प्रथम गृहमंत्री भारत सरकार ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कराया था? हां उसमें स्वर्ण छड़ी से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी कि नही यह में पक्के तौर पर नहीं कह सकता। जहां तक मुझे स्मरण है कि, मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद प्रतिमा स्थापना तो हुई थी परंतु प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल ने तो यह कार्य 1950 के दशक में कराया था तो क्या यह संस्कृति पर शर्मिंदगी का चलना माना जाएगा।

स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल ने, यह पुनर्निमाण, सार्वजनिक रूप से तथा उसके लिए जन सहयोग से कराया था। उसमें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सलाह पर सरकारी खजाने के धन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्योंकि, एक धर्मनिरपेक्ष देश में मंदिरों, मस्जिदों, गिरजागरों का निर्माण कराना सरकार का कर्तव्य नहीं है। इनका निर्माण तो उनके मानने वालों के द्वारा ही होना चाहिए। हालांकि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो सब जगह मंदिरों के पुनर्निमाण या विकास के नाम पर या लोक के निर्माण के नाम पर शासन का पैसा लगा रही हैं।

क्या किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर के पुनर्निर्माण का काम सरकारी खजाने से हो सका है या होना चाहिए। फिर संस्कृति क्या है? यह भी एक विचार का बिंदु है? संस्कृति का मतलब क्या केवल मंदिर या धार्मिक स्थलों,पूजा स्थलों तक ही सीमित है? आजकल लोग सनातन की बहुत चर्चा कर रहे हैं तो सनातन क्या है? क्या वैदिक काल को सनातन का हिस्सा नहीं माना जाएगा? पर वैदिक काल में यज्ञों व हवन का तो जिक्र मिलता है पर मंदिरों का नहीं मिलता। तो क्या यह माना जाए की वैदिक कालीन लोगों को भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं थी? या फिर उन्हें संस्कृति पर शर्मिंदिगी होती थी?

भारत की संरचना में छँटवी शताब्दी के पूर्व की व बाद की स्थिति में फर्क है। इस्लाम के उदय के पूर्व भारत आज के राजनीतिक भूभाग मात्र में सीमित नहीं था वरन कंधार तक फैला था। उस भारत में लगभग एक ही धर्म व परंपराएं प्रचलित थी, पर इस्लाम के उदय के बाद भारत की धार्मिक सीमाएं और फिर कालांतर में राजनीतिक सीमाएं सिकुड़ने लगी। लगभग सातवीं शताब्दी से ही मुगल आक्रमण भारतीय सीमाओं में शुरू हो गए, पहले सिंध व पंजाब में और फिर दिल्ली व समूचे भारत में। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बने, वे उसके पूर्व क्या थे? क्या वे बुद्ध नहीं थे? तो बौद्ध मंदिर भी तो भारतीय संस्कृति की धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हुआ। पर संघ के विचार में बौद्ध या सिख या जैन यह क्या भारतीय संस्कृति या धार्मिक इतिहास का हिस्सा माने जाते है। या क्या संघ एक योजना के तहत सभी गैर हिंदू धर्म परंपरा वालों को उनके धार्मिक स्थलों को, मिटाने की योजना रखता है। फिर एक प्रश्न यह भी है, कि संस्कृति क्या है? क्या संस्कृति केवल मंदिरों मठों या धार्मिक स्थलों में है। क्या संस्कृति व इतिहास एक है। इन प्रश्नों पर गहन विचार की आवश्यकता है। फिर संस्कृति व सभ्यता क्या एक है? इस पर भी विचार करना होगा।

दरअसल इतिहास संस्कृति और सभ्यता तीनों में समय क्रम एक हो सकता है परंतु भिन्नता भी है। इतिहास उन सारी घटनाओं का संकलन है जो अच्छी या बुरी सही या गलत जब जैसी घटी उनका संग्रह व वर्णन है। संस्कृति वे अच्छे सामयिक जीवन मूल्य है या परंपराएं , जो समाज के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकते हैं, मसलन भारत की जाति प्रथा यह संस्कृति या सभ्यता नहीं कहीं जा सकती। परंतु इतिहास का हिस्सा रहेगी और उसके अच्छे बुरे प्रभावों का विश्लेषण होता रहेगा। सभी जीवों या वस्तुओं में जीवन है और इसलिए उसकी रक्षा की जानी चाहिए। वायु, जल, प्रकृति,मानव यह सभी एक ही रूप के कई हिस्से हैं। यह एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो शाश्वत जीवन मूल प्रस्तुत करता है। भारत के इतिहास में दो प्रकार के कालखंड है एक राजा भरत का कालखंड है, जहाँ उनके राज्य के भूभाग का फैलाव भी बहुत व्यापक था और आज के अफगानिस्तान तक या कुछ आगे तक वह भूभाग रहा होगा। हालांकि उस समय की आबादी भी शायद हजारों या लाखों में ही रही होगी और वह कालखंड भी राजतंत्र का है। राजा अच्छा या बुरा होगा यह व्यक्ति पर निर्भर है परंतु लोकतंत्र में शासन अच्छा होगा या बुरा होगा यह जनमत पर निर्भर होगा। भारत का दूसरा कालखंड विभाजित रजवाड़ों का है, जिसमें मोटा-मोटी तौर पर एक धार्मिक या जातीय वर्चस्व का प्रभाव तो था पर राजा अनेक थे एक नहीं। लगभग 475- 500 छोटे-छोटे राजतंत्र में वह प्राचीन भारत बंट चुका था और इनमें भी आदिवासी अंचलों के छोटे-छोटे राज्य थे, राजा थे वे अलग ही हैं। दरअसल 475- 500 रजवाड़ों की संख्या या गिनती आजादी के समय हुई, जब भारत आजाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें भारतीय राज्य में विलय कराया। परंतु ये वह राजवाड़े थे जो भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए आमतौर पर अनिच्छुक थे या लाचार हुए। परंतु आदिवासी अंचलों के जो राजवाड़े थे और उनमें भी विशेषतरू जो आदिवासी राजा थे उन्होंने बाहर से अलग रहने के बारे में कभी नहीं सोचा और उनके विलय के लिए तत्कालीन भारत सरकार को या सरदार पटेल को कोई प्रयास नहीं करना पड़े। जिन आदिवासी अंचलों में गैर आदिवासी राजा थे वह अवश्य अपने रजवाड़े को भारतीय राज्यों में विलय करने के मन से इच्छुक नहीं थे। याने एक अर्थ में आदिवासी और उनके आदिवासी राजा अधिक राष्ट्रीयता के पोषक थे। जबकि उनकी परंपराओं में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी, देश के अन्य राजाओं व रजवाड़ों से अलग थी। उनके ईश्वर के रूप में वे बूढ़ा देव को मानते हैं और इस बूढ़ा देव के रूप में किसी वृक्ष या पत्थर को मानते हैं। बूढ़ा देव से तात्पर्य होता है सबसे प्राचीन यानी उनका सनातन बूढ़ा देव है, परंतु आर्य सभ्यता से प्रभावित या उसके मानने वालों की परंपराएं अलग रही हैं। आरंभिक काल में वे अग्नि को देवता मानते थे और पूजा करते थे? शायद इसका कारण यह रहा होगा कि जिस अंचल में उनका जन्म हुआ वह बर्फीला व सर्दी वाला क्षेत्र रहा होगा और इसलिए उन्हें अग्नि ही सर्वोपरीय थी। बाद के काल में भारतीय समाज के बड़े हिस्से ने राम,कृष्ण,शिव को अपना भगवान माना और विभिन्न व्याख्याएं की। इस्लाम के अनुयायियों ने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया और वह एक अल्लाह को मानते रहे। ईसाई, ईसा मसीह के अनुयायी हैं जिनकी प्रतिमाएं हैं। बौद्ध व जैन भी प्रतिमा पूजक है, परंतु सिख पंथ व्यक्ति के बजाय गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा करता है। यह सब अपने अपने कालखंड और मान्य लोगों के चिंतन व कार्य के परिणाम है। जिनके बारे में अच्छे बुरे सही या गलत की बहस हो सकती है। सभ्यता से तात्पर्य मानव जीवन के विकास की कहानी है कि, किस प्रकार मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक पहुंचा है। उसमें विज्ञान, कृषि कार्य, विचार, धर्म व्यवस्था आदि सभी शामिल है। अब प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि देश के तीर्थ व मंदिर सभ्यता यात्रा की निशानियां है तो उनके ज्ञान पर प्रसिद्ध चिन्ह लगना स्वाभाविक है? तीर्थ और मंदिर समाज के एक हिस्से की मान्यता और परंपराओं का हिस्सा है।यह सभ्यता की यात्रा की निशानियां नहीं है और अगर इसे सभ्यता की निशानियां माना जाएगा तो फिर देश को संकीर्ण नजरिए से देखना होगा। यह एक प्रकार का मानसिक विभाजन हो रहा है। क्योंकि पूजा के स्थल लगभग सभी धर्मावलंबियों के अलग-अलग हैं और उनके मान्य तीर्थ स्थल भी अलग-अलग है। इस्लाम को मानने वालों का तीर्थ, मक्का मदीना हो सकता है, सिख धर्म को मानने वालों का ननकाना साहिब हो सकता है, और यह दोनों भारत की राजनीतिक सीमाओं के बाहर है। यह एक प्रकार के नए मानसिक विभाजन व विवाद को जन्म देगा। संभव है कि, अभी सत्ता या मीडिया के प्रभाव में यह प्रश्न बड़ी संख्या में लोगों के दिलों या मनों के अंदर दबे हैं और उनके प्रस्फुटन का यह अनुकूल समय ना हो, परंतु व्यक्ति की मूल आस्थाओं को दुनिया में कभी भी स्थाई तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। बदलाव तो हो सकता है परंतु यह स्वैच्छिक होता है। सत्ता या विचार के मानसिक दबाव में कई बार कुछ विचार दब जाते है, परंतु समय पाकर वे पुनरू सामने आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरी बात कही कि हमारी नीति विकास व विरासत की है। विकास की बात तो समझ में आती है भले ही विकास की धारणा भिन्न-भिन्न प्रकार की हो। जैसे वह कहते हैं सबका विकास सबका साथ और इस शब्द में अदानी, अंबानी,टाटा सभी का विकास है, और खेत पर काम करने वाले मजदूर का भी। यह एक सुनिश्चित बात है कि पूंजीवाद का विकास, मजदूर और श्रमिक के अर्थ उपार्जन के बड़े हिस्से को पूंजी के आधार पर अपने पास रख लेना होता है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि श्रमिकों के शोषण से पूंजीवाद का विकास हुआ है। मतलब साफ है कि, पूंजीपति का विकास और सामान्य व्यक्ति का विकास एक साथ समान रूप से संभव नहीं है। विषम रूप से संभव है कि, उद्योगपति या पूंजीपति की संपत्ति लाखों करोड़ों की हो जाए और मजदूर की आय कुछ हजार या लाख तक पहुंच जाए यह सब का विकास नहीं कहा जा सकता। सबके विकास का तात्पर्य यह होना चाहिए कि सबका सम विकास।

अगर एक व्यक्ति या देश के कुछ लाख लोग करोड़ों रुपया प्रति माह कमाते हैं तथा 80-90 करोड़ लोग सरकारी भीख रूपी 5 किलो अनाज को लेकर जिंदा रहते हैं तो यह सब का विकास नहीं हो सकता और फिर विरासत भी सब की वाह्य प्रतीकों में एक नहीं हो सकती है। मूल्यों व सिद्धांतों की विरासत तो वैश्विक, सार्वदेशिक या संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। परंतु धार्मिक स्थलों की विरासत संपूर्ण समाज के लिए एक समान नहीं हो सकती। इसे एक करने का प्रयास ग्रह कलह जैसा होगा और इसलिए धार्मिक विरासत धर्मावलंबियों की अपनी-अपनी होती है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में इसीलिए यह सिद्धांत तय किया जाता है कि, व्यक्ति को धर्म के मानने की आजादी और राज्यों को किसी एक धर्म की बजाय सभी को समान व्यवहार देना यही लोकतंत्र का मूल्य व आत्मा है।

अध्यात्म

भक्त का भाव ही प्रभु को प्रिय है

बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था।

वे ब्राह्मण के पास पहुँचे जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था । डोगरे जी ने उसको इक्कीस रुपये दिये और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोगरे जी को जबर बुखार ने धर दबोचा। बनारस के सर्वोत्तम डाक्टर के यहाँ पहुँच गए। भोर के सवा चार बजे ही उठकर डोगरे जी बैठ गये और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की।

एक छोटी-मोटी सी भीड़ साथ लिये डोगरे जी मंदिर पहुँचे, वही ब्राह्मण अपने ठीहे पर बैठा पाठ कर रहा था। डोगरे जी को उसने प्रणाम किया और बताया कि वह अब उनके बताये मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक ने सिर इनकार में हिलाया, और बोले- पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिये। वे क्रुद्ध थीं, बोलीं कि तू अपने काम से काम रखा कर बस। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था। तू उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया और वो रुक-रुक कर सावधानीपूर्वक पढ़ रहा है। जा और कह दे उसे कि जैसे पढ़ रहा था, बस वैसे ही पढ़े। इतना कहते-कहते डोगरे जी के आँसू बह निकले। रुंधे हुए गले से वे बोले-महाराज, उमर बीत गयी, पाठ करते, माँ की झलक न दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुये, जिसके लिये जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो, करो। जब सामने पड़ें, आशीर्वाद का हाथ इस मदांध मूढ के सर पर रख देना।

नए दल और नए मुखौटे में कितना भाएंगे..

मध्यप्रदेश में दूसरे दल से भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पाला बदलने की राजनीति से आम लोग अब अजिज आ गए हैं। क्यों कि लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के घर के सामने दलबदलुओं का बाजार लगने लगा है। लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा है,कि मतदाताओं के गुस्से का वो शिकार भी हो सकते हैं। एक दूसरे को पूछ रहे हैं, कि तू कब भाजपा में जा रह है। तू कांग्रेस में क्यों जा रहा है। बहुत हो गया अब बसपा और सपा,छोड़ भी दो। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में जाने की होड़ मची हुई है।बीजेपी ने कांग्रेस से आने वालों का स्वागत करके साबित किया,कि राजनीति में किसी के लिए कोई अछूत नहीं है। समीकरण ही सब कुछ है। सवाल यह है कि कई दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में जाने वालों को क्या मिल जाएगा? कहीं यह भटकाव उनकी राजनीति का अंत तो नहीं कर देगा।

रमेश कुमार 'रिपु'

विपक्ष का आरोप है,कि केन्द्र की बीजेपी सरकार चुनावी समर की तैयारी में सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। उससे कांग्रेसी नेताओं के साथ अन्य दल के नेताओं में भय है। वो यही मान कर चल रहे हैं,कि बीजेपी में चले जाने से ही उनका सियासी वजूद झक सफेद हो जाएगा। साथ ही उन्हें लगता है,कि आने वाला कल बीजेपी का ही है। चुनाव गैर बराबरी का मुकाबला है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सत्ताई पार्टी के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं,'' चुनाव तक 70 हजार से एक लाख कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जरूरी हुआ तो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे।''अभी तक पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित 7पूर्व विधायक,दो महापौर,207 पार्षद,सरपंच और 1500 पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित 21 हजार कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल गांधी,प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके की तारीफ किया करते थे,उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ सभापति प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी बदल ली। इससे पहले अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस छोड़ी थी। देवालपुर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के फुफेरा भाई बलराम ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। कमलनाथ के साथ 50 साल से रह रहे सबसे भरोसेमंद दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उनके बेटे अजय ने बीजेपी ज्वाइन की। कुछ दिनों बाद दीपक भी बीजेपी में शामिल हो गए।गौरतलब है,कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब वे विधानसभा सदस्य नहीं थे। उनके लिए प्रोटेम स्पीकर रहे दीपक सक्सेना ने फरवरी 2019 में पद से इस्तीफा देकर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट खाली की थी। इसके बाद उपचुनाव जीतकर कमलनाथ विधायक बने थे। उस समय कयास लगाए जा रहा था,कि कमलनाथ के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद दीपक सक्सेना यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को मैदान में उतारा। दीपक सक्सेना तभी से कांग्रेस में अपने आपको उपेक्षित महूसस कर रहे थे। दीपक के बेटे अजय कहते हैं कि नकुलनाथ के सांसद बनने के बाद छिंदवाड़ा में पार्टी की कार्यप्रणाली बदल गई थी। मैंने अपनी नाराजगी कमलनाथ जी को बता दी थी। कमलनाथ हमारे पिता के समान हैं। उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये वक्त बीजेपी का है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हैं,छिदवाड़ा अब हमारे लिए छिन्न भिन्न वाड़ा हो गया है। अब यहां भी कमल खिलेगा।पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश पचौरी कहते हैं,कैलाश विजयवर्गीय से हमें मंत्र सीखना चाहिए,कि चुनाव लड़ें तो जीता कैसे जाता है। भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा को आयोजन पर मिले निमंत्रण पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने ठुकरा दिया गया। मुझे अघात लगा। मैं शुरू से अयोध्या में राम मंदिर बने, इसका पक्षधर रहा। कभी कांग्रेस में एक नारा लगा करता था। न जात पर न पात पर,मोहर लगेगी हाथ पर। अब इस नारे को दरकिनार कर दिया गया है। इन दिनों राजनीति से जाति जा नहीं रही है। जाति को अहमियत दी जा रही है। किस जाति के नेता को अपने दल में शामिल करने से कितना फायदा होगा। इसका आकलन किया जाता है।कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे नेताओं को लेकर जुबानी जंग जारी है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में आकर सुकून महसूस करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक तरीके से काम करने की प्रणाली सभी को आकर्षित करती है।उधर आगर.मालवा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई होती है। जो छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें धंधा करना है। दलाली करनी है। लेकिन वे अकेले ही जा रहे हैं जनता उनके साथ नहीं जा रही।

बीजेपी में कांग्रेसियों के आने का साइड इफेक्ट तो शुरू नहीं हो गया मीडिया के इस सवाल पर पूर्व मंत्री और छतरपुर से विधायक ललिता यादव ने कहा था,हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन है, कि भाजपा को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं को एडजस्ट होना पड़ेगा,एडजस्ट नहीं करेंगे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा,ग्वालियर में अमित शाह कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे। एक कार्यकर्ता ने पूछा. साहब जो ये नई भर्ती हो रही है इसका क्या करें। इसके जवाब में शाह ने कहा. ऐसे लोग हाथ उठाओ जिनको पार्टी में काम करते 15 साल हो गए। बहुत लोगों ने हाथ उठा दिए। शाह ने कार्यकर्ताओं से पूछा, तुम्हें 15 साल में क्या मिला। कार्यकर्ताओं ने कहा,कुछ नहीं मिला। इस पर शाह बोले,जब तुम्हें 15 साल में कुछ नहीं मिला तो जिनको आज 15 दिन हुए, उनको क्या ही मिलेगा।लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेसियों को लेकर कांग्रेस में हलचल है तो वहीं बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने भूपेन्द्र सिंह के इस भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेता और कार्यकर्ता इस वीडियो को जरूर सुनें। क्योंकि ये हम नहीं,भाजपा नेता स्वयं बोल रहे हैं।

संभागीय मुख्यालय रीवा के अल्पसंख्यकों के रहनुमा और पूर्व जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ मुजीब जो कि दो बार विधान सभा चुनाव लड़ चुके हैं। जीते नहीं मगर, कांग्रेस से हमेशा ज्यादा वोट पाया। उनके भाजपा में शामिल होने से रीवा जिले की मुस्लिम राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। डॉ मुजीब कहते हैं, कांग्रेस में बहुत सालों तक रहा। अब कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की पूछ नहीं है।राजनीति की बदलती हवा कहती है,भाजपा में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। समाज सेवा करना है तो भाजपा में शामिल होना बेहतर समझा। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि डॉ मुजीब की धर्म निरपेक्षता की कलई खुल चुकी है। उनके कांग्रेस छोड़ने से हमारी पार्टी में कोई असर नहीं पड़ने वाला।इसी कड़ी में पूर्व जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष और सेमरिया विधान सभा का चुनाव लड़ चुके त्रियुगी नारायण भगत शुक्ला लोकसभा की टिकट विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को दिये जाने पर नाराज होकर भाजपा में चले गए। उनका कहना था कि महिला को टिकट देना ही था तो कविता पांडे को देते। अब कांग्रेस में अच्छे और सक्रिय कार्य कर्ताओं की पूछ परख नहीं है। शिवेन्द्र सिंह पूर्व नगर पंचायत सिरमौर,रामावतार यादव महामंत्री जिला कांग्रेस, जमुना यादव कांग्रेस पिछड़ा वर्ग पूर्व उपाध्यक्ष सहित कई लोाग भाजपा में शामिल हुए। पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के निज सचिव और सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा भी भाजपा में शामिल हो गए। डिप्टी सी.एम.राजेन्द्र शुक्ला पूरी कोशिश में हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं,वो भाजपा में आ जाए। दरअसल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की शुरूआत विधान सभा से हुई। पूर्व सांसद सुन्दर लाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को त्योंथर से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो भाजपा में चले गए। भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया। वो विधायक बन गए। अब श्रीनिवास तिवारी से जुड़े जितने भी कांग्रेसी हैं, सभी एक-एक करके भाजपा में जाने लगे हैं। रीवा में 68सरपंच,19जनपद सदस्य और दो हजार कांग्रेस कार्य कर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

बेवजह के खर्चों से आपको बचना चाहिये। गुस्से के बजाय शान्तिपूर्वक कार्य करें। सोच-विचार में ज्यादा समय व्यर्थ न गँवायें।

वृषभ

आपकी दिनचर्या काफी अनुशासित रहने वाली है। मित्र आपकी काफी मदद करेंगे। व्यापार में नये अनुबन्ध हो सकते हैं।

मिथुन

आप कार्यक्षेत्र में काफी सक्रिय रहेंगे। मान-सम्मान में कमी आ सकती है। जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। लेकिन आपके कार्य बाधा के साथ पूर्ण होंगे।

कर्क

आपको इच्छित जगह पर स्थानान्तरण मिल सकता है। धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी। अविवाहितों को वैवाहिक प्रस्ताव मिलने की सम्भावना है।

सिंह

आज दिन की शुरुआत उदासीन हो सकती है। नया कार्य शुरू करने में कठिनाइयाँ होंगी। विरोधियों के सामने आपको सावधान रहना चाहिये।

कन्या

प्रभावशाली लोगों के बीच आप काफी लोकप्रिय रहेंगे। व्यापार में नये प्रयोग करने से बचें। जीवनसाथी की सेहत को लेकर कुछ चिन्ता होगी।

तुला

आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। नये विषयों के अध्ययन में आप रुचि लेंगे। भावनात्मक रूप से काफी कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक

दाम्पत्य जीवन काफी सुखद रहेगा। व्यापारिक यात्राओं के लिये दिन बहुत बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास के कारण बॉस प्रसन्न रहेंगे।

धनु

आज पूरा ध्यान अपने काम पर ही रखें। छोटी सी त्रुटि के कारण काम रुक सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़ी परेशानी होगी।

मकर

कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी काफी प्रसन्न रहेंगे। पदोन्नति मिलने की सम्भावना बन रही है। घर में मेहमान आ सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है।

कुंभ

स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिये। अनावश्यक विषयों पर चर्चा करने से बचें।

मीन

जनसम्पर्क का दायरा मजबूत होगा। जीवनसाथी से मन की बातें शेयर करेंगे। गुमी वस्तु वापस मिल सकती है। विद्यार्थियों को करियर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

अपराधियों को संरक्षण देती ममता सरकार

पश्चिम बंगाल में आपराधिक घटनाओं को सियासी रंग देने का पुराना इतिहास रहा है। अब चाहे वहां वामपंथी शासन रहा हो, कांग्रेस का हो या अब तृणमूल कांग्रेस का हो। लेकिन शुरूआती सूचनाओं के हिसाब से जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ठीक नहीं है। निस्संदेह, आम चुनाव की तरफ बढ़ रहे देश में जांच एजेंसियों के एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठना भी स्वाभाविक ही है। इससे जहां एजेंसियों की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं देश की चुनाव प्रक्रिया पर भी आंच आती है। बहरहाल इस घटनाक्रम के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के दस सांसदों ने सोमवार को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर धरना दिया। पुलिस बाद में सांसदों को जबरन उठाकर ले गई। लेकिन इसके बावजूद किसी मामले में जांच-पड़ताल को गई किसी एजेंसी के अधिकारियों पर हमला करना भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। ऐसे मामले में भीड़ की अराजकता स्वीकार्य नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर क्षेत्र में शनिवार की सुबह एनआईए अधिकारियों पर हमले का निष्कर्ष है कि राज्य के तंत्र ने विगत के घटनाक्रम से कोई सीख नहीं ली। ध्यान रहे कि इस साल की शुरूआत में संदेशखाली प्रकरण में भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम भीड़ के हमले का शिकार बनी थी। फिर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी। जाहिर है ऐसे घटनाक्रम राजनीति से इतर स्वतंत्र जांच की उम्मीद को खत्म करते हैं। निस्संदेह घटनाक्रम से जुड़े वास्तविक तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां उल्लेखनीय है कि एनआईए यह जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पर कर रही है। दरअसल, मामला साल 2022 में हुए एक बम धमाके से जुड़ा है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। जिसकी जांच लंबे अर्से बाद उच्च न्यायालय द्वारा एनआईए को सौंपी गई। एजेंसियों ने पूछताछ के लिये आरोपियों को कई बार बुलाया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि एजेंसी ने यह कार्रवाई उचित नियमों के अनुरूप ही की है। बहरहाल, राजनीति से इतर हमें मानना होगा कि किसी मामले में केंद्रीय एजेंसी से जुड़े अधिकारियों पर हमला व कामकाज में अवरोध पैदा करना संघीय व्यवस्था के लिये घातक ही है। उल्लेखनीय है कि संदेशखाली में भी ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था। लेकिन राज्य सरकार ने मुख्य आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में विवाद बढ़ते देख आरोपियों को तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। आरोपी पार्टी का बाहुबली नेता था। घटनाक्रम से राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे।

ओडिसा का चुनावी रण

ओडिशा में नवीन पटनायक का सिक्सर कितना आसान !

महेश खरे

147 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को समाप्त होगा। नवीन पटनायक विधानसभा में सिक्सर मारने की तैयारी में हैं। लोकसभा में भाजपा जीती तो नरेन्द्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। सवाल यही है कि आखिर बीजेपी और बीजेडी में एकराय क्यों नहीं बन पाई। सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि बीजेडी को अकेले चुनाव लड़ना फायदेमंद रहा। 2009 में एनडीए से अलग होने के बाद नवीन पटनायक ने अपने बूते सरकार बनाई। 2014 में भी बीजेडी को 117 सीटें मिलीं। जबकि कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 2019 में जीत का सिलसिला जारी रहा। 112 सीटों के साथ बीजेडी सरकार बनी। बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें मिलीं। एनडीए से अलग होने के बाद नवीन पटनायक हमेशा केन्द्र की मोदी सरकार के साथ टकराव की नीति अपनाने के बजाय सहयोग की मुद्रा में रहे। मोदी भाजपा का इकलौता लोकप्रिय चेहरा हैं। वे सीना ठोक कर कहते भी हैं। एक अकेला सब पर भारी। नवीन पटनायक भी ओडिशा के अपने हैं। सरल और सहज। उनकी ताकत भी वही विकास है जिसके बूते भाजपा अपनी विजय यात्रा जारी रखे हुए है। यह अलग बात है कि आज जाति, धर्म, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के शोर में विकास की बातें गाहे बगाहे ही उभर कर सामने आ पाती हैं। महाभारत की सीख भी यही है कि जब परनिंदा हथियार बनती है तो प्रेम और सद्भाव मन वचन से तिरोहित हो जाते हैं। चुनावी सियासत में कड़वे और जहरीले बोल मतदाता को कितना आकर्षित कर पाएंगे अभी कहना मुश्किल है।

सियासत के रिश्ते भी बड़े निराले हैं। दोस्त बनो या दुश्मन। भाजपा ने बहुत कोशिश की पर बात नहीं बन पाई। नतीजतन अब ओडिशा के चुनावी महासमर में बीजू जनता दल (बीजेडी) और भाजपा आमने सामने हैं। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। 147 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को समाप्त होगा। नवीन पटनायक विधानसभा में सिक्सर मारने की तैयारी में हैं। लोकसभा में भाजपा जीती तो नरेन्द्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। सवाल यही है कि आखिर बीजेपी और बीजेडी में एकराय क्यों नहीं बन पाई। सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि बीजेडी को अकेले चुनाव लड़ना फायदेमंद रहा। 2009 में एनडीए से अलग होने के बाद नवीन पटनायक ने अपने बूते सरकार बनाई। 2014 में भी बीजेडी को 117 सीटें मिलीं। जबकि कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 2019 में जीत का सिलसिला जारी रहा। 112 सीटों के साथ बीजेडी सरकार बनी। बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें मिलीं। एनडीए से अलग होने के बाद नवीन पटनायक हमेशा केन्द्र की मोदी सरकार के साथ टकराव की नीति अपनाने के बजाय सहयोग की मुद्रा में रहे।

मोदी भाजपा का इकलौता लोकप्रिय चेहरा हैं। वे सीना ठोक कर कहते भी हैं। एक अकेला सब पर भारी। नवीन पटनायक भी ओडिशा के अपने हैं। सरल और सहज। उनकी ताकत भी वही विकास है जिसके बूते भाजपा अपनी विजय यात्रा जारी रखे हुए है। यह अलग बात है कि आज जाति, धर्म, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के शोर में विकास की बातें गाहे बगाहे ही उभर कर सामने आ पाती हैं। महाभारत की सीख भी यही है कि जब परनिंदा हथियार बनती है तो प्रेम और सद्भाव मन वचन से तिरोहित हो जाते हैं। चुनावी सियासत में कड़वे और जहरीले बोल मतदाता को कितना आकर्षित कर पाएंगे अभी कहना मुश्किल है।

शोर कम, काम ज्यादा

सफर में ओडिशा सरकार के एक अधिकारी भी मिले। कहते हैं हमारे राज्य में प्रचार कम काम ज्यादा होता है। पीएम मोदी और सीएम नवीन की तुलना करते हुए वे कहते हैं। मोदी शो मैन हैं। काम से ज्यादा प्रचार है। नवीन एक साइलेंट सेवक हैं। काम का शोर नहीं करते। एक पंक्ति में अगर कहा जाए तो हमारे सीएम सच्चे अर्थों में 'ए मैन फॉर द पीपल' हैं। जबकि नवीन के आलोचक यह आरोप लगाने से नहीं चूकते कि मुख्यमंत्री से विधायक भी मिल नहीं पाते हैं।

महिलाओं को तरजीह

ओडिशा में महिलाओं को तरजीह मिलती रही है। इस बार 3, 29, 83, 643 कुल मतदाताओं में 1, 61, 83, 835 महिलाएं हैं। ओडिशा महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में बीजेडी सबसे आगे है। बीजेडी ने अब तक 20 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छह सीटों पर महिलाओं को मौका मिला है।

एकमात्र बालेश्वर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। अगर इस सीट पर बीजेडी किसी महिला प्रत्याशी को उतारती है तो पार्टी 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का वादा पूरा कर लेगी। वर्तमान लोकसभा में बीजेडी के महिला सांसदों की संख्या भी सबसे अधिक है। 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनकर पहुंचीं थीं। इनमें से सात महिला सांसद ओडिशा से हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

हिंदू कालगणना पर आधारित है वर्ष प्रतिपदा

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित कालगणना को विश्व की सबसे प्राचीन पद्धति माना जाता है। दरअसल भारत में कालचक्र प्रवर्तक भगवान शिव को काल की सबसे बड़ी इकाई के अधिष्ठाता होने के चलते ही उन्हें महाकाल कहा गया। वहीं कलयुग में विक्रमादित्य द्वारा नए संवत का प्रारम्भ परकीय विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त कराने के महाअभियान की सफलता का प्रतीक माना गया है। इधर स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. मेघनाद साहा की अध्यक्षता में एक ह्यकलैंडर रिफार्म कमेटीह्ल का गठन किया गया था। वर्ष 1952 में ह्यसाइंस एंड कल्चरह्ल पत्रिका में प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार, लगभग पूरे विश्व में लागू ईसवी सन का मौलिक सम्बंध ईसाई पंथ से नहीं है और यह यूरोप के अर्धसभ्य कबीलों में ईसामसीह के बहुत पहले से ही चल रहा था। इसके अनुसार एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन ही होते थे। वर्ष के कैलेंडर में जनवरी एवं फरवरी माह तो बाद में जोड़े गए हैं। पुरानी रोमन सभ्यता को भी तब तक ज्ञात नहीं था कि सौर वर्ष और चंद्रमास की अवधि क्या थी। यही दस महीने का साल वे तब तक चलाते रहे जब तक उनके नेता सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं कर लिया। ईसा के 530 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, ईसाई बिशप ने पर्याप्त कल्पनाएं कर 25 दिसम्बर को ईसा का जन्म दिवस घोषित किया। वर्ष 1572 में तेरहवें पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर को दस दिन आगे बढ़ाकर 5 अक्टोबर (शुक्रवार) को 15 अक्टोबर माना, जिसे ब्रिटेन द्वारा 200 वर्ष उपरांत अर्थात वर्ष 1775 में स्वीकार किया गया। साथ ही, यूरोप के कैलेंडर में 28, 29, 30, 31 दिनों के महीने होते हैं, जो विचित्र है क्योंकि यह न तो किसी खगोलीय गणना पर आधारित हैं और न ही किसी प्रकृति चक्र पर।

इसके अनुसार एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन ही होते थे। वर्ष के कैलेंडर में जनवरी एवं फरवरी माह तो बाद में जोड़े गए हैं। पुरानी रोमन सभ्यता को भी तब तक ज्ञात नहीं था कि सौर वर्ष और चंद्रमास की अवधि क्या थी। यही दस महीने का साल वे तब तक चलाते रहे जब तक उनके नेता सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं कर लिया।

भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार नए वर्ष का प्रारम्भ वर्षप्रतिपदा के दिन होता है। वर्षप्रतिपदा की तिथि निर्धारित करने के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। ब्रह्मपुराण पर आधारित ग्रन्थ ह्यकथा कल्पतरुह्ल में कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और उसी दिन से सृष्टि संवत की गणना आरम्भ हुई। समस्त पापों को नष्ट करने वाली महाशांति उसी दिन सूर्योदय के साथ आती है।

वर्ष प्रतिपदा का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए इसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पूजा ह्यॐह्ल का सामूहिक उच्चारण, नए पुष्पों, फलों, मिष्ठानों से युग पूजा और सृष्टि की पूजा करनी चाहिए। सूर्य दर्शन, सुर्यर्ध्य प्रणाम, जयजयकार, देव आराधना आदि करना चाहिए। परस्पर मित्रों, सम्बन्धियों, सज्जनों का सम्मान, उपहार, गीत, वाध्य, नृत्य से सामूहिक आनंदोत्सव मनाना चाहिए तथा परस्पर साथ मिल बैठकर समस्त आपसी भेदों को समाप्त करना चाहिए। चूंकि यह ब्रह्मा द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ तिथि है अत इसको प्रथम पद मिला है, इसलिए इसे प्रतिपदा कहते हैं। हमारा यह शास्त्रीय विधान पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। जागरण के इस काल में हमें काल पुरुष जगा रहा है, ऐसी सनातन संस्कृति में मान्यता है। आइये, हम भी हिंदुत्व के उगते सूरज के सम्मान और अभ्यर्थना में उठ खड़े हों।

वैदिक शुभकामना

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तावश्र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिरदधातु।।

अर्थात, महान यशस्वी इंद्र एश्वर्य प्रदान करें, पूषा नामक सूर्य तेजस्विता प्रदान करें। ताक्षर्य नामक सूर्य रसायन तथा बुद्धि द्वारा रोग-शोक का निवारण करें तथा बृहस्पति नामक गृह सभी प्रकार के मंगल तथा कल्याण प्रदान करते हुए उत्तम सुख समृधि से ओतप्रोत करें। उक्त मन्त्र में खगोल स्थित क्रान्तिव्रत के समान चार भाग के परिधि पर समान दूरी वाले चार बिन्दुओं पर पड़ने वाले नक्षत्रों क्रमशः इंद्र, पूषा ताक्षर्य एवं बृहस्पति अर्थात चित्रा, रेवती, श्रवण ०पुष्य नक्षत्रों द्वारा क्रान्ति व्रत पर 180 अंश का कोण बनता है। यह वैदिक पुरुष द्वारा की गई जन कल्याण की कामना है।

वर्ष प्रतिपदा हिंदू काल गणना पर आधारित है और इसके साथ अन्य कई वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हैं। इसी दिन वार्सतिक नवरात्रि का भी प्रारम्भ होता है और वर्ष प्रतिपदा से ही नौ दिवसीय शक्ति पर्व प्रारम्भ होता है तथा सनातनी हिंदू इसी दिन से शक्ति की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सतयुग के खंडकाल में भारतीय (हिन्दू) नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रारंभ हुआ था क्योंकि इसी दिन ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया गया था। आगे चलकर त्रेतायुग में वर्षप्रतिपदा के दिन ही प्रभु श्रीराम का लंका विजय के बाद राज्याभिषेक हुआ था। भगवान श्रीराम ने वानरों का विशाल सशक्त संगठन बनाकर असुरी शक्तियों (आतंक) का विनाश किया था। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और रामराज्य की स्थापना हुई थी। अगले खंडकाल अर्थात द्वापर युग में युधिष्ठिर संवत का प्रारम्भ भी वर्षप्रतिपदा के दिन हुआ था। महाभारत के धर्मयुद्ध में धर्म की विजय हुई और राजसूय यज्ञ के साथ युधिष्ठिर संवत प्रारम्भ हुआ। आगे कलयुग के खंडकाल में विक्रम संवत प्रारम्भ हुआ। सम्राट विक्रमादित्य की नवरत्न सभा की चर्चा आज भी चहुंओर होती है। यह भारत के परम वैभवशाली इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस नवरत्न सभा में निम्नलिखित रत्न शामिल थे - (1) धन्वन्तरि-आयुर्वेदाचार्य; (2) वररुचि-व्याकरणचार्य; (3) कालीदास-महाकवि; (4) वराहमिहिर-अंतरिक्षविज्ञानी; (5) शंकु-शिक्षा शास्त्री; (6) अमरसिंह-साहित्यकार; (7) क्षणपक-न्यायविद दर्शनशास्त्री; (8) घटकर्पर-कवि; (9) वेतालभट्ट-नीतिकार।

भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित कालगणना को विश्व की सबसे प्राचीन पद्धति माना जाता है। दरअसल भारत में कालचक्र प्रवर्तक भगवान शिव को काल की सबसे बड़ी इकाई के अधिष्ठाता होने के चलते ही उन्हें महाकाल कहा गया। वहीं कलयुग में विक्रमादित्य द्वारा नए संवत का प्रारम्भ परकीय विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त कराने के महाअभियान की सफलता का प्रतीक माना गया है।

इधर स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. मेघनाद साहा की अध्यक्षता में एक ह्यकलैंडर रिफार्म कमेटीह्ल का गठन किया गया था। वर्ष 1952 में ह्यसाइंस एंड कल्चरह्ल पत्रिका में प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार, लगभग पूरे विश्व में लागू ईसवी सन का मौलिक सम्बंध ईसाई पंथ से नहीं है और यह यूरोप के अर्धसभ्य कबीलों में ईसामसीह के बहुत पहले से ही चल रहा था। इसके अनुसार एक वर्ष में 10 महीने और 304 दिन ही होते थे। वर्ष के कैलेंडर में जनवरी एवं फरवरी माह तो बाद में जोड़े गए हैं। पुरानी रोमन सभ्यता को भी तब तक ज्ञात नहीं था कि सौर वर्ष और चंद्रमास की अवधि क्या थी। यही दस महीने का साल वे तब तक चलाते रहे जब तक उनके नेता सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं कर लिया। ईसा के 530 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, ईसाई बिशप ने पर्याप्त कल्पनाएं कर 25 दिसम्बर को ईसा का जन्म दिवस घोषित किया। वर्ष 1572 में तेरहवें पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर को दस दिन आगे बढ़ाकर 5 अक्टोबर (शुक्रवार) को 15 अक्टोबर माना, जिसे ब्रिटेन द्वारा 200 वर्ष उपरांत अर्थात वर्ष 1775 में स्वीकार किया गया। साथ ही, यूरोप के कैलेंडर में 28, 29, 30, 31 दिनों के महीने होते हैं, जो विचित्र है क्योंकि यह न तो किसी खगोलीय गणना पर आधारित हैं और न ही किसी प्रकृति चक्र पर।

उक्त वर्णित कारणों के चलते कैलेंडर रिफोर्म कमेटी ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत बनाने की सिफारिश की थी। विक्रम संवत, ईसा संवत से 57 साल पुराना था। परंतु, दुर्भाग्य से भारत में अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित लोगों के यह सुझाव पसंद नहीं आया और देश में यूरोप के कैलेंडर को लागू कर दिया गया। हालांकि, विदेशी सिद्धांतो पर आधारित गणनाओं में कई विसंगतियाँ पाई गई हैं।

चिल्ड्रन्स ब्रिटानिका के प्रथम खंड (1964) में कैलेंडर का इतिहास बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अंग्रेजी कैलेंडरों में अनेक बार गड़बड़ हुई हैं एवं इसमें समय समय पर कई संशोधन करने पड़े हैं। इनमें माह की गणना चंद्र की गति से और वर्ष की गणना सूर्य की गति पर आधारित है। आज भी इसमें कोई आपसी तालमेल नहीं है। ईसाई मत में ईसा मसीह का जन्म इतिहास की निर्णायक घटना मानी गई है। अतः कालक्रम को बीसी (बिफोर क्राइस्ट) और एडी (अनोडोमिनी) में बांटा गया। किंतु, यह पद्धति ईसा के जन्म के बाद भी कुछ सदियों तक प्रचलन में नहीं आई थी। इसके साथ ही, आज के ईस्वी सन का मूल रोमन संवत है। यह ईसा के जन्म के 753 वर्ष पूर्व रोम नगर की स्थापना से प्रारम्भ हुआ। तब इसमें 10 माह थे (प्रथम माह मार्च से अंतिम माह दिसम्बर तक) वर्ष होता था 304 दिन का। बाद में राजा नूमा पिंपोलियस ने दो माह (जनवरी एवं फरवरी) जोड़ दिए। तब से वर्ष 12 माह अर्थात 355 दिन का हो गया। यह ग्रहों की गति से मेल नहीं खाता था, तब जूलियस सीजर ने इसे 365 और 1/4 दिन का करने का आदेश दे दिया। इसमें कुछ माह 30 दिन व कुछ माह 31 दिन के बनाए गए और फरवरी के लिए 28 दिन अथवा 29 दिन बनाए गए। इस प्रकार पश्चिमी कैलेंडर में गणनाएं प्रारम्भ से ही अवैज्ञानिक, असंगत, असंतुलित विवादित एवं काल्पनिक रहीं।

इसके विपरीत सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित काल गणना पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध पाई गईं हैं। इस दृष्टि से वर्षप्रतिपदा का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है और भारत में आज हिंदू सनातनियों द्वारा वर्षप्रतिपदा के दिन ही नए वर्ष का प्रारम्भ माना जाता है एवं वर्ष भर की काल गणना भी हिंदू सनातन संस्कृति के आधार पर की जाती है, जिसे अति शुभ माना गया है।

शिक्षक की संवेदनहीनता

अहमदाबाद के एक नामचीन निजी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने नौवीं कक्षा के मिर्गी की बीमारी से पीड़ित 'एक्स छात्रा के समक्ष उसके पिता से कहा 'अगर मिर्गी की बीमारी की वजह से आपकी बेटी कक्षा में लगातार अनुपस्थित रह रही है तो आप किसी ओपेन स्कूल में उसका दाखिला करवा दीजिए, ताकि उसे रोज स्कूल जाने के बंधन से मुक्ति मिल जाए और सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही स्कूल जाना पड़े। प्रत्युतर में 'एक्स छात्रा के अभिभावक ने कहा, 'मैडम, इस बीमारी में बच्चे का कम से कम 9 से 10 घंटे सोना जरूरी होता है, अन्यथा मिर्गी का ट्रिगर आ सकता है। इसलिए नींद नहीं पूरा होने पर 'एक्स स्कूल नहीं जा पाती है, इस वजह से पूर्व के स्कूलों में भी 'एक्स का 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरा नहीं हुआ था, पर कभी भी किसी शिक्षक या प्रिंसिपल ने इस तरह की आपत्तिजनक सलाह नहीं दी, एक शिक्षक होकर आप ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकती हैं, क्या आपको नहीं मालूम है कि ऐसा करने से बच्चे पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास भी बाधित हो सकता है आदि। वाइस प्रिंसिपल से इस तरह के संवेदनहीन और अनैतिक सलाह की कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वह भी पीड़ित छात्रा के सामने, लेकिन शिक्षा के संक्रमण के दौर में शिक्षा और शिक्षकों का इस कदर बाजारीकरण हो चुका है कि शिक्षकों के संवेदनशील होने की कल्पना करना बेमानी है। अब टीचर और ट्यूटर के बीच के फर्क की परत बहुत तेजी से छीज रही है। शायद इसी वजह से कोटा और देशभर में बड़ी संख्या में बच्चे हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। निजी स्कूलों में सुविधाओं की बात करें तो मुश्किल से 5 प्रतिशत स्कूलों में ही खेल का मैदान है। ऐसे में, इंडोर गेम खेलकर बच्चे शारीरिक रूप से कितने फिट रहेंगे? अमूमन, निजी स्कूलों में न ही लाइब्रेरी होती है और न ही फस्ट एड की व्यवस्था। आजकल निजी स्कूलों में बच्चों को विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने के लिए काउंसलर भी रखा जा रहा है, लेकिन इनकी उपयोगिता भी सवालों के घेरे में हैं। कुछ स्कूलों में तो आज ड्रग्स और पॉर्न का बाजार भी फल-फूल रहा है। नर्सरी कक्षा से ही निजी स्कूलों में अभिभावकों से 1 से 1.5 लाख रु एप सालाना फीस वसूली जा रही है।

लोकसभा चुनाव में एक नये अध्याय की शुरुआत हो

आरती कुमारी

लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान सज गया है, सभी राजनीतिक दलों में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला हमेशा की तरह परवान चढ़ने लगा है। राजनीति में स्वच्छता, नैतिकता एवं मूल्यों की स्थापना के तमाम दावों के अनैतिकता, दल-बदल, आरोप-प्रत्यारोप की हिंसक मानसिकता पसरी है। राजनेता दलबदल की ताल ठोक रहे हैं। दलबदलुओं को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं रहा, क्योंकि सवाल, येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने तक जो सीमित रह गया है। सिद्धांतों और राजनीतिक मूल्यों की परवाह कम ही लोगों को रह गई है। चुनावी राजनीति देश के माहौल में कड़वाहट घोलने का काम भी कर रही है। स्वस्थ एवं मूल्यपरक राजनीति को किनारे किया जा रहा है। राजनीति पूरी तरह से जातिवाद, बाहुबल और धनबल तक सिमट गई है। हालत यह है कि अब तक राजनीति दलों ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है, उनमें आधे से अधिक दलबदलू, अपराधी अथवा दागी हैं। ऐसे में राजनीति के स्तर में सुधार की उम्मीद आखिर कौन, किससे करे? इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की चुप्पी तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी समझ से परे है। लोकसभा चुनाव नेतृत्व चयन का ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर पर लाओत्जु ताओ ते चिंग की पुस्तक''द ताओ ऑफ लीडरशिप'' राजनीति एवं राजनेताओं के लिये एक रोशनी है। यह एक अद्भुत, अद्वितीय एवं अप्रतिम कृति हैं जो नये युग के लिए नेतृत्व की रचनात्मक व्यूह रचना प्रस्तुत करती है। आज जबकि देश और दुनिया में सर्वत्र नेतृत्व के प्रश्न पर एक घना अंधेरा छाया हुआ है, निराशा और दायित्वहीनता की चरम पराकाष्ठा ने राजनीति एवं नेतृत्व को जटिल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। समाज और राष्ट्र के समुचे परिदृश्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें जिन विषम और जटिल परिस्थितियों से रू-ब-रू होना पड़ता है, उन विषम हालातों के बीच ठीक से राह दिखाने वाला कोई नेतृत्व नजर नहीं आता। यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र धुंधलका सब देख रहे हैं, लेकिन खामोशी के साथ। शायद सबकी अपनी-अपनी मजबूरियां हैं। मतदाता की मजबूरी यह है कि आखिर उसे मैदान में डटे उम्मीदवारों में से ही एक को चुनना है। इस देश ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, गरीबी, साम्प्रदायिकता के खिलाफ भी जनता को सड़कों पर उतरते देखा है लेकिन राजनीति में टकराव, अपराध, देश-विरोध और हिंसा की राजनीति के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन जेल में बैठे-बैठे लोग चुनाव लड़ भी लेते हैं और जीत भी जाते हैं। खलनायक नायक बनने लगे हैं। चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम खर्च की सीमा सरेआम ध्वस्त होती है, लेकिन आयोग कुछ कर नहीं पाता। चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्दों का उच्चारण-गालीगलोच खुल्लम-खुल्ला होता है, लेकिन आयोग नोटिस देकर ही अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। मतदाताओं के वोट खरीदने के लिए उन्हें सरेआम पैसे ही नहीं शराब तक बांटी जाती है, लेकिन किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जनता राजनीति के गिरते स्तर से त्रस्त तो है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। इन लोकसभा चुनाव में यह चुप्पी टूटनी चाहिए और आजादी के अमृतकाल को अमृममय बनाने वाला नेतृत्व सामने आना चाहिए। ऐसा नेतृत्व जो देश को अग्रणी आर्थिक महाशक्ति के रूप में ले जाये एवं विकास की स्वर्णिम गाथा को गढ़े। एक सफल, सार्थक, समर्थ एवं चरित्रसम्पन्न विपक्षी नेतृत्व की आवश्यकता हर दौर में रही है, लेकिन आज यह ज्यादा तीव्रता से महसूस की जा रही है। विपक्षी नेतृत्व कैसा हो, उसका अपना साथियों के साथ-साथ सत्तापक्ष के साथ कैसा सलूक हो? उसमें क्या हो, क्या न हो? वह क्या करे, क्यों करे, कब करे, कैसे करे? इत्यादि कुछ जटिल एवं गंभीर प्रश्न हैं जिनके जवाब ढूंढे बिना हम एक सक्षम विपक्षी नेतृत्व को उजागर नहीं कर सकते। इन प्रश्नों के उत्तरों की कसौटी पर ही हमें आने वाले सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेतृत्व को कसना होगा। जिस नेतृत्व के पास इन प्रश्नों के उत्तर होंगे, जो समयज्ञ होगा, सहिष्णु होगा, तटस्थ होगा, दूरदर्शी होगा, निःस्वार्थी होगा, वैसा ही नेतृत्व जिस राष्ट्र को प्राप्त होगा, उसकी प्रगति को संसार की कोई शक्ति बाधित नहीं कर सकेगी। ऐसा ही नेतृत्व नया इतिहास बना सकेगा और भावी पीढ़ी को उन्नत दिशाओं की ओर अग्रसर कर सकेगा। आज चुनाव प्रचार में जिस तरह की आरोप-प्रत्यारोप की हिंसक संस्कृति पनपी है, एक दूसरे पर जूते-चप्पल फेंके जाते है, पत्थर से हमला किया जाता है, छोटी-छोटी बातों पर अभद्र शब्दों का व्यवहार, हो-हल्ला, छींटाकशी और हंगामा आदि घटनाएं ऐसी है जो नेतृत्व को धुंधलाती है। नेतृत्व को लेकर लोगों की मानसिकता में बहुत बदलाव आया है, आज योग्य नेतृत्व की प्यासी परिस्थितियां तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से अपेक्षित नेतृत्व नहीं हैं। जलाशय है, जल नहीं है। नगर है, नागरिक नहीं है। भूख है, रोटी नहीं है-ऐसे में हमें सोचना होगा कि क्या नेतृत्व की इस अप्रत्याशित रिक्तता को भरा जा सकता है? क्या राष्ट्र के सामने आज जो भयावह एवं विकट संकट और दुविधा है उससे छुटकारा मिल सकता है? हालही में नेतृत्व के प्रश्न पर एक करारा व्यंग्य पढ़ा था-'देश और ट्रेन में यही अंतर है कि ट्रेन को लापरवाही से नहीं चलाया जा सकता।' यानी देश के संचालन में की गई लापरवाही तो क्षम्य हैं पर ट्रेन के पटरी से उतरने की गई लापरवाही क्षम्य नहीं, क्योंकि इसके साथ आदमी की जिंदगी का सवाल जुड़ा है। मगर हम यह न भूलें कि देश का नेतृत्व अपने सिद्धांतों और आदर्शों की पटरी से जिस दिन उतर गया तो पूरी इन्सानियत एवं राष्ट्रीयता की बरबादी का सवाल उठ खड़ा होगा। आज देश में लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, नैतिक जीवन-मूल्यों के मानक बदल गये हैं न्याय, कानून और व्यवस्था के उद्देश्य अब नई व्याख्या देने लगे हैं। चरित्र हासिए पर आ गया, सत्ता केन्द्र में आ खड़ी हुई। ऐसे समय में कुर्सी पाने की दौड़ में लोग जिम्मेदारियां नहीं बांटते, चरित्र बांटने लगते हैं और जिस देश का चरित्र बिकाऊ हो जाता है उसकी आत्मा को फिर कैसे जिन्दा रखा जाए, चिन्तनीय प्रश्न उठा खड़ा हुआ है। आज कौन अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदार है? कौन नीतियों के प्रति ईमानदार है? इस संदर्भ में आचार्य तुलसी का कथन यथार्थ का उद्घाटन करता है कि ''ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञ का अर्थ देश में सुव्यवस्था बनाए रखना नहीं, अपनी सत्ता और कुर्सी बनाए रखना है। राजनीतिज्ञ का अर्थ उस नीतिनिपुण व्यक्तित्व से नहीं, जो हर कीमत पर राष्ट्र को प्रगति, विकास-विस्तार और समृद्धि का सर्वोपरि महत्व दें, किन्तु उस विदूषक-विशारद व्यक्तित्व से है, जो राष्ट्र के विकास और समृद्धि को अवनति के गर्त में फेंककर भी अपनी कुर्सी को सर्वोपरि महत्व देता है।'' राजनैतिक लोगों से महात्मा बनने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, पर वे पशुता पर उतर आएं, यह ठीक नहीं है। वर्तमान विपक्षी नेतृत्व की सबसे बड़ी विसंगति और विषमता यह है कि वह परदोषदर्शी है, जो सत्तापक्ष की अच्छाई में भी बुराई देखने वाले हैं। यह नेतृत्व कुटिल है, मायावी है, नेता नहीं, अभिनेता है, असली पात्र नहीं, विदूषक की भूमिका निभाने वाला है। यह नेतृत्व सत्ता- प्राप्ति के लिये कुछ भी करने से बाज नहीं आता, यहां तक जिस जनता के कंधों पर बैठकर सत्ता तक पहुंचने के लिये जैसी राजनीति यह कर रहा है, घोषणा-पत्रों में जनता को ठगने एवं लुभाने के जो प्रयास हो रहे हैं, वे एक तरह से जनता की पीठ में भी सबसे पहले छुरा भोंकते हुए प्रतीत होते हैं। इससे भी अधिक घातक है इस नेतृत्व का असंयमी, अपराधी और चरित्रहीन होना, जो सत्ता पर काबिज होने के लिये राष्ट्र से भी अधिक महत्व अपने परिवार को देता है। देश से भी अधिक महत्व अपनी जाति और सम्प्रदाय को देता है। चुनाव जीतना जिनके लिये सेवा का साधन नहीं, विलास का साधन है। नेतृत्व का चेहरा साफ-सुथरा बने, इसके लिये अपेक्षित है कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के चरित्र का परीक्षण हो। आई-क्यू टेस्ट की तरह करेक्टर टेस्ट की कोई नई प्रविधि प्रयोग में लाई जाये तो यह लोकसभा चुनाव का संग्राम अधिक सार्थक होगा।

सरकार क्यों भूल जाती है सिंधियों के' आराध्य देव झुलेलाल' के जन्म दिन व 'सिन्धी नव वर्ष चेटीचंड 'को

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अशोक भाटिया

भारत देश में सभी समुदाय के आराध्य देव की समान रूप से पूजा होती है पर सरकार सिंधियों के आराध्य देव झुलेलाल के जन्म दिन को भूल जाती है जबकि सिंधियों का नव वर्ष भी इसी दिन शुरू होता है । झूलेलाल जयंती अथवा चेटीचंड चैत्र माह की शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जाता हैं। इस दिन पहली बार पूर्ण चन्द्र दर्शन होता हैं। वरुण देव का अवतार माने जाने वाले झूलेलाल जी की जयंती का पर्व सिंधियों का सबसे बड़ा पर्व हैं। वर्ष 2024 में यह 10 अप्रेल के दिन मनाया जा रहा है । वैसे चार साल में एक बार यह हिन्दू नव वर्ष गुडी पड़वा के साथ आता है पर बाकी वर्ष यह गुडी पड़वाके दूसरे दिन आता है इस कारण भी यह सरकारी केलेन्डर में नहीं गिना जाता और न ही इस दिन सरकारी छुट्टी भी नहीं होती है । और कुछ सरकारी बेरुखी को बताने के पहले हम पाठकों को भगवान झुलेलाल के बारे में बताते है । कहते है जब जब धरती पर अन्यायियों ने लोगों को त्रस्त किया तब तब भगवान् ने मसीहा के रूप में अवतरित होकर उनके संकट को टारा हैं। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल जी कि जीवनी कुछ ऐसी ही हैं । दरअसल जो लोग सिंध में रहते हैं अथवा विभाजन के बाद उस स्थान से पलायन कर किसी अन्य स्थान को गये हैं उन्हें सिंधी कहा जाता हैं सिंध पाकिस्तान में हैं। झुलेलाल को कोई संत कहता है तो कोई फकीर जो भी हो हिन्दू मुस्लिम दोनों इन्हें मानते हैं तथा यह सिन्धी समाज के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईशा, अल्लाह से भी बढ़कर हैं। झूलेलाल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता हैं। उदेरोलाल, घोड़ेवारो, जिन्दपीर, लालसाँई, पल्लेवारो, ज्योतिनवारो, अमरलाल आदि।झूलेलाल जी को जल के देवता वरुण का अवतार माना जाता हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में चन्द्र दर्शन की तिथि को सिंधी चेटीचंड मनाते हैं। इनकी पूजा तथा स्तुति का तरीका कुछ भिन्न हैं जल के देव होने के कारण इनका मंदिर लकड़ी का बनाकर जल में रखकर इनके नाम दीपक जलाकर भक्त आराधना करते हैं। चेटीचंड के अवसर पर भक्त इस मंदिर को अपने शीश पर उठाते हैं जिन्हें बहिराना साहिब कहा जाता हैं जिनमें परम्परागत छेज नृत्य किया जाता हैं। सिंध प्रान्त से भारत में आकर भिन्न भिन्न स्थानों पर बसे सिंधी समुदाय के लोगों द्वारा झूलेलाल जी की पूजा की जाती हैं। ये उनके इष्ट देव हैं। सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि के महापुरुष के रूप में इन्हें मान्यता दी गुई हैं। ताहिरी, छोले (उबले नमकीन चने) और शरबत आदि इस दिन बनाते हैं तथा चेटीचंड की शाम को गणेश विसर्जन की तरह बहिराणा साहिब का विसर्जन किया जाता हैं। भगवान झूलेलाल जी का जन्म चैत्र शुक्ल 2 संवत 1007 को हुआ था, इनके जन्म के सम्बन्ध में कई पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। मगर इन सभी में बहुत सी समानताएं भी हैं यहाँ आपकों भगवान झूलेलाल जी की सर्वमान्य कथा बता रहे हैं जिन पर अधिकतर लोगों का विश्वास हैं। बात सिंध इलाके की हैं 11 वीं सदी में वहां मिरक शाह नाम का शासक हुआ करता था। वह प्रजा का शासक कम अपनी मनमानी करने वाला जनता को तरह तरह की शारीरिक यातनाएं देने में आनन्द खोजने वाला अप्रिय एवं अत्याचारी था। उसके लिए मानवीय मूल्य तथा व्यक्ति जीवन गरिमा व धर्म कुछ भी मायने नहीं रखते थे। दिन ब दिन बढ़ते शाह के जुल्मों से सिंध की प्रजा तंग आ चुकी थी। राजतन्त्र में वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। उनके पास पुकार का एक ही जरिया था वह था ईश्वर से मदद की गुहार। राज्य की जनता सिन्धु के तट पर एकत्रित होकर भगवान से इस मुश्किल से निकालने के लिए प्रार्थना करने लगे।

वरुणदेव उदेरोलाल ने जलपति के रूप में मछली पर सवार होकर लोगों को दर्शन दिया। तथा आकाशवाणी हुई कि हे भक्तों तुम्हारे दुखों का हरण करने के लिए मैं ठाकुर रतनराय के घर माँ देवकी के घर जन्म लूँगा तथा आपके जुल्मों को खत्म करूँगा। चैत्र शुक्ल 2 संवत 1007 के दिन नसरपुर में माँ देवकी पिता रतनराय के घर चमत्कारी बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उदयचंद रखा गया। जब शासक मीरक शाह को यह खबर मिली तो उसने अपने सेनापति को इस बालक का वध करने के लिए भेजा। सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ नसरपुर के रतनराय जी के यहाँ पहुचकर बालक उदयचंद तक पहुचने का प्रयास किया तो झूलेलाल जी ने अपनी दैवीय शक्ति से शाह के राजमहल में आग लगा दी तथा उसकी फौज को पंगु बना दिया। जब शाह की किसी ईश्वरीय शक्ति के ताकत का अंदाजा हुआ तो वह माँ देवकी के घर गया तथा झूलेलाल जी के कदमों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। इस तरह अल्पायु में ही झूले लाल जी ने आमजन में सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा उन्हें निडर होकर अपना कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इस पर मुस्लिम शासक के द्वारा हाथ जोड़कर के यह कहा गया कि है पीरों के पीर आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है और इस प्रकार से भगवान झूलेलाल के चमत्कार से हिंदू जनता को मुस्लिम शासक के अत्याचार से आजादी मिली। सिंध का शासक मीरक शाह जिन्होंने झूलेलाल जी को मारने के लिए आक्रमण किया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया तथा वह उनका परम शिष्य बनकर उनके विचारों को जन जन तक पहुचाने के कार्य में जुट गया। शाह ने अपने आराध्य के लिए कुरु क्षेत्र में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। सर्वधर्म समभाव तथा अमन का पैगाम देने वाले झूलेलाल जी एक दिव्य पुरुष थे। इस दिन जगह जगह पर मन्दिरों में पूजा अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम व जुलुस निकाले जाते हैं। इस अवसर पर दिन प्रसाद के तौर पर उबले काले चने व मीठा भात सबको बांटा जाता हैं। चलिओ उर्फ़ चालिहो को चालिहो साहिब भी एक सिंधी पर्व हैं जिन्हें अंग्रेजी कलैंडर के अनुसार अगस्त या जुलाई माह में सिंधी समुदाय मनाता हैं। चालीस दिन चलने वाले इस पर्व में साधक अपने आराध्य झूलेलाल का आभार प्रकट करते हैं। सिन्धी समाज का देश की आज़ादी कि लड़ाई , सामाजिक दायित्व व राजनीति में भी बड़ा योगदान रहा है । लोग आज़ादी के मतवाले हेमू कालानी को नहीं भूले होंगे । स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के अनगिनत सपूतो ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। आजादी की लड़ाई में भारत के सभी प्रदेशो का योगदान रहा। अंग्रेजो को भारत से भगा कर देश को जिन वन्दनीय वीरो ने आजाद कराया उनमे सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालाणी को भारत देश कभी नही भुला पायेगा।हेमू कालाणी सिन्ध के सख्खर में २३ मार्च सन् १९२३ को जन्मे थे। हेमू बचपन से साहसी तथा विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। हेमू कालाणी जब मात्र 7 वर्ष के थे तब वह तिरंगा लेकर अंग्रेजो की बस्ती में अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे।1942 में 19 वर्षीय किशोर क्रांतिकारी ने "अंग्रेजो भारत छोड़ो " नारे के साथ अपनी टोली के साथ सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया था और उसके उत्साह को देखकर प्रत्येक सिंधवासी में जोश आ गया था। हेमू समस्त विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार करने के लिए लोगो से अनुरोध किया करते थे। शीघ्र ही सक्रिय क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल होकर उन्होंने हुकुमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रियाकलापों में भाग लेना शूरू कर दिया।अत्याचारी फिरंगी सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियों एवं उनके वाहनों को जलाने में हेमू सदा अपने साथियों का नेतृत्व करते थे। हेमू ने अंग्रेजो की एक ट्रेन ,जिसमे क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए हथियार एवं अंग्रेजी अफसरों का खूखार दस्ता था। उसे सक्खर पुल में पटरी की फिश प्लेट खोलकर गिराने का कार्य किया था जिसे अंग्रेजो ने देख लिया था। 1942 में क्रांतिकारी हौसले से भयभीत अंग्रजी हुकुमत ने हेमू की उम्र कैद को फाँसी की सजा में तब्दील कर दिया। पुरे भारत में सिंध प्रदेश में सभी लोग एवं क्रांतिकारी संघठन हैरान रह गये और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। हेमू को जेल में अपने साथियों का नाम बताने के लिए काफी प्रलोभन और यातनाये दी गयी लेकिन उसने मुह नही खोला और फांसी पर झुलना ही बेहतर समझा।२१ जनवरी १९४३ को उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब फांसी से पहले उनसे आखरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इन्कलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया। सिंधी समाज रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला समाज है। सिंधियों की संख्या जरूर मुट्ठी भर है, लेकिन देश के विकास में समाज का बड़ा योगदान है। सरकार को राजस्व देने में ये समाज हमेशा अग्रणी रहा है। भारत की राजनीति में भी सिन्धी समाज अग्रणी रहा है।अनेक प्रान्तों में सिन्धी विधायक व सांसद है और तो और श्री लालकृष्ण आडवानी भारत के उपप्रधानमंत्री रह चुके है जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से नवाज़ा गया है । ऐसे समाज को भारत सरकार को नहीं भूलना चाहिए ।

जानिए क्यों कुंवारी नदी है नर्मदा?

रिपोर्ट अनमोल कुमार

नदियां हमारी आस्था की प्रतीक रही है. हर नदी का अपना इतिहास, अपनी कहानियां हैं. नर्मदा की बात करें तो यह केवल नदी नहीं है, बल्कि इसे 'मां नर्मदा' कहकर संबोधित किया जाता है. भारत की सबसे लंबी नदियों में शुमार इस नदी का अपना पौराणिक इतिहास है. कहा जाता है कि सभी नदियों में केवल नर्मदा ही हैं जो कुंवारी हैं. उनका बहाव और गति इतनी तेज है कि उसे साध पाने की ताकत बड़े से बड़े बांध में भी नहीं है.मां नर्मदा की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे इकलौती हैं जिस पर पुराण लिखा गया. 'नर्मदा पुराण' हमेशा से लोगों का मार्ग दर्शन करता आया है. पर जब भी बात होती है कि नर्मदा के उल्टे बहाव की तो अलग-अलग तथ्य निकल कर आते हैं. वैज्ञानिकों ने इसे अपने तरीके से समझा है पर वे भी इसके पौराणिक कारण पर एक मत होते नजर आते हैं.नर्मदा के उल्टे बहाव और उनके कुंवारे रहने के बीच में गहरा संबंध है. शिव के पसीने से बनी थी नर्मदामत्स्यपुराण में नर्मदा की महिमा के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का तीन दिन में, गंगाजल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है. इस पवित्र नदी के अवतरण की कथा काफी रोचक है. जिसका जिक्र वेदव्यास जी ने स्कन्द पुराण के रेवाखंड़ में किया है.इसके अनुसार भगवान शिव अमरकण्टक के मैखल पर्वत पर ध्यान कर रहे थे. तेज गर्मी के कारण उनका शरीर तप रहा था और लगातार पसीना बह रहा था. इसी पसीने के प्रवाह से एक कन्या की उत्पत्ति हुई. यह कन्या शिव के चरणों में बैठ गई. फिर जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, तो उन्हें अपने सामने लगभग 12 साल की एक बच्ची दिखाई दी. उन्होंने उस रूपवति कन्या का नाम नर्मदा रखा.इस तरह से नर्मदा का उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई और चूंकि वह मैखल पर्वत पर थी इसलिए आगे चलकर उन्हें राजा मैखल की पुत्री के नाम से जाना गया. नर्मदा ने भगवान शिव के आर्शीवाद से उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10 हजार दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था. फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि 'तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा. तुम्हारे हर कण में मेरा वास होगा.'यही कारण है कि नर्मदा से निकले हर कण, हर पत्थर को शिवलिंग समझकर पूजा जाता है. नर्मदा नदी के तट पर 'नर्मदेश्वर शिवलिंग' विराजमान है. हिंदू धर्म में शिवलिंग स्थापना के लिए पाषण के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है.जबकि, नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग स्वप्रतिष्ठित हैं.स्कंद पुराण में बताया गया है कि राजा-हिरण्यतेजा ने चौदह हजार दिव्य वर्षों की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था. साथ ही वरदान स्वरूप उनसे नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने आग्रह किया था.शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर धरती पर अवतरित हुई थी.पुराण में बताया गया है कि केवल नर्मदा नदी ही हैं जो कुंवारी हैं. इसके पीछे एक पौराणिक कथा है. जिसके अनुसार मैखल राज की पुत्री नर्मदा गुणवती और रूपवति थी. मैखल राज ने उनके विवाह के लिए अनोखी शर्त रखी. उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमार गुलबकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे. नद राजकुमार शोण भद्र ▪ नद यानी नदी का पुरुष रूप• ने नर्मदा के रूप और गुणों के बारे में सुन रखा था. वे चाहते थे कि नर्मदा उनकी पत्नी बने. इसलिए वे सबसे पहले गुलबकावली के दुर्लभ पुष्प लेकर मैखल राज के पास पहुंचे. मैखल उनकी योग्यता से प्रभावित हुए और अपनी बेटी का विवाह उनसे तय कर दिया. किन्तु, उस वक्त न तो सोनभद्र ने नर्मदा को देखा था न ही नर्मदा अपने होने वाले पति को देख पाईं. दोनों ने केवल लोगों की बातों में एक दूसरे का जिक्र सुना था. नर्मदा की सखियों ने उन्हें बताया कि शोण भद्र बेहद बलशाली राजकुमार हैं. उनका रूप जितना लुभावना है वे उससे ज्यादा मधुर बोलते हैं. यह सब सुनकर नर्मदा बिना देखे ही शोण भद्र से प्रेम करने लगी.वे मन ही मन में उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थीं. विवाह के दिन अभी दूर थे और पिता की आज्ञा न होने के कारण नर्मदा शोण भद्र से मिल नहीं सकती थी. इसलिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला (यह आदिवासी

नदी मंडला के पास बहती है) से कहा कि वे शोण भद्र को एक प्रेम पत्र भेजना चाहती हैं. जुहिला ने उनकी मदद का आश्वासन दिया. नर्मदा ने अपनी सारी भावनाओं को समेंटकर एक पत्र शोण भद्र के नाम लिखा और उसे जुहिला को देते हुए कहा कि यह राजकुमार को दे आओ. जुहिला पत्र लेकर राजकुमार शोण भद्र के महल पहुंची. चूंकि वह पहली बार राजकुमार से मिल रही थी इसलिए नर्मदा ने उसे अपने वस्त्र और आभूषण पहना दिए थे. जैसे ही शोण भद्र ने जुहिला को देखा उन्हें लगा कि जो चरित्र नर्मदा का बताया गया है वह साकार हो गया. उन्हें लगा कि वह नर्मदा है. वहीं दूसरी ओर जुहिला शोण भद्र के रूप पर मोहित हो गई. जब शोण भद्र ने उन्हें नर्मदा समझा तो जुहिला ने उस गलतफहमी को बने रहने दिया और राजकुमार के नजदीक आ गई. वहीं नर्मदा जुहिला का इंतजार कर रहीं थी. जब काफी देर तक जुहिला वापस नहीं आई तो वे शोण भद्र के महल पहुंची. जहां उन्होंने जुहिला और शोण भद्र को साथ में देखा. नर्मदा यह देखकर बर्दाश्त न कर सकतीं. शोण भद्र नर्मदा को देखकर आश्चर्य से भर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. नर्मदा गुस्से में थी और उसके असर से धरती पर उनका बहाव तेज हो गया.

शोण भद्र ने खुद को नर्मदा के सामने झुका दिया पर वे उन्हें देखे बिना वहां से उल्टे पांव लौट गईं. उसी क्षण धरती पर नर्मदा का बहाव उल्टा हो गया. शोण भद्र नर्मदा के पीछे भागे और उन्हें रोकने का प्रयास किया पर वे वापस नहीं आई.नर्मदा शोण भद्र के छल से इतनी दुखी थीं कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया. जो नर्मदा कल तक बंगाल सागर की यात्रा करती थी उसने अरब सागर में समा जाने का निर्णय ले लिया.

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो इससे आपके काम जल्दी निपटेंगे। आज आप संतान के करियर की समस्याओं को किसी अनुभवी और जानकार की मदद से सुलझा लेंगे। थोड़ी विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी। आज किसी से विवाद की स्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें।

वृष राशि : आज का दिन आपके लिए ठीकठाक रहने वाला है। कोई भी छोटा-बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको मुनाफा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी, परिवार में सभी एकदुसरे की भावनाओं को समझेंगे। स्टूडेंट अपना कीमती समय सोशल मीडिया में खराब न करें, अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो आपकी सफलता के जल्द ही योग बन रहे है आपकी जरा सी लापरवाही से आपको पछतावा हो सकता है।

मिथुन राशि:आज आपको लोगों का पूरापूरा साथ मिलेगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आज जीवनसाथी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। शाम को मेहमानों के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको पैत्रक सम्पति मिलने की संभावना है, जिससे आपके धनसंपत्ति में वृद्धि होगी। खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे।

कर्क राशि: आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। आपकी खुशियों में इजाफा होगा। ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम मिलने की संभावना है, जिसे पूरा करने पर फायदा होगा। आट्र्स स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा,कोई ग्राफिक डिजाइन सीखने का मौका मिलेगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी।

सिंह राशि : आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो आपके संतुलित रवैया से फायदा मिलेगा। आज थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थान पर बीताएंगे। आज शाम माता जी से आप भविष्य को लेकर विचारविमर्श करेंगे, आपको माता जी का साथ मिलने से खुशी होगी। आज आपके मन में किसी प्रकार का डर रहेगा लेकिन डरने की बात नहीं है यह आपकी ओवर थिन्किंग के कारण हो सकता है।

कन्या राशि : आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनकी काम करने की क्षमता बेहतर होगी, आज आपका काम समय से पहले भी पूरा हो सकता है। महिलाएं अपने बिजनेस में ज्यादा एक्टिव रहेंगी, आपको ज्यादा धनलाभ भी होगा।

तुला राशि : आज का दिन आपके लिए बहुत सामान्य रहेगा। आज पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हर एक बात पर ध्यान देकर स्थिति को सुधारने कोशिश करें। आज पुरानी गलती दोबारा न हो, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ रहा है, नई जिम्मेदारियों के लिए आप खुद को तैयार करेंगे। आज अपनी कार्यक्षमता के अनुसार आपको कुछ बड़े अवसर भी मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि: आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज किसी करीबी व्यक्ति से काम संबंधी नाराजगी दूर होगी। जिन बातों में आपकी ज्यादा रुचि है, उन पर ध्यान देंगे आपको ख़ुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुडऩे से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अन्य लोगों ने जिस प्रकार से अपने काम में प्रगति की है, वैसे ही अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढऩे की कोशिश करेंगे आपको जल्द ही सफलता मिलेंगी।

धनु राशि: आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियाँ लाया है। आपका दिन परिवार के साथ बीतेगा। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। आप दूसरों पर अपना प्रभाव बनाने में सफल होंगे,आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरुरत है। आसपास के कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीकठाक रहेगी। गंभीर बातचीत में आपको सफलता मिलने की संभावना है।

मकर राशि:आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज व्यापार के मामलों में आपके मन में नएनए विचार आयेंगे। नए लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। आपके कामकाज की तारीफ होगी।

कुंभ राशि : आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज ऑफिस के सहकर्मी आपके कामों में सहयोग करेंगे, आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे होंगे।

मीन राशि: आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। अपने दोस्तों से निजी समस्याओं को शेयर करने से बचना चाहिए। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ेगी, समय के साथ सब ठीक हो जायेगा। पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे।

शिखरपर शेयर और सोना

चैत्र नवरात्रिका प्रथम दिवस शेयर और सोना दोनोंके लिए अत्यन्त ही मंगलकारी रहा। शेयर और सोना दोनोंने नये शिखरपर पहुंचकर इतिहास रचा है। पहली बार दोनोंके भावोंमें भारी उछाल आना मणिकांचन योग है। प्राय: ऐसा होता रहा है कि कभी शेयरोंमें तेजी आयी थी तो सोना नरम रहता था या सोना तेज रहा तो शेयरके भाव नरम रहते थे लेकिन एक साथ दोनोंका नये शिखरपर पहुंचना विलक्षण माना जायगा। मंगलवारको शेयर बाजारका संवेदी सूचकांक (सेंसेक्स) पहली बार ७५ हजारके आंकड़ेको पार करते हुए ७५,१२४ अंकोंपर और निफ्टी २२,७६५ अंकोंके उच्चतम स्तरपर पहुंच गया। सूचकांकने सोमवारके ७४,८६९ अंकोंको भी पीछे छोड़ दिया। इसी प्रकार निफ्टी भी सोमवारको २२,६९७ के स्तरपर बंद हुआ था। इसी प्रकार दस ग्राम सोना १३९७ रुपये महंगा होकर मंगलवारको ७१,२७९ रुपये हो गया और चांदी ८१ हजार ४९६ रुपये प्रति किलोके भावपर बंद हुई। चांदीके भावमें २४ सौ रुपयेकी वृद्धि दर्ज की गयी। यह अबतकका सर्वाधिक उच्च स्तर है। नवरात्रिके पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग देखनेको मिला। नवरात्रिमें सोना खरीदना या सोनेमें निवेश करना शुभ माना जाता है और पूरे नौ दिनोंतक इसकी खरीदारी भी होती है। स्वर्णाभूषणोंके अतिरिक्त सोनेके बिस्किट या सिक्कोंमें भी निवेश करनेकी परम्परा है। इसे निवेशका सुरक्षित माध्यम माना जाता है और धनकी आवश्यकता पड़नेपर इसे आसानीसे बेचा या उसपर कर्ज लिया जा सकता है। लोकसभा चुनावोंकी घोषणाके बाद शेयरों और सोनेमें तेजीका एक बड़ा कारण धारणात्मक है। बाजारमें ऐसी धारणा है कि केन्द्रमें सत्तारूढ़ पार्टी पुन: सत्तामें आ सकती है। इसलिए बाजारमें तेजी है लेकिन यह भविष्यके गर्भमें है कि कौन पार्टी या गठबन्धन सत्तामें आयेगा। इसके बारेमें पक्के तौरपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। शेयर बाजारमें तेजीका एक महत्वपूर्ण कारण देशकी मजबूत अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेशकोंका भरोसा भी है। इसीके चलते पिछले कारोबारी सत्रमें विदेशी निवेशकोंने १,६५९.२७ करोड़ रुपयेका निवेश किया, जिसका सकारात्मक प्रभाव बाजारकी भावनापर पड़ा है। शेयर बाजारको जून माहमें अमेरिकी ब्याज दरोंमें कटौतीकी भी उम्मीद है। बाजारमें आयी तेजी अच्छी बात है लेकिन खुदरा निवेशकोंको सतर्क रहना होगा, क्योंकि बाजारमें करेक्शन भी होगा और इससे भावोंमें गिरावट आ सकती है।

राहतकारी फैसला

देशभरके प्राथमिक विद्यालयोंमें तैनात बीएड धारक सहायक शिक्षकोंके लिए शुक्रवारको सर्वोच्च न्यायालयका आया फैसला राहतकारी है। ११ अगस्त, २०२३ को सर्वोच्च न्यायालयने अपने एक फैसलेमें नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के २०१८ के उस नोटिफिकेशनको रद कर दिया था, जिसके जरिये प्राथमिक विद्यालयोंमें शिक्षककी नौकरीके लिए बीएडको भी शैक्षणिक योग्यताओंमें शामिल किया गया था। ऐसेमें २०१८ के बादसे नियुक्ति पाये बीएड धारक शिक्षकोंकी नौकरीपर खतरा मंडरा रहा था। सर्वोच्च न्यायालयने अपने उसी फैसलेपर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ११ अगस्त, २०२३ के फैसलेसे पहलेसे नियुक्त बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकके तौरपर अपनी सेवामें बने रहेंगे। न्यायालयका यह फैसला सम्भवत: एक तरहसे नियुक्ति पाये बीएड धारक शिक्षकोंके लिए मानवीय हितोंको ध्यानमें रखकर दिया गया है। भारतमें प्राथमिक शिक्षाका संवैधानिक अधिकार १४ वर्षसे कम उम्रके बच्चोंके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षाके प्रावधानको अनिवार्य बनाता है। ऐसेमें सर्वोच्च न्यायालयने माना था कि बीएड डिग्रीवाले प्राथमिक विद्यालयोंके बच्चोंको गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं दे पायेंगे। प्रारम्भिक शिक्षामें डीएलएड (पूर्वमें बीटीसी) धारकको ही इस मानसिक स्तरके छात्रोंको सम्भालनेके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए विशेष रूपसे डिजाइन किया गया एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम होता है, जबकि बीएडको माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिकवाले मानसिक स्तरके छात्रोंको शिक्षण प्रदान करनेके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसेमें प्राथमिक शिक्षकके लिए योग्यताके रूपमें बीएडको शामिल करना मनमाना और शिक्षाका अधिकार अधिनियमके उद्देश्योंके खिलाफ है। न्यायालयमें चल रहा मामला प्राथमिक विद्यालयोंमें गुणवत्तायुक्त शिक्षाके साथ डीएलएड धारकोंके हककी भी लड़ाई थी। भले ही पूर्वके नियुक्त बीएड धारक शिक्षकोंकी नौकरी बच गयी, परन्तु आगामी शिक्षक भर्तियोंमें डीएलएड ही शैक्षणिक योग्यता होगी। ऐसेमें न्यायालयका फैसला डीएलएड धारक अभ्यर्थियोंके लिए भी राहतकारी है।

उत्तर-दक्षिण विभाजनकी झूठी कहानी

लंदनसे प्रकाशित दी इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिकाने बेहद शरारती लेखके जरिये उत्तर और दक्षिणके बीच विभाजनकी नयी परिभाषा गढ़नेकी कोशिश की है। पत्रिका कहती है कि दक्षिण भारतीय राज्य आर्थिक दृष्टिसे शेष भारतसे अलग हैं। क्योंकि भारतकी केवल बीस प्रतिशत आबादी पांच दक्षिणी राज्योंमें रहती है।

❐ डा.अश्विनी महाजन

दी इकोनॉमिस्ट पत्रिका दावा करती है कि दक्षिण भारतीय राज्योंमें बीस प्रतिशत आबादी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगानामें रहती है, लेकिन इन राज्योंको कुल विदेशी निवेशका ३५ प्रतिशत प्राप्त होता है। इन राज्योंने देशके अन्य हिस्सोंकी तुलनामें अधिक विकास किया है और जहां १९९३ में ये राज्य देशकी जीडीपीका २४ प्रतिशत उत्पन्न करते थे, वहीं अब यह बढ़कर ३१ प्रतिशत हो गया है। ४६ प्रतिशत टेक यूनिकॉर्न दक्षिण भारतसे हैं और भारतका ४६ प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इन्हीं पांच दक्षिणी राज्योंसे होता है। इतना ही नहीं, पत्रिका लिखती है कि ६६ फीसदी आईटी सेवाओंका निर्यात भी दक्षिणी राज्योंसे होता है। कुछ एजेंडाधर्मी लोगोंको छोड़, सारा विश्व जनता है कि उत्तरसे दक्षिणतक, पूर्वसे पश्चिमतक भारत एक है। इस उपमहाद्वीपमें रहनेवाले सभी लोग विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, वेशभूषा और खान-पानके बावजूद स्वयंको भारतीय मानते हैं। विष्णु पुराणमें कहा गया है-उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षम् तद् भारतम् नाम भारती यत्र सन्ति:। इसका अर्थ है, समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिणमें स्थित भूमिको भारत भूमि कहा जाता है और भारतकी इस पवित्र भूमिपर रहनेवाले लोगोंको भारतीय कहा जाता है। यह सच है कि भारतमें अलग-अलग क्षेत्रोंपर अलग-अलग समयमें अलग-अलग शासकोंका शासन था। लेकिन पूरे भारतमें रहनेवाले सभी लोगोंके बीच एक अटूट संबंध बना रहा। देशके विभिन्न हिस्सोंमें स्थित हमारे ज्योतिर्लिंग, तीर्थ और धाम इस बातके गवाह हैं कि सभी भारतीय पूरे राष्ट्रको अपना राष्ट्र मानते रहे हैं और भाषाई, क्षेत्रीय, खान-पान और अन्य विविधताएं कभी भी इसमें बाधक नहीं बनीं। लेकिन अफसोसकी बात है कि विदेशी शासनके दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा साहित्य रचा गया और जान-बूझकर इतिहास लेखनके माध्यमसे झूठी कहानियां गढ़ी गयीं, जिससे दक्षिण भारतके लोगोंके मनमें उत्तर भारतके लोगोंके खिलाफ जहरभर गया। झूठा इतिहास रचा गया कि आर्य विदेशोंसे आये थे और उनके क्रूर आक्रमणसे द्रविड़ लोग आहत होकर दक्षिणकी ओर जानेको मजबूर हुए। ऐसी स्थितिमें हिंदी भाषाके प्रति शत्रुताको दक्षिणी राज्योंमें, तमिलनाडुमें और भी अधिक तीव्रतासे बढ़ावा दिया गया। कहा जाता है कि इस झूठी कहानीकी शुरुआत एक जर्मन प्राच्यविद् और भाषाशास्त्रीने की थी। आज प्रचुर मात्रामें वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत पूरी तरहसे एक मिथकए मनगढ़ंत और काल्पनिक और अवैज्ञानिक सिद्धांतोंपर आधारित है। भारत, अमेरिका और अन्य देशोंके शोधकर्ताओं द्वारा हालमें प्रकाशित शोध पत्रोंके अनुसार, हड़प्पा कालके वैज्ञानिक तथ्योंके साक्ष्यके आधारपर यह कहा जा सकता है कि मध्य एशियासे आर्योंका इतने बड़े पैमानेपर प्रवास कभी नहीं हुआ। इसके अलावा कई इतिहासकारोंने भी इस झूठी कहानीको उजागर करनेका काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भारतमें हो रहे तेजीसे विकाससे ईर्ष्या करनेवाले पश्चिमी दुनियाके देशों द्वारा यह एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है। दक्षिणमें हुए विकासके आंकड़ोंका सहारा लेकर, पत्रिकाने शरारतपूर्ण तरीकेसे इस मुद्देको राजनीतिसे जोड़ा और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टीके पास दक्षिणी राज्योंमें मजबूत आधार नहीं है। पत्रिकाका यह भी तर्क है कि इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकारके पास पूरे देशका जनादेश नहीं है।

गौरतलब है कि जिस देश (ब्रिटेन) में इकोनॉमिस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है, वहां अबतक किसी भी प्रधान मंत्रीको चुनावमें पूरे देशसे समान जनादेश नहीं मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रधान मंत्रीके पास पूरे देशका जनादेश नहीं है। दुनियाभरके लोकतंत्रके इतिहासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब सभी क्षेत्रोंसे समान रूपसे बहुमत वोट प्राप्त करके सरकार बनायी गयी हो। इसी तरह दक्षिण भारतके कुछ नेता भी इसी प्रकारके तर्क देकर अपनी अलगाववादी राजनीतिको बढ़ावा दे रहे हैं। देशमें कुछ भ्रष्ट और अयोग्य नेताओंके कारण कई राज्योंका विकास बाधित हुआ, जिनमें दक्षिणी राज्य भी शामिल थे। पूर्वोत्तरके कई राज्य पूर्ववर्ती केन्द्र सरकारकी उपेक्षाके शिकार रहे हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर जैसे कई राज्योंको उनकी जनसंख्याके अनुपातसे कहीं अधिक संसाधन मिलते रहे। हमें यह भी समझना होगा कि सभी राज्योंका विकास एक-दूसरेके सहयोगसे ही हो सकता है। जहांतक विकासका सवाल है, देशमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आयवाले दस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंमेंसे केवल दो दक्षिणसे हैं और वह भी पांचवें और छठे स्थानपर हैं और वह भी आईटी सेक्टरके कारण, जहां भारतके सभी हिस्सोंसे आनेवाले लोग काम कर रहे हैं।

जहां हमारे देशमें खाद्यान्न उपलब्ध करानेमें उत्तरी राज्योंका महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद उपलब्ध करानेमें दक्षिणी राज्योंके योगदानको कम नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार भारत एक परिवारकी तरह है और सभी राज्य इसके सदस्य हैं। परिवारमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होताय इसमें अमीर-गरीबका कोई विचार नहीं है, जरूरत इस बातकी है कि सब मिलकर काम करें और अपने अभिन्न परिवार यानी भारतको समृद्ध बनायें। इसके अलावा हम श्वसुधेव कुटुंबकमश् यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, को माननेवाले हैं। राजनीतिक उद्देश्योंवाले लोगोंने अब दक्षिणी राज्योंको कर धनके हस्तांतरणमें भेदभावका मुद्दा उठाकर उत्तर-दक्षिण विभाजनको एक और आयाम दे दिया है। मुख्य मंत्री सिद्धारमैया सहित कर्नाटक कांग्रेसके नेताओंने यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि दक्षिणी राज्योंको केंद्रीय करोंसे उनके वैध हिस्सेसे वंचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कर हिस्सेदारी वित्त आयोगकी सिफारिशोंके आधारपर तय की जाती है। १५वें वित्त आयोगकी कार्यवाहीके दौरान, इन राज्योंने केन्द्र सरकारके समक्ष संदर्भकी शर्तोंके बारेमें अपनी शिकायत व्यक्त की, जिसके अनुसार वित्त आयोगको पिछले आयोग द्वारा उपयोग की जानेवाली जनसंख्याको १९७१ के बजाय २०११ की जनगणनाके अनुसार उपयोग करनेका निर्देश दिया गया था। उनका आरोप था कि यह दक्षिणी राज्योंके खिलाफ जायगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्याको कई अन्य राज्योंकी तुलनामें बेहतर तरीकेसे नियंत्रित किया है। इन चिंताओंको दूर करनेके लिए, १५वें वित्त आयोगने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन यानी जनसंख्या नियंत्रणको भी महत्व दिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि दक्षिणी राज्योंमें धीमी जनसंख्या वृद्धि वहांकी शिक्षा और औद्योगिक विकासके कारण थी। लेकिन अधिकांश दक्षिणी राज्य जनसांख्यिकीय लाभांशको जनसंख्या नियंत्रण द्वारा पार कर चुके हैं और प्रवासी श्रमिकोंपर उनकी निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जो आपसी सहयोगके महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, केंद्रीय करोंके कुल हस्तांतरणमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरलकी हिस्सेदारी पिछले वित्त आयोगकी तुलनामें १५वें वित्त आयोगकी सिफारिशोंमें कमोबेश वही रही। हालांकि कर्नाटककी हिस्सेदारी ४.७१ प्रतिशत से घटकर ३.६४ प्रतिशत हो गयी। केरलका हिस्सा इस अवधिमें २.५ प्रतिशतसे घटकर १.९२ प्रतिशत हो गया। लेकिन केंद्रीय राजस्वमें हिस्सेदारीके अलावा, इन राज्योंको महत्वपूर्ण राजस्व घाटा अनुदान भी दिया गया। आंध्र प्रदेशके मामलेमें यह २०२१-२२ से २०२३-२४ के लिए ३०,४९७ करोड़ रुपये और कर्नाटकके लिए २०२१-२२ के लिए १६३१ करोड़ रुपये बैठता है। केरलके लिए यह २०२१-२२ से २०२३-२४ के लिए ३७,८१४ करोड़ रुपये और तमिलनाडुके लिए २०२१-२२ के लिए २२०४ करोड़ रुपये था। इसलिए आंकड़े किसी भी तरहसे वित्त आयोगके कथित पूर्वाग्रहको साबित नहीं करते। हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सद्भावके मुद्दोंपर, हमें अलगाववादी बयानोंसे बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रकी राष्ट्रीय एकता और जन-कल्याणपर काफी हदतक प्रभाव डाल सकता है। अलगाववादी आवाजोंपर अंकुश लगानेकी जरूरत है और अलगाववादी एजेंडेमें शामिल अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और मीडियासे भी सख्तीसे निबटा जाना चाहिए।

अफसोस है कि विदेशी शासकों द्वारा जानबूझकर इतिहास लेखनके माध्यमसे झूठी कहानियां गढ़ी गयीं जिससे दक्षिण भारतके लोगोंके मनमें उत्तर भारतके प्रति जहर भर गया। झूठा इतिहास रचा गया कि आर्य विदेशोंसे आये और उनके क्रूर आक्रमणसे द्रविड़ दक्षिणकी ओर जानेको मजबूर हुए। ऐसी स्थितिमें हिंदी भाषाके प्रति शत्रुताको दक्षिणी राज्योंमें अधिक तीव्रतासे बढ़ावा दिया गया। इस झूठी कहानीकी शुरुआत एक जर्मन प्राच्यविद् और भाषाशास्त्रीने की थी। प्रचुर मात्रामें वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत पूरी तरहसे मिथक और काल्पनिक है जो अवैज्ञानिक सिद्धांतोंपर आधारित है।

विकासका वाहक बन रहा मध्यम वर्ग

पर्सनल केयर आइटम्सकी मांग और आपूर्ति भी मध्यम वर्गके कारण ही बढ़ी है। आनलाइन बाजारको मध्यम वर्गने ही गति दी है। यही कारण है कि देशी-विदेशी कम्पनियां मध्यम वर्गको केन्द्रित कर अपने उत्पादोंको बाजारमें उतार रही है।

❐ डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देशके आर्थिक-सामाजिक विकासमें मध्यम वर्गकी प्रमुख भूमिका रही है। यह केवल हमारे देशके सन्दर्भमें ही नहीं अपितु समूचे विश्वकी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओंका अध्ययन किया जायगा तो कारण यही सामने आयगा। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियोंके बदलावमें मध्यम वर्गकी प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिक क्रांतिके बाद जिस तरहसे श्रमिक वर्ग उभर कर आया तो औद्योगिक क्रांतिका ही बाई प्रोडक्ट मध्यम वर्गका उत्थान माना जा सकता है। आर्थिक विश्लेषकोंकी माने तो आर्थिक विकासका कोई ग्रोथ इंजन है तो वह मध्यम वर्ग है। ज्यादा दूर नहीं जाय और केवल वर्तमान दशककी शुरुआत, बल्कि २०२१ की ही बात करें तो देशमें ३० फीसदी परिवार मध्यम आय वर्गकी श्रेणीमें आ गये थे। ऐसा माना जा रहा है कि २०३१ तक यह आंकड़ा बढ़कर ४६ फीसदीको छू जायगा। यानी कि इस दशकमें बचे साढ़े पांच सालमें भी मध्यम आय वर्गकी श्रेणीमें तेजीसे सुधार होगा। २०२१ में जहां ९.१ करोड़ परिवार मध्यम आय वर्गकी श्रेणीमें थे वहीं २०३१ तक यह संख्या बढ़कर १६.९ करोड़ होनेका अनुमान लगाया गया है। किसी भी देश और उसकी अर्थ व्यवस्थाके लिए यह अपने आपमें किसी बड़ी उपलब्धिसे कम नहीं आंकी जा सकती। विशेषज्ञोंके अनुसार पांच लाखसे ३८ लाख सालान आयवाले परिवारोंको मध्यम आय वर्ग श्रेणीमें माना गया है। यह भी समझना होगा कि मध्यम वर्गका विस्तारका सीधा सीधा अर्थ गरीबी रेखासे लोगोंका बाहर आना और बाजारू गतिविधियोंमें तेजी आनेका कारण मध्यम वर्ग ही है। मांग और आपूर्तिको भी मध्यम वर्गके सन्दर्भमें ही देखा और समझा जा सकता है। मध्यम आय वर्गमें इजाफा होनेका मतलब साफ-साफ यह हो जाता है कि देशकी अर्थव्यवस्था तेजीसे बढ़ रही है। इसे यूं समझा जा सकता है कि मध्यम आय वर्ग या दूसरे अर्थमें हम मध्यम वर्गकी बात करें तो जीवन जीनेका कोई आनन्द लेता है तो वह मध्यम वर्ग ही है। मध्यम वर्गके लोग जीवनको जीनेमें विश्वास रखते हैं भले ही उन्हें ऋणं कृत्वा घृतं पीबेतकी मानसिकताके अनुसार जीवनयापन करना पड़े। यही कारण है कि मध्यम वर्ग दिल खोलकर पैसा खर्च करता है। इसका एक कारण सामाजिक ताने-बानेकी भाषामें हम कहें तो यह कहा जा सकता है कि बहुत कुछ वह दिखावेके लिए करता है। जीवनयापनकी दिखावेकी इस प्रतिस्पर्धामें वह वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके परिवार, पड़ोसी, मित्रगण या आसपासके लोगोंके पास है। इसमें रहन-सहन, खान-पान, पहनना-ओढ़ना, शिक्षा और इसी तरहकी अन्य वस्तुओं-साधनोंको प्राप्त करना मध्यम वर्गका ध्येय रहता है और इसी कारण बाजारमें नित नये उत्पादोंकी मांग बढ़ती है तो देशके लोगोंके जीवन स्तरका पता चलता है। दरअसल मध्यम वर्ग ह्वाईट कालरका प्रतिनिधित्व करता है। वह इस प्रयासमें रहता है कि दिन-प्रतिदिन वह अधिकसे अधिक साधन जुटायें, भले ही उसके लिए उसे उधारका सहारा लेना पड़े। यहां यह भी समझ लेना जरूरी हो जाता है कि उच्च आय वर्गकी अपनी समझ एवं पहुंच होती है। पहली बात तो उच्च आय वर्गकी दायरेंमें कम लोग है। उनकी पसंद न पसंद अलग होती है। उनके लिए जो उत्पाद बाजारमें आयंगे वह अलग श्रेणीके होंगे। मध्यम वर्ग लगभग उसी दौड़में दौड़नेका प्रयास करता है। उच्च वर्गके पास लक्जिरियस चौपहिया वाहन है तो उसकी मांग पहले चरणमें चौपहिया वाहन एवं उसके बाद ज्यों-ज्यों वह थोड़ा आगे बढ़ना चाहेगा अपनी पहुंचके सुविधाजनक चौपहिया वाहन पानेकी कोशिशमें जुट जायगा। इसी तरहसे बाजारकी मांगको मध्यम वर्ग ही बढ़ाता है। तस्वीर हमारे सामने हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं दो दशक ही हुए होंगे कि घरोंमें पंखोंकी जगह कूलरोंने ली और कूलरोंमें भी हैसियत अनुसार ब्राण्डेड कम्पनियोंसे लेकर लोकल कंपनियोंके कूलरोंने घरोंमें जगह बनायी। आज तस्वीरका दूसरा पहलू सामने आ गया है जिस एयर कण्डीशनरके लिए केवल सोचा जा सकता था वह आज घर-घरमें पहुंच गया है। कमसे कम एक एसी तो मध्यम वर्गीय परिवारमें देखनेको आसानीसे मिल जायगा। इसे यूं समझा जा सकता है कि मध्यम वर्गके विस्तारके अनुसार बाजारमें मांग बढ़ी तो नित नयी कम्पनियां बाजारमें आयी और इससे अर्थव्यवस्थाको गति मिलनेके साथ ही रोजगारके अवसर बढ़े। यह तो एक उदाहरण मात्र है। देखा जाय तो फास्टफूड हो या कंफेक्सरी या शॉफ्ट ड्रिंक या इसी तरहकी अन्य खाने-पीनेकी चीजें इसको बाजार मिला है तो इसका श्रेय मध्यम वर्गको ही जाता है। पर्सनल केयर आइटम्सकी मांग और आपूर्ति भी मध्यम वर्गके कारण ही बढ़ी है। आज आनलाइनका जो बाजार खड़ा हुआ है उसको गति दी है तो वह मध्यम आय वर्गके लोगोंने ही दी है। स्कूटर, स्कूटी, कारसे लेकर वाहनोंकी जो रेलम पेल देखी जा रही है वह इस मध्यम वर्गके कारण ही है। रियल स्टेट जिस तरहसे आगे बढ़ रहा है और गगनचुंबी इमारतोंका जिस तरहसे जाल बिछ रहा है वह मध्यम वर्गके कारण ही संभव हो पा रहा है। यही कारण है कि आज देशी-विदेशी कम्पनियां मध्यम वर्गको केन्द्रित कर अपने उत्पादोंको बाजारमें उतार रही है। सही मायनेमें कहा जाये तो जिसने मध्यम वर्गकी मांगको समझा वह मालामाल होता जा रहा है और उसकी बाजारमें पकड़ तेज होती जा रही है। ऐसेमें यह माननेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तेजीसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाका बहुत कुछ श्रेय मध्यम वर्गको जाता है।

आत्मबोध

श्रेष्ठ समय

❐ अमितेष शास्त्री

चैत्रमें आनेवाले नवरात्रमें अपने कुल देवी-देवताओंकी पूजाका विशेष प्रावधान माना गया है। आजके भागमभागके युगमें अधिकांश लोग अपने कुल देवी-देवताओंको भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग समयाभावके कारण भी पूजा-पाठमें कम ध्यान दे पाते हैं, जबकि इस ओर ध्यान देकर आनेवाली अनजान मुसीबतोंसे बचा जा सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशतीमें स्वयं भगवतीने इस समय शक्ति-पूजाको महापूजा बताया है। कलश स्थापना, देवी दुर्गाकी स्तुति, सुमधुर घंटियोंकी आवाज, धूप-बत्तियोंकी सुगंधि नौ दिनोंतक चलनेवाले साधना पर्व नवरात्रका चित्रण है। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। सर्वप्रथम मां जगदंबाके सभी नौ स्वरूपोंका स्मरण करते हुए घरमें प्रवेश करते ही कन्याओंके पांव धोएं। उन्हें उचित आसनपर बैठाकर उनके हाथमें मौली बांधें और माथेपर बिंदी लगायें। उनकी थालीमें हलवा-पूरी और चने परोसें। अब अपनी पूजाकी थाली जिसमें दो पूरी और हलवा-चने रखे हुए हैं, के चारों ओर हलवा और चना भी रखें। बीचमें आटेसे बने एक दीपकको शुद्ध घीसे जलायें। कन्या पूजनके बाद सभी कन्याओंको अपनी थालीमेंसे यही प्रसाद खाने को दें। कन्याओंको उचित उपहार तथा राशि भी भेंट में दें। उनके चरण छुएं और उनके प्रस्थानके बाद स्वयं प्रसाद खानेसे पहले पूरे घरमें खेत्रीके पास रखे कुंभका जल सारे घरमें बरसायें। पौराणिक कथानुसार प्राचीन कालमें दुर्गम नामक राक्षसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जीको प्रसन्न कर लिया। उनसे वरदान लेनेके बाद चारों वेद एवं पुराणोंको कब्जेमें लेकर कहीं छिपा दिया, जिससे संसारमें वैदिक कर्म बंद हो गया और घोर अकाल पड़ गया। हाहाकार मच गया। सृष्टिको बचानेके लिए देवताओंने व्रत रखकर नौ दिनतक मां जगदंबासे सृष्टिको बचानेकी विनती की। तब मां भगवतीने दुर्गाका वध कर देवताओंको निर्भय कर दिया। तभीसे नवदुर्गा तथा नव व्रतका शुभारंभ हुआ।

लोक संवाद

अहंकार एवं आत्मविश्वास

महोदय,-जैसे ही हम भरोसा करना छोड़ते हैं, वैसे ही हम खुदको भीतरसे बंद कर लेते हैं और अकेलेपनकी कंदरामें खो जाते हैं। हम प्यार कम करते हैं और डरते ज्यादा हैं। अब रिश्तोंका मनोविज्ञान बिल्कुल बदल चुका है। कब कौन किसका भरोसा तोड़ दे, कब कौन किसे सरेआम लूट ले, रिश्तेकी ओटमें कब कौन रिश्ता नापाक कर जाय। सच है कि आज हम किसीपर भरोसा नहीं करते, न हमपर कोई भरोसा करता है। ऐसा नहीं है कि भरोसा टूटनेकी कोई एक वजह है। असलमें व्यक्ति, समाज और देश सभी एक-दूसरेसे अंतर्सम्बंधित हैं। समाज ऐसा बन चुका है जहां हम भरोसा करना छोड़ चुके हैं तो दोषी कौन है। कोई खास समाज या सरकार या समूह दोषी नहीं है, बल्कि समस्त मानवता जिम्मेदार है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोग रिश्तोंको सीढ़ीकी तरह इस्तेमाल कर ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं और जब कहीं पहुंच जायं फिर उन्हीं रिश्तोंको रौंद डालते हैं। कई बार आलम बहुत ही खौफनाक होता है। शारीरिक शोषणकी शिकार सिर्फ स्त्री ही नहीं, बल्कि छोटे लड़के भी कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी तो यह भी देखनेमें आता है कि प्रेमी-प्रेमिकाओंके तार भी मनसे और आत्माकी गहराइयोंसे जुड़े नहीं होते, वैसेमें प्रेम महज प्रदर्शनका जरिया बन जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कैसे कोई प्रेमी या प्रेमिका जिसने इतने भरोसेसे रिश्ता जोड़ा हो, उससे ही बदला ले लेता है। अकसर सुननेमें आता है कि विवाहके लिए राजी न होनेपर लड़कीको उसके प्रेमीने एसिडसे जला दिया या धोखेसे हत्या कर दी या फिर प्रेमजालमें फंसाकर लम्बे समयतक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और बादमें उसे या तो बेच दिया या फिर उसका नाजायज इस्तेमाल करता रहा। प्रेममें पड़ जानेवाली उस लड़कीने भी तो भरोसा ही किया होगा। यदि कोई प्रेमी विवाह कर भी ले तो मानो कि बड़ा अहसान कर दिया हो, परन्तु फिर भी दहेज चाहिए होता है। कैसे कोई स्त्री ऐसे पुरुषको प्रेम करे या उसपर भरोसा करे। जीवनमें एक बार भी भरोसा टूटता है तो आजीवन किसीपर भी भरोसा नहीं हो पाता। शक और संदेहके कारण हम खुदमें सिकुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि खुदके बाहरकी दुनियामें सभी अविश्वसनीय दिखने लगते हैं। इनसानोंके बीच भरोसा कायम करनेकी हर सम्भव और हर व्यक्ति कोशिश करे। **-डा. जेन्नी शबनम, वाया ईमेल।**

धरतीका बढ़ता तापमान

महोदय,- धरतीका तापमान बढ़ रहा है। गर्मीमें हर वर्ष बेहताश इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर झीलोंपर खतरा मंडरा रहा है। एक सर्वेके मुताबिक १८८ झीलें तबाहीका बड़ा कारण बन सकती हैं। इसमें तीन करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। सरकार इस और ध्यान केंद्रित नहीं करके तबाहीको निमंत्रण दे रही है। सरकार गम्भीर नहीं है। जलवायु परिवर्तनके लिए मोदीने अंतराष्ट्रीय मुद्दे उठाये हैं। उत्तराखंडकी ग्लेशियर झीलोंका आकलन किया गया है। हमारी सरकारें गलेतक आफत नहीं आ जाय उससे पूर्व कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। हर बार ग्लोबल वार्मिंगकी चेतावनी मीडियामें छप रही है। ऐसा तो नहीं है कि ग्लेशियरसे पहले कोई नुकसान नहीं हुआ है। केदारनाथमें ३० हजार लोगोंकी ग्लेशियर फटनेसे मौत हो गयी है। सिक्किम, लदाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेशकी कुल सैकड़ों झीले हैं। इनपर ज्यादा खतरा है। खतरेवाली झीलोंको पंचर नहीं किया गया तो बमकी तरह फटनेवाली इन झीलोंका कहर मानवजाति आफत बनकर आयगा। तब हम कुछ नहीं करते है। मिट्टीके साथ मलबा आनेसे कई जिन्दगी लील गयी थी। मानवताके लिए ही सही इस संकटको दूर करनेके लिए कदम उठाना चाहिए। संवेदनशील ग्लेशियरपर ध्यान देनेकी जरूरत है। यह खतरेकी घण्टी है। इसको हल्केमें नहीं लिया जा सकता है। **-कांतिलाल मांडोत, सूरत।**

आर्थिक दरपर भ्रम फैलानेका प्रयास

❐ मिथिलेश झा

चुनावको देखते हुए दुनियाभरकी शक्तियां सक्रिय हो गयी हैं। जार्ज सोरेभका धन चुनावको प्रभावित करनेके लिए सक्रिय हो गया है। वे चाहते हैं कैसे भी जनताको भ्रमित कर दिया जाय। रघुराम राजनका मानना है कि वर्तमान ८.४० का विकास दर बढ़ा-चढ़ाकर दिखा दिया गया है। यह अकेला देश है जहांपर अभिव्यक्तिकी आजादीके नामपर कुछ भी बोल देनेकी आजादी है। जनताको भ्रमित कर देना इनका उद्देश्य होता है। ब्लैक रॉकके सीडीओका बयान आया कि मैं बिल्कुल असहज पाता हूं कि भारतीयका सोनेके प्रति भौहे दिखाकर भारतीय लगातार विश्व बाजारसे सोना खरीदते रहते हैं। यह सोना आर्थिक विकासमें किसी प्रकारका योगदान नहीं करता है। किन्तु सोना खरीदकर जमा करते रहते हैं। ब्लैक रॉकके सीईओको कुछ और खुलकर बताना चाहिए था। सोनेकी खरीद देशमें गरीबी बढ़ाता है, देशको गरीब बनाता है। यह वक्तव्य अनोखा है। विश्वपटलपर इनका ज्ञान टाय-टाय फिस हो जाता है। ये यदि वाकई अर्थशास्त्रके ज्ञानके धनी होते तो जनताको जागरूक करना इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन नहीं ये मात्र बोलनेके लिए है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश कहां जा रहा है, इस बातपर विचार-विमर्श करें। आजादीके बादसे भारतने चार सौ अरब डालरसे ज्यादाका सोना खरीदा है। ठीक है आपने चार सौ अरब डालरका सोना खरीदा लेकिन आपके पैसेका क्या हुआ। विदेशी कम्पनियां अर्थात् एफआईने भारतके अन्दर आपके अच्छी कम्पनियोंका शेयर १८ प्रतिशतसे ज्यादा खरीद रखे हैं। उनको हर साल डिविडेण्टके तौरपर अरबों रुपये मिल रहा है। जैसे-जैसे देश विकास करता जायगा। इनकी शेयरकी कीमत बढ़ती जायगी। हमारे सोनेका क्या इसको जब भी बेचने जायंगे कहीं १५ से २० प्रतिशततक कीमत घटती जायगी। कहावत है यदि सोनेकी चार-पांच बार खरीद-बेच कर ली जायगी तो इसका मूल्य शून्य हो जाता है। लेकिन इन महान अर्थशास्त्रियोंकी टीमको यह नहीं हुआ कि देशकी जनताको जागरूक करें और देशको गरीबी बेरोजगारी और महंगीमुक्त करें।

दूसरी बात विकास दरकी है। इनको लगता है यह बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था पेट्रोल-डीजल या कच्चे तेलकी कीमतोंके इर्द-गिर्द घूमती रही है। अर्थव्यवस्था कच्चे तेलके इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन इनपर कुछ अध्ययन करनेकी जरूरत नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्धके समयके कुछ दिन बादसे ही हमें २४ डालर डिस्काउण्टपर तेल मिलना शुरू हो गया था। डा. मनमोहन सिंहने जब देशकी कुर्सीका त्याग किया था उस दिन ११६-११७ डालरपर कच्चे तेलकी कीमत थी। अब भी यह ८० डालर प्रति बैरलकी कीमतपर उपलब्ध है। जब मनमोहन सिंह जा रहे थे तब देशकी आर्थिक विकास दर ४.५ प्रतिशत थी। डा. मनमोहन सिंहने कहा था कि दस डालरकी कीमतका असर हमारे अर्थव्यवस्थाको आधा प्रतिशत प्रभावित करता है। दस डालरपर आधा प्रतिशत वर्तमानमें किसी प्रकारका फेरबदल नहीं करना है तो भी सस्ते तेलके कारण हमारी अर्थव्यवस्थाका विकास दर ६.५ प्रतिशत होना चाहिए। अब आईये देखते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्थाका वास्तविक तस्वीर कहांपर टिकता है। रूससे २४ डालरके डिस्काउण्टके भावको भी जोड़ दिया जाय तो हमारी अर्थव्यवस्थाकी विकास दर ७.७५ पर टिकता है। दस वर्षोंमें क्या हुआ है। जहांपर हम १८९ मिलियन टनके लिए १६५ अरब डालरका भुगतान किये थे। तेलकी मात्रा बढ़ती गयी और भारतको भुगतान कम करना पड़ा। यह अन्तर ५०-५० लाख करोड़ रुपयेका है।

कच्चे तेलके आयातसे होनेवाले बचतको निवेशके रूपमें देखा जाय तो इससे आर्थिक विकासको कितना रफ्तार मिला होगा। सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इससे रोजगार कितना मिला होगा। इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्थाकी विकास दर ८.४० है तो यह ज्यादा नहीं है, बल्कि ८.४० से ज्यादाका होगा। यह विकास दर कहीं भी हो सकता है। किन्तु नौ प्रतिशतसे ज्यादाका ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था यदि तेलपर आधारित है और इसका प्रबन्धन मौजूदा सरकार नौ जितना अच्छा किया है। इस प्रबन्धनके कारण ही देशकी अर्थव्यवस्था तेजीकी ओर उड़ान भर रहा है। किन्तु इस ओर ध्यान देनेकी जरूरत भी नहीं समझा गया। नहीं तो झूठ फैलानेके बजाय देशकी अर्थव्यवस्थाकी गुणगान करनेमें मुंह नहीं थकता। किन्तु बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं तो कुछ तो बोलना है। बोलकर निकल जाते हैं।

यह सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इनका गोल पहलेसे निर्धारित है। अभीतक पेट्रोलमें दस प्रतिशतसे ज्यादा अल्कोहल मिलाया जा रहा है। अभी १२-१४ लाख करोड़का कच्चा तेल हर साल बाहरसे आयात किया जा रहा है। सरकार यदि यह आयात मात्र शून्य कर लेती है तो १२-१४ लाख करोड़ रुपया भारतीय अर्थव्यवस्थामें बचने लगेगा। इसका निवेश अर्थव्यवस्थामें ही होगा। आर्थिक विकास दर कहां जायगा। यह बड़े एवं महान अर्थशास्त्रियोंको नहीं दिख रहा है। यह दिखता तो अर्थव्यवस्थापर भ्रामक बयानबाजीसे परहेज करते। यदि ये राष्ट्रहितमें सोचते तो झूठ फैलानेका प्रयास नहीं करते। जो लक्ष्य मोदी सरकार लेकर चल रही है। इससे आसानीसे पूरा किया जा सकता है। भारत आसानीसे विकसित राष्ट्र बन सकता है। बड़े अर्थशास्त्री मात्र नजरिया बदलकर अर्थव्यवस्थाको देखना शुरू करें तो मोदी सरकारके तेल प्रबन्धनके गुणगानसे मुंह नहीं थकेगा। यह अलग बात है कि अर्थव्यवस्थाको तेल नजरियेके बजाय और पैरामीटरसे देखेंगे तो स्वयं भ्रमित रहेंगे और भ्रम फैलायेंगे भी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

आम चुनाव और इंडिया गठबंधन की कछुआ चाल

लोकसभा चुनाव 2024 वैसे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए करो या मरो की स्थिति में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के लोग लगातार पार्टी छोड़ भाजपा व अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। इन्हें बांधकर रखने की बात तो दूर समझाने और साधने वाला भी दूर-दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। हद यह है कि जो दम भरते थे कभी कि भले जेल हो जाए या जान चली जाए वो कांग्रेसी थे, हैं और आगे भी कांग्रेसी ही रहेंगे, अब अन्य दलों के परचम लहराते नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को लगातार कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है, लेकिन क्या मजाल कि किसी ने चुनाव के बारे में सोचा हो और एक पुख्ता रणनीति के तहत चुनाव में उतरने और पार्टी व गठबंधन को मजबूत करने की बात भी की हो। जो जहां है, ठीक है और जहां होगा बेहतर होगा की तर्ज पर कारवां चलता रहा और हालात यहां तक पहुंच गए कि पार्टी टिकट पर चुनाव में उतरने से भी अनेक नेताओं ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि इससे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अनभिज्ञ है। मालूम सब है और बातें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन परिणाम सिफर है। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि चुनावी रणनीति बनाने से लेकर चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस और अब इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से खासा पिछड़ गया है। एक तरफ सत्ता में रहते हुए भी भाजपा अपने आप को चुनाव मोड से कभी अलग ही नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने आपको साबित करने की खातिर जमीनी कार्य करते भी नजर नहीं आए हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार को महज एक हफ्ते का समय ही रह गया है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन की अब तक ऐसी कोई ऐतिहासिक रैली नहीं हुई, जिसे लेकर कहा जा सके कि इसके माध्यम से संपूर्ण देश को यह संदेश दिया गया, जो चुनाव को प्रभावित करता है। ना ही चुनाव को लेकर बूथ स्तर की ही कोई योजना ही अभी तक सामने आई है। इससे हटकर यदि बात भाजपा के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो अबकी बार, 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है। हद यह है कि शुरु से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मोर्चा खुद संभाल रखा है। जिस कारण विरोधी खेमे में भगदड़ की स्थिति नजर आई है। इस स्थिति में कहना गलत न होगा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि संपूर्ण इंडिया गठबंधन की चुनावी जंग खुद जनता ने संभाल रखी है और वक्त आने पर बतला देंगे जैसी स्थिति प्रतीत हो रही है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव 2024 में भी ईवीएम को लेकर सवाल जस के तस मौजूद हैं। इसे लेकर जहां चुनाव आयोग के समक्ष अर्जियां लगाई गई हैं तो वहीं अदालत के दरवाजे भी खूब खटखटाए गए हैं, लेकिन विपक्ष की मांग के मुताबिक कोई माकूल हल निकलता नहीं दिखा है। अंततः यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव एक करिश्माई परिणाम से परिपूर्ण होता है, तभी अनेक दफा अप्रत्याशित चुनाव परिणाम जनता के सम्मुख आ जाते हैं।

घर घर में लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप

– बाल मुकुन्द ओझा

खानपान और खराब लाइफ स्टाइल को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में लाइफ स्टाइल से जुडी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। फिटनेस टेक्नोलॉजी कंपनी गोकी इंडिया फिट रिपोर्ट 2024 का गहनता से अध्ययन करें तो पाएंगे देश में गलत आदतों और जीवन शैली के कारण घर घर में बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 45 फीसदी लोगों की सेहत फिट नहीं है और वे विभिन्न बीमारियों का शिकार होकर शारीरिक पीड़ा भुगतने को मज़बूर है। रिपोर्ट के अनुसार देशभर में शुगर और बीपी के मरीज निरंतर साल दर साल बढ़ते ही जा रहे है। देश में हर पांचवा व्यक्ति बीपी का मरीज है। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। पुरुषों का अनुपात जहां 40 प्रतिशत है वहां 59 प्रतिशत महिलाएं स्वस्थ नहीं है। मोटापे की शिकार महिलाओं की संख्या 16 प्रतिशत है। तनावग्रस्त महिलाओं का अनुपात भी पुरुषों के 26 प्रतिशत के मुकाबले 35 प्रतिशत है। शुगर की बात करें तो 17 प्रतिशत लोग शुगर, 18 प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल और 8 प्रतिशत थायराइड से पीड़ित है। लाइफ स्टाइल बीमारियों में बुजुर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित है। देश के आधे बुजुर्ग बीपी और 38 प्रतिशत शुगर की समस्या से परेशान है। भारत में आम तौर पर लोगों में स्वास्थ्य चेतना का अभाव है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी लोग तभी चिंतित होते हैं जब कोई रोग उन्हें घेर लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि निष्क्रियता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। विश्व लगातार बढ़ रही निष्क्रियता नामक महामारी का शिकार हो रहा है आरामदेह जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे हृदय रोग, बीपी और डायबीटीज, अब तक संपन्न देशों की बीमारियाँ मानी जाती थीं लेकिन अब विकासशील देश भी अब इसके शिकार हो रहे हैं। विश्व भर में इन बीमारियों से हर वर्ष दो करोड़ लोगों की मौत होती है और इनमें से अस्सी प्रतिशत गरीब देशों से हैं। इस तरह की बीमारियाँ दौड़–भाग से रोकी जा सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि विश्व के पचासी प्रतिशत लोग निष्क्रिय जीवनशैली बिता रहे हैं और विश्व के दो–तिहाई बच्चे भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हैं और इससे उनके भविष्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। संगठन का कहना है कि साधारण व्यायाम जैसे पैदल चलना, नृत्य करना और यहाँ तक की सीढ़ियाँ चढ़ना भी सेहत को ठीक रख सकता है। शोध बताते हैं कि खानपान में साधारण परिवर्तन और हल्के व्यायामों से आंतों के कैंसर के खतरे को सत्तर प्रतिशत और डायबिटीज को साठ प्रतिशत कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ आर्थिक विकास किया है, लेकिन इस विकास के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कुपोषण के शिकार हैं जो भारत के स्वास्थ्य के प्रति चिंता उत्पन्न करता है।

शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से तनाव, अवसाद और दर्द को कम करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित व्यायाम उच्च रक्तचाप, शुगर और गठिया सहित अनेक व्याधियों को रोकने में मदद करता है। सेहत को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम के साथ शरीर को गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट, बिना चर्बी वाला प्रोटीन, आवश्यक वसा और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमें अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में से कुछ समय अपने स्वास्थ्य की देखरेख के लिए निकालना होगा तभी हम अपनी सेहत को पुष्ट कर सकेंगे। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में सफलता अर्जित कर सकते है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी दौलत उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। आज हर व्यक्ति अच्छी सेहत की बात करता है और इसके प्रति काफी हद तक लोगों में जागरूकता भी आई है। मगर आज भी अधिकांश व्यक्तियों के रोग का या तो समय पर पता नहीं चल पाता है या उसका सही तरह से उपचार नहीं हो पाता है, जिसके कारण हर साल पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की असमय ही मृत्यु हो जाती है। स्वस्थ जीवन का अधिकार हर मनुष्य को है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। मन को कभी गंदा या खराब नहीं रखना चाहिए। मानव की सबसे बड़ी दौलत उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य होता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। इनमें ताजी हवा, स्वच्छ पानी, उचित धूप, संतुलित आहार, जंक फूड से दूर, स्वच्छ, स्वस्थ और हरियाली का वातावरण, सुबह की सैर, व्यक्तिगत स्वच्छता, उचित शिक्षा आदि की आवश्यकता होती है। अच्छा स्वास्थ्य तनाव के स्तर को कम करता है और बिना किसी कष्ट के स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है। हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में पता होना चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाना चाहिए। हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए समय पर ताजे फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही और छाछ आदि का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

कानूनी सख्ती के बावजूद क्यों पनप रही है बाल-तस्करी

एक सर्वे में खुलासा हुआ था कि भारत के नौ फीसदी युवा शादी तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। संतान सुख के लिए उन्हें बच्चे खरीदने से परहेज नहीं है। हैरत की बात यह है कि देश के ढाई करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चों में से किसी को गोद लेने का विकल्प होने के बावजूद ऐसे युवा कई बार बाल तस्करी करने वालों से संपर्क तक साध लेते हैं। बाल–तस्करी भारत की एक उभरती एवं ज्वलंत समस्या है।

– ललित गर्ग –

देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जांच एजेंसियों की नाक के नीचे नवजात बच्चों की खरीद–फरोश्त की मंडी चल रही थी जहां दूधमुंहे एवं मासूम बच्चों को खरीदने–बेचने का धंधा चल रहा था। दिल्ली की 'बच्चा मंडी' के शर्मनाक एवं खौफनाक घटनाक्रम का पर्दापाश होना, अमानवीतया एवं संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा है। जिसने अनेक ज्वलंत सवालों को खड़ा किया है। आखिर मनुष्य क्यों बन रहा है इतना क्रूर, अनैतिक एवं अमानवीय? सचमुच पैसे का नशा जब, जहां, जिसके भी सर चढ़ता है वह इंसान शैतान बन जाता है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी कर ऐसे ही शैतानों के कुकृत्यों का भंडाफोड किया और एक महिला समेत सात लोगों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया, इसके साथ ही तीन नवजात शिशुओं को उनके चंगुल से बचाया। आरोपियों में एक अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर को इस धंधे का मास्टर माइंड माना जा रहा है। न केवल दिल्ली वालों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए यह खबर चिंता पैदा करने वाली ही नहीं है, बल्कि खौफ पैदा करने वाली भी है। दिल दहाले देने वाली इस घटना में सीबीआई की अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते थे। आरोपी कथित तौर पर वास्तविक माता–पिता के साथ–साथ सेरोगेट माताओं से भी नवजात बच्चे खरीदते थे। इन नवजात बच्चों को चार से छह लाख रुपए में बेच दिया जाता था। जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारियों के अनुसार एजेंसी की गिरफ्त में आए आरोपी बच्चों को गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। आरोपी कई निसंतान दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी करने में भी संलिप्त हैं। इस गिरोह के तार कहां–कहां हैं इसकी भी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। यह गिरोह आईवीएफ के माध्यम से युवतियों को गर्भधारण कराता था फिर इन शिशुओं को बेचता था। गरीब माता–पिता से भी बच्चे खरीदे जाते थे। बच्चों की खरीद–फरोख्त और बच्चों की तस्करी एक ऐसी समस्या है जिस पर तभी ध्यान जाता है जब कोई सनसनीखेज खबर सामने आती है। अर्थ की अंधी दौड़ में इंसान कितने क्रूर एवं अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने लगा है कि चेहरे ही नहीं चरित्र तक अपनी पहचान खोने लगे हैं। नीति एवं निष्ठा के केन्द्र बदलने लगे हैं। मानवीयता एवं नैतिकता की नींव कमजोर होने लगी है। आदमी इतना खुदगर्ज बन जाता है कि उसकी सारी संवेदनाएं सूख जाती है। बाल तस्करी के खिलाफ कई सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत में यह समस्या नासूर बनती जा रही है। नवजात बच्चे चुराने वाले गिरोह के पर्दाफाश से फिर यह तथ्य उभरा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में कानून का कोई खौफ नहीं है। बच्चों की तस्करी पर भारी जुर्माने के साथ उम्रकैद तक का प्रावधान होने के बावजूद यह कड़वी हकीकत है कि ऐसे दस फीसदी से भी कम मामले दोषियों को सजा तक पहुंच पाते हैं। मुकदमों की पैरवी सही तरीके से नहीं होने के कारण अपराधी बच निकलते हैं और वे फिर बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद–फरोश्त में लिप्त हो जाते हैं। बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद–फरोश्त के अनेक कारण हैं। निसंतान दंपतियों द्वारा बच्चों को खरीदना एकमात्र कारण नहीं है बल्कि गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, सुविधावादी जीवनशैली, भौतिकवाद, बच्चों की अधिक संख्या, बेरोजगारी भी बड़ा कारण है। पैसे की अपसंस्कृति ने अपराधों को अनियंत्रित किया है। पैसे कमाने के लिए कई लोग बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद–फरोश्त के व्यापार में लग गए हैं। वो गरीब लोगों को बहकाकर उनके बच्चों को काम दिलवाने का झांसा देकर शहर ले जाते हैं फिर शहर में जाकर उन बच्चों को बेचा जाता है फिर शुरू होता है बच्चों के शोषण का अंतहीन सिलसिला। जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपराधी अगवा कर बेच देते हैं। लड़कियों को देह व्यापार के लिए विवश किया जाता है। हजारों बच्चों को फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। 16–16 घंटे काम कराके इन को भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। इन सब कारणों से देश का बचपन कराह रहा है। देश में युवाओं के एक वर्ग की सोच में बदलाव भी परोक्ष रूप से बाल–तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। एक सर्वे में खुलासा हुआ था कि भारत के नौ फीसदी युवा शादी तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। संतान सुख के लिए उन्हें बच्चे खरीदने से परहेज नहीं है। हैरत की बात यह है कि देश के ढाई करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चों में से किसी को गोद लेने का विकल्प होने के बावजूद ऐसे युवा कई बार बाल तस्करी करने वालों से संपर्क तक साध लेते हैं। बाल–तस्करी भारत की एक उभरती एवं ज्वलंत समस्या है। यह केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी समस्या है। पिछले साल एक एनजीओ की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016 से 2022 के बीच बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे, तीसरे नंबर पर थे। इस अवधि में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भी कई मामले दर्ज हुए। कोरोना काल के बाद दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों में 68 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह भी देखने में आया कि जिलों की बाल तस्करी से जुड़े मामलों में जयपुर पहले स्थान पर रहा। पिछले साल संसद में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2021 में हर दिन औसतन आठ बच्चों की तस्करी हुई। देश के ही भीतर यह तस्करी होती है लेकिन संगठित गिरोह कुछ बच्चों की खाड़ी और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में भी तस्करी करते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच देश में 18 साल से कम उम्र की 2.51 लाख लड़कियां लापता हुई। इनमें से ज्यादातर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की थी। बचपन अगर बाल तस्करी के बीच फंसकर रह जाए तो बच्चा अपने बचपन, क्षमता और मानवीय गरिमा के साथ–साथ शारीरिक और मानसिक विकास से भी वंचित रह जाता है। गौरतलब है कि बच्चों के घरेलू काम, विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम, भीख मांगना, अंग तस्करी और व्यावसायिक यौनकर्म जैसी अवैध गतिविधियां बाल तस्करी की कोख से ही जन्म लेती हैं। सरकार और समाज को इससे मिलकर निपटना होगा। इस समस्या की जड़ में गरीबी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यावहारिक और ठोस नीति बनाई

जानी चाहिए कि बाल तस्करी के समूल उन्मूलन की जमीन तैयार हो सके। इसे देश की विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि आज बहुत से अजन्मे मासूम तो मां के गर्भ में आते ही जीवन–मृत्यु से जूझने लगते हैं। जन्म लेने के बाद इस देश में बच्चों को बेच दिया जाता है या ऐसे बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग चौराहों, रेलवे स्टेशन, गली–मोहल्ले में भीख मांगता मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का बचपन होटलों पर काम करते या जूठे बर्तन धोते हुए या फिर काल कोठरियों में जीवन बिताते हुए कट जाता है। यों भी कह सकते हैं कि उनका जीवन आज अंधेरे में कट रहा है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत का बचपन आर्थिक कारणों से घायल है। बच्चे को बेचे और खरीदे जाने में जितने लोग, जिस तरह शामिल होते थे, वह नये बनते भारत के भाल पर एक बदनुमा दाग है। क्यों कानून का डर ऐसे अपराधियों को नहीं होता? क्यों सरकारी एजेंसियों की सख्ती भी काम नहीं आ रही है और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां प्रश्न कार्रवाई का नहीं है, प्रश्न है कि ऐसी विकृत एवं अमानवीय सोच क्यों पनप रही है?

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार ई–253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली–92)

पत्नी जी की छह बातें !

– रामविलास जांगिड़

बात एक– पत्नी जी बाजार गई। बाजार मतलब साड़ी! महाभारत से बचने के लिए पतिदेव साथ हैं। पत्नी श्री 50 साड़ियों की दुकानें घूम कर हजार साड़ियां देखती है। पतिदेव से पूछती– कौनसी अच्छी लग रही है। पतिदेव– ये अच्छी है। पत्नी श्री– ये तो घर में 10 पहले से पड़ी है। पतिदेव दूसरी ओर इशारा करते हुए– ये भी अच्छी है। पत्नी श्री– देख नहीं रहे हो ये तो मैंने अभी पहन रखी है। पतिदेव– तो वह देख लो। वह भी अच्छी है। पत्नी श्री– तुम्हारे को बिल्कुल अकल नहीं है। हर चीज को अच्छी कह देते हो। पतिदेव– रहने दो किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। पत्नी श्री चीख कर सप्तम स्वर में बोलती हैं– रहने दो! मुझे पता है। तुम साड़ी नहीं दिला पाओगे! पूरे दिन दुकानों पर घूमाते रहोगे। बात दो– पत्नी– सुनो! आज खाने में क्या बनाऊं? पति मिमियाता है– कुछ भी बना लो। पत्नी– कुछ का नाम तो बताओ? आप जो बताएंगे, वही बनाउंगी। पति– करेला, भिंडी, आलू कुछ भी बना लो। पत्नी– रोज–रोज ये नहीं चलेगा। पति– गोभी टमाटर कुछ! पत्नी– ये कल ही खाए थे। पति– तो कुछ भी बना लो। पत्नी– बता तो दो! बताने में भी जोर आता है क्या? जाने कहां रहते हो आजकल! देख रही हूं, तुम्हारा घर में मन नहीं है! बात तीन– पत्नी जी को हल्का सर दर्द है। पतिदेव उसकी सेवा करते है। पत्नी जी कहती है कि रहने दीजिये। आप थक जाएंगे। पतिदेव– इसमें थकान कैसी है? ये तो मेरा धर्म है। पत्नी जोर देकर कहती– रहने दीजिए। तब पतिदेव अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं। पत्नी चीखती है– तुम मेरा कभी ध्यान नहीं रखते! पति महोदय मरी मक्खी की तरह जमीन पर पसर जाते हैं।

बात चार– पत्नी जी कहती है– सुनो! मैं कैसी लग रही हूं! पतिदेव– बहुत सुंदर! पत्नी चिढ़कर– आपको तो मैं हमेशा ही सुंदर लगती हूं। पत्नी– सुनो! ये चूड़ियां कैसी लग रही है? पतिदेव– जरा लाल कलर की होती तो और ज्यादा सुंदर लगती। पत्नी श्री दहाड़े मार कर रोते हुए चिल्लाती– हां हां। मुझे पता है। मैं आपको कभी सुंदर नहीं लगती। तभी देख रही हूं छत पर खड़े होकर कहां झांकते रहते हो! बात पांच– पत्नी जी का आज मूड ऑफ है। पतिदेव पूछते हैं– क्या हुआ? कुछ बताओ मुझे। पत्नी जी– रहने दो तुम नहीं समझोगे! पति– बताओ तो जरा कुछ! पत्नी जी– कहा ना रहने दो! तुम नहीं समझोगे! पतिदेव– ठीक है। कहकर मोबाइल में कुछ देखने लग जाते हैं। पत्नी जी चीखती है– तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। हरदम मोबाइल में घुसे पड़े रहते हो। मैं तो बच्चों की खातिर यहां हूं, वरना तुम्हें कब की छोड़ जाती। बेचारा पति मुर्गा बनाकर बांग लग रहा है। बात छह– पति थका–हारा ऑफिस से घर आया है। वह सिर झुकाए नीचे बैठा हुआ है। पत्नी श्री– मुझे सब पता है। घर में आते ही तुम घुग्घू बनकर बैठ जाते हो। बाहर तो खूब हंसते रहते हो। घर में मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते हो। पतिदेव– नहीं! ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत थक गया हूं। बताओ! आज क्या–क्या किया। पत्नी– ओहो! कितना बोलते हो? मुझसे हिसाब मांगते हो! पूरे दिन भर क्या–क्या किया? ये पूछते हो? सच में! तुमसे बहुत परेशान हो गई हूं! आजकल बहुत बोलने लग गए हो!

(उत्तम नगर, घूघरा, अजमेर)

कविता 'लोकसभा चुनाव 2024'

हो गई 18 वीं लोकसभा गठन
2024 की तैयारी।
देशहित में मतदान करने की है
अब ज़िम्मेदारी॥
कार्यों के सही विश्लेषण की है
अब निर्णायक भूमिका।
देश के विकास को दृष्टिगत रख
करेंगे समीक्षा॥
भ्रामक जानकारी का नहीं करें
कोई प्रचार–प्रसार।
आचार–संहिता के नियमों के
अनुरूप हो व्यवहार॥
मतदान के अधिकार का करेंगे
सही उपयोग।
भारत में उत्तरोत्तर उन्नति का
करना है निरंतर योग॥
संकीर्ण विचारधारा से ऊपर हो
राष्ट्रहित सर्वोपरि।
प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ना है हमें
नवीन आयामों की कड़ी॥
भारत की एकता और अखंडता
को रखना है संरक्षित।
तुच्छ मानसिकता से नहीं होना
है प्रभावित॥
नवीन विचारधारा एवं सोच को
करना है सम्मिलित।
उन्नयन के नवीन पुष्प करने है
देश में पल्लवित॥
हमारा मतदान करेगा देश के
विकास की दिशा निर्धारित।
शत–प्रतिशत मतदान से होगा
सभी का हित सुरक्षित॥
लोकसभा चुनाव के परिणाम
पर रहेगी सभी देशों की नजर।
डॉ. रीना कहती, मताधिकार के
उपयोग में नहीं छोड़ेंगे कोई
कसर॥

डॉ. रीना रवि मालपानी
(कवयित्री एवं लेखिका)

क्या भाजपा के रणनीतिकार अब विदेशी मीडिया को भी साध रहे हैं? बेशक राष्ट्रवादी विचारों वाले वोटर को इस तरह की एक विदेशी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट मनमोहक लग सकती है? भाजपा गार्डियन के इस लेख का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि के लिए कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषण में इस लेख का हवाला देते हुए जमकर जिक्र कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गार्डियन गोदी मीडिया तो नही है?

घर में घुसकर मारता है नया भारत

– मनोज कुमार अग्रवाल

हाल ही में ब्रिटेन के बड़े अखबार में प्रकाशित एक लेख काफी चर्चा का विषय बना हुआ है ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में मारे गए कम से कम 20 लोगों के पीछे भारतीय रिसर्च विंग (रॉ) का हाथ है। गार्डियन का खुलासा सही हो या गलत इस पर चर्चा तो बाद में होगी पर यह तय है कि भारत में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बूस्टर साबित हो सकती है। पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारत ने फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसने लोकसभा चुनाव का रुख भी मोड़ दिया था। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से वोटरों के लिए संवेदनशील रहा है। इसीलिए मोदी के नाम पर 56 इंच की छाती वाला जुमला गढ़ा गया है। पाकिस्तान में 20 आतंकियों के खात्मे पर इंग्लैंड के प्रमुख अखबार गार्डियन ने जो खुलासा किया है, वह बीजेपी के चुनाव में रंग भरने का काम करेगा। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिए गए। हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपये देने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंटों ने हत्याओ को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर जिहादियों को भी भर्ती किया, उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वे काफिरों को मार रहे हैं। भारत ने इजरायल की मोसाद और रूस की केजीबी जैसी खुफिया एजेंसियों से प्रेरणा ली। ये विदेशी एजेंसियां विदेशी धरती पर अपना काम करने के लिए कुख्यात रही हैं। अखबार कहता है कि सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट जमाल खशोगी जिनकी 2018 में सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी। इस घटना से रॉ के अधिकारियों ने प्रेरणा ली। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बैठक में कहा कि अगर सउदी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? रिपोर्ट के अनुसार जमाल खशोगी की हत्या के कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस बात पर बहस हुई थी कि इस मामले से कैसे कुछ सीखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में कहा गया कि 'सऊदी ने जो किया वह बहुत प्रभावी था। आप न केवल अपने दुश्मन से छुटकारा पाते हैं बल्कि आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों को एक भयावह संदेश, चेतावनी भी भेजते हैं। हर खुफ़िया एजेंसी ऐसा करती रही है। अपने शत्रुओं पर शक्ति डाले बिना हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता।' भारत ने इजरायल की मोसाद और रूस की केजीबी जैसी खुफिया एजेंसियों से प्रेरणा ली। ये विदेशी एजेंसियां विदेशी धरती पर अपना काम करने के लिए कुख्यात रही हैं। अखबार कहता है कि सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट जमाल खशोगी जिनकी 2018 में सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी। इस घटना से रॉ के अधिकारियों ने प्रेरणा ली ।एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बैठक में कहा कि अगर सउदी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? रिपोर्ट के अनुसार जमाल खशोगी की हत्या के कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस बात पर बहस हुई थी कि इस मामले से कैसे कुछ सीखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में कहा गया कि 'सऊदी ने जो किया वह बहुत प्रभावी था। आप न केवल अपने दुश्मन से छुटकारा पाते हैं बल्कि आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों को एक भयावह संदेश, चेतावनी भी भेजते हैं। हर खुफ़िया एजेंसी ऐसा करती रही है। अपने शत्रुओं पर शक्ति डाले बिना हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हत्याओं को अंजाम देने के लिए अक्सर अपराधियों या गरीब स्थानीय लोगों को लाखों रुपये का भुगतान किया जाता था। दस्तावेजों में दावा किया कि हत्याओं की निगरानी करने वाले रॉ संचालकों की बैठकें नेपाल, मालदीव और मॉरीशस में भी होती रही है। रिपोर्ट हालांकि पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया विभाग के पूर्व अफसरों से बातचीत पर आधारित है लेकिन रिपोर्ट पढकर ऐसा नहीं लगता है कि सीधे–सीधे भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में इस तरह के तर्क रखे गए हैं कि भारत हो या कोई भी देश अपने देश में हो रहे आतंकी कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में इस तरह कदम उठाता है। किंग्स कॉलेज लंदन के राजनीतिक वैज्ञानिक वाल्टर लाडविग कहते हैं कि रणनीति में कथित बदलाव मोदी की विदेश नीति के प्रति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण के अनुरूप है और जिस तरह पश्चिमी देशों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशों में हत्याओं का आरोप लगाया गया है, वैसे ही कुछ भारत ने भी किया।

दरअसल लम्बे समय से आतंकवाद के दंश झेल रही भारत सरकार को भी लगा कि भारत के पास भी ऐसा करने का अधिकार हैं। अब विदेशों में हत्याओं का आरोप लगाया गया है कि इसी पैटर्न पर कुछ भारत ने भी किया। आप को बता दें कि जिस दिन यह रिपोर्ट छपी है उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई लोकसभा में अरुण भारती के लिए वोट मांगते हुए कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर यह रिपोर्ट मुहर लगाती है क्या यह महज संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहते हैं कि छोटे–छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। पीएम मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। सवाल फिर ज्यो का त्यों वहीं खड़ा है कि आखिर देश में आम चुनाव के ठीक पहले एक विदेशी अखबार में एक जलते विषय पर ऐसे आलेख प्रकाशित करने के पीछे क्या कोई छिपा मंतव्य है? क्या गार्डियन पर भी विपक्ष गोदी मीडिया होने की तोहमत लगाएगा? क्या भाजपा के रणनीतिकार अब विदेशी मीडिया को भी साध रहे हैं? बेशक राष्ट्रवादी विचारों वाले वोटर को इस तरह की एक विदेशी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट मनमोहक लग सकती है? भाजपा

गार्डियन के इस लेख का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि के लिए कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषण में इस लेख का हवाला देते हुए जमकर जिक्र कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गार्डियन गोदी मीडिया तो नही है? लेकिन यदि भारत सरकार पर विदेशों में अपने दुश्मनों को भाड़े के हत्यारों के मार्फत निबटाने का आरोप सही साबित होता है तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस के दूरगामी विपरीत परिणाम भी हो सकते है और फिर हम किस मुहं से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुडो के उन आरोपों को गलत ठहराएंगे जो उन्होंने कनाडा में मारे गए खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों की हत्या पर लगाए थे? बेशक देश की अस्मिता और सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद अंगीकार करना अनुचित नहीं है लेकिन तथापि भारत को लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत संतुलन बना कर चलना होगा

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जो अपनी गरीबी में भी संतुष्ट है वह वास्तव में धनवान है : प्रसाद

पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के मामले में कांग्रेस की हवाबाजी

कांग्रेस की कथनी-करनी में भारी अंतर होने के कारण भी जनता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। एक ओर राहुल गांधी जातिगत जनगणना, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के मुद्दे उठाकर उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन जब अवसर आता है तो कांग्रेस इस मुद्दों को भूल जाती है। मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची देखें तो ध्यान में आता है कि पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को टिकट देने के मामले में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। भाजपा ने जहाँ 29 में से 10 पिछड़ा वर्ग से आनेवाले नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने केवल 5 ओबीसी चेहरों को मौका दिया है। यदि कांग्रेस की कथनी-करनी एक होती तो यहाँ उसे बड़ी संख्या में ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारने चाहिए थे। इसी तरह कांग्रेस महिलाओं को अवसर देने और उन्हें बराबरी का अधिकार देने की बातें तो करती है लेकिन अवसर आने पर यहाँ भी वही हाल हैं- कथनी-करनी में भारी अंतर। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में केवल एक ही महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। कहाँ गया महिलाओं को 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत भारीदारी का वादा? वहीं, भाजपा ने 6 महिला उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है। यानी भाजपा ने 20 प्रतिशत से अधिक महिला उम्मीदवारों को अवसर दिया है। याद हो जब मोदी सरकार ने देश की लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक 'नारी वंदन अधिनियम-2023' को लोकसभा और राज्यसभा रखा था तब कांग्रेस ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि इसे 2029 से लागू करने की जगह 2024 से ही लागू क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस को सच में महिलाओं की भागीदारी की चिंता थी, तो उसे लोकसभा चुनाव-2024 में अपनी ओर से देशभर में 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देकर लकीर खींच देनी चाहिए थी। सोचिए, जो कांग्रेस मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही थी, उसने मध्यप्रदेश में केवल एक महिला को टिकट दिया है। इससे एक बात साफ होती है कि कांग्रेस केवल ढोल बजाती है जबकि भाजपा क्रियान्वयन में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव 'सबका साथ-सबका विकास' के विचार में अपना विश्वास दिखाया है और उसी दिशा में निर्णय भी लिए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच का यह अंतर जनता को भी स्पष्ट दिखायी देता है। जनता देख पा रही है कि कांग्रेस ओबीसी और महिलाओं को सशक्त करने की बातें ही कर रही है, वहीं भाजपा सभी वर्गों के उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के नये आयाम स्थापित करने के लिए धरातल पर काम कर रही है। जब देश की जनता यह सब देख पा रही है, तब वह भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस पर विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि कांग्रेस अपने विचारों पर अभी ही खरी नहीं उतर रही है तो आगे वह अपने वायदों पर शत-प्रतिशत कायम रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? वास्तव में लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण करते समय कांग्रेस के पास अवसर था कि वह अपनी नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखा पाती है। शीर्ष नेता जो विचार प्रकट कर रहे हैं, सार्वजनिक भाषणों में बार-बार जो दावे कर रहे हैं, व्यवहार में उनका अनुपालन कहीं तो दिखायी देना चाहिए। अन्यथा देश की जनता को विश्वास कैसे होगा? कांग्रेस के बनिस्वत भाजपा के नेता जो कह रहे हैं, धरातल पर उसका क्रियान्वयन होते हुए जनता देख पा रही है। इसलिए ही देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है।

मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची देखें तो ध्यान में आता है कि पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को टिकट देने के मामले में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। भाजपा ने जहाँ 29 में से 10 पिछड़ा वर्ग से आनेवाले नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने केवल 5 ओबीसी चेहरों को मौका दिया है।

हिन्दवी स्वराज्य स्थापना का 350 वां वर्ष

नेताजी का बड़ा पराक्रम

फाजलखान अपने प्राण बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। नेताजी को लगा, कुछ रास्ता भटक गये इसलिए नेताजी व मावळे वाई की तरफ मुडे अन्यथा फाजलखान जीवित वापस नहीं जा पाता - यह घटना है दि.11 नवम्बर 1659 की सुबह का प्रथम पहर।

दि.10 नवम्बर 1659 - एक विजय प्राप्त करने पर विश्राम करना ऐसा महाराज के कभी नहीं किया। जिस दिन खान को मार गिराया उसी दिन महाराज ने अपने दोरोजी नाम के पराक्रमी वीर को कोंकण में राजापुर भेजा। क्योंकि गुप्तचरो ने खबर दी थी कि राजापुर बंदरगाह पर अफजल खान के सामान से भरे कुछ जहाज खडे हैं, वह सामान लाने के लिए महाराज ने दोरोजी को रवाना किया। महाराज के कार्यशैली की यह विशेषता रही है, परिस्थिति के सभी पहलुओं पर विचार कर वे योजना बनाते थे, ठीक से कार्यविभाजन करते थे इसलिए तुरंत नये मोर्चे पर भी कार्यवाही करते थे। दूरदर्शिता से एक-एक बिन्दु पर सोचकर योजना के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते थे कारण वह एक प्रकार की जंजीर बनती थी, एक ने भी गलती की तो सारी योजना असफल होने की सम्भावना रहती थी। उनके साथी भी सौपा गया कार्य निष्ठा से करते थे व निर्देशों का अक्षरशः पालन करते थे। केंद्रिकरण के स्थान पर कार्य विभाजन यह महाराज के योजना की ताकत थी।

11 नवम्बर की सुबह पाँच हजार सिपाहियों को लेकर महाराज वाई जाने के लिए निकले। वाई वासियों ने खान की वध की खुशी में अपने घरों के आँगन रंगोली मांडकर सुशोभित किये थे, महाराज के आने से खुशी दुगनी हुई। नेताजी भी वाई पहुँचे। कल नेताजी व उनके सैनिकों ने बडा पराक्रम किया था, शत्रु को धूल चटायी थी। अफजलखान की फौज में नाईक जी पांढरे, नाईक जी खराटे, सिद्दी हिलाल वाई में शरण आये व स्वराज्य की चाकरी करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार से सभी चौकीयाँ व शूर सरदार स्वराज्य में शामिल हुए। सरदारों का शामिल होना यह सकारात्मक संकेत था। बस केवल एक मराठा सरदार खंडोजी खोपडे भाग गया। जो आदिलशाही दरबार का शाही फरमान मिलने पर वतनदारी बचाने के लिए खान से जा मिला था।

बोध कथा

अनमोल कला

एक अमेरिकी करोड़पति ने पिकासो को अपनी तस्वीर बनाने को दी। वह करोड़पति इस बीच बार-बार पूछता रहा कि तस्वीर बनी कि नहीं। पिकासो खबर भिजवाता कि थोड़ा धैर्य रखिये। दो वर्ष के बाद पिकासो ने खबर भिजवाई कि अपना चित्र ले जाएं। करोड़पति ने पूछा, 'इसका दाम?' पिकासो ने कहा, पांच हज़ार डॉलर! करोड़पति चौंक उठा बोला, 'क्या? पांच हज़ार! थोड़ा-सा कैनवास और थोड़े से रंग और इसके दाम पांच हज़ार डॉलर? पांच-दस डॉलर में ये सारे सामान बाजार में मिल जायेंगे!' पिकासो ने अपने सहयोगी को कहा कि जाओ भीतर इससे बड़ा कैनवास और रंगों की ट्यूब लेकर आओ और इन्हें दे दें। ये जितना भी दाम देते हों, ले ले। उसने ऐसा ही किया सारा सामान उस करोड़पति के सामने रख दिया और कहा ये रहा आपका पोर्ट्रेट अब आपकी जो मर्जी दस-पांच डॉलर दे जाएं और यह सब लेते जाएं। करोड़पति घबरा कर बोला, ये सब ले जाकर मैं क्या करूंगा?' तब पिकासो ने कहा, 'तस्वीर रंगों और कैनवास का जोड़ नहीं है उससे कहीं ज्यादा है। इनके द्वारा तो हम उसे उतारते हैं जो कैनवास और रंग नहीं है। और हम दाम उसके मांगते हैं जिसका रंग और कैनवास से सम्बन्ध नहीं है। अब पांच हज़ार में निपटारा नहीं होगा पचास हज़ार देते हो तो ठीक वरना यह तस्वीर अब नहीं बिकेगी। वह तस्वीर आखिर पचास हज़ार डॉलर में बिकी।

चुनावी रण में जनता कांग्रेस के वायदों पर कितना भरोसा कर पाती है?

न्याय और गारंटियों के बीच कांग्रेस के वायदों का पिटारा

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते हुए घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम्‌ने बड़े जोर देकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह सिर्फ नौकरी, नौकरी और नौकरी ही देगी। चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक निगमों में खाली पड़े तीस लाख पदों को भरने का वादा किया गया है।

चुनाव घोषणा पत्र जारी करने में देश की सबसे पुरानी पार्टी बाजी मारने में कामयाब रही है। जैसा कि अक्सर होता है, चुनाव घोषणा पत्र राजनीतिक दल का भावी शासन का रोडमैप होता है। कांग्रेस ने इस रोड मैप को हाल के दिनों में अख्तियार किए दो शब्दों 'न्याय' और 'गारंटी' के इर्द-गिर्द ही केंद्रित किया है। लेकिन इस रोडमैप को मोटे तौर पर देखें तो वह कुछ मुद्दों पर अपनी पुरानी गलतियों को दुरूस्त करती दिख रही है, तो कई बार वह नेहरूवादी समाजवाद की ओर बढ़ती नजर आ रही है तो कई मुद्दों पर राहुल-प्रियंका के वामपंथी सलाहकारों का असर भी नजर आ रहा है।

कांग्रेस इन दिनों जिस तरह न्याय और गारंटी पर जोर दे रही है, उससे कुछ सवाल जरूर उठते हैं। देश की आजादी का 77वां साल चल रहा है। इतने दिनों में पचपन साल तक उसका ही शासन रहा है। जाहिर है कि आजाद भारत के दो तिहाई हिस्से पर कांग्रेस का ही शासन रहा है। इसके बावजूद वह लोगों को न्याय दिलाने का वादा करती है, गारंटियां देने की बात करती है तो यह सवाल जरूर उठेगा कि कांग्रेस क्या अपने शासनकाल में लोगों को न्याय नहीं दे पाई या फिर वह पहले गारंटी नहीं दे पाई। जाहिर है कि जब ये सवाल उठेंगे तो कांग्रेस और उसके समर्थक जवाब में कह सकते हैं कि पार्टी का न्याय और गारंटियों का वादा भाजपा शासन काल के दौरान हुए अन्याय और अनदेखी का जवाब है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पार्टी कुछ ऐसे मुद्दों पर अपनी गलती को सुधार करती दिख रही है, जिन्हें राष्ट्रवादी राजनीति के मुद्दे माना जाता है। आर्थिक सुधार प्रक्रिया के तहत नई पेंशन योजना को स्वीकार करना और समान नागरिक संहिता को स्वीकार करना राष्ट्रवादी राजनीति के ही मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इन दोनों अहम मुद्दों पर चुप्पी साध ली गई है। यानी एक तरह से पार्टी का रूख इस मुद्दे पर बदला हुआ नजर आ रहा है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते हुए घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम ने बड़े जोर देकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह सिर्फ नौकरी, नौकरी और नौकरी ही देगी। चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक निगमों में खाली पड़े तीस लाख पदों को भरने का वादा किया गया है। पार्टी खुद ही अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के एक सर्वे आंकड़े का हवाला देते हुए कहती है कि देश के पच्चीस साल तक की उम्र वाले युवाओं में से 42 फीसद बेरोजगार हैं। अगर इसी आंकड़े पर भरोसा करें तो यह संख्या

करोड़ों में होगी। कांग्रेस सिर्फ तीस लाख सरकारी पदों को भरने का स्पष्ट वादा तो कर रही है, लेकिन शेष युवाओं का क्या होगा, पार्टी इस पर मौन है। हां, वह तकनीकी शिक्षा ले चुके युवाओं के लिए एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप का वादा जरूर कर रही है, जिसमें एक लाख सालाना मिलेंगे। इस रकम का आधा हिस्सा सरकारें वहन करेंगी। यूपीए एक के शासन के दौरान पार्टी ने मनरेगा की शुरूआत की थी। इसे पार्टी अपना बेहतरीन कदम मानती है। घोषणा पत्र में इसकी चर्चा नहीं होती तो आश्चर्य होता। पार्टी ने मनरेगा की मजूदरी 400 रूपए तक बढ़ाने का वादा कर रही है।

इसे संयोग कहें या कुछ और कि कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता गौरव बल्लभ और धाकड़ सांसद रहे संजय निरूपम ने पार्टी छोड़ी, उसके ठीक बाद ही कांग्रेस ने अपने महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र को जारी किया। दल चाहे जो भी हो, उसका घोषणा पत्र एक या दो दिन में नहीं तैयार किए जाते हैं। इसलिए यह उम्मीद करना कि चुनाव घोषणा पत्र में कुछ ऐसा होगा, जिसके जरिए पार्टी अपने यहां मची भगदड़ को रोकने या उसे संबोधित करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संस्थानों की स्वायत्तता पर भी एक तरह से सवाल खड़ा किया है। इसमें चुनाव आयोग और न्यायपालिका शामिल है। यह सोच भी वामवैचारिकी की ही है। कांग्रेस ने जहां चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाने का वादा किया है, वहीं न्यायपालिका में वंचित तबकों को बढ़ावा देने के साथ ही न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का भी वादा किया है। मीडिया को भी स्वायत्त बनाने की भी बात कही गई है। माना जा रहा है कि इसके जरिए पार्टी ने मीडिया में कार्यरत लोगों के समर्थन की उम्मीद रखी है।

अब बात करते हैं, कांग्रेस की पांच न्याय की। पार्टी ने जिन न्याय की बात की है, उसमें पहला है युवा न्याय। इस गारंटी के तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। दूसरे नंबर पर पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय की चर्चा की है, जिसके तहत जाति जनगणना कराने की 'गारंटी' दी गई है। तीसरे नंबर पर किसान न्याय की चर्चा की गई है। जिसके तहत कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने के साथ ही किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग के गठन के साथ-साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। चौथे नंबर पर पार्टी ने श्रमिक न्याय की बात की गई है। पार्टी ने इसके तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, मनरेगा की न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये रोजाना करने के साथ ही शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। पांचवां न्याय है नारी न्याय। इसके तहत कांग्रेस ने 'महालक्ष्मी' गारंटी देने का वादा किया है। इसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये सालाना देने समेत कई वादे किए गए हैं। इसके साथ ही गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख की मदद का भी ऐलान किया गया है।

पार्टी के घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख वायदों पर निगाह डाल लेते हैं। पार्टी ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वह महिलाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह देगी। इसके साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में एक तिहाई आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाने का भी वादा किया है। पार्टी अपनी हर चुनावी सभा में महंगाई का हवाला देती है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का भी वादा किया है। पार्टी ने संवैधानिक न्याय और आर्थिक न्याय का भी वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रक्षा न्याय का भी वादा किया है, जिसके तहत देश की रक्षा करने वाली विदेश नीति पर काम करने की बात की गई है। मछुआरों के लिए डीजल सब्सिडी दे के साथ ही अगले 10 वर्षों में देश की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे कदमों का जोरदार विरोध किया है। इसके साथ ही वन रैंक, वन पेंशन आदि मुद्दों को भी छुआ गया है।

हाल में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने ऐसे ही कुछ वायदे किए थे, लेकिन तेलंगाना छोड़ उसे कहीं समर्थन नहीं मिल पाया। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी रण में जनता उसके इन वायदों पर कितना भरोसा कर पाती है?

यह लेखक के निजी विचार है

नारी शक्ति की अपरिमितता के पर्व नवरात्रि की वैज्ञानिकता एवं आसुरी प्रवृत्तियों का उन्मूलन

डॉ. आनंद सिंह राणा
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग श्रीजानकीरमण महाविद्यालय जबलपुर एवं इतिहास संकलन समिति महाकोशल प्रांत

'या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता, मातृरुपेण संस्थिता, नारी रुपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः।'

ऋग्वेद के देवी सूक्त में मां आदिशक्ति स्वयं कहती हैं, 'अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, अहं रूद्राय धनुरा तनोमि।' अर्थात मैं ही राष्ट्र को बांधने और ऐश्वर्य देने वाली शक्ति हूं, और मैं ही रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूं। हमारे तत्वदर्शी ऋषि मनीषा का उपरोक्त प्रतिपादन वस्तुतः स्त्री शक्ति की अपरिमितता का प्रतीक है।

नारीशक्ति की सर्वोत्तम व्याख्या भारतीय पुराणैतिहासिक संदर्भों में प्राप्त होती है जो वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ शब्द के रूप में आक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 'नारीशक्ति' को चुनकर इस दिशा में और गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया है। भारत में नवरात्र आराधना के प्रसंग में ॐ ऐं ह्रीं क्लीं के अंतर्गत ऐं = वाग्बीज (ज्ञानशक्ति Power of knowledge), क्लीं = कामराज (क्रिया शक्ति, Power of action), ह्रीं = मायाबीज (पदार्थ, Power of Matter) के माध्यम से सृष्टि निर्माण, स्थिति और ध्वंस की विज्ञान-सम्मत व्याख्या मिलती है। इनसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों की व्याख्या की मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई है।

रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भारत में रात्रि का विशेष महत्व है। भारतीय पर्वों के मूल में आध्यात्मिक चेतना के साथ वैज्ञानिकता उसके मूल में निहित है। वैज्ञानिक तथ्य है कि दिन में अन्य तरंगों के कारण ध्वनि तरंगों में अवरोध उत्पन्न होता है इसलिए रात्रि काल में उपासना पर विशेष रूप से भारतीय मनीषियों ने बल दिया है। नवरात्र दीपावली, महाशिवरात्रि और होली जैसे अधिकांश पर्व रात्रि में ही मनाए जाते हैं, ताकि ध्वनि की तरंगों का ठीक प्रकार से विस्तार हो। एतदर्थ मंत्र, तंत्र और यंत्र के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों और शंख बजाकर वातावरण को न केवल रोगाणु मुक्त किया जाता है वरन अपकारी शक्तियों के साथ आसुरी प्रवृत्तियों का भी शमन भलीभांति होता है। नवरात्र के संबंध में यह सर्वविदित है कि एक वर्ष में चार संधि काल होते हैं और इसलिए क्रमशः चार नवरात्र चैत्र, आषाढ़ अश्विन, और माघ में मनाए जाने की विधान है। भारत में 51 शक्तिपीठों का विशेष महत्व है और इनमें से कई शक्तिपीठ जनजातियों द्वारा पूजित संरक्षित किए गए हैं। चार संधि कालों में सत्व गुण तमोगुण और रजोगुण के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करना ही नवरात्र का मूल आधार है। तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने का अनुष्ठान ही नवरात्र है।

वस्तुतः नौ रातों के समूह को नवरात्र कहा जाता है, जो शरीर के अंदर निवास करने वाली जीवनी शक्ति दुर्गा के ही स्वरुप हैं। उपनिषदों में उमा या हेमवती का उल्लेख किया है। भारतीय अवधारणा में हिरण्यगर्भ जिसे पाश्चात्य विज्ञान बिग बैंग के रुप समझता है, तदनुसार शक्ति या ऊर्जा के आलोक में जड़ - चेतन की व्याख्या करता है। शिव-शक्ति का अद्वैत

है। यजुर्वेद में स्पष्ट है कि 'यद् पिण्डे, तद् ब्रम्हाण्डे'। इसी के परिप्रेक्ष्य में
भौतिकी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने द्रव्य - ऊर्जा समीकरण ($E=mc2$)
के माध्यम से अद्वैत की पुष्टि की है। ऊर्जा से ही सब गतिमान हैं। आंध्र ऊर्जा और आंध्र पदार्थ के संबंध में भी यही अवधारणा है। विज्ञान में ऊर्जा का अध्ययन वास्तव में आदिशक्ति का ही अन्वेषण है। आदिशक्ति त्रिगुणात्मक हैं। अपने तीन स्वरूपों क्रमशः ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से सत्व, रज और तम गुणों को उद्भूत करती है। तीनों गुणों के क्रियात्मक वेग के परस्पर संयोग से 9 के यौगिक की व्युत्पत्ति होती है जो सृष्टि का प्रथम गर्भ है। यही ब्रह्म (ब=23, र =27, ह=33, म =25, 23+27+33 +25 =108..1+0+8 =9) की पुष्टि करता है यही सर्वत्र चराचर में व्याप्त है। हमारे मनीषियों ने नारी को शक्ति के रूप में स्वीकार किया है सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा के मानवीय रूपों के माध्यम से उनके गुणों और क्रिया सहित व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह भी स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा हमारे यहां प्रतीकात्मक है यजुर्वेद कहता है कि 'ना तस्य प्रतिमा अस्ति'। बौद्धों के पूर्व मूर्ति पूजा शिरोधार्य नहीं थी वरन आकृतियों का निर्माण कर पूजा की गई है जैसे शिवलिंग, शालिग्राम और पिंडी का पूजन। देवी के लिए पिंडी पूजन क्योंकि वह गर्भ का द्योतक है। ईशवास्योपनिषद के शांति पाठ में स्पष्ट है कि 'ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते..पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।' जिसका अर्थ है वह भी पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है, और फिर भी पूर्ण शेष बचता है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाए फिर भी पूर्ण शेष बचे, वही ईश्वर है। यह स्पष्ट है कि एक मादा गर्भधारण कर एक संतान को जन्म देती है जो पूर्ण होती है, और मां भी पूर्ण रहती है इसलिए मां ईश्वर का स्वरूप है। संसार की सभी मादाएं ईश्वर का ही स्वरूप है। यही मातृत्व शक्ति मां दुर्गा के रुप में सकल ब्रम्हांड में व्याप्त है। भौतिकी में 9 ऊर्जाओं का क्रमशः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा उल्लेख है जिनसे 9 प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यही नवरात्र के मूल में वैज्ञानिक तथ्य हैं। भौगोलिक और भूगर्भीय दृष्टि से नवरात्र का बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर विषव (Equinox) की विशिष्ट स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसलिए नवरात्र पर्व में व्रत, उपवास और ध्यान के माध्यम से चक्रों और नाड़ियों का शोधन होता है। जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यही समय होता है जब हार्मोनल, और आंतरिक परिवर्तन के साथ जैविक चक्रों पर प्रभाव पड़ता है तब अनेक रोग की बाढ़ आ जाती है, जिसके शोधन के लिए दिव्य ब्रम्हांडकीय आदिशक्ति, मां दुर्गा को 9 रुपों शिरोधार्य किया जाता है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से दुर्गा शब्द की व्युत्पत्ति 'दुर्ग' और 'आ' प्रत्यय जोड़कर हुई है जिसका अर्थ 'जो शक्ति दुर्ग की रक्षा करती हैं, दुर्गा हैं'। यहां दुर्ग का अर्थ साधक के शरीर और चेतना के लिए ही है। वह शक्ति दुर्ग की रक्षा करती हैं वही दुर्गा है, दुर्ग साधक का शरीर है, और उसकी चेतना है, दुर्गा।

भारतीय सनातन धर्म में यह स्पष्ट है कि मानव शरीर में आसुरी प्रवृत्ति के नाश के लिए ही नवरात्र पर्व मनाने की महान परंपरा प्रवहमान है। शक्ति मां दुर्गा का आह्वान कर मानव शरीर में उत्पन्न आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया जाता है। इस संबंध में भाषा विज्ञान के अनुसार आसुरी प्रवृत्तियों के नामकरण किए गए हैं, वर्तमान परिस्थितियों में षड्यंत्रपूर्वक इनका मानवीकरण कर वामियों और सेक्यूलरों द्वारा भ्रमित कर गलत मतप्रवाह स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। यह स्पष्ट शक्ति के संतुलन के लिए ही नवरात्र पर्व बनाए गए हैं। भाषा विज्ञान के दृष्टि से असुर का शाब्दिक अर्थ है - 'अ' (बिना) +सुर (हमारी चेतना का ताल या सुर का बिगड़ना)। यही मानव में निहित असुर है। यही आसुरी प्रवृत्ति है। महिषासुर का शाब्दिक अर्थ है - महिष (मह शब्द से बना है अर्थात महान) और असुर प्रवृत्ति है। जिसका पर्याय है कि व्यक्ति और समाज से जड़ता समाप्त करना। वास्तव में प्रगट रुप में महिषासुर समाज में जड़ता की निशानी है और उसके शोधन के लिए नवरात्र पर्व को रखा जाता है।

हिंदुओं को आक्रांताओं से बचाने हेतु भगवान झूलेलाल अवतरित हुए

प्रहलाद सबनानी
सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

भारत के प्राचीन काल में सिंध प्रांत को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था क्योंकि सिंध प्रांत को पार करते हुए ही भारत में दिल्ली तथा अन्य राज्यों तक पहुंचा जा सकता था। सिंध का कराची बंदरगाह भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था क्योंकि कराची बंदरगाह के माध्यम से भारत से कृषि पदार्थों आदि का निर्यात किया जाता था। सिंध के निवासी कई कई महीनों तक लगातार जलयान एवं नौकाओं के माध्यम से भ्रमण करते हुए अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार करते थे। सिंध प्रांत की बहिने अपने भाईयों, पिता एवं पति को बिदा करने समुद्र (दरयाह शाह) के किनारे आती थी और अपने सम्बंधियों के कुशलता पूर्वक विदेश से वापिस आने की जल देवता को प्रार्थना करती थीं। कुल मिलाकर सिंध प्रांत उस खंडकाल में अति विकसित अवस्था में गिना जाने वाला राज्य था। परंतु, 700 ईसवी आते आते शायद सिंध प्रांत को जैसे किसी की नजर लग गई और सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के राजा श्री दाहिर सेन को 712 ईसवी में विश्वासघात करके युद्ध में मार दिया। इस प्रकार, श्री दहिर सेन जी सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू शासक सिद्ध हुए।

712 ईसवी के बाद अल हिलाज के खलीफा ने सिंध प्रांत को अपने राज्य में शामिल कर लिया और सिंध प्रांत पर खलीफा के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाने लगा। इसके बाद तो सिंध के सनातनी हिंदूओं पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा क्योंकि इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र में तलवार की नोंक पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाने लगा और इस्लाम को इस क्षेत्र में फैलाया जाने गया।

उस खंडकाल में सिंध राज्य की राजधानी थट्टा नामक नगर थी। इस नगर की अपनी एक अलग पहचान और अपना एक अलग प्रभाव था। इस क्षेत्र का शासक मिरखशाह न केवल अत्याचारी और दुराचारी था बल्कि एक कट्टर इस्लामिक आक्रमणकारी राजा था। मिरखशाह ने इस क्षेत्र में इस्लाम को फैलाने के लिए अनेक आक्रमण किए एवं नरसंहार किया। मिरखशाह के सलाहकारों और मित्रों ने उसे सलाह दी कि इस क्षेत्र में जितना अधिक इस्लाम को फैलाओगे उतने अधिक समय के लिए आपको मौत के बाद जन्नत अथवा सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होगी। सलाहकारों की इस सलाह के बाद मिरखशाह ने हिंदुओं के "पंच प्रतिनिधियों" को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आप सभी हिंदू लोग इस्लाम ग्रहण कर लो अथवा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिंदुओं के पंच प्रतिनिधियों ने मिरखशाह की इस सलाह पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा और मिरखशाह ने उन्हें 40 दिन का समय दे दिया।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वह प्रभु परमात्मा की शरण में जाने लगता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अपने सामने मौत और धर्म पर संकट को देखते हुए सिंधी हिंदुओं ने जल के देवता वरुण देव की ओर रूख किया। चालीस दिनों तक हिंदुओं ने तपस्या की। इस बीच न तो उन्होंने अपने बाल कटवाए और ना ही कपड़े बदले और ना ही भोजन किया। इन 40 दिनों तक कठिन उपवास करते हुए केवल ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर प्रभु परमात्मा से रक्षा की उम्मीद लिए नदी के किनारे बैठे रहे। 40वें दिन स्वर्ग से एक आवाज आई, जिसमें कहा गया कि "आप लोग डरो मत, मैं तुम्हें आक्रांताओं की बुरी नजर से बचाऊंगा। मैं एक नश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर आऊंगा और माता देवकी के गर्भ से इस धरा पर जन्म लूंगा। यह सुनकर सिंधी समाज के सनातनी हिंदुओं ने मिरख शाह से जाकर अपने ईश्वर के आने तक रुकने की प्रार्थना की। जिसके बाद मिरख शाह ने इसे अपने अहंकार के रूप में देखा और "भगवान" से भी लड़ने की चाह में उसने हिंदुओं को कुछ दिन का और समय दे दिया।

भगवान झूलेलाल ने अपने चमत्कारिक जन्म और जीवन से ना सिर्फ सिंधी हिंदुओं के जान की रक्षा की बल्कि हिन्दू धर्म को भी बचाये रखा। मिरखशाह जैसे ना जाने कितने इस्लामिक कट्टरपंथी आये और धर्मांतरण का खूनी खेल खेला लेकिन भगवान झूलेलाल की वजह से सिंध में एक दौर में यह नहीं हो पाया। भगवान झूलेलाल आज भी सिंधी समाज के एकजुटता, ताकत और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं। सिंधी समुदाय को भगवान राम के वंशज के रूप में माना जाता है।

समय-बोध

डंपिंग यार्ड बनते समुद्र तल

मनीष कुमार चौधरी

जैसे-जैसे यूरोपीय और अमेरिकियों की वाणिज्यिक और क्षेत्रीय आकांक्षाएं दुनिया भर में विस्तारित हुई, महासागर के बारे में अधिक सटीक और अधिक विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ी, लेकिन जल्द ही विकास की अंधाधुंध दौड़ में समुद्र की इन गहराइयों का बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया। समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में भी किया गया।

पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षो में ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सैकड़ों-हजारों टन अप्रचलित रासायनिक

हथियारों को दुनिया भर के पानी की गहराई में या तो ड्रमों में या टुकड़ों में भेज दिया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के कारण इस प्रथा को 1972 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2019 के एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर के तल पर कम से कम 18 हजार रेडियोधर्मी वस्तुएं बिखरी हुई पाई गई, उनमें से कई को सोवियत संघ द्वारा वहां फेंक दिया गया था। जब ये वस्तुएं अपनी जहरीली विरासत को पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी, तब क्या होगा? कई पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को 'समुद्र तल पर धीमी गति से चल रहा चेर्नोबिल' कहा है। हालांकि सोवियत संघ ने किसी भी अन्य देश की तुलना में समुद्र तल पर अधिक परमाणु कचरा फेंका था, लेकिन वह निश्चित रूप से अकेला नहीं था। 1948 और 1982 के बीच, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 70 हजार टन परमाणु कचरा समुद्र की गहराई में भेज दिया। भले ही कम मात्रा में ही सही, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान और नीदरलैंड ऐसे कुछ देश हैं, जिन्होंने रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान के लिए समुद्र का उपयोग किया है। अब जबकि अंतरराष्ट्रीय संधियां समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री के डंपिंग पर रोक लगाती हैं, ब्रिटिश सरकार कुम्ब्रिया के समुद्र तल के नीचे 100 टन से अधिक प्लूटोनियम सहित 750,000 क्यूबिक मीटर परमाणु कचरे के निपटान की योजना तलाश रही है।

संपादकीय

प्रेम और करुणा से भरा हृदय आंतरिक शक्ति, खुशी, शांति और इच्छाशक्ति का मुख्य स्रोत है।

-दलाई लामा

एनारॉक और नरेडको की संयुक्त रिपोर्ट लोकसभा चुनाव से पहले देश में रियल एस्टेट क्षेत्र की सुखद तस्वीर पेश करती है, जिसका श्रेय पिछले दस वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों को जाता है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए इस गति का बने रहना जरूरी है।

रियल एस्टेट की चमक

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक और नेशनल रियल एस्टेट डेवलेपमेंट काउंसिल (नरेडको) की संयुक्त रिपोर्ट का यह कहना कि पिछले दस वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, इस क्षेत्र की सुखद तस्वीर पेश करता है, जिसका श्रेय हालिया संरचनात्मक सुधारों को जाता है। इस क्षेत्र में 2013 में कुल चार करोड़ रोजगार उपलब्ध थे, जो 2023 में बढ़कर 7.1 करोड़ हो गए, तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल, इस दौरान यानी 2014 से 2023 के बीच शीर्ष सात शहरों में करीब 29 लाख मकान बिके, तो करीबन इतने ही नए लॉन्च भी हुए, जिससे स्वाभाविक ही नई नौकरियां पैदा हुईं। हालांकि, करीब 24 लाख करोड़ रुपये के भारतीय रियल एस्टेट बाजार का, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः 80 और 20 फीसदी है, 2017 से पहले कोई नियामक न होना हैरत में डालता है। लेकिन, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाई), किफायती और मध्य-आय आवास (स्वामी) फंड के लिए स्पेशल विंडो और वस्तु व सेवा कर जैसी पहलों ने रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदली है। कई राज्यों में रेरा लागू होने के बाद इस क्षेत्र में पारदर्शिता आई है और परियोजनाएं भी समय से पूरी हो रही हैं। गौरतलब है कि रेरा की स्थापना के बाद से आज तक राज्यों में करीब सवा लाख परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं और ग्राहकों की करीब इतनी ही शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। लेकिन, लोगों की सोच में क्रांतिकारी बदलाव कोविड काल के दौरान आया, जब उन्हें अपना घर होने की अहमियत का अहसास हुआ। इन सुधारों से देश के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े बदलाव तो आए, लेकिन देश के कुल रोजगार में 18 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब सात फीसदी का योगदान देने वाले इस क्षेत्र को अब तक पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा न मिल

पाना एक प्रमुख बाधा है, जिसके चलते डेवलपर्स को कर्ज मिलने में परेशानी होती है। इसके बावजूद, रिपोर्ट का यह कहना महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र का आकार 2030 तक दस खरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह शीर्ष पांच में पहुंची है और पिछले लगातार तीन वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि यह क्षेत्र अपनी यही गति बनाए रखे।

चुनावी अर्थशास्त्र की चुनौतियां

भारत सरकार के कुल बजट, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपये है, में चुनावी खर्च बहुत छोटी-सी रकम है। लिहाजा, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या चुनाव पर सार्वजनिक खर्च वास्तव में कोई मुद्दा है।

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में पहले चरण का मतदान भी होने वाला है। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जोर-शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। अक्सर चुनाव के दिनों में चुनावी खर्च की चिंता जताई जाती है और बढ़ते चुनावी खर्च का तर्क देकर 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर भी विचार किया जाने लगा है।

जहां तक चुनावों में होने वाले खर्च की बात है, तो वैश्विक स्तर पर चुनाव कराने की प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तीय लागत काफी भिन्न होती है और विभिन्न देशों के बीच और देश के भीतर भी चुनावी लागत अलग-अलग होती है। सामान्य अर्थों में देखें तो, अपने देश में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न चुनावों पर सार्वजनिक खर्च में प्रति वर्ष 19.98 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017-18 में चुनाव पर केंद्र सरकार के सार्वजनिक व्यय की लागत 1322.22 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में बढ़कर 2724.26 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक चुनावों पर सार्वजनिक लागत का सबसे उच्चतम स्तर वर्ष 2022-23 में दर्ज किया गया है, जो 3775.42 करोड़ रुपये था।

पिनाकी चक्रवर्ती

एनआईपीएफपी के पूर्व निदेशक

इस चुनावी खर्च में छह प्रमुख मदें शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं -निर्वाचन अधिकारियों पर किया जाने वाला खर्च, मतदाता सूची तैयार करने और उसकी छपाई पर खर्च, लोकसभा और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव के संचालन के लिए किया जाने वाला खर्च, पंचायतों/स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए किया जाने वाला खर्च, आदि और चुनाव संबंधी अन्य खर्च। जैसा कि सार्वजनिक व्यय की इन व्यापक मदों से स्पष्ट है, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा चुनाव कराने के लिए किए जाने वाले प्रशासनिक खर्च हैं।

भारत सरकार के कुल बजट, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपये है,

में चुनावी खर्च बहुत छोटी-सी रकम है। लिहाजा, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या चुनाव पर सार्वजनिक खर्च वास्तव में कोई मुद्दा है।

आइए, अब जरा चुनावों के अर्थशास्त्र पर भी विचार कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव संबंधी खर्च में बढ़ोतरी को अक्सर अल्पावधि में उपभोग खर्च को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। अल्पावधि में उपभोक्ता बाजार पर चुनावी खर्च के लाभ अलग-अलग होते हैं और इसका आर्थिक प्रभाव विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा की चुनावी प्रकृति समेत कई कारकों पर निर्भर करता है।

हालांकि चुनावी प्रतिस्पर्धा की प्रकृति का सार्वजनिक वित्त पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल जीत हासिल कर सरकार का गठन करता है, उस सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक नीतियों का सार्वजनिक खर्च पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे खर्चों का विकास, राजकोषीय संतुलन और मानव विकास पर दीर्घकालीन असर पड़ता है। हाल के वर्षों में चुनाव पूर्व किए गए वादे के बड़े सार्वजनिक खर्च प्रतिबद्धता में तब्दील होने का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम है। हमें चुनाव पूर्व किए गए इस तरह के वादे के ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, जिन्होंने सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के साथ नई सार्वजनिक नीतियों का भी निर्माण किया है।

भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार, विभिन्न राज्यों का एक संघ है। लिहाजा, एक संघीय देश में राष्ट्रीय निर्वाचन और राज्यों के निर्वाचन की चुनावी प्रतिस्पर्धा अलग-अलग होनी चाहिए, खासकर तब, जब राष्ट्रीय सरकार की भूमिका राज्यों की सरकारों से बहुत अलग हो। हालांकि हमारे अपने देश भारत में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वादे यह अंतर करने में विफल रहते हैं। राजनीतिक वादों से इस अंतर को समझना भी मुश्किल होता है।

केंद्र और राज्यों, दोनों के चुनाव में किए जाने वाले वादे बड़े पैमाने पर परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए पुनर्वितरण खर्च पर केंद्रित होते हैं। पुनर्वितरण खर्च उसे कहते हैं, जो संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित होते हैं, इसलिए इस मामले में राज्य कुछ हद तक केंद्र पर भी निर्भर होते हैं। इसके परिणामस्वरूप समस्या यह पैदा होती है कि चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों में कार्यात्मक टकराव पैदा होता है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें एक ही तरह की सेवा या सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों और जिम्मेदारियों का विभाजन स्पष्ट है।

संसाधनों के सांविधानिक विभाजन को देखते हुए स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि जैसे ज्यादातर पुनर्वितरण खर्च राज्य स्तर के होते हैं। आदर्श रूप में राज्यों के चुनाव इस तरह के पुनर्वितरण के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। कानून-व्यवस्था की बहाली भी राज्य का विषय है।

इसलिए राज्यों के चुनाव कानून-व्यवस्था और शासन (गवर्नेंस) के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। जबकि राष्ट्रीय चुनाव आदर्श रूप में अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी संरचनाओं के विकास, रेलवे, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। लेकिन अपने देश में वास्तविकता बिल्कुल अलग है।

हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रमुख पुनर्वितरण संबंधी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय चुनावी वादों की कोई भूमिका नहीं है। कहने का मूल तात्पर्य यह है कि यदि संविधान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणापत्र में मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्थान दिया जाता है, तो चुनाव के बाद सरकार का गठन होने पर चुनावी वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऐसे वादों को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी।

जीवन धारा

सत्यानंद महाराज

दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है। इसके विपरीत भीरुता, क्रोध एवं विवेकहीनता पाशविक वृत्ति हैं। बालक झूठ बोलने की आदत तब तक नहीं छोड़ सकता, जब तक कि उसमें सच बोलने की निर्भयता नहीं आएगी।

चरित्र निर्माण के बिना जीवन सार्थक नहीं

मनुष्य के जीवन को चरित्रवान एवं प्रभावशाली बनाने के लिए श्रीभगवद्गीता में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। इसमें मनुष्य जीवन को सुंदर और उच्च बनाने का जो विचार सुझाया गया है, वह अनुकरणीय है। यद्यपि बहुत से लोगों ने उसे बहुत बार और अनेक तरह से पढ़ा है, लेकिन सही तरीके से उसे कुछ ही गिने-चुने महात्माओं ने समझा और अपने जीवन में अपनाया है। जिस तरह बच्चा अपने बड़ों से कुछ सीखकर या सिखाए जाने पर बहुत कुछ सीख जाता है, उसी तरह हमें भी गीता से बहुत कुछ सीखकर जीवन में अपनाना चाहिए। चरित्र निर्माण के बिना जीवन सार्थक नहीं है। मानव, माया-मोह के झंझटों में तो पशुओं-पक्षियों से ही मिलता-जुलता है। शेर के मुंह से अपने बछड़े की जान बचाने के लिए गाय उसके सामने आ जाती है। ममता का यह उच्च स्तर मनुष्य में भी पाया जाता है। मनुष्य की तरह पशु-पक्षी दूसरे की निंदा में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दूसरों की निंदा, चुगली में मानव बहुत दिलचस्पी लेता है। परंतु वह जीवन प्राणमय जीवन के दुर्गुण हैं। इस जीवन में झगड़े भी बहुत हैं। संतान की रक्षा एवं पालन का मोह स्वाभाविक है। पशु-पक्षियों में भी यह भावना कम नहीं। लेकिन बुद्धि और विवेक सिर्फ मानव में ही है। यही मानव जीवन की क्रीड़ा है। लेकिन इसमें पाशविक वृत्ति भी जरूरत से ज्यादा है। इंसान के जीवन में ज्ञान और विचार ही अधिक होना चाहिए। जो अच्छे विचार वाले मनुष्य हैं, वे ही दैवी संपत्ति के अधिकारी हैं।

दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है। इसके विपरीत भीरुता, क्रोध एवं विवेकहीनता पाशविक वृत्ति है। जब तक आत्मज्ञान न हो, तब तक मनुष्य और पशु में भेद ही क्या? क्रोध, मोह, ममता, लालच जैसे विकार ही तो मानव को गंदे कीचड़ से निकलने नहीं देते। बालक झूठ बोलने की आदत किसी के डर से तब तक नहीं छोड़ सकता, जब तक कि उसमें सच बोलने की निर्भयता नहीं आएगी। दैवी संपत्ति के लिए सच बोलना आवश्यक है। यही कारण है कि निर्भयता के बलबूते पर भारत ऊंचे स्तर पर उठ गया। हमारे महापुरुषों ने निर्भयता का प्रचार किया। फलस्वरूप गोले-बारूद से नहीं, बल्कि निर्भयता के कारण ही भारत स्वतंत्र हुआ। तप करना, सत्याग्रह करना और व्रत रखना आसान है, लेकिन मन की निर्मलता बनाए रखना कठिन है। वस्त्रों की उज्ज्वलता और बाहरी आडंबर से मानव को क्षणिक मान मिलता है। इसलिए निंदा रूपी कीचड़ को अपने अंतःकरण में न उभरने दें। मित्र द्रोह, जाति द्रोह और देश द्रोह बहुत बुरा है। दूसरों को मजबूर करके अपने प्रयोजन सिद्ध करना बुरी बात है। मन का मैल धोने के लिए सत्याग्रह करना घोर तप है। सबके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। वैर-विरोध रूपी वैतरणी में गोते लगाने के बजाय परहित के लिए अपना तन-मन-धन बलिदान कर देना ही प्रत्यक्ष यज्ञ है। मानव अपने जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित करे, तो बेहतर।

सदाचार ही मूल...

सूत्र

सदाचार का जीवन ही वास्तव में मूल है। ऐसा वचन बोलना चाहिए, जो सत्य हो, प्यारा हो, मधुरता से भरा हो। दैवत्व गुण में आडंबर और दिखावा नहीं है। चुप रहने से सत्य बोलना अच्छी बात है। अपना पुरुषार्थ दूसरों के जीवन के लिए समर्थवान बनाएं-यही देवत्व जीवन है। श्रीभगवद्गीता के चरित्र निर्माण का यह भी एक अंग है। दूसरे को पीड़ा देने वाला अच्छा नहीं माना जाता।

दूसरा पहलू

मौलाना आजाद रोड स्थित बंगले को 1962 में उपराष्ट्रपति आवास बनाया गया था। पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इसी बंगले में रहे।

इतिहास बन जाएगा पहला उपराष्ट्रपति आवास

करीब 62 वर्षों तक देश के उपराष्ट्रपति का आवास रहने के बाद 6, मौलाना आजाद रोड स्थित बंगला इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति आवास में रहने चले गए हैं, जो 15 एकड़ में फैला हुआ है। अब 6, मौलाना आजाद रोड का बंगला जल्द ही जमींदोज होगा। सरकार यहां दस मंजिला इमारत बनाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के दफ्तर होंगे।

6, मौलाना आजाद रोड स्थित बंगले को 1962 में उपराष्ट्रपति आवास बनाया गया था। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसी बंगले में रहे। उनके बाद डॉ. जाकिर हुसैन, वी.वी.गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी. डी. जत्ती, एम हिदायतउल्ला, आर. वेंकटमण, शंकर दयाल शर्मा, डॉ. के. आर. नारायणन, कृष्णकांत, भैरोसिंह शेखावत, हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू इसी बंगले में रहे। कृष्णकांत का इसी बंगले में निधन हो गया था। दरअसल किंग एडवर्ड रोड (अब मौलाना आजाद रोड) के चार नंबर के बंगले में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद रहते थे। उनके निधन के बाद इस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया। कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन के महान डिजाइनर रोबर्ट टोर रसेल ने ही इस बंगले का डिजाइन तैयार किया था। इस बंगले में एक मस्जिद भी है। यह कब बनी, कोई नहीं बता पाता। यह सिर्फ रमजान के महीने में खुलती है। हालांकि इसकी साफ-सफाई नियमित होती है। 6, मौलाना आजाद रोड के भीतर जाकर लगता है, मानो आप किसी हरे-भरे टापू में हों। यहां अनार और जामुन के काफी पेड़ हैं। यहां के बुजुर्ग पेड़ों पर शाम के वक्त सैकड़ों तोते और दूसरे पक्षी आकर बैठ जाते हैं। भैरों सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति थे, तो इस बंगले के द्वार सबके लिए खुले रहते थे। शेखावत जी खुद यारबाश और किस्सागो इंसान थे। उनके पास मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उनके विरोधी तो थे, मगर शत्रु कोई नहीं। जब तक हामिद अंसारी इस बंगले में रहे, यहां अनेक लेखकों की किताबों के विमोचन होते रहे। उन्हें लेखकों और विद्वानों से मिलना पसंद था। उन्होंने खुद भी कई किताबें लिखी थीं। वेंकैया नायडू भी उपराष्ट्रपति आवास में लेखकों, नौजवानों, कलाकारों वगैरह से मिला करते थे। अब जब यहां गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी, तो यहां के तमाम छायादार पेड़ कट जाएंगे। इनमें नीम और पीपल के भी पेड़ हैं। पेड़ों के कटने से यहां के परिंदे भी बेघर होंगे।

विवेक शुक्ला

दरअसल किंग एडवर्ड रोड (अब मौलाना आजाद रोड) के चार नंबर के बंगले में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद रहते थे। उनके निधन के बाद इस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया।

अब जब यहां गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी, तो यहां के तमाम छायादार पेड़ कट जाएंगे। इनमें नीम और पीपल के भी पेड़ हैं। पेड़ों के कटने से यहां के परिंदे भी बेघर होंगे।

आंकड़े

फलों के उत्पादन में वृद्धि

वित्त वर्ष 2012-22 (दस वर्षों में) के बीच फलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है।

राज्य	वृद्धि
मध्य प्रदेश	265.95%
हरियाणा	265.15%
हिमाचल प्रदेश	202.25%
उत्तर प्रदेश	191.78%
आंध्र प्रदेश	179.50%

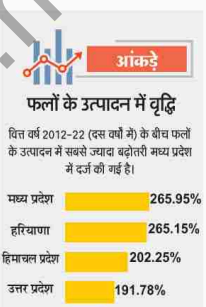

स्रोत :TII; GOI Horticulture Status

परोपकार से पुण्य

सेठ ने प्रसन्न होकर दूसरी बहुओं से कहा, जिस प्रकार धान बोने से बढ़े हैं, उसी प्रकार सेवा-परोपकार से पुण्य बढ़ते हैं।

अंतर्यात्रा

संकलित

राजगृह में एक बुद्धिमान सेठ रहता था। उसकी पत्नी का निधन हो गया था। चार पुत्रवधुएं थीं। सेठ ने सोचा, क्यों न इन चारों को परखकर किसी एक को घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। एक दिन उसने चारों बहुओं को बुलाकर कहा, तुम चारों को मैं धान के पांच-पांच दाने देता हूं। इन्हें रखना और जब मैं मांगू, उन्हें लौटा देना।

बड़ी बहू ने सोचा कि कोठार में धान भरा है, जब ससुर जी मांगेंगे, तो वहीं से पांच दाने लाकर दे दूंगी। उसने दाने फेंक दिए। दूसरी ने भी यही किया। तीसरी कुछ समझदार थी। उसने दानों को रेशमी कपड़े में बांधकर रत्नों से भरी पेटिका में रख दिया। चौथी बहू ने सत्संग में सुना था कि कोई भी सद्कर्म करने से बढ़ते हैं, इसलिए उसने दानों को खेत में बो दिया। उससे जो फसल पैदा हुई, उसने उन्हें फिर से बो दिया। इस तरह कुछ ही वर्षों में उसके पास काफी धान हो गया। पांच वर्ष बाद सेठ ने बहुओं से दाने मांगे। शुरू की तीन बहुओं ने दाने वापस कर दिए, पर चौथी ने कहा, पिताजी, वे पांच दाने कोठार में बंद हैं और मैं उसे लाने में असमर्थ हूं।

सेठ ने प्रसन्न होकर दूसरी बहुओं से कहा, जिस प्रकार धान बोने से बढ़े हैं, उसी प्रकार सेवा-परोपकार से पुण्य बढ़ते हैं। उसने छोटी बहू को घर की मालकिन बना दिया।

आज का इतिहास

अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर निकला अभागा टाइटैनिक

'कभी न डूब सकने वाले' पोत के रूप में प्रचारित किए गए टाइटैनिक जहाज का 10 अप्रैल से गहरा नाता है। यह बदकिस्मत जहाज 10 अप्रैल के दिन ही ब्रिटेन के साउथहैंपटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ था। वैसे टाइटैनिक जहाज का जिक्र आते ही इससे जुड़ी दुर्घटना के तमाम मंजर आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। वैसे यह भी हकीकत है कि जहाज कब बना, किसने बनाया, यह कब अपनी यात्रा पर निकला यह सब तथ्य 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक ने धुंधले कर दिए और याद रह गई जेम्स कैमरन की यह शानदार फिल्म, विशाल जहाज के डेक पर बांहें फैलाए खड़े लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंस्लेट, नीले हीरे वाली माला और पानी का रौद्र रूप।

'प्राकृतिक बॉन्ड' पर भी चर्चा हो

जलवायु परिवर्तन के मौजूदा संकट के दौर में प्रकृति के साथ हमारा जो बॉन्ड है, उसके प्रति हम कब प्रतिबद्ध होंगे?

गुंजन मिश्र

मुद्दा

अपने देश की जनसंख्या के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी है। हमारे देश में दुनिया की 18 फीसदी आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास वैश्विक भूमि का 2.4 फीसदी, वन का दो फीसदी, स्वच्छ जल का मात्र चार फीसदी ही उपलब्ध है। भविष्य में जैसे-जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाएगा, ये संसाधन और कम होते जाएंगे। अभी जिस दर से हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ष 2030 तक हमें 25 गुना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होगी।

पारिस्थितिकी के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स ऐंड पीस के अनुसार, अगर खाद्य सुरक्षा पर 25 फीसदी खतरा होगा, तो देश में टकराव/ संघर्ष की आशंका 36 फीसदी तक बढ़ जाएगी और इतने ही पानी की कमी होगी, तो संघर्ष की घटनाएं 18 फीसदी बढ़

जाएंगी। जैव विविधता की दृष्टि से हमारे देश में चार हॉटस्पॉट हैं, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन स्थानों का भी 90 प्रतिशत क्षेत्र कम हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण भारत को हर साल औसतन सात अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। यही कारण है कि पिछले पांच वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वर्ष 2022 में भारत 121वें स्थान पर था। इन सब घटनाओं को देखते हुए आज प्राकृतिक बॉन्ड के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यह प्राकृतिक बॉन्ड है क्या? हमने अब तक प्रकृति से जो लिया है या ले रहे हैं, उसे उसी अनुपात में प्रकृति को हम लौटा सकें, यह प्रतिबद्धता ही प्राकृतिक बॉन्ड है। अगर हम नहीं लौटा पाते हैं, तो हम इस प्रकृति के कर्जदार हैं। प्रकृति कोई वित्तीय संस्था नहीं है, जो पूरी जांच-पड़ताल के साथ हमें कर्ज देती है। इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन सह अस्तित्व के सिद्धांत के तहत होता है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, पर उसका ऋण चुकाना भूलकर हम सुख-साधनों की तरफ भाग रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आखिर कैसी पृथ्वी सौंप कर जाएंगे? कोरोना महामारी के संकट ने हमें सिखा दिया है कि वास्तविक धन क्या है। प्रकृति की उपेक्षा करके मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। जलवायु परिवर्तन और उसके कारण होने वाले विस्थापन का मुकाबला करने तथा पीड़ित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब तक देश में कोई ठोस नीति या कार्य योजना नहीं है। यही कारण है कि एक अनुमान के मुताबिक, अकेले भारत में जलवायु आपदाओं के कारण 2050 तक 4.5 करोड़ लोगों को अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में चरम मौसमी घटनाओं के परिणामस्वरूप पलायन करने वाले लोगों की संख्या वर्तमान संख्या से तीन गुना हो जाएगी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, 2021, अनुसंधान समूह जर्मनवॉच की वार्षिक रैंकिंग, भारत को जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में रखती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते 2035 तक खाद्य कीमतों में सालाना 3.2 फीसदी की वृद्धि होने का अंदेशा है। यही नहीं, इससे फसलों की उपज पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु में आ रहे बदलावों के कारण आम आदमी के खाने की थाली कहीं ज्यादा महंगी हो सकती है। इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। लेकिन बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, और उससे निपटने के लिए राजनीतिक दलों के पास क्या कार्ययोजना है, यह इस चुनावी बहस का मुद्दा नहीं है। अगर सही में देखा जाए तो यह चुनाव भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए हम अपने देश की लोकतांत्रिक संरचना को हरित लोकतंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। मौजूदा जलवायु परिवर्तन के दौर में यह आवश्यक है कि देश को एक हरित लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की पहल की जाए, और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोका जाए। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर किया जाने वाला विकास अंततः हमें विनाश के रास्ते पर ही ले जाएगा। इसलिए समय रहते सचेत होने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, प्लाट नंबर 24 सेक्टर-बी, रेल नीर प्लांट के पास सिरगिट्टी इंडस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर से मुद्रित एवं नवभारत भवन, पुराना बस स्टैण्ड के पास, बिलासपुर से प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादकः अरुण उपाध्याय* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार) ■ बिलासपुरः 07752-230591, 224563 फैक्सः 405338 ■ रायपुर फोनः (0771) 2535577-88-99, विज्ञापनः 2545599, फैक्सः (0771) 2535555 ■ दिल्लीः 011-23379021, फैक्स- 011-23379026 ■ मुंबईः 022-24900929, फैक्स- 022-24938684 ■ वर्ष 40 ■ अंक 194 (रजि. नं. 38549/85 आरएनआई), डाक रजिस्टर्ड क्रमांक जी. 2-112/सी.जी./बी.एल.पी./15/2022-2024

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।

भावार्थ : रसबुद्धि रहने के कारण यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं। इस वजह से उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती है।

मनी लांड्रिंग के मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिलती तो फिर उन्हें और अधिक समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि शराब नीति के जरिये घोटाले को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को करीब छह माह बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया एक वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। भ्रष्टाचार के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से गिरफ्तार लोगों को लंबे समय तक इसलिए जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि मनी लांड्रिंग संबंधी कानून में जमानत के प्रविधान अत्यंत कठोर हैं। चूंकि ऐसे मामलों का ट्रायल शुरू होने में अन्य अनेक मामलों की ही तरह समय लगता है, इसलिए कई बार मनी लांड्रिंग के आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यदि ट्रायल शुरू होने में देर होती है तो मनी लांड्रिंग के आरोपित को जमानत दी जा सकती है, लेकिन प्रायः ईडी की ऐसी दलीलें जमानत में बाधक बन जाती हैं कि यदि आरोपित बाहर आया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फिर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। कई बार तो आरोप पत्र दायर होने के बाद भी ईडी की यही दलील आरोपित की जमानत में बाधक बन जाती है और उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। बतौर उदाहरण महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल मनी लांड्रिंग मामले में 26 माह बाद जमानत पर जेल से बाहर आ पाए थे। आम तौर पर जब किसी आरोपित को उच्चतर अदालतों से भी जमानत नहीं मिलती तो यह धारणा कायम होती है कि उस पर लगे आरोप सही हैं और यदि कहीं उसे जमानत मिल जाती है तो यह प्रचारित किया जाता है कि ईडी के आरोपों में दम नहीं और उसे गलत फंसाया गया है। दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं। कौन दोषी है और कौन नहीं, यह तो ट्रायल कोर्ट और फिर ऊपरी अदालतों के फैसलों से ही तय हो सकता है। चूंकि कई नेता मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिलने या न मिलने के आधार पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। यह सिलसिला तभी बंद हो सकता है, जब कठोर प्रविधानों वाले मनी लांड्रिंग कानून के तहत दर्ज मामलों का निपटारा तेजी से हो। जितना जरूरी यह है कि मनी लांड्रिंग के अपराध पर लगाम लगे, उतना ही यह भी कि इससे जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण हो।

बंद हो नशे की राह

प्रदेश में आए दिन नशे के तस्करों का पकड़ा जाना चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक दिन में ही अनेक स्थानों पर कभी शराब तो कभी गांजा तस्कर दबोचे जाते हैं। यह ऐसे तस्कर हैं जो अन्य राज्यों में नशे का सामान ले जाकर बेचते हैं। जल्द करोड़ों रुपये कमाने के चक्कर में यह तस्कर प्रदेश पर बदनामी का दाग लगा रहे हैं। पुलिस की ओर से इस पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसे स्थायी रूप से रोकने के लिए सरकार को भी सख्त कदम उठाने होंगे। रविवार को रायपुर में ट्रेन से 68 किलो गांजा पकड़ा गया। इसी दिन बलौदाबाजार में भी सूखे नशे की 752 किलो की बड़ी खेप पकड़ी गई। भिलाई में एक क्विंटल गांजा पकड़ा गया। एक ही दिन में इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होना यह बताता है कि छत्तीसगढ़ तस्करों के लिए सुरक्षित कारीडोर बनते जा रहा है। राज्य से नशे का यह सामान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ले जाकर बेचने वाले तस्कर मोटी रकम कमाते हैं। ओडिशा से चलने वाला नशे का सामान अन्य राज्यों तक पहुंचता है, लेकिन बदनामी छत्तीसगढ़ की होती है। एक बड़ी चिंता यह भी है कि तस्करी के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा ट्रेन और बस के साथ एंबुलेंस तक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पुलिस और सुरक्षा बलों को यात्रियों के बीच तस्करों को पकड़ने की चुनौती बनी रहती है। हालांकि मुखबिर तंत्र के ज्यादा सजग होने से अनेक बड़े रैकेट का राजफाश हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार ऐसा तंत्र विकसित करे जो तस्करी के इस कारीडोर को पूरी तरह से खत्म कर सके। जिससे देश में छत्तीसगढ़ और यहां के निवासियों की छवि बिगड़ न सके। बाहर जाने वाले लोगों को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े।

अब जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार ऐसा तंत्र विकसित करे जो तस्करी के इस कारीडोर को पूरी तरह से खत्म कर सके। जिससे देश में छत्तीसगढ़ और यहां के निवासियों की छवि बिगड़ न सके। बाहर जाने वाले लोगों को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े।

समाधान की मांग करता जल संकट

विवेक देबराय | आदित्य सिन्हा

जल संकट से निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र को एकीकृत रणनीति बनानी चाहिए

एक वक्त 'झीलों की नगरी' के रूप में विख्यात बेंगलुरु शहर बीते दिनों पानी की भारी किल्लत के चलते सुर्खियों में रहा। यह शहर पारंपरिक रूप से जल संपदा से संपन्न रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान कहानी उसके समृद्ध अतीत से मेल नहीं खाती। भारत की आइटी राजधानी के रूप में स्थापित हुए इस महानगर में अब बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि यह केवल बेंगलुरु की ही कहानी नहीं है। हैदराबाद में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। देश के तमाम शहर पानी के इसी प्रकार के अभाव से दो-चार हैं। निरंतर बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से दुनिया भर के शहर पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 'नेचर' में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (करीब 93.3 करोड़ लोग) पानी की किल्लत से जूझ रहा था। यह आंकड़ा वर्ष 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब तक पहुंच सकता है। यानी विश्व की करीब आधी जनसंख्या को पानी की कमी की समस्या का सामना करना होगा। चूंकि भारत में शहरीकरण का दायरा और गति तेजी से बढ़ने पर है तो भारतीय शहर भी पानी के गहराते संकट के लिहाज से खासे संवेदनशील हैं।

जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर पर रुझानों को रेखांकित किया गया। इस सूचकांक के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जहां गुजरात जैसा राज्य करीब 76 अंकों के साथ जल प्रबंधन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था तो मेघालय जैसा राज्य 26 अंकों के साथ इस सूचकांक की तलहटी पर था। यह विषमता देश भर में जल प्रबंधन को सुधारने के लिए तात्कालिक कदम उठाने का संकेत करती है। भारत में जल प्रबंधन वैसे तो मूल रूप से राज्यों का दायित्व है, लेकिन जिस प्रकार का विकराल जल संकट आकार ले रहा है, उससे निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र और स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर एकीकृत रणनीति बनाना आवश्यक है। प्रभावी एवं टिकाऊ समाधानों के लिए बहुस्तरीय रणनीति की भारत के विविधतापूर्ण भौगोलिक, जलवायविक एवं सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से सुसंगति भी आवश्यक है।

राज्यों के स्तर पर सरकारों को कानूनी एवं नियामकीय मोर्चे पर प्रभावी ढांचा स्थापित करना होगा, जो लचीला होने के साथ ही अपने प्रविधानों को लागू करने की दृष्टि से सक्षम हो और जो पानी के आवंटन का काम तार्किक रूप से कर सके। इस दिशा में आस्ट्रेलिया से सीख ली जा सकती है, जहां तात्कालिक डाटा और मानसून के रुझान के हिसाब से पानी का आवंटन होता है। भारत में जल अधिकारों और उसके व्यापार को लेकर एक राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाया जाए। इसमें ब्लाकचेन तकनीक की मदद ली जा सकती है, जो प्रभावी जल प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और राज्यों के बीच नदियों के जल से जुड़े विवादों के निपटारे में भी मददगार होगी। पानी के मूल्य को लेकर भी कोई प्रगतिशील व्यवस्था बनाना बेहद अहम हो गया है, ताकि उसका मोल समझ आए। इससे जल संरक्षण और उसके किफायती उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिजिटल तकनीक से बड़ी सहायता मिल सकती है, जिसमें पानी की उपलब्धता, मांग और उपभोक्ता के व्यवहार से उसकी दरें निर्धारित करने के विभिन्न आधार तय हो सकेंगे। इसके आधार पर उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संरक्षण की नीतियों को आकार देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

अवधेश राजपूत

शहरों में स्थापित जल अवसंरचना में इंटरनेट आफ थिंग्स सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता, वितरण में अक्षमता और रिसाव आदि की तात्कालिक जानकारी जुटाई जा सकती है। इससे जुटाए गए डाटा का एआइ के साथ जुड़ाव पानी से संबंधित ढांचे के बेहतर रखरखाव, पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति के मोर्चे पर कोई सार्थक राह दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में रिसाव पर अंकुश लगाकर व्यापक स्तर पर पानी को बचाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाकर भी जल संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। मैनेज्ड एक्विफर रीचार्ज जैसी तकनीक की मदद से खासतौर से उन इलाकों की सूरत संवारी जा सकती है, जहां बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेन गार्डेंस और कुछ विशेष संरचनाओं के माध्यम से भूजल को रीचार्ज करने के साथ ही बाढ़ की समस्या पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की क्षमताओं को और बेहतर बनाना होगा, ताकि अपशिष्ट जल से अधिक से अधिक साफ पानी मिल सके। इस पूरे अभियान में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही नियामकीय सुदृढ़ता और जनजागरूकता बेहद जरूरी होगी। स्थानीय निकायों को भी इसमें अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा, क्योंकि कई शहर इस मोर्चे पर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार 78 प्रतिशत शहरी निकाय ऐसी स्थिति में पाए गए, जिनके लिए पानी के मामले में अपने गवर्नेंस माडल को सुधारना आवश्यक है। करीब आधे नगर निकायों को जल के प्रबंधन से जुड़े अपने डाटा और सूचनाओं तक पहुंच को प्राथमिकता के स्तर पर देखना होगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 90 प्रतिशत नगर निकायों को इस क्षेत्र में लक्षित वित्तीय नियोजन एवं निवेश करना होगा।

अगर राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य उपयोग किए गए जल के प्रबंधन के मामले में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी हैं। इसके उलट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र जैसे राज्य काफी पीछे हैं। जल संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को अपने प्रयास बेहतर करने होंगे, क्योंकि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन जैसी पहल के माध्यम से केंद्र सरकार इस मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। इन प्रयासों के साथ ही अमृत 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम उस बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं, जो बढ़ती मांग और जलवायु अनिश्चितताओं के बीच निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

(देबराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

कपड़ों की तरह बदली जाती विचारधारा

राजीव सचान

ऐसे नेता निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं और जिनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जा रहा है

मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह पत्नी प्रेमलता सिंह के साथ फिर से कांग्रेस में लौट गए। प्रेमलता भी हरियाणा से भाजपा की विधायक रह चुकी हैं। इसके एक महीने पहले 2019 में भाजपा से लोकसभा सदस्य चुने गए उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। बीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के चाहे जो कारण गिनाए, माना यही जाता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में न तो बृजेंद्र सिंह को भाजपा का टिकट मिलने की संभावना थी और न ही विधानसभा चुनाव में प्रेमलता को। बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बेटे भाजपा छोड़ने वाले इकलौते नेता नहीं हैं। कई अन्य नेताओं ने भी भाजपा छोड़ी है और इसका एक बड़ा कारण उन्हें या उनके स्वजनों को लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलना रहा। भाजपा छोड़ने वालों की तुलना में कांग्रेस और दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या कहीं अधिक है। कुछ समय पहले तक तो यह स्थिति थी कि करीब-करीब हर दिन कांग्रेस या फिर अन्य किसी दल का कोई न कोई नेता भाजपा में शामिल हो रहा था। अब यह सिलसिला थोड़ा धीमा हुआ है। इससे अन्य दलों से अधिक राहत की सांस भाजपा नेताओं ने ली होगी, क्योंकि दूसरे दलों से आए कई नेता भाजपा में शामिल होते ही लोकसभा के प्रत्याशी बन जा रहे थे। ऐसे नेता भले ही यह कहते हों कि उन्हें भाजपा की विचारधारा भा गई, लेकिन सच यह है कि अधिकतर नेता कोई पद पाने या प्रत्याशी बनने या फिर अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति की चाह में भाजपा में आ रहे हैं।

भाजपा ने अभी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जितने किए हैं, उनमें से 30 से अधिक वे हैं, जिन्होंने दो साल और कुछ ने तो दो सप्ताह पहले ही उसका दामन थामा है। इसके चलते कई जगह भाजपा को असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा उन दलों में है, जिसमें ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, जो विचारधारा के कारण उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। यदि ये निराश-हताश हुए तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी तय है कि जैसे ही प्रतिकूल स्थितियां उभरीं या फिर दूसरे दलों से आए नेताओं के वांछित स्वार्थ पूरे नहीं हुए, वैसे ही वे अन्यत्र कूच करने में न तो देर करेंगे और न ही संकोच। निःसंदेह ऐसा भी नहीं है कि अन्य दलों से भाजपा में आया हर नेता उसका प्रत्याशी बन जा रहा है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि उनका सचमुच अचानक हृदय परिवर्तन हो जा रहा है और इसलिए वे भाजपाई होना पसंद कर रहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ एवं तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए और फिर तृणमूल कांग्रेस में जाकर पुनः भाजपा में लौटे अर्जुन सिंह ने विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपाई होने का फैसला किया होगा? जो आसानी से कहा जा सकता है, वह यह कि उनकी न तो पहले कोई विचारधारा रही होगी और न ही अब। राजनीति में ऐसे नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं। उनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। चुनावों के अवसर पर विशेष तौर पर ऐसा होता है। देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं, जो कपड़ों की तरह अपनी विचारधारा बदलकर करीब-करीब सभी राजनीतिक दलों की यात्रा कर चुके हैं।

भाजपा में शामिल होते कांग्रेस नेता • प्रेट्र

विचारों में बदलाव कोई बुरी बात नहीं है। देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से लोगों के विचार बदलते हैं और बदलने भी चाहिए, लेकिन विचार बदल जाने या फिर हृदय परिवर्तित होने का ढोंग भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल ऐसा हो रहा है। यह गजब ही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह पिछले पांच महीने में तीन दल बदल चुके हैं। फिलहाल वह भाजपा में हैं। इसी तरह इसी राज्य में सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा कांग्रेस से भाजपा में आईं और 48 घंटे के अंदर फिर कांग्रेस में चली गईं। यह समझ आता है कि कोई दल विस्तार के क्रम में उन राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाए, जहां वह कमजोर है, जैसे भाजपा के मामले में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, लेकिन आखिर वह अपने मजबूत गढ़ समझे जाने वाले राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं को क्यों महत्व दे रही है? आखिर ऐसा करके वह पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नेताओं को क्या संदेश दे रही है?

एक समय था, जब हर दल की विचारधारा होती थी, लेकिन धीरे-धीरे विचाराधाराहीन दलों की संख्या बढ़ने लगी और अब गिनती के दल ऐसे हैं, जिनकी अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा है। राष्ट्रीय दलों में भाजपा और वाम दल ऐसे दलों में गिने जाते हैं, जिनकी अपनी विचारधारा है। एक वक्त कांग्रेस की भी विचाराधारा होती थी, लेकिन आज शायद कांग्रेसजन भी यह न समझा पाएं कि उनके दल की विचारधारा क्या है, क्योंकि आज की कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सेक्युलर दल है और विभाजन के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के बचे-खुचे नेताओं की ओर से बनाई गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी। बदलते समय और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विचारधाराओं में बदलाव आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उनका हाल वामपंथ की विचारधारा जैसा होता है, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं के पालाबदल को जनता की आकांक्षाओं का परिणाम बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यह तो शुद्ध अवसरवाद है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्म-जागरण

हमारे शास्त्रों में उल्लेख है-कलैव ब्रह्म अर्थात कला ही ब्रह्म है। यह कला ही है, जो पत्थरों में छिपी मूर्तियों को निखारती है। कला ही शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती है। वीणा में सोए संगीत को जगाती है, लेकिन इन सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला वह है जो सोए आत्मा को जगाती है। आत्मा को जगाने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आत्मा हमारा ही है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं कोई और नहीं। वर्तमान में हम आत्म-जागरण की कला भूल दूसरों की पसंद या नापसंद के दास बन गए हैं। नादिरशाह ने हाथी पर बैठने से यह कह कर इन्कार कर दिया था कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में न हो, उस पर बैठना खतरे से खाली नहीं है।

अपने जीवन की लगाम यदि हमारे हाथ में है तो हम स्वयं के मालिक हैं और स्वतंत्र हैं। न जाने क्यों अपना बुद्धि, विवेक त्याग कर हमने बाहर वालों को हमारी गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। वस्तुतः, हम स्वभाव से नहीं, अपितु दूसरों के प्रभाव से जी रहे हैं। किसी की प्रशंसा से मंत्रमुग्ध होकर उसके मुरीद बन गए। कोई हमारे ऊपर लांछन लगा गया तो उससे शत्रुता पाल ली। हम दूसरों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि स्वयं के भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। हमारी प्रसन्नता और नाराजगी दूसरों पर आधारित हो गई है, क्योंकि जीवन में सब कुछ दूसरे तय कर रहे हैं। हम भी अपनी समस्त क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करने के लिए और उनकी कसौटी पर खरे उतरने के लिए कर रहे हैं।

हम अपनी समस्त मौलिकता खो बैठे हैं। जबकि हमारा हित इसी में है कि अपने मालिक बनें। अपने मालिक बनते ही भीतर की संपदाओं से परिचय हो जाएगा। फिर संसार का सारा शोर, विसंगतियां और विकार लुप्त हो जाएंगे। इन सबसे परे होकर स्वयं का अन्वेषण करना ही सच्ची साधना है। यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है।

डा. निर्मल जैन

कह के रहेंगे

माधव जोशी

नईदुनिया जनमत

कल का परिणाम

क्या अखिलेश यादव वोट बैंक के लालच में माफिया मुख्तार अंसारी के घर गए?

आज का सवाल
क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पाठकनामा

letter@naidunia.com

अपने अहित पर आमादा कांग्रेस

'कांग्रेस के न्याय पत्र पर वामपंथ की छाप' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में उमेश चतुर्वेदी ने कांग्रेस की दिशाहीनता से परिचय कराया गया है। लेखक ने उचित ही लिखा है कि कांग्रेस इस समय वामपंथ की ओर मुड़ रही है। जबकि देश-दुनिया से वापमंथी विचारधारा का निरंतर संकुचन होने पर है। केरल को छोड़कर कहीं उसकी मुखर मौजूदगी नहीं रही। यहां तक कि एक समय उसके गढ़ रहे बंगाल और त्रिपुरा भी उसके हाथ से निकल गए हैं। एक समय कांग्रेस में वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी सभी प्रकार की वैचारिकी से प्रेरित नेता मौजूद थे और व्यापक रूप से पार्टी की पहचान भी मध्यमार्गी दल की रही जिसका अन्य धाराओं को साधकर चलने में विश्वास रहा, लेकिन राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद से पार्टी पर वामपंथ का प्रभाव बढ़ा है। फिर चाहे उद्यमियों या औद्योगिक घरानों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप हो या फिर पुरानी पेंशन का शिगूफा या फिर सरकारी नौकरियों का मोह दिखाना। वर्तमान में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर कर रही हैं, उनमें कांग्रेस की नीतियां आर्थिकी को पीछे ले जाने वाली ही अधिक लगती हैं। कांग्रेस वक्त की दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पाने का प्रयास नहीं कर रही। वह खुद ही अपने कायाकल्प में अवरोध बन रही है।

– **गुंजन शर्मा**, कमला नगर-नई दिल्ली

मोदी ने बदल दिया सोचने का तरीका

आलेख "विकसित देशों से सीख ले भारत" में श्रीकांत शर्मा ने बहुत ही सटीक और आवश्यक मुद्दा उठाया है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय समाज में रोजगार का अर्थ केवल नौकरी ही रह गया। उसमें भी सरकारी नौकरी को श्रेष्ठ माना जाने लगा। किंतु मोदी सरकार ने कौशल विकास अभियान प्रारंभ करके इस समस्या की जड़ पर प्रहार किया है। मैकाले की किताबी शिक्षा की जगह अब युवाओं को विभिन्न व्यवहारिक विधाएं सिखाई जा रही हैं। जिनके चलते बहुत कम पढ़े हुए बच्चे भी एक या दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद रोजगार पाने के योग्य बन रहे हैं। इनमें से अधिकांश स्वयं अपना कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं। इस अभियान के व्यापक परिणाम आने वाले पांच वर्षों में दिखने लगेंगे।

– **माणकलाल बियानी**, बिचोली मर्दाना, इंदौर

सोना-चांदी ने लगा दी आग

समाचार : सारे रिकार्ड तोड़े, चांदी 79 हजार तो सोना 71 हजार के पार। भाव शिखर पर पहुंचने से आमजन की पहुंच से दूर हुई मूल्यवान धातु सोना व चांदी। बाजार में भी ग्राहकी नहीं।

टिप्पणी : इधर चुनाव के कारण राजनीति में आग लगी है और उधर सोना-चांदी अपना अलग अलाव लगा बैठे हैं। अब आम आदमी के पास पंकज उधास की गजल सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं।

– **डा. श्रीकांत द्विवेदी**, महावीर मार्ग, धार

इतिहास को तो स्वीकारना ही होगा

संपादकीय अग्रलेख 'हिंदू प्रतीकों के प्रमाण' के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि समूची भारत-भूमि ईश्वर की लीला से भरी हुई है। तमाम देवी-देवताओं के सिद्ध पीठ के उल्लेख भारत के विभिन्न राज्यों में मिलते हैं। सनातन की सहृदयता और अपनों की गद्दारी का तत्कालीन आक्रांताओं ने खूब लाभ उठाया और प्राचीन व स्वयंभू क्षेत्रों को जमींदोज कर अपने मत-मतांतरों के पुतले खड़े कर दिए। अयोध्या, काशी, मथुरा के प्रमाणों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मंदिरों की शक्ल बिगाड़ी गई है। धार की भोजशाला के सर्वे में प्रारंभिक रुझान भी हिंदू मंदिर होने के संकेत दे रहे हैं। आगे सर्वे और उसकी रिपोर्ट से इसका और अधिक खुलासा हो सकेगा। चूंकि कैमरों की निगरानी में सर्वे हो रहा है, ऐसे में किसी फर्जीवाड़े की आशंका का सवाल ही नहीं। अब जरूरत इस बात की है कि दूसरा पक्ष इसे सहजता से स्वीकारे कि तत्कालीन शासकों ने मंदिरों का भूगोल बदला था। ऐतिहासिक प्रमाणों से मंदिर का आधिपत्य अब स्वयं सिद्ध है। ऐसे में केवल सद्भावना पूर्ण हस्तांतरण ही अंतिम उपाय है। अगर दूसरे पक्षकार ऐसी हिम्मत दिखाते हैं, तो यह बड़ी मिसाल साबित हो सकती है।

– **अमृतलाल मारू 'रवि'**, इंदौर

X पोस्ट

खराब नेता पैदा नहीं होते। बल्कि वे तो बनाए जाते हैं, वह भी उन लोगों द्वारा, जो मतदान के दिन पिकनिक मनाने चले जाते हैं। परेश रावल @SirPareshRawal

किसी साधु-संत की कोई जाति नहीं होती, अपितु वे तो सभी समाजों के साझा होते हैं। उन्हें जाति के बंधन में बांधना सनातन संस्कृति का अपमान है।
अंकेश भाटी @AnkeshBhatii

अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ हाई कोर्ट से झटका लगा है, बल्कि अदालत ने जो टिप्पणी की है, वह उनके लिए आगे की कानूनी डगर मुश्किल करने वाली है।
रोमाना ईसार खान @romanaisarkhan

बसपा पर तमाम लोग भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बहनजी के राजनीतिक वारिस आकाश आनंद सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को निशाने पर ले रहे हैं। सौरभ त्रिपाठी @Saurabh_LT

कृपया मेरी पोस्ट को अन्यथा न लें, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि मीडिया में भले ही दिखाया जा रहा हो कि देश अपना मन बना रहा है, मगर मुझे लगता है कि देश अपना मन पहले ही बना चुका है। मेरे हिसाब से इस चुनाव का फैसला लगभग हो चुका है।
शेखर कपूर @shekharkapur

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/18897 जागरण प्रकाशन लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस प्लॉट नं. 47/3, भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर से मुद्रित एवं तीसरी मंजिल, कृष्णा ग्लोरी कॉम्पलेक्स, सांई नगर, होटल बेबीलॉन इन के पीछे, जेल रोड, रायपुर से प्रकाशित
फोन नं. 0771-4711000 फैक्स : 0771-4711024 इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com **संपादक** : सद्गुरु शरण* *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 10 अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए कानूनों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बुरे लोग कानूनों के बाहर एक रास्ता खोज लेंगे।
-प्लेटो

अभिव्यक्ति को सर्वोच्च सुरक्षा

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक विचारों से जुड़े तथा सत्ता से असहमति रखने वाले यूट्यूब या अन्य माध्यमों से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तियों को भारी राहत प्रदान की है। यह राहत तमिलनाडु के एक राजनीतिक कार्यकर्ता यूट्यूबर दुरई मुरुगन के मामले में दिए गए जमानत बहाल रखने के फैसले में आई है। दरअसल, मुरुगन को अक्टूबर, 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि मुरुगन ने स्टालिन की तुलना रामायण के खलनायक रावण से की थी। मुरुगन को इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी कि वह जमानत

के दौरान कोई भी न्यायविरोधी कार्य या टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जमानत के दौरान भी स्टालिन की आलोचना जारी रखी जिसे लेकर तमिलनाडु सरकार पुनः उच्च न्यायालय पहुंची और मुरुगन की जमानत रद्द कर दी गई। इस फैसले के विरुद्ध मुरुगन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सरकार का पक्ष सुनने और मुरुगन का पक्ष जानने के बाद सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा कि यूट्यूबर की टिप्पणियों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जमानत रद्द करने की बाध्यता बनती हो। यूट्यूबर की जमानत बहाल रखते हुए बड़ी बात यह कही कि ऐसी टिप्पणियों पर चुनाव के समय यूट्यूबरों को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। आशय था कि ऐसा करने से जेलों में जगह नहीं बचेगी। फैसले का निहितार्थ यह है कि राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को, सोशल मीडिया के इस युग में जहां सामान्य व्यक्ति भी अभिव्यक्ति की अपनी आजादी का उपयोग करना चाहता है, अपने विरुद्ध की गईं टिप्पणियों को सहजता से लेना चाहिए। उन्हें तत्काल अपमान का मुद्दा नहीं बना देना चाहिए। विडंबना देखिए कि जिन स्टालिन के पुत्र उदयगिरि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करके बड़े वर्ग को आहत किया था और स्टालिन को अपने पुत्र के समर्थन में उतरना पड़ा था और सफाई के लिए तर्क गढ़ने पड़े थे और मंशा प्रकट की थी कि उदयगिरि के बयान को गलत न माना जाए वही स्टालिन अपने विरुद्ध कही बात से इतना तिलमिला गए कि एक यूट्यूबर को दंडित करने के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक की दौड़ लगानी पड़ी। बहरहाल, राजनीतिज्ञों को इस फैसले के आलोक में अपने मान-अपमान का आकलन करना चाहिए।

कानून से परे रिवाज

हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत हिन्दू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह बात कही है। उसका कहना है कि केवल सप्तपदी ही हिन्दू विवाह का जरूरी समारोह है, अनुष्ठान के लिए कन्यादान आवश्यक नहीं है। एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कन्यादान किया गया था या नहीं, यह मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए जरूरी नहीं होगा। इसलिए इस तथ्य को साबित करने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत गवाहों को नहीं बुलाया जा सकता। अभियोजन के अनुसार विवाद में जोड़े के विवाह में कन्यादान आवश्यक था। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा सात के अनुसार, विवाह किसी भी पक्ष के प्रथागत संस्कारों और समारोहों के अनुसार

मनाया जा सकता है जिसमें सप्तपदी यानी दूल्हा-दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि की समक्ष संयुक्त रूप से सात फेरे लेना शामिल है। सातवां फेरा लेते ही विवाह पूर्ण हो जाता है। अव्वल तो रीति-रिवाजों को लेकर कानूनी जंग करना किसी भी नजर से जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर, यह भी कि सामाजिक होने के बावजूद विवाह नितांत निजी मसला होता है। अपने यहां होने वाली शादियों में पीढ़ियों से चली आ रहीं परंपराएं, रीति-रिवाज और रस्में इनका अभिन्न हिस्सा हैं जो विभिन्न परिवारों या समुदायों में एक-दूसरे से विपरीत या अलग तरह से निभाई जाती रही हैं। बावजूद इसके कन्यादान जैसी कोई भी रस्म न अदा की जाए तो विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी विवाह में इस तरह की कोई भी रस्म नहीं निभाई गई तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। निस्संदेह सम्मानित अदालत ने कन्यादान की प्रचलित रस्म को नकारा नहीं है, बल्कि स्पष्ट किया है कि प्रचलित रस्मादायिकी के बगैर भी विवाह संपूर्ण ही होता है। आपसी झगड़ों या दांपत्य के दरम्यान होने वाले झंझटों को लेकर की जाने वाली अदालती लड़ाइयों में कई बार बिला-वजह के मामलों को तूल देकर अदालत का कीमती समय बर्बाद किए जाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जो विवाद घर के भीतर आपस में बैठ कर सुलझाए जा सकते हैं, उनके लिए भी कानून की आड़ लेने वालों को सामाजिक तौर पर सांकेतिक सजा दी जा सकती है, जिससे ऐसे अन्य लोग भी समय रहते सबक ले सकें। बेशक, अनेक मसले होते हैं जिन्हें परिवार के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है।

दल-बदल/ललित गर्ग

लोकतंत्र पर चोट

कांग्रेस से लगातार वफादार नेताओं का पलायन जारी है। नये नामों में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार एवं मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, निशाना साधने वाले मुक्केबाज विजेंदर, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय कर दी है। इन सभी ने कांग्रेस के मुद्दाविहीन होने, मोदी के विकसित भारत के एजेंडे, राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति एवं कांग्रेस के सनातन-विरोधी होने को पार्टी से पलायन का कारण बताया है।

कुछ भी कहें, यह राजनीति में अवसरवाद का उदाहरण है, इस तरह का बढ़ता दौर चिंताजनक है। भारत की राजनीति में दल-बदल की विसंगति एवं विडंबना आजादी के बाद से लगातार देखने को मिलती रही है। पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहे हैं। दल-बदल के बढ़ते दौर ने अनेक सवाल खड़े किए हैं। कल तक विपक्ष में जो नेता दागी होते थे, सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनके दाग दाग नहीं रहते। राजनीति में निष्ठाएं बदलने की स्थितियां आम नागरिकों को उद्वेलित कर रही हैं कि आखिर, ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगा कर दूध का धुला घोषित हो जाता है। निश्चिय ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं कही जा सकती। देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दल-बदल का बढ़ता दौर कैसे रुके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धांतों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है। 'राजनीति में सब कुछ जायज है' वाली सोच एवं स्वार्थ की नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का समय हर राजनेता के लिए अपने हित एवं स्वार्थ को चुनने का समय होता है, लेकिन उसके सामने लोकतंत्र के हिताहित का प्रश्न बहुत गौण हो जाता है। चुनावों में आचार संहिता के चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में दल-बदल पर नियंत्रण का प्रावधान ही नहीं है, जबकि लोकतंत्र की जीवंतता एवं पवित्रता के लिए इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

सत्ता की आत्मघाती सनक

बेंजामिन नेतन्याहू

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

मध्य-पूर्व में सत्ता में बने रहने की सनक और सत्ता से उखाड़ फेंकने वालों की कोशिशों के बीच हिंसक प्रतिद्वंद्विता का पुराना इतिहास रहा है। अरब कबीलाई संस्कृति को अपनी गौरवशाली परंपरा से जोड़कर देखते हैं, अतः अधिकांश देश अमीर और शहजादों से अभिशप्त रहे। वहीं जहां लोकतंत्र की गुंजाइश दिखाई दी, उसे शिया और सुन्नी विवाद की आड़ में खत्म कर दिया गया। यूरोप ने सदा इस्राइल को मध्य-पूर्व में लोकतंत्र का आदर्श मॉडल कहा। लेकिन अरब देशों के बीच बसे इस एकमात्र गैर-मुस्लिम देश की राजनीति भी सत्ता में बने रहने की सनक का शिकार होकर हिंसक रास्ते पर बढ़ रही है।

करीब आठ दशक पहले बड़ी मुश्किल से अस्तित्व में आया इस्राइल स्वस्थ लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राजनीति के साथ कदम ताल मिलाते-मिलाते अरब राष्ट्रवाद की तानाशाह सत्ता को आत्मसात करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 1948 में अलग देश का दर्जा पाने वाले इस्राइल के संसदीय इतिहास में अब तक किसी पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई, इस कारण सरकारें तेजी से बदलती रहीं। लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। नेतन्याहू की इस्राइल की सत्ता के शिखर पर बने रहने की कोशिशों ने देश की राजनीति को बदल दिया है। नेतन्याहू का संबंध एक धर्मनिरपेक्ष परिवार से रहा। जिस राजनीतिक दल लिकुड पार्टी से आते हैं, उसकी नीतियां उदार और मिली-जुली रहीं। नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक पारी को पुख्ता करने के लिए कमजोर गठबंधनों, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी गठबंधनों के साथ वामपंथी दल को भी अपना सहयोगी बनाने से परहेज नहीं किया। लेकिन अब वे अतिधार्मिक समूहों के साथ यहूदी आक्रामकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए उनकी यह नीति बेहद कारगर रही है, लेकिन इसी कारण इस्राइल असुरक्षित होकर हिंसा की आशंका से भयाक्रांत भी है।

2020 में इस्राइल में नेतन्याहू का ऐतिहासिक विरोध पूरे देश में हो रहा था। इसके साथ ही यह नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था जिसमें युवाओं के हाथों में नेतन्याहू के पोस्टर के साथ लिखा होता था कि, आपका समय समाप्त हो गया है। इस्राइल की समस्याओं को लेकर जो लोग सड़कों पर थे। धोखाधड़ी, विश्वासघात, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कोरोना वायरस संकट से निपटने के तरीकों को लेकर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने देश भर के मुख्य राजमार्गों और जंक्शनों को बंद कर दिया। इस्राइल में कोरोना वायरस को लेकर

लोगों को अपनी नौकरियां गवांनी पड़ी हैं। इससे व्यवसायों पर गहरा असर पड़ा है। इसे जनता पीएम की विफलता मान रही है, और उनसे लगातार इस्तीफा देने की मांग कर रही थी।

नेतन्याहू का जब सत्ता से जाना तय लग रहा था, तब उन्होंने यहूदीवाद का सहारा लेकर लोगों के सामने खुद को एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। सार्वजनिक संस्थानों में यहूदी पहचान लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए दक्षिणपंथी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा दी। विरोधी पार्टी के कई नेता, नेतन्याहू के समर्थन में खड़े हो गए। विपक्ष की एकता को धराशायी करते हुए नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के विभिन्न इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाने का पासा भी फेंका। जब नवम्बर, 2022 में चुनाव हुए तो इस्राइल की यहूदी पहचान का नेतन्याहू का दांव कामयाब रहा और मतदाताओं ने उन्हें अप्रत्याशित बढ़त दिला दी। नेतन्याहू देश के फिर प्रधानमंत्री बने, इस बार उनके सहयोगी दलों को देखकर कहा गया कि यह देश की सबसे कट्टरपंथी सरकार है।

नेतन्याहू खुद को ऐसे राजनेता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं जो इस्राइल को मध्य-पूर्व की खतरनाक ताकतों से सुरक्षित रखता है, फिलिस्तीन को लेकर बहुत सख्त है, और शांति वार्ता से ज्यादा कड़ी सुरक्षा को तवज्जो देता है। ईरान को सीमित करता है तथा दुनिया में नये सहयोगियों को तैयार करता है। लेकिन एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्राइल की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए हैं, नेतन्याहू के इस्तीफे और जल्द चुनाव करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग यह भी है कि हमास के कब्जे में अब भी जो 130 इस्राइली बंधक हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए जल्द से जल्द डील की जाए। इनमें से कुछ लोगों के बारे में माना जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। इन सबके बीच फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू का रुख बेहद सख्त है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा के भीतर ही 17 लाख से अधिक लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा है। रिहायशी इलाके बर्बाद और मलबे में तब्दील हो गए हैं। फिलिस्तीन के शिक्षा संस्थान, अस्पताल ध्वस्त हो गए हैं। युद्ध, बीमारी, भुखमरी और मौतों ने फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर दिया है।

इस्राइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के छह महीने बाद भी नेतन्याहू न तो अपने बंधकों को छुड़ा पाए हैं, और न ही हमास को पूरी तरह खत्म कर पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से इस्राइल को आदेश दिया है कि अकाल से गाजा को बचाने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति को बाधित न करे। नेतन्याहू ने एक समय हेब्रोन के 80 प्रतिशत भाग को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण में सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और कब्जे वाले वेस्ट बैंक से अधिक निकासी के लिए सहमति जताने का साहस दिखाया था। 2009 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्राइल के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य की सशर्त स्वीकृति की घोषणा भी की थी और यह अभूतपूर्व था।

अब नेतन्याहू की राजनीति पूरी बदल चुकी है। युद्ध के बाद वे बुरी तरह घिर चुके हैं। हमास, हिज्बुल्ला, हूती विद्रोहियों के साथ ईरान से निपटने की चुनौती सामने है। फिलिस्तीन को लेकर इस्राइली आक्रामकता से विश्व समुदाय नाराज है लेकिन नेतन्याहू बेपरवाह राष्ट्राध्यक्ष की तरह व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू वैश्विक नेता और मध्य-पूर्व के सबसे बड़े संकटमोचक बनने से कहीं ज्यादा खुद को सत्ता में बनाए रखने को तरजीह दे रहे हैं। देश की सत्ता के शीर्ष पर बने रहने की उनकी यही सनक इस्राइल और मध्य-पूर्व में शांति की उम्मीद को ध्वस्त कर रही है।

> बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति अब पूरी बदल चुकी है। युद्ध के बाद वे बुरी तरह घिर चुके हैं। हमास, हिज्बुल्ला, हूती विद्रोहियों के साथ ईरान से निपटने की चुनौती उनके सामने है। फिलिस्तीन को लेकर इस्राइली आक्रामकता से विश्व समुदाय नाराज है, लेकिन नेतन्याहू बेपरवाह राष्ट्राध्यक्ष की तरह व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू वैश्विक नेता और मध्य-पूर्व के सबसे बड़े संकटमोचक बनने से कहीं ज्यादा खुद को सत्ता में बनाए रखने को तरजीह दे रहे हैं। देश की सत्ता के शीर्ष पर बने रहने की उनकी यही सनक इस्राइल और मध्य-पूर्व में शांति की उम्मीद को ध्वस्त कर रही है

- इस साल आम की फसल की संभावनाएं अच्छी हैं। फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में उत्पादन बढ़कर 2.4 करोड़ टन हो सकता है जबकि फसल वर्ष 2022-23 में यह 2.1 करोड़ टन था। इस प्रकार उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है
- आम भारत का एक महत्त्वपूर्ण फल है, और इसे 'फलों का राजा' कहा जाता है। भारत प्रमुख आम उत्पादक देश है, जो विश्व उत्पादन में लगभग 42 प्रतिशत का योगदान देता है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

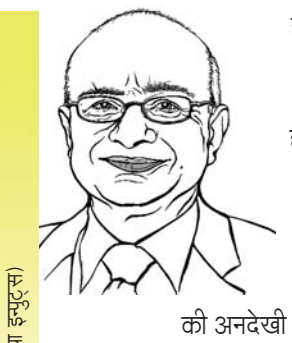

इस्राइल ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई का सामना करने को तैयार है, जो कभी भी हो सकती है, जिससे बड़े स्तर पर क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाने का खतरा है। सीरिया स्थित ईरान के दूतावास पर इस्राइल के हवाई हमले से न केवल जेनेवा कन्वेंशन की अनदेखी हुई है, बल्कि वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन हुआ है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक विशेषज्ञ
@chellaney

परमाणु धमकी डॉ. एन.के. सोमानी

रणनीतिक आयाम या महज धमकी

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि वैश्विक परमाणु युद्ध का खतरा व्यावहारिक रूप से गायब हो गया है, और दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है, तो इस बयान के बाद विश्व समुदाय के माथे पर उभरी चिंता की रेखाएं कुछ कम हुईं और दुनिया ने राहत की सांस ली। इसकी बड़ी वजह यह थी कि गोर्बाचेव के बयान के पार्श्व में कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की विचारधारा भी काम कर रही थी।

गोर्बाचेव-रीगन के बयान के तीन दशक बाद 2021 में दुनिया एक बार फिर आश्वस्त हुई। मौका था जिनेवा शिखर सम्मेलन का जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गोर्बाचेव-रीगन के बयान को दोहराते हुए कहा कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है, और इसे कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए। लेकिन फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद दुनिया को फिर परमाणु आक्रमण का भय सताने लगा है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जिस तरह पुतिन बार-बार परमाणु हथियारों के उपयोग की बात कर रहे हैं, उससे यह प्रश्न फिर परेशान करने लगा है कि क्या मानव जाति विनाशकारी हथियारों के खतरे के सन्निकट है। यह सवाल इसलिए भी बहस के केंद्र में है कि पिछले दिनों पुतिन ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में नाटो देशों को धमकाते हुए कहा कि वे यूक्रेन में रूस के खिलाफ सेना भेजते हैं, तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा।

अब राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की रिकॉर्ड जीत के बाद पश्चिमी देश सकते में हैं। जीत के तत्काल बाद पुतिन ने बिना लाग-लपेट के कहा कि अब रूस पहले से ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। निस्संदेह, पुतिन की प्रतिक्रिया एक तरह से पश्चिम के लिए चुनौती है। सवाल यह है कि पुतिन की परमाणु बयानबाजी क्या महज धमकी है, या उसका कोई रणनीतिक आयाम भी है।

सच तो यह है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्रेमलिन के परमाणु सिद्धांत का एक हिस्सा है। इस सिद्धांत में साफ कर दिया गया है कि किन परिस्थितियों में रूस विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। तो क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें पुतिन अपने परमाणु सिद्धांत को अमली जामा पहना सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध को लंबा

खिंचता देखकर पुतिन की ओर से स्वयंमेव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जो उनके परमाणु विकल्प को उचित ठहराती हों। निस्संदेह यह सवाल पहले के सभी सवालों से बड़ा और गंभीर है। पश्चिमी देश अगर यूक्रेन के लिए रणक्षेत्र में उतरते हैं, तो निश्चय ही पुतिन के लिए अपने परमाणु सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल, पुतिन की परमाणु धमकी के कई अंतर्निहित कारण हैं। पहला और तात्कालिक तो यह कि आरंभ में पुतिन यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रवाद जैसे भावुक विचार से जोड़ना चाहते थे। इसलिए युद्ध के शुरुआती दौर में उन्होंने जनता को युद्ध संबंधी कार्रवाई में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया लेकिन युद्ध के मनोवांछित परिणाम न आने से पुतिन के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। बहुत संभव है कि पुतिन साइकोलॉजिकल वारफेयर के सहारे देशवासियों के गिरते हुए मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। दूसरा, युद्ध में रूस अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। उसने युद्ध में जीत की जमीन तैयार कर ली है। नाटो देशों का दखल उसके मंसूबों पर पानी फेर सकता है। इसलिए नाटो सैनिकों की संभावित भागीदारी को रोकने के लिए पुतिन परमाणु विकल्प के प्रचार का सहारा ले रहे हैं। तीसरा, परमाणु धमकी यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की चाल भी हो सकती है। पुतिन को लगता है कि परमाणु धमकी से नाटो देश भयभीत हो जाएंगे और यूक्रेन के लिए अपना समर्थन कम कर देंगे। चौथा, परमाणु धमकी को यूक्रेन और पश्चिम के लिए चेतावनी भी कहा जा रहा है। इस चेतावनी के बाद अब गेंद यूक्रेन के पाले में है, या तो वह पीछे हट जाएगा या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा।

रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके शास्त्रागार में करीब 6,000 परमाणु हथियार हैं। इनमें 1500 के करीब अलग-अलग टॉरगेट पर तैनात हैं। उसके पास जार बॉम्बा एएन602 (परमाणु बमों का राजा) उच्च मारक क्षमता वाला बम भी है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में पुतिन के बयान को कोरी धमकी मान लेना भूल होगी जिसकी बड़ी कीमत मानवता को चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, पुतिन की रणनीति खुद रूस के लिए भी घातक साबित हो सकती है। यदि पश्चिमी देश परमाणु धमकियों को महज प्रोपेगेंडा मानते हुए यूक्रेन को सैन्य समर्थन के मुद्दे पर बढ़ते हैं तो निस्संदेह युद्ध और अधिक भड़क सकता है। कोई दो राय नहीं कि यदि यूक्रेन में संघर्ष तेज होता है, तो क्रेमलिन के उद्देश्य कमजोर हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो सारा दारोमदार पश्चिमी देशों के इस दृष्टिकोण पर निर्भर है कि वे पुतिन के बयान को किस संदर्भ में देखते हैं। क्या पुतिन के भ्रामात्मक प्रोपेगेंडा को स्वीकार करेंगे या उनके उच्च दांव वाले परमाणु रुख के आगे झुक जाएंगे।

प्रेम सद्‌गुरु

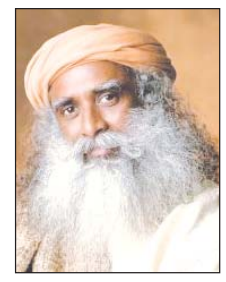

संबंधविहीन जीवन में अव्यवस्था का होना निश्चित है और अव्यवस्था तो जन्म ही तब लेती है, जब मन संबंधों में अतीत के ज्ञान के आधार पर बर्ताव करता है। तो यह कैसे हो कि मन यह तो जाने कि अपमान हुआ है, या सम्मान हुआ है, पर उसे दर्ज न करे? क्या यह हो सकता है कि मन हमेशा निर्मल, साफ-सुथरा, स्वस्थ रहे, संबंधों में परिपूर्ण रहे? यदि आपकी इसमें वाकई दिलचस्पी है कि संबंधों में कैसे जिया जाए कि मन को कभी ठेस न लगे, मन में कभी विकार-विकृति न आए। ऐसा सोचना ही प्रेम है। वह मन जो कोई मान-अपमान दर्ज नहीं करता, वही जानता है कि प्रेम क्या होता है। यदि संभव हो जाता है कि किसी के मान-अपमान को दर्ज न करे, तो मानो हमने संबंधों की समस्या को सुलझा लिया है। संबंध तो दिन-प्रतिदिन के जीवन की वास्तविकता है। चाहे आप अपने काम पर जाते हों और लौट कर अपनी पत्नी के साथ झगड़ते हों या उसके साथ प्यार से रहते हों, आप हमेशा किसी न किसी संबंध से जुड़े हैं और यदि आपके और दूसरे के बीच, या आपके और बहुतों या एक के बीच के संबंध में व्यवस्था नहीं है, तो आप ऐसी संस्कृति का निर्माण करेंगे जो अंत में अव्यवस्था ही पैदा करेगी। यही आजकल हो रहा है। जानने की कोशिश करना परम आवश्यक है कि अपमान, ठेस, दुर्व्यवहार या कटुता और कठोरता मिलने पर भी क्या मन एक पल के लिए भी उसे बिना थामे रह सकता है? जिस भी पल हम उसे थामते हैं, वह तुरंत दर्ज हो जाती है, मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाती है। क्या मन ऐसा कर सकता है कि पूरी तरह निर्मल और अबोध बना रहे? निर्मल और अबोध मन वह होता है जिसे ठेस लग ही नहीं सकती क्योंकि जिसे ठेस नहीं लगती है, वह किसी दूसरे को भी ठेस नहीं पहुंचाएगा। दिखावा करने से कुछ दोष हमारे भीतर ही बैठ जाते हैं, ज्ञान ही है जो हमें इन अवगुणों से बचाता है। इस आयाम तक आने के लिए देखना और जानना होगा कि प्रेम क्या है। क्या विचार की उपज है? क्या समय के दायरे में आता है? क्या सुख-विलास है? क्या एक स्वाद का वही सुख है, जिसे फिर से चाहने लगता हूं, या उससे भी बढ़िया? मन जिसे दर्ज कर लेता है, और फिर उसे ही बार-बार चाहने लगता है। यही तो प्रेम है।

रीडर्स मेल

स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन

मानव जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। मनुष्य यदि स्वस्थ नहीं रहता तो वह न तो परिवार और न ही समाज में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, और न ही राष्ट्र निर्माण में ही योगदान दे सकता है। समय का सही सदुपयोग न करने वाले अस्वस्थ मनुष्य का जीवन निराशा और कुंठा से ग्रस्त रहता है। इसीलिए स्वास्थ्य को जीवन का अनमोल रत्न माना जाता है या यूं कहें कि स्वास्थ्य ही धन होता है। इसीलिए भारत में 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना है, जिससे स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। भारत में यदि स्वस्थ जनमानस होगा तो सकल घरेलू उत्पाद में 2 फीसद तक की वृद्धि हो सकती है। उत्पादकता और आय में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार होने से बीमारी में होने वाले खर्च में बहुत कमी होने की संभावना होती है। अतः स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समझ लें-स्वास्थ्य ही बड़ा धन होता है।

संजीव ठाकुर, रायपुर, छत्तीसगढ़

अराजक तत्वों को समर्थन

पश्चिम बंगाल में संदेशखालि के बाद अब एक बड़े अपराधी को पकड़ने गई ईडी की टीम पर भीड़ द्वारा फिर से हमला करने की घटना सामने आई है! पश्चिम बंगाल सरकार का रुख शुरू से ही केंद्रीय संस्थानों के खिलाफ हिंसात्मक ढंग से पेश आने का रहा है, और जहां सरकार की शह मिल जाएगी वहां अराजक तत्वों को खुल कर अराजकता करने का मौका मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अराजक तत्वों को किस कदर समर्थन प्राप्त है, इसका उदाहरण तो पूर्व में भी हम देखते आए हैं। ममता बनर्जी का रवैया भारत के संघीय ढांचे को तहस-नहस करने वाला है। वे हर बात में आरोपियों को बचाते हुए नजर आती हैं। राज्यों और केंद्र के बीच की तल्खी को तानाशाही से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार की शह पर ही पश्चिम बंगाल की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों को सहयोग देने की बजाय उनके कार्य में रोड़े डालने का पूरा प्रयास करती है। संदेशखालि के आरोपी को भी इन्होंने ईडी को नहीं सौंपा और ईडी को कोर्ट से हस्तक्षेप करवाना पड़ा। केंद्र सरकार को समय रहते सख्त कदम उठाने होंगे!

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम, मप्र

मध्यम वर्ग है महत्त्वपूर्ण तबका

मानें या न मानें पर इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। यह केवल हमारे देश के संदर्भ में ही नहीं अपितु समूचे विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा तो कारण यही सामने आएगा। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। रियल स्टेट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और गगनचुंबी इमारतों का जिस तरह से जाल बिछ रहा है, वह मध्यम वर्ग के कारण ही संभव हो पा रहा है। यही कारण है कि आज देशी-विदेशी कंपनियां मध्यम वर्ग को केंद्रित कर अपने उत्पादों को बाजार में उतार रही हैं। सही मायने में कहा जाए तो जिसने मध्यम वर्ग की मांग को समझा वह दिनोंदिन मालामाल होता जा रहा है, और उसकी बाजार में पकड़ तेज होती जा रही है। ऐसे में यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बहुत कुछ श्रेय मध्यम वर्ग को जाता है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, ईमेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 238

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

संपादकीय

'गुड गवर्नेंस' की रीढ़ है सांख्यिकी शुद्धता

कल्याणकारी-राज्य वाली शासकीय व्यवस्था में गरीबों को मूलभूत सुविधाओं से संपुष्ट करना, ताकि उन्हें भी उन्नति का समान अवसर मिले, किसी भी सरकार की प्रथम, और शायद अंतिम भी, प्राथमिकता होती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक बाध्यताओं के कारण यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वह केवल सुपात्रों को मिले। भारत में पिछले 13 वर्षों से जनगणना नहीं हुई और सारी योजनाएं या तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मान कर प्रोजेक्टेड आंकड़ों पर या अवैज्ञानिक एप-आधारित छोटे सैंपल सर्वे के भरोसे बनाई जा रही हैं। यही कारण है कि घोषणा से पहले और बाद तक, ना तो सरकार यह जान पाई कि किसानों की आय कितनी है और दोगुनी करने पर कितनी होगी। बाल-कुपोषण को लेकर भी सरकार कुछ कहती है और उसी के आंकड़े कुछ और बताते हैं। अब तो सरकार ने यह भी बताना बंद कर दिया कि जनगणना क्यों नहीं की जा रही है। सही आंकड़ों के अभाव में तमाम विभाग अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए परिभाषा बदल देते हैं। बेरोजगारी के आकलन में रोजी न मिलने से घर बैठे युवाओं को 'अवैतनिक गृह-व्यवसाय' में शामिल कर बेरोजगारी को मात्र 3.4 प्रतिशत मानने का सरकारी दावा भी इन्हीं कारणों से है। तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत में इस स्थिति को लेकर संदेह व्यक्त कर रही हैं। ताजा उदाहरण आईएलओ-आईएचसी की संयुक्त रिपोर्ट है, जिसमें 2019 के बाद (कोविड के बावजूद) बेहतर रोजगार के आंकड़ों पर स्वयं रिपोर्ट लिखने वाले विशेषज्ञों ने संदेह जताया है। आलीशान मकान वालों के पास आयुष्मान कार्ड और हजारों मजदूरों का मजबूरी में महंगा इलाज करना बताता है कि सही आंकड़े 'गुड गवर्नेंस' की पूर्व-शर्त हैं।

प्रेरणा

चतुर आदमी समस्या सुलझाता है, पर बुद्धिमान आदमी इसे नजरअंदाज करता है। - **अल्बर्ट आइंस्टीन**

दूरदृष्टि • हमारा ध्यान 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है, सम्पत्ति के समान वितरण पर नहीं...

इकोनॉमी में अब समानता पर हो फोकस

कौशिक बसु
विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट

अगर हम सुर्खियों और पोस्टरों को पढ़ें तो इस हकीकत को भूल सकते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। लेकिन देश की बेहतरी के लिए हमें आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को समझना होगा। वित्त-वर्ष 2023-24 में- जीडीपी के मानक पर- भारत की कुल आय 7.6% बढ़ी थी। लेकिन यह 2003 से 2011 तक के भारत के प्रदर्शन से कम है। वर्ष 2008 को छोड़कर- जब पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में थी- भारत ने लगातार हर साल लगभग 8% की वृद्धि हासिल की थी। फिर भी, 7.6% की बढ़ोतरी सराहनीय है।

बहरहाल, अगर हम इस एग्रीगेट के नीचे झांककर देखें और जमीनी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि- सुपर-रिच व्यक्तियों के एक छोटे-से हिस्से को छोड़कर- अधिकांश भारतीयों को मुश्किल से ही कोई आर्थिक वृद्धि दिख रही है। इसके अलावा, भारत की कहानी- जिसका कि 1990 के दशक के मध्य से ही उत्सव मनाया जा रहा था- उसकी नींव असमानता की वजह से कमजोर हो रही है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त डेटा इसे स्पष्ट करते हैं।

पिछले साल प्रकाशित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2022 में तो इन्होंने शिखर छू लिया, जब कर्ज और गरीबी के बोझ से दबे 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। अकेले 2014 से 2022 तक 1 लाख से अधिक किसान अपनी जान दे चुके हैं।

एक और सेगमेंट- जिससे अर्थव्यवस्था की बदहाली का अंदाजा लगता है- युवाओं की बेरोजगारी है। यह 1994 से लगातार बढ़ रही है। 1994 में युवाओं की बेरोजगारी 11.8% थी। 2018 में यह आंकड़ा चौंकाने वाले चरम पर पहुंच गया, जब भारत के 25.9% युवा नौकरी की तलाश कर रहे थे और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। तब से इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी भारत की युवा बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। यहां के हालात की तुलना मध्य-पूर्व के देशों से की जा सकती है, जो अकसर युद्ध स्थिति से जूझते रहते हैं। विशेषकर शिक्षित युवाओं के लिए स्थितियां बहुत खराब हैं। 2022 में स्नातकों के बीच युवा बेरोजगारी 29.1% थी। स्वतंत्र भारत में यह सर्वाधिक है!

एक और चिंताजनक आंकड़ा- जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है- 'निवेश दर' है। यानी देश की आय का वह हिस्सा, जिसका कारखानों, सड़कों, मशीनों और मानव-पूंजी में निवेश किया जाता है। हम इस लंबी सूची में से कुछ वस्तुओं के बारे में सुर्खियां देखते हैं, जैसे कि बंदरगाह और हवाई अड्डे, जिनमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जब आप सभी प्रकार के निवेशों का जायजा लेते हैं तो एक अलग ही कहानी उभरकर सामने आती है। सच यह है कि हम इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। उच्च निवेश दर दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण चालक है। भारत की निवेश दर 2006 में 38% के आंकड़े को पार कर गई थी और 2013 तक इससे नीचे नहीं गिरी। तब भारत का निवेश दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बराबर था। लेकिन तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है, और जैसा कि सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, 2022-23 तक इसका आंकड़ा गिरकर 27.9% हो गया था। इससे विश्वास में गिरावट का पता चलता है।

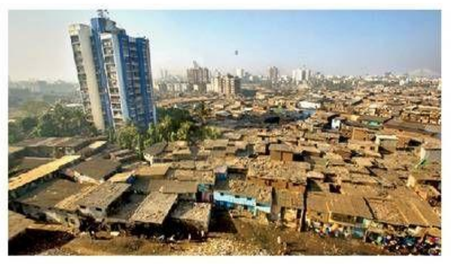

सबसे अमीर 1% के पास पूरे देश की 22.6% आय...

भारत में विषमता नए शिखर पर पहुंच रही है। सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की आय का 22.6% हिस्सा है। यह पिछले सौ वर्षों में धन का सबसे अधिक संकेंद्रण है। पिछली बार ब्रिटिश राज में ही हम इसके करीब पहुंचे थे।

इतनी सारी एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न चीजें गलत क्यों हो रही हैं? जब हम 18 मार्च को प्रकाशित विश्व विषमता लैब की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इसे समझना आसान हो जाता है। इससे पता चलता है कि भारत में असमानता- जो कई दशकों से अधिक रही है- अब नए शिखर पर पहुंच रही है। सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास अब पूरे देश की आय का 22.6% हिस्सा है। यह पिछले सौ वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक हिस्सेदारी है। पिछली बार हम 1930 के दशक में इसके करीब पहुंचे थे, लेकिन तब औपनिवेशिक शासन था। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा 'बड़े व्यवसायों और सरकार के बीच सांठगांठ' के कारण हो रहा है। भारत में लंबे समय से क्रोनिज्म रहा है। लेकिन अब तो यह नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसकी तुलना मध्य पूर्वी देशों, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि में अतीत में देखे गए क्रोनिज्म से की जा सकती है। जैसा कि 'टाइम' (27 मार्च) में बताया गया है, भारत में विषमता का स्तर अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका से भी अधिक है।

ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान सुर्खियों और पोस्टरों पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। हमारा पूरा जोर आज इस पर है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनें और कुल राष्ट्रीय आय के मामले में जर्मनी से कैसे आगे निकलें। लेकिन हम शायद ही कभी इस बारे में बात करते हैं कि कुल राशि का लोगों में कैसे वितरण हो पा रहा है और गरीब किस स्थिति में रह रहे हैं।

गांधीजी ने भारत को एक आदर्श वाक्य दिया था : 'जब भी तुम्हें संदेह हो तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उसके लिए कितना उपयोगी होगा!'

लेकिन आज जब युवाओं के लिए नौकरियां खत्म हो रही हैं और किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है तो नया आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है : 'जब भी आर्थिक स्थिति के बारे में उदास महसूस करें और गरीबी को लेकर चिंतित हों, तो सबसे अमीर आदमी का चेहरा याद करें, और गर्व महसूस करें!'

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

शक्ति का सम्मान करके ही जीवन का सृजन होगा

ईश्वर जब अवतार लेते हैं, तो साफ घोषणा करते हैं कि मैं अपनी आदिशक्ति के साथ इस संसार में आऊंगा। क्योंकि ब्रह्म भी बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए जब वो राम बनकर आते हैं, तो लक्ष्मी भी सीता बन जाती हैं। जब उनका अवतार कृष्ण के रूप में होता है, तो वही आद्या शक्ति रुक्मिणी और राधा का रूप ले लेती हैं। ईश्वर ने नारी शक्ति को बड़ा मान दिया है। मनुष्यों के पहले माता-पिता मनु और शतरूपा ने जब तपस्या की तब भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वर मांगो। तब मनु ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने कहा कि मेरे जैसा इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनके आऊंगा। तपस्या पति-पत्नी ने की थी, लेकिन पहला वर पति यानी मनु ने मांगा। शतरूपा हाथ जोड़कर खड़ी थीं। मनु को वरदान देने के बाद भगवान ने शतरूपा को देखा। 'सतरूपहिं बिलोकि कर जोरें। देबि मागु बरु जो रुचि तोरें'। शतरूपा हाथ जोड़कर खड़ी थीं, तो भगवान ने कहा कि आपकी भी जो इच्छा हो, वही मांग लो। यही ईश्वर की कार्य शैली है कि बराबर मान देना चाहिए। नारी-पुरुष बनकर ही प्रकृति अपना पूरा रूप लेती है। इसलिए इस नवरात्र में हम संकल्प करें कि हमारे जीवन में शक्ति का जो भी रूप हो, हम उसका सम्मान करेंगे और उसी के माध्यम से अपने जीवन का सृजन करेंगे।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

डिफ्रेंट एंगल • जीमेल के 20 साल पूरे हुए, पीछे लौटकर देखें इतने सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया...

जीमेल का स्टोरेज देखते ही देखते समस्या बन गया है

एजरा क्लेइन
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के कॉलमिस्ट

आजकल इंटरनेट इतना निरर्थक क्यों लगता है? 'द न्यूयॉर्कर' इसके लिए एल्गोरिदम के फीड में बदलाव को दोषी मानता है। वहीं 'वायर्ड' का कहना है, क्योंकि कंपनियों ने यूजर्स को सेवाएं देना बंद कर दी हैं और उनसे पैसे कमाने लगी हैं। 'एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू' ने विज्ञापन-आधारित बिजनेस मॉडल को दोषी करार दिया। 'द वर्ज' ने आरोपों की तर्जनी सर्च इंजनों पर तान दी। मैं सारी दलीलों से सहमत हूं। लेकिन एक और बात है : हमारा डिजिटल जीवन एक के बाद एक दयनीय कोठरियों की श्रृंखला बन गया है!

यहां कोठरियों से मेरा आशय आपके घर की उस जगह से है, जहां आप उन तमाम चीजों को ठूंसते रहते हैं, जिनके लिए कहीं और जगह नहीं होती। वह जगह गैरेज भी हो सकती है, कोई कमरा या अलमारियों की दराजें भी। वहां जमा की जाने वाली चीजों की कोई एक विशेषता नहीं होती। वहां आपके काम की चीजें भी हो सकती हैं और बेकार भी। लेकिन समय के साथ इन कोठरियों को करीने से साफ करके जमाना इतना कठिन हो जाता है कि आप इस काम को हमेशा के लिए स्थगित कर बैठते हैं।

इंटरनेट में भी कोठरियों का ऐसा ही युग शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते जीमेल के 20 साल पूरे हो गए। अगर आप 20 साल पहले इंटरनेट-यूजर नहीं थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता जब गूगल ने जीमेल शुरू करने की घोषणा की थी तो इस पर कैसा आश्चर्य जताया गया था। उस समय जब इनबॉक्स नियमित रूप से 15 मेगाबाइट पर टॉप-आउट हो जाते थे, तब गूगल एक मुफ्त गीगाबाइट की पेशकश कर रहा था! हर कोई इसका लाभ उठाना चाहता था, लेकिन यह केवल आमंत्रितों के लिए था। मुझे उन आरंभिक निमंत्रणों में से एक के लिए की गई भागदौड़ याद आती है। उसको पाकर मुझे लगा मैं बहुत भाग्यशाली हूं।

कुछ महीने पहले मैंने अपने उस जीमेल अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया। आज मेरे इनबॉक्स में दस लाख से अधिक ऐसे मैसेज हैं, जो मैंने कभी नहीं पढ़े। उनमें से अधिकांश जंक हैं, लेकिन सभी नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं बहुत सारे ऐसे ईमेल्स को मिस कर रहा था, जिन्हें मुझे देखना चाहिए था। सर्च ऑप्शन मेरी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या खोजना है। गूगल के एल्गोरिदम मुझे धोखा देने लगे थे। उन्हें जो चीज महत्वपूर्ण लगती, वह मेरी प्राथमिकता में नहीं होती।

जीमेल के विचार के साकार होने के पीछे एक आश्चर्यजनक तकनीकी सफलता थी। स्टोरेज की कीमतें लगातार घट रही थीं। 1985 में, एक गीगाबाइट हार्ड ड्राइव मेमोरी की कीमत लगभग 75,000 डॉलर थी। 1995 तक यह लगभग 750 डॉलर रह गई। 2004 में- यानी जिस वर्ष जीमेल शुरू हुआ- यह कुछ ही डॉलर रह गई थी। और आज तो यह कौड़ियों के मोल है और उलटे जीमेल 15 गीगाबाइट मुफ्त ऑफर करता है। क्या हमें इस पर आश्चर्य करना चाहिए? या इसे एक गड़बड़ी मानना चाहिए?

जीमेल ने हमसे वादा किया था कि वह हमें शक्तिशाली सर्च-टूल्स द्वारा संचालित एक बड़ा स्टोरेज मुहैया कराएगा, लेकिन वह लगभग हर ऑनलाइन चीज का साधन बन गया। आईक्लाउड के अनुसार, मेरे पास एपल के सर्वर पर 23,000 से अधिक फोटो और लगभग 2,000 वीडियो मौजूद हैं। मेरे पास स्पोटिफाई में कहीं न कहीं पसंद किए गए हजारों गाने हैं। मेरे नोट्स ऐप में कितना कुछ लिखा हुआ है। मैंने संदेशों में, व्हाट्सएप में, सिग्नल में, एक्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक डीएम में कितनी चैट्स सहेजी हुई हैं। इस आर्काइव में ऐसा बहुत कुछ है, जो मुझे पसंद होगा। ऐसा भी बहुत कुछ है, जिसे दोबारा खोजकर मुझे खुशी होगी। लेकिन उसे खोज निकालना अब मेरे बस का रोग नहीं। इसलिए मैंने कोशिशें करना भी छोड़ दिया है।

जो बात फाइलों से शुरू हुई थी, वह जल्द ही दोस्तों और परिवार तक आ गई। सोशल नेटवर्क ने उन लोगों से भी दोस्ती करना सरल बना दिया, जिनसे हम कभी नहीं मिले। हम एक साथ उन सबसे कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन इतने थोड़े-से प्रयास से एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने का विचार भ्रामक था। हम आज असंख्य लोगों से डिजिटली-कनेक्टेड होने के बावजूद बहुत अकेले हैं। किसी से निकटता के लिए समय की जरूरत है, और समय की न तो कीमत घटी है न मात्रा बढ़ी है। मेरी निष्क्रियता से डिजिटल दिग्गजों को मुनाफा होता है। मैं अधिक स्टोरेज के लिए एपल और गूगल को शुल्क देता हूं, क्योंकि उनकी सीमा के अंतर्गत रहने के लिए आवश्यक चीजों को हटाने में बहुत समय लगेगा। एल्गोरिदम मुझे मेरी ही मेमोरी-बुक्स बेचने की पेशकश करते हैं। मेरी फीड प्रभावशाली लोगों और विज्ञापनदाताओं के रिकमेंडेड कंटेंट से भरी है, जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं।

लेकिन मैं इस सबके लिए खुद ही को दोषी ठहराता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी डिजिटल लाइफ कोठरी की तरह हो। मैं चाहता हूं कि वह ऐसे बाग के जैसी लगे, जहां मैं खुद को तरोताजा करने के लिए जाता हूं। क्या यह मुमकिन है?

('द न्यूयॉर्क टाइम्स' से)

वेब भास्कर

दांतों की तरह दिखती हैं फ्रांस की ये चट्टानें, इनके ऊपर गोल्फ कोर्स भी

एट्रेटा (Étretat) फ्रांस के उत्तर में स्थित एक समुद्र तटीय कस्बा है। पर्यटन पर आधारित इस कस्बे की ये सफेद चट्टानें दूर से दांतों की तरह दिखाई देती हैं। हालांकि चट्टानों का आकार शुरू से ही ऐसा नहीं था। समय के साथ इनमें क्षरण हुआ, और दांतों जैसी आकृति उभर आई। इसलिए इस जगह को 'टीथ ऑफ एट्रेटा' नाम दिया गया है। फ्रांस में स्कूल की किताबों में भी इनका जिक्र है। पर्यटक इन चट्टानों पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बना गोल्फ कोर्स भी आकर्षण का केंद्र है। फोटोग्राफर्स की इस पसंदीदा जगह को कई प्रसिद्ध पेंटर्स अपने कैनवास पर भी उकेर चुके हैं।

• **तस्वीर साभार** : airpano.com

विश्लेषण • दोनों के मॉडलों में कुछ अंतर देख सकते हैं

यूपीए से एनडीए तक वेलफेयर योजनाओं में क्या-कुछ बदला

रीतिका खेड़ा
अर्थशास्त्री, दिल्ली आईआईटी में पढ़ाती हैं

पिछले दस सालों में कल्याणकारी योजनाओं का क्या रिकॉर्ड रहा है? अगर हम यूपीए काल (2004-14) की तुलना एनडीए काल के बीते दशक (2014-24) से करें तो कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। वास्तव में इन दोनों दशकों की मुख्य कल्याणकारी योजनाओं का चयन सत्ताधारी पार्टी की प्राथमिकताओं को दिखाने वाला है।

यूपीए के राज में 2005 में नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) कानून पारित हुआ था और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना। इसमें चार योजनाएं शामिल थी : जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)/आंगनवाड़ी और मातृत्व लाभ। इनमें भी अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन (जो वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाती हैं) को जोड़ दें तो कुल-मिलाकर मोटा-मोटी वह कल्याणकारी ढांचा सामने आता है, जो यूपीए सरकार में निर्मित हुआ था।

2014 में जब भाजपा की सरकार आई, तब उसकी अपनी प्राथमिकताएं थीं। उसके द्वारा चलाई गई योजनाओं में पांच मुख्य हैं : स्वच्छ भारत अभियान (जिसके तहत ही लोगों के घरों में सुविधाघर भी बने), पीएम-आवास, जल जीवन मिशन, बिजली व एलपीजी कनेक्शन (उज्ज्वला योजना) और पीएम-किसान। एक और बड़ी माने जाने वाली योजना आयुष्मान भारत है, लेकिन 2019 से 24 तक उस पर कुल खर्च 32,000 करोड़ रुपए ही रहा, जो कि इसी अवधि में पीएम-आवास पर एक वर्ष के औसत खर्च से लगभग आधा है। वहीं कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जिन पर सरकारी खर्च की जरूरत नहीं- जैसे कि महिलाओं के बैंक खाते खोलने के लिए जन-धन योजना।

यूपीए और एनडीए, इन दोनों के ही मॉडलों में कुछ अंतर रेखांकित किए जा सकते हैं। अगर हम आवास, शौचालय, पानी कनेक्शन की बात करें तो हर पात्र परिवार को उसका लाभ एक बार मिलते ही लक्ष्य पूरा हो जाता है। उज्ज्वला भी कुछ हद तक ऐसी ही योजना है। सिलेंडर का केवल पहला रिफिल मुफ्त है, आगे के रिफिल मोल चुकाने पर मिलते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय दामों के अनुसार बढ़ते-घटते हैं। चूंकि ये 'निजी गुड्स' हैं, जिन्हें सरकार लोगों को उपलब्ध करवा रही है, इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस मॉडल को 'न्यू वेलफेयरिज्म' नाम दिया है।

इसके विपरीत यूपीए की योजनाएं पुरानी सोच पर आधारित थीं, जिसमें सरकारें लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी लेती हैं। उनमें हर साल सभी पात्र परिवारों को लाभ मिलता है, जैसे नरेगा में 100 दिन काम, खाद्य सुरक्षा में हर माह अनाज, स्कूल या आंगनवाड़ी में बच्चों को रोज पका खाना इत्यादि।

दोनो मॉडल में एक और अंतर है- यूपीए-काल की ज्यादातर कल्याणकारी पहलों को कानूनी जामा दिया गया- सामाजिक सुरक्षा पेंशन को छोड़कर। जबकि दूसरे दशक की योजनाओं में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं हैं। एनडीए-काल की कुछ योजनाएं किसी न किसी रूप में यूपीए-काल में भी चल रही थीं। उदाहरण के लिए, जिसे आज पीएम-आवास योजना के नाम से जानते हैं, उसे पहले इंदिरा-आवास के नाम से चलाया जाता था। स्वच्छ भारत पहले निर्मल भारत था। बेशक कुछ योजनाएं नए सिरे से शुरू की गई हैं, जैसे पीएम-किसान। दोनों दशकों में कल्याणकारी योजनाओं पर कुल खर्च बहुत कम रहा।

एनडीए सरकार की प्रमुख योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान (जिसके तहत ही लोगों के घरों में सुविधाघर भी बने), पीएम-आवास, जल जीवन मिशन, बिजली व एलपीजी कनेक्शन (उज्ज्वला योजना) और पीएम-किसान रही हैं।

यूपीए के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और एनडीए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फर्क यह है कि पहले जहां 2-3 रुपए प्रति किलो की दर पर अनाज दिया जा रहा था, वहीं अब वह लगभग मुफ्त दिया जा रहा है। हां, 2021 की जनगणना के ना होने की वजह से जन वितरण प्रणाली में लगभग 10 करोड़ लोग जरूर अब तक छूटे हुए हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं। इस लेख के सहलेखक मोहम्मद असजद हैं)

नया विचार • देश की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है, अगले 30 साल देश के लिए अहम

2054 के भारत के लिए युवा 2024 में मतदान करें

मेघना पंत
पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार और वक्ता
meghnapant@yahoo.com

अपने जीवन में हम कई वाकियों को पीछे छोड़ आते हैं, कई बातें भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी पहला प्यार नहीं भूलता। पहली बरसात, पहला पक्का दोस्त और कॉलेज का पहला दिन, पहली सैलरी, पहला शिक्षक... लगभग यही रिश्ता अमूमन हर पहली चीज के साथ होता है। लेकिन अब, इस चुनावी साल में क्या हम अपना पहला वोट डालना भूल सकते हैं?

नहीं, हर्गिज नहीं। हमारे देश की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है और 65 फीसदी आबादी की उम्र 35 साल से कम है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सर्वोपरि है। लेकिन युवाओं को क्या सिर्फ इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है या मौलिक अधिकार? दरअसल यह दोनों है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यही युवा देश का भविष्य तय करेंगे। इसलिए, युवाओं को 2024 में एक ऐसे भारत के लिए मतदान करना चाहिए, जो उनके बच्चों को 2054 में विरासत में मिलेगा।

मतदान हमें सशक्त बनाता है। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रतिनिधियों को चुनकर मतदाता उन्हें उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जवाबदेही जरूरी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि चुने गए प्रतिनिधि लोगों के हित में काम करें। इससे युवाओं को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करने का बढ़ावा मिल सकता है, उनकी चिंताएं दूर हो सकती हैं और अंततः समाज की बेहतरी होगी।

मतदान के अधिकार का प्रयोग करके युवा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज, चिंताओं, आकांक्षाओं को सत्ता के गलियारों में प्रतिनिधित्व मिले। निर्णय लेने की प्रक्रिया में यह युवाओं की आवाज बनती है। युवाओं में वह क्षमता है कि वे उन पर असर डालने वाले मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को एक दिशा दिखा सकें।

मतदान भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है, जिससे समावेशिता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक न्याय, समानता व समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध नेताओं को चुनकर, युवा अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं जो हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हैं, सतत विकास को बढ़ावा देते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में काम करते हैं।

हमारे देश का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां मजबूत सत्ताओं को चुनौती और परिवर्तनकारी सुधारों को प्रभावित करने में मतदान महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के संघर्ष से लेकर सामाजिक न्याय के आंदोलनों तक, बैलेट बॉक्स अक्सर बदलाव की लड़ाई का मैदान रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को मतदान के अधिकार के लिए कितनी कड़ी लड़ाई लड़ी? विशेष रूप से युवा महिलाओं को घर से बाहर निकलकर उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करने के लिए मतदान करना चाहिए, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी।

अगर आप अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों को मतदान करने के लिए कहें। इससे उनमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना पैदा होगी। यह उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

याद रखिए, मतदान हमारा कर्तव्य और विशेषाधिकार भी है। युवा भारत के पास देश के भविष्य की कुंजी है। भारत की लोकतांत्रिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में, यह उनका कर्तव्य है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, सोच-समझकर और सक्रिय रूप से अपना वोट डालें और अपनी आवाज सुनें।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

गाजा युद्ध
शांति की उम्मीद

गाजा में शांति की उम्मीद बढ़ गई है। 6 महीने से जारी भयानक युद्ध और उसके कारण पैदा मानवीय संकट के बाद अब इज़राइल ने दक्षिण गाजा से अपने सैनिक वापस बुलाने का फैसला किया है। इससे युद्ध की तीव्रता में व्यापक कमी आएगी। 32,000 लोगों की मौत, 75,000 के घायल होने तथा 75 प्रतिशत जनसंख्या के विस्थापित होने के बाद अब इज़राइल ने दक्षिणी गाजा से अपने सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की है। इज़राइल और हमास के बीच जारी युद्ध में संभावित महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में यह निर्णय तनाव घटाने के लिए लगातार बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण आया है। दोनों पक्षों के बीच भयानक टकराव में फंसे सिविलियनों को बमबारी का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है तथा वे अकल्पनीय आघात एवं पीड़ा का शिकार हुए हैं। इज़राइल द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुलाने के साथ युद्ध के 'मनुष्यों पर प्रभाव' के आंकलन तथा समस्या के टिकाऊ समाधान के प्रयास तत्काल होने चाहिए। युद्ध के दौरान दक्षिण गाजा के सिविलियनों को लगातार हवाई हमलों, बमबारी और जमीनी हमलों का सामना करना पड़ा जिसके कारण असाधारण जन हानि हुई। हमलों की अनियंत्रित प्रकृति ने परिवारों को उजाड़ दिया है, घर खंडहर बन गए हैं और समुदाय विभाजित हुए हैं। युद्ध में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। इज़राइल में गाजा सीमा से सटे समुदायों को हमेशा हमास तथा उससे अलग हुए उग्रवादी समूहों के राकेट हमलों का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही युद्ध ने पहले से मौजूद घाव और हरे किए हैं तथा दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी बढ़ाई है। दशकों से समाधान की प्रतीक्षा कर रही समस्याओं और क्षेत्रीय विवादों ने हिंसा के दुष्चक्र पैदा किए हैं। इससे टकराव का दुष्चक्र तोड़ना तथा दोनों पक्षों के

बीच विश्वास बहाल करना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

इज़राइल द्वारा सैनिकों की वापसी का निर्णय संभवत: अनेक कारकों का नतीजा है जिसमें आंतरिक व बाहरी दबाव शामिल हैं। इनमें दो घटनाओं ने इज़राइल के इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1 अप्रैल को सहायता कर्मियों पर हुए हमले ने एक प्रेरक का काम किया जिससे अंतरराष्ट्रीय निन्दा व आलोचना बहुत बढ़ गई। इस हमले से व्यापक रूप से लोगों का गुस्सा भड़का और जवाबदेही की मांग की गई। इससे इज़राइल पर सैनिक रणनीति की समीक्षा करने तथा राजनयिक समाधानों को प्राथमिकता देने का दबाव पड़ा। दूसरा, इज़राइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने परिवर्तन के लिए घरेलू दबाव डाला। महीनों से जारी ये प्रदर्शन नेतनयाहू के नेतृत्व के प्रति बढ़ती निराशा को अभिव्यक्त करते हैं। इस बीच गाजा गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इसमें व्यापक गरीबी, खाद्य असुरक्षा तथा सफाई व स्वास्थ्यरक्षा सुविधाओं की भारी कमी शामिल हैं। अब रक्तपात से राहत की धुंधली उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन स्थाई शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है। ऐसे में इज़राइल और हमास, दोनों को संवाद, लेन-देन तथा समझौते के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए जमीनी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। राजनयिक प्रयासों के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसे शांति-निर्माण पहलों का समर्थन करने के साथ ही टकराव से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता देनी चाहिए। इज़राइली सैनिकों की वापसी के साथ ही सभी पक्षों की कठिनाइयां दूर करने के लिए टिकाऊ प्रयास होने चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिंसा का दुष्चक्र समाप्त हो।

माफिया की मौत से भाजपा लाभान्वित

माफिया डॉन की मौत पर दु:ख प्रकट करने वालों की तुलना में इससे राहत अनुभव करने वालों का मौन ज्यादा मुखर व महत्वपूर्ण है। इससे उत्तर प्रदेश में भाजपा लाभान्वित हो सकती है।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं)

अक्सर कहा जाता है कि कभी-कभी शोर की तुलना में मौन ज्यादा मुखर होता है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट फेल होने के कारण हुई मौत पर दु:ख प्रकट करने वालों की तुलना में इससे राहत अनुभव करने वालों का मौन ज्यादा मुखर व महत्वपूर्ण है। उसने पूरे क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य कायम किया था और अदालतों ने उसे कई मामलों में लंबी सजा दी थी। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्तार अंसारी की मौत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी-भाजपा को चुनावों में लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से माफिया तत्वों और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और मुख्तार अंसारी को मिली सजा इसका एक प्रमाण है। माफिया डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित मुहम्मदाबाद में अंतिम संस्कार में शोक जताने वालों की संख्या 30,000 या संभवत: इससे भी अधिक थी। इन लोगों ने दिवंगत मुख्तार अंसारी के लिए 'माफिया नहीं, मसीहा हैं' के नारे लगाए।

ऐसी ही भावनायें माफिया से राजनेता बने उत्तर प्रदेश के एक और व्यक्ति अतीक अहमद की हत्या पर भी व्यक्त की गई थीं। इस बीच उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं ने जेल में बंद गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी-सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ कर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वोटों पर नजर रखने वाली उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी-बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी इस दृष्टिकोण से अंसारी की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है कि मृतक के परिवारीजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसे जहर दिया गया था।

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश 'सरकारी अराजकता' के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन राज्य में रहने वाले बहुत से लोगों की इससे सहमति जरूरी नहीं है। मुख्तार अंसारी दशकों से पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कुख्यात गैंगस्टर माना जाता था। इस क्षेत्र में अतीत में अन्य गैंगस्टर से राजनेता बने लोग सक्रिय हुए थे। इनमें से कई के साथ उसके संबंध थे, जबकि उस पर कई की हत्या कराने के आरोप भी लगे थे। मुख्तार अंसारी को वर्ष 2005 में हिंसा भड़काने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से उसे पंजाब और उत्तर प्रदेश की अनेक जेलों में रखा गया था। अपने राजनीतिक कॅरियर में मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रहा था। पहली बार उसने बहुजन समाज पार्टी-बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इसके बाद उसे बसपा से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वह चुनाव जीतता रहा।

2002 और 2007 में उसे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय मिली। उसने 2012 में अपनी पार्टी 'कौमी एकता दल' का गठन किया और उससे विधायक बना। इसके बाद उसने अपनी पार्टी का बसपा में विलय कर दिया और पुन: बसपा में शामिल हो गया। 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे ने पिता के स्थान पर चुनाव लड़ा और वह मऊ विधानसभा सीट से विधायक बनने में सफल रहा। मुख्तार अंसारी की मौत पर राहत महसूस करने वाले लोगों का मौन उसे मसीहा मानने और मौत पर शोक मनाने वालों के शोर-शराबे की तुलना में ज्यादा मुखर और महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस बात के कोई संकेत नहीं है कि जेल में बंद माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की मौत में राज्य की कोई संलिप्तता है, पर उसकी मौत से राहत महसूस करने वाले लोग इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर प्रशासन को देते हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने माफियाओं और अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान चलाया है और इसी के चलते मुख्तार समेत अनेक अपराधियों व गैंगस्टरों को लंबी सजा मिली। लोकसभा चुनाव के पहले माफिया मुख्तार अंसारी की मौत ने राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल दिया है।

अंसारी को 63 आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया था जिनमें से 14 हत्या के मामले थे। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने से पहले ये मुकदमे अदालतों में लंबित थे। इसके बाद मुकदमों की सुनवाई में तेजी आई और सितंबर, 2022 के बाद से इन आठ मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा मिली। उसके खिलाफ लंबित गंभीर मामलों में भारतीय जनता पार्टी-भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या का मुकदमा था। उस पर 1991 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का आरोप भी था। कृष्णानंद राय और अंसारी के बीच क्षेत्र में सरकारी ठेकों पर वर्चस्व कायम करने के लिए टकराव होता रहता था क्योंकि इनसे भारी मुनाफा प्राप्त होता था। सरकारी ठेके प्राप्त करने के लिए आतंक का सहारा लिया जाता था और अपहरण कर फिरौती की धमकियां दी जाती थीं। अपराधी और माफिया गिरोहों के बीच 'गैंग वार' केवल गाजीपुर जिले तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इसके तार उत्तर प्रदेश में पूरब के लगभग सभी जिलों तक फैले थे। इसके साथ ही राय और अंसारी गिरोहों के बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी झड़प हुई थी।

देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश 545 सदस्यों वाली लोकसभा में 80 सांसद भेजता है जिससे प्रदेश का राजनीतिक महत्व स्पष्ट होता है। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी भाजपा की प्रबल बहुमत वाली सरकार ने हर प्रकार के अपराधी तत्वों और माफिया तत्वों के खिलाफ शुरू से ही कठोरतम अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से गैंगस्टरों का पूरी तरह से सफाया करना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन प्रयासों से प्रदेश की कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास बहुत बड़ी सीमा तक बहाल हुआ है। भाजपा सरकार आने के पहले प्रदेश में अक्सर दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, लेकिन आज यह सब अतीत की बात हो गई है। आज सड़के जाम कर आपराधिक गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर लूट और डकैती जैसी घटनायें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। कानून व्यवस्था में सुधार तथा प्रदेश की चहुंमुखी आर्थिक प्रगति के चलते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा को 2022 में विधानसभा चुनाव में रिकार्डतोड सफलता मिली। योगी सरकार के सात साल के शासन में माफिया तत्वों के सफाए का भाजपा को भारी लाभ मिलना तय है। मुख्तार अंसारी की मौत ने समाजवादी पार्टी-नीत विपक्ष के लिए स्थितियां ज्यादा कठिन बना दी हैं। सपा और उसके सहयोगियों को और अधिक अल्पसंख्यक वोट मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वे पहले ही उसके पीछे एकजुट हो गए हैं। लेकिन माफिया और अपराधी तत्वों के सफाए ने निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ सरकार की 'प्रभावशीलता' के बारे में कानून का पालन करने वाले आम नागरिकों में बहुत अच्छा संदेश दिया है। प्रशासन और पुलिस ने विगत वर्षों में अपराधों की जांच के साथ ही वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रयोग कर अभियोजन को सटीक बनाया है। इसके परिणामस्वरूप सालों से लंबित आपराधिक मामलों में अदालतें अपराधियों को कठोर सजा दे रही हैं। इससे समाज-विरोधी तत्व गंभीर अपराध करने के मामले में हतोत्साहित भी हुए हैं।

अब भी स्थानीय लोगों के मन में अंसारी के खुले वाहनों में घूमने तथा कर्फ्यू के बावजूद हथियार लहराते और एक खास समुदाय को डराने की छवियां बनी हुई हैं। सरकारी बुलडोजर अंसारी के साम्राज्य के कंक्रीट में ढले स्तंभ ढहा रहे हैं। उसकी मौत से पहले ही ऐसे दृश्यों ने सरकारी मशीनरी में जनता का विश्वास बढ़ा दिया था। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजरों ने उन लोगों में भी विश्वास पैदा किया है जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित नहीं थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार सबका साथ, सबका विकास और तुष्टीकरण किसी का नहीं की नीति पर चलती रही है। उसने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी पंथ या समुदाय के साथ पक्षपात नहीं किया है। इन सभी चीजों को देखते हुए मुख्तार अंसारी की मौत भाजपा को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में निर्णायक लाभ दे सकती है।

कैंसर से जूझते व्यक्तियों की मानसिक दशा

योग, प्राणायाम और लंबी सांस लेने की तकनीक शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं।

रवि वलूरी
(लेखक, रेलवे से संबद्ध हैं)

दादा दादी के पास यूरोप की वार्षिक यात्राओं के लिए दस साल का वीजा था और वे बीमा कराने के लिए मेडिकल जांच से गुजर रहे थे। एक गमगीन मां ने इंग्लैंड और हॉलैंड में अपने बेटों को फोन करके बताया कि उनके पिता कैंसर से पीड़ित हैं। भावनात्मक रूप से परेशान माता-पिता को समझाने के लिए बेटे दौड़ पड़े। लेकिन कैंसर से लड़ने का वीज़ा कहां है?

पिता फिलहाल कीमोथेरेपी और ब्रेविंग रेडिएशन थेरेपी से गुजर रहे हैं। माँ पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है और वह उच्च रक्तचाप, उच्च शर्करा स्तर, रुक-रुक कर होने वाली खांसी जैसी असंख्य बीमारियों का शिकार हो गई है और एक तरह से मानसिक रूप से परेशान हो गई है। मैं क्यों? कोई भी मरीज यह सवाल पूछेगा और परिवार के लिए यह खबर सुनाना दुखदायी है। कैंसर, जिसे घातक ट्यूमर या घातक नियोप्लाज्म के रूप में भी जाना जाता है, बीमारियों का एक समूह है जिसमें मानव शरीर के अन्य भागों में फैलने और प्रवेश करने की प्रवृत्ति के साथ असामान्य वृद्धि होती है। सूर्य राशि बन जाती है रोगग्रस्त!

जिनेवा स्थित यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर एंड कंट्रोल के 155 देशों में फैले लगभग 800 सदस्य हैं। संस्था ज़ोर देकर कहती है कि बीमारी का शीघ्र पता लगाना और उपशामक उपाय बीमारी को चुनौती दे सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने विश्लेषण किया है कि भारत में कैंसर से लगभग 7 लाख मौतें होती हैं और हर साल लगभग 10 लाख लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्टों का दावा है कि महिलाओं में स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा और डिम्बग्रंथि कैंसर बेहद प्रचलित है। तम्बाकू का सेवन, धूम्रपान और शराब

का अत्यधिक सेवन अन्य सहायक कारक हैं जो कैंसर में व्यापक वृद्धि का कारण बन रहे हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने तम्बाकू के उपयोग को %विकसित देशों में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोकथाम योग्य जोखिम और दुनिया भर में समय से पहले मौत का एक महत्वपूर्ण कारण% बताया है। कई देशों ने तम्बाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए उपयोग और बिक्री प्रतिबंधों के साथ-साथ पैकेजिंग पर मुद्रित बोल्ड चेतावनी संदेशों के साथ कड़े उपाय अपनाए हैं। धूम्रपान पर्यावरण को प्रदूषित करने के अलावा स्वरयंत्र और मुंह के कैंसर और उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। द्वितीयक धूम्रपान निष्क्रिय धूम्रपान करने वालों के लिए भी उतना ही दुर्बल करने वाला है। डब्ल्यूएचओ का तर्क है कि अविकसित देशों में बेची जाने वाली सिगरेट में टार की मात्रा अधिक होती है और इन्हें फ़िल्टर किए जाने की संभावना कम होती है, जिससे संभावित रूप से तंबाकू और धूम्रपान से संबंधित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है।

एक चिंतित रोगी प्रार्थना करता है और आशा करता है कि विकास सौम्य हो। हालाँकि, कभी-कभी वे गलत स्थान पर होते हैं और ट्यूमर घातक होता है। मरीज को खबर कैसे दी जाए? रोगी और परिवार को सच्चाई बताने के लिए अत्यधिक कौशल और निपुणता की आवश्यकता होती है क्योंकि दोनों ही अत्यधिक संकट में हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रंजना श्रीवास्तव का मानना है कि खबर को अत्यधिक सावधानी, सावधानी और मानवीय स्पर्श के साथ पेश किया जाना चाहिए। इस घातक बीमारी से निपटने के लिए शीघ्र पता लगाने और शीघ्र इलाज के अलावा जीवनशैली में बदलाव भी मौलिक है।

डॉक्टर यकीनन धूम्रपान को मना करते हैं और मरीज को शराब से परहेज करने की सलाह देते हैं। व्यक्तियों को आहार और व्यायाम का एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है जिसका मानव शरीर और दिमाग पर एनाल्जेसिक प्रभाव पड़ता है। योग का अभ्यास (एक योग्य चिकित्सक के तहत), प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया जैसी श्वास तकनीकें मानव शरीर को विषहरण करने में मदद करती हैं। चाहे रोगी हो या स्वस्थ, मनुष्य को सकारात्मक संगति और विचारों से घिरा रहना चाहिए।

मन को शांत और संतुष्ट रखने का प्रबंधन मानसिक रूप से मजबूत और मजबूत होने में मदद करता है। कैंसर से बचे लोगों और उनके जीवन की कहानियों का प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना एक जीवन नौका के रूप में कार्य करता है। समय छोटा हो रहा है। लेकिन हर दिन जब मैं इस कैंसर को चुनौती देती हूं, वह मेरे लिए एक जीत है, करिश्माई अभिनेत्री इंग्रिड बर्गमैन ने कहा।

आप की बात

जल-सेवा

भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी का पात्र अवश्य रखे। पक्षियों के लिए दीवार पर या घर मे जल पात्र टांग कर एवं पशुओं के लिए घर के बाहर हौदी या बड़ा जल पात्र भर कर रखा जाए ताकि भीषण गर्मी में उनको जल आसानी से मिल सके। यह जल-सेवा पुनीत कार्य है। पशु पक्षियों को भी धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना इंसान का। पशु-पक्षियों में अद्भुत शक्ति होती है जिसका लाभ मनुष्यों को मिल सकता है। वे भूगर्भीय हलचलों जैसे हादसों से सचेत कर देते हैं तथा मालिक के प्रति वफादारी भी निभाते है। पशु-पक्षियों को कैद कर रखना अनुचित है। पक्षियों का अकस्मात ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर कोलाहल करना तथा पशुओं के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आना जैसी घटनायें प्रकृति में परिवर्तन का संकेत देती हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आंधी-तूफान, भारी बारिश या भूकंप जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान पशु-पक्षियों को मनुष्यों से पहले हो जाता है। उनके व्यवहार के अध्ययन के लिए उनको अपने आसपास रखना, उनके भोजन का प्रबंध करना तथा गर्मियों में उनके लिए जल-सेवा जरूरी है। पशु-पक्षियों के साथ प्राकृतिक परिवेश में रहना मनुष्य को अनेक तनावों से मुक्त कर उसका जीवन सहज बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है।

– **संजय वर्मा,** मनावर

मोदी का आत्मविश्वास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में किए गए अपने काम को महज एक नमूना और मुख्य भोजन से पहले वाला ऐपेटाइज़र बताया है। उन्होंने ते कहा है कि अभी तो आपके सामने पूरी थाली का भोजन आना बाकी है। मोदी का कथन दिखाता है कि उनके अंदर कितना आत्मविश्वास है। वे आज हर सभा में कहते हैं कि यह 10 साल मात्र ट्रेलर थे, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। मोदी का यह आत्मविश्वास जनता में बहुत प्रसन्नता, उम्मीदों तथा भविष्य के प्रति विश्वास भरने का काम करता है। लेकिन अनेक ऐसे विपक्षी नेता मोदी के इस आत्मविश्वास से बहुत भयभीत हैं जिन्होंने राजनीति को अपना घर भरने, जनता को लूटने तथा अपने परिवार को अमीर बनाने का साधन मान लिया था। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भयभीत होना भी चाहिए क्योंकि मोदी बार-बार यह भी कहते हैं कि जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसे लौटाना भी पड़ेगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता की बन गई है। ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में देश की जनता हर जगह मोदी को ही उम्मीदवार मान कर वोट देगी, भले ही वह अपने पुराने या नए उम्मीदवार से नाराज ही क्यों न हो।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

संतुलित दृष्टिकोण

राजस्थान व गुजरात में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड-सोहन चिड़िया के लिए खतरनाक माने गए सोलर एनर्जी प्रॉजेक्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाया है। यह पर्यावरण, परिस्थितिकी और विकास को लेकर न्यायपालिका की नई सोच का संकेत करता है। यह शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ कानूनी किताबों में ही उलझा हुआ नहीं रहकर देश-काल और परिस्थिति के हिसाब से उचित दृष्टिकोण अपना कर फैसला दे रहा है। ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि हम एक पहलू के प्रति ही दूराग्रह रखकर वर्तमान समय की जरूरत को नजरंदाज करेंगे तो वह भी हमारे लिए घातक होगा। सोन चिरैया के अलावा भी कई अन्य पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं और इसके लिए कोई क्षेत्र विशेष जिम्मेदार नहीं है। अनेक लोगों में बड़ी संख्या में पक्षियों को मार कर अपना भोजन बना लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है । इसके चलते भी यह सुंदर पक्षी नष्ट होते जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी मार कर खाने में लोग गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे में जीव-जंतुओं की रक्षा और प्रजाति संवर्धन के लिए जागरूकता एवं शाकाहार के पक्ष में अभियान चलाने की जरूरत है।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

शत-प्रतिशत मतदान

भारत सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। यह बात सबको पता है। लेकिन देश का आम नागरिक रोजमर्रा की जिन्दगी में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकारों पर गौर नहीं करता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। हम अपने सभी संविधान प्रदत्त अधिकारों को जानकर उनका उपयोग कर सकते हैं। सरकार चुनने के लिए मतदान करना हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। आम चुनाव के रूप में सामने आए इस लोकतंत्र के त्योहार में किसी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता या समर्थक बनाने से कई गुना अच्छा होगा कि हर नागरिक मतदाता निष्पक्ष होकर अपना मतदान उसे करे जो उसके और देशहित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। हमें उसे वोट देना चाहिए जो वास्तविक सेवक बनकर पूरे आत्म समर्पण से देश की जनता के लिए कुछ नया करे जिससे सबका भविष्य उज्जवल हो सके। आप सिर्फ मतदाता न बनकर रह जाए बल्कि देश के लोकतंत्र में सामने आएं, नेतृत्व क्षमता विकसित करें तथा समस्याओं के समाधान में योगदान करें। शत-प्रतिशत मतदान हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

-**अवनीश कुमार गुप्ता,** आजमगढ़

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://epaper.dainikpioneer.com

कल्पमेधा

युद्ध शुरू करने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि मनुष्य की जिंदगी अमूल्य है।

– बर्ट्रेंड रसेल

बेअसर दलील

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत के बाद माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी गलत नहीं है। हवाला के जरिए गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भेजे गए पैसों का सीधा संबंध बेशक अरविंद केजरीवाल से न हो, पर पार्टी का संयोजक होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत और अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने शुरू में ही यह बात स्पष्ट भी कर दी थी कि चूंकि याचिका जमानत के लिए नहीं, बल्कि गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई है, इसलिए सुनवाई उसी पर होगी। अदालत ने केजरीवाल की तरफ से पेश तमाम दलीलों को बिंदुवार खारिज करते हुए गिरफ्तारी को उचित ठहराया। यानी अभी केजरीवाल को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जाहिर है, यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पर कहा जा रहा है कि पार्टी इस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में करेगी। वहां भी उसकी इन दलीलों को कितना वाजिब माना जाएगा, कहना मुश्किल है।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया, इसलिए संवैधानिक तकाजे की दुहाई देते हुए दलील दी जा रही है कि इस तरह एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि कथित शराब घोटाले में पैसे के लेनदेन का कोई तार अरविंद केजरीवाल से जुड़ा नहीं पाया गया है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी गलत है। मगर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का मुखिया होने के नाते उनकी भी जवाबदेही बनती है। अगर आम आदमी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी, तो वहां भी उसे उच्च न्यायालय के इस फैसले को गलत साबित करना मुश्किल हो सकता है। अगर केजरीवाल अपनी जमानत की याचिका लगाते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय का रुख सकारात्मक रहने की उम्मीद की जा सकती है। मगर आम आदमी पार्टी यह साबित करने पर तुली हुई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गलत है। अगर उच्च न्यायालय यह दलील मान लेता, तो कथित शराब घोटाले का सारा मामला ही कमजोर हो जाता। इस तरह दूसरे लोगों की गिरफ्तारी भी अवैध साबित हो जाती। मगर उसकी ये चतुराई भरी दलीलें बेअसर साबित हुईं।

शराब घोटाले को शुरू से ही राजनीतिक रंग दे दिया गया है। जबसे चुनावी चंदे का खुलासा हुआ है, तबसे आम आदमी पार्टी को यह कहने का एक आधार मिल गया है कि जिस व्यक्ति को इसी मामले में पहले गिरफ्तार किया गया, उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया, बाद में उसी ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी रकम चंदे के रूप में दे दी और फिर सरकारी गवाह बन गया तो उसे छोड़ दिया गया। मगर अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह मामला दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार नहीं, बल्कि केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय है। यह ठीक है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मगर इससे शराब घोटाले की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अगर आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि इस मामले में उसके नेता बेदाग हैं, तो उन्हें इस मामले की जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए।

अभिव्यक्ति का पक्ष

संवाद और संचार के संसाधनों के रूप में सोशल मीडिया मंचों के विस्तार के साथ-साथ एक समस्या यह उभरी है कि उस पर अभिव्यक्तियों को किस रूप में देखा जाए। कई बार यूट्यूब, फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी मसले को लेकर जाहिर की गई राय को आपत्तिजनक सामग्री के तौर पर देखा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मगर फिर सवाल उठा कि अगर स्वतंत्र मंचों पर जाहिर किए गए विचारों को इस तरह बाधित किया जाएगा तो अभिव्यक्ति के अधिकार का क्या मतलब रह जाएगा। फिर ऐसे आरोपों में लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एक चलन बनी, तो यह कहां जाकर थमेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के एक मामले में साफ कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे, तो कल्पना कीजिए कि कितने लोगों को जेल होगी।

अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पिछले कुछ समय से आशंका जाहिर की जा रही है कि सरकारें सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ अवांछित गतिविधियों और झूठी खबरों की आड़ में आलोचना के सभी स्वरों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगेगा और लोकतंत्र कमजोर होगा। मगर अब शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक युवक को जमानत दे दी है। उस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने विचार की अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया और उसने अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। सच है कि आज सोशल मीडिया पर कई बार कुछ अपरिपक्व लोग अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी की गरिमा का हनन हो सकता है। मगर एक लोकतांत्रिक समाज और शासन में खासकर सरकारों को अधिकतम सीमा तक सहनशील होने की जरूरत है। आलोचना से सरकार को भी अपना रुख सुधारने का मौका मिलता है। जबकि अभिव्यक्ति में अवरोध लोकतंत्र को कमजोर करता है।

सौर कचरे से बढ़ती मुश्किलें

अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजंसी के मुताबिक बड़ी मात्रा में सौर पैनलों के उत्पादन और संस्थापन के चलते 2030 तक इससे निकलने वाले अपशिष्टों की अच्छी-खासी वृद्धि होगी, जिसके असर से पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने का अनुमान है।

अखिलेश आर्येंदु

बिजली की किल्लत से पार पाने के लिए अपनाए जा रहे मौजूदा सौर पैनलों को पच्चीस से तीस वर्ष तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, मगर मौसम की खराबी, दुर्घटनाओं या दूसरी वजहों से ये अनुमानित समय से पहले भी खराब हो सकते हैं। खराब सौर पैनल काम करना बंद करते ही पर्यावरण प्रदूषण की वजह बन जाते हैं। प्लास्टिक, वाहन, कारखानों और ई-कचरे के बाद पर्यावरण को प्रदूषित करने में सौर पैनलों की अहम भूमिका मानी जा रही है। गौरतलब है कि सौर पैनल में सिलिकान, कांच, एल्युमीनियम, सीसा, तांबा और कैडमियम का मिश्रण होता है, जो आसानी से पुनर्चक्रित नहीं होता। इसलिए अभी से इस पर गहन शोध और समझ बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजंसी के मुताबिक बड़ी मात्रा में सौर पैनलों के उत्पादन और संस्थापन के चलते 2030 तक इससे निकलने वाले अपशिष्टों की अच्छी-खासी वृद्धि होगी, जिसके असर से पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने का अनुमान है। इसलिए ऐसे पैनल बनाने की जरूरत है, जो लंबे समय तक चल सकें यानी अपशिष्ट बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो। शोध के अनुसार भारत का सौर कचरा 2030 तक छह सौ किलोटन हो जाने की उम्मीद है। यह मात्रा 2050 तक बत्तीस गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तकरीबन उन्नीस हजार किलोटन संचयी कचरा निकलेगा। 2040 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 74 फीसद हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा सोलर पैनल अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह 2050 तक पैदा होने वाले संचयी कचरे का 77 फीसद नई क्षमताओं की वजह से होगा।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और स्वतंत्र शोध संस्थान 'काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर' (सीईईडब्ल्यू) द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक यह ओलंपिक आकार के 720 स्वीमिंग पूल (तरणताल) भरने के बराबर है। शोध की रपट के मुताबिक कचरे का 67 फीसद पांच राज्यों राजस्थान, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से पैदा होगा। 2030 तक पैदा होने वाले कचरे में राजस्थान का हिस्सा 24 फीसद, गुजरात का 16 फीसद और कर्नाटक का हिस्सा 12 फीसद होगा। 'भारत के सौर उद्योग में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को सक्षम करना: सौर अपशिष्ट मात्रा का आकलन' वाले अध्ययन में कहा गया है कि भारत में मौजूदा स्थापित 66.7 गीगावाट क्षमता से पहले ही 100 किलोटन कचरा पैदा हो रहा है, जो 2030 तक बढ़कर 340 किलो टन हो जाएगा। इसमें तकरीबन दस किलो टन सिलिकान, 12 से 18 किलो टन चांदी और 16 टन कैडमियम और टेलरियम होगा। इन तत्त्वों को दुबारा प्राप्त करने के लिए सौर कचरे का पुनर्चक्रण करने से आयात निर्भरता कम होगी और भारत की खनिज सुरक्षा बढ़ेगी।

शोध में पाया गया है कि शेष 260 किलो कचरा 2024 से 2030 के बीच स्थापित होने वाली नई क्षमताओं से पैदा होगा। अध्ययन के मुताबिक सौर कचरा 2050 तक बढ़कर 19,000 किलो टन हो जाएगा, जिसमें से 77 फीसद हिस्सा नई क्षमताओं से पैदा होगा। सीईईडब्लू ने कहा है कि भारत में सौर उद्योग के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की अग्रणी और जुझारू सौर

आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने का एक अवसर है। पच्चीस वर्षों में 7.8 करोड़ टन सौर फोटोवोल्टिक कचरा निकलने की संभावना वैज्ञानिक बता रहे हैं, जिसका 2050 तक पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण किया जा सकता है, हालांकि, यह एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सौर पैनलों का समग्र पुनर्चक्रण

> बिजली की समस्या से पार पाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में बहुत बड़ी मात्रा में सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसलिए सौर पैनल अपशिष्ट को खपाने के लिए अभी से सोचना जरूरी है। दुनिया के तमाम देशों में सौर प्रणालियों का उचित प्रबंधन, पुनर्चक्रण और निपटान सरकारी नीतियों और कानूनों के जरिए निर्देशित होता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और आस्ट्रेलिया में सौर पैनल पुनर्चक्रण के लिए निजी या अनिवार्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में भी इसके लिए बेहतर नीतियां और नियम बनाकर उन्हें लागू करने की जरूरत है।

वैश्विक स्तर पर अभी भी लागू नहीं किया जा सका है। इसकी वजह है दुनिया के बाजारों में उचित बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय नियमों का न बनाया जा सकना। जाहिर है, सौर अपशिष्ट आने वाले वक्त में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

बिजली की समस्या से पार पाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में बहुत बड़ी मात्रा में सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसलिए सौर पैनल अपशिष्ट को खपाने के लिए अभी से सोचना जरूरी है। दुनिया के तमाम देशों में सौर प्रणालियों का उचित प्रबंधन, पुनर्चक्रण और निपटान सरकारी नीतियों और कानूनों के जरिए निर्देशित होता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और आस्ट्रेलिया में सौर पैनल पुनर्चक्रण के लिए निजी या अनिवार्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में भी इसके लिए बेहतर नीतियां और नियम बनाकर उन्हें लागू करने की जरूरत है।

गौरतलब है कि भारत ने 2030 तक लगभग 292 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है, जिसमें पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारणों से सौर पीवी कचरा प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन का विकास ईपीआर (विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी) कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है, जो उत्पादकों को उनके जीवन के अंत के उत्पादों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर कचरे के पर्यावरणीय असर को कम करने के लिए एक और बेहतर समाधान बंद-लूप प्रणाली विकसित करना जरूरी है। एक निरापद सौर प्रणाली विकसित कर इससे बढ़ने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है। सौर पैनल लगाने वाले व्यक्ति के लिए यह जानना भी जरूरी है कि उसके सौर पैनल की उम्र और उसमें इस्तेमाल होने वाले तत्त्व किस स्तर के हैं। खराब होने पर उनका निपटान किस तरह और कहां करना चाहिए।

यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि सौर कचरा निपटान का बेहतर समाधान क्या है। इसमें बेहतर रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे सौर पैनलों की उम्र बढ़ती है। इसी के साथ सौर प्रणाली कचरा प्रबंधन के लिए आसानी से पुनर्चक्रित सौर पैनलों पर लगातार अनुसंधान और विकास होना चाहिए। सौर पैनल के आधुनिक और टिकाऊ माडल ही बाजार में बेचने की मंजूरी दी जानी चाहिए। सौर पैनलों के दो बेहतर तरीकों को अपनाया जा सकता है। इसमें पारंपरिक थोक सामग्री पुनर्चक्रण है, जिसमें कचरे को कुचलना, छानना और कतरना शामिल है। लेकिन अगर पैनल कांच, तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी और सिलिकान के मिश्रण से बना है, तो इस तरीके से इसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। दूसरा तरीका उच्च-मूल्य पुनर्चक्रण का है। इसमें थर्मल, रासायनिक और यांत्रिक तरीका अपनाया जाता है। यह तरीका हर तरह से बेहतर है। इसमें रासायनिक विधि से चांदी और सिलिकान को भी पुनर्चक्रित किया जा सकता है।

सौर पैनल भारत में सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों को चलाने में बिजली के एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाए गए हैं। इनसे बिजली पर होने वाले खर्च में कमी आ रही है। आम और खास दोनों को घरेलू स्तर पर सहूलियत मिल रही है, लेकिन जब तक पैनल अपशिष्ट का आसानी से, पर्यावरण पर असर डाले बगैर, निपटान सुनिश्चित नहीं होता, तब तक इसे निरापद मानकर इस्तेमाल करना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सौर पैनलों की सबसे बढ़िया डिजाइन का इस्तेमाल के लिए सरकार को जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सरकारी योजनाओं के तहत भी जो सौर पैनल घरों पर लगाए जाएं, वे भी पर्यावरण के नजरिए से बेहतर होने चाहिए।

साझेपन की संवेदना

सुभाष चंद्र शर्मा

एक समय था जब हमारे अपने पड़ोसियों से भी चाचा-चाची, ताऊ-ताई, दादा-दादी के उसी प्रकार के रिश्ते होते थे, जैसे हमारे अपनों से। मगर जैसे-जैसे पश्चिम से प्रेरित शहरी जीवनशैली हम पर हावी होती चली गई, लोगों ने समाज के रूप में सिमटना भी आत्मसात लिया। अब नौबत यह आ गई है कि आज का युवा वर्ग किसी की सलाह को भी दखल बताता है और उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसमें वह अपनी तौहीन मानता है। चिंता की बात यह है कि यह स्थिति अब केवल शहरों में सीमित नहीं रही, गांवों में भी परसती जा रही है। नतीजा यह हुआ कि अधिकांश दंपति शादी के बाद अपने परिवार से अलग ज्यादा पसंद करते हैं।

संयुक्त परिवारों का सबसे बड़ा लाभ यह था कि सुख में तो सभी मिल-जुलकर खुशी बांटते ही थे, असली सहभागिता दुख की स्थितियों में होती थी। साझेपन और संवेदना की जरूरत दुख में ही पड़ती है। परिवार के रूप में एकल स्वरूप में सिमटने वाले समाज को यह तब समझ में आता है, जब दुख से भरा वक्त आता है। बच्चों को घर के बुजुर्ग उनके जीवन के लिए ऐसी सीख दे जाते थे, जो भविष्य में उनके काम आती थी। यह सिलसिला निरंतर जारी रहता था। पानी के बहाव की स्थिति होती है कि वह ऊपर से नीचे को बहता है। यह संयुक्त परिवारों के जीवन की पाठशाला की पढ़ाई थी। आज बच्चों को रोजी-रोटी की शिक्षा यानी जीविका की शिक्षा तो स्कूल-कालेज में दी जा रही है। उसमें कोई कसर नहीं है। उस ओर मां बाप का भी बच्चों पर पूरा दबाव है। वे रात-दिन एक किए हुए हैं। अलग से कोचिंग भी कराते हैं। जीविका की शिक्षा स्कूल-कालेजों में मिल जाती है, लेकिन जीवन की शिक्षा का स्कूल-कालेजों में ही नहीं, घर-परिवारों में भी अभाव हो गया। जीवन की सीख किसे कहते हैं यह आज के अधिकांश युवाओं को पता ही नहीं है। उनकी केवल एक ही धुन है कि जैसे भी हो, बस पैसा कमाओ। यही वह परिवार और समाज से सीख रहा है। इसी चक्कर में उसके अपनों से भी रिश्ते-नाते टूटते जा रहे हैं।

गांवों को लेकर चिंता इसलिए होगी कि आज भी हमारे देश के करीब सत्तर फीसद लोग गांवों में रहते हैं। जिन लोगों ने गांवों से शहरों की ओर कूच किया, उसमें उनकी कोई न कोई मजबूरी रही। रोजी-रोटी की तलाश या फिर गांवों में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा से जुड़ी समस्या तो हल हो जा सकती है, लेकिन इसी के साथ-साथ धीरे-धीरे उन पर महानगरीय रंग चढ़ता जाता है। यह सब कोई एक दिन में नहीं हो जाता है। इसमें वर्षों और कई दशक भी लगते हैं। गांवों से शहरों में लोगों को इसकी चकाचौंध ने इस कदर अपने आगोश में लिया कि धीरे-धीरे गांवों से उनके रिश्ते नाते खत्म होते चले गए।

हालांकि ऐसा नहीं कि शहर के लोग अपने बच्चों को जीवन की बेहतर सीख नहीं देते हैं, मगर गांवों में बच्चों को मिले पाठ के मुकाबले के शहरों के संस्कारों में जमीन-आसमान का अंतर है। शहरों के बच्चे अपने घर में और बाहर देखते हैं कि किस प्रकार से अनेक परिजन दांवपेच लगा कर पैसा कमा कर लाते हैं। कैसे रातों रात लोग लखपती, करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। वे यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से लोग इस आपाधापी और गलाकाट प्रतिस्पर्धा में लोग किसी का बुरे से बुरा करने में भी नहीं हिचकते।

एक समय था जब गांव की बेटी सबकी बेटी के रूप में प्यार और संरक्षण पाती थी। गांव का कोई व्यक्ति जब अपनी बेटी से मिलने उसकी ससुराल जाता था, तो उस गांव में अपने गांव की ब्याही गई किसी अन्य लडकी के भी घर मिलने चला जाता था और उसे आशीर्वाद देता था। वह महिला भी उसे अपने गांव के रिश्ते के अनुसार भइया, चाचा, ताऊ, बाबा कहकर संबोधित करती थी। वह आने वाले से अपने परिवार के बारे में समाचार तो सुनती ही थी, पूरे गांव के बारे में भी पूछती थी। यह था एक दूसरे से जुड़ाव। एक कहावत है कि हमें दूध मिले तो हमारे पड़ोसी को हमारे यहां से कम से कम छाछ तो अवश्य मिलनी ही चाहिए। यही सब चीजें थी, जो हमें एक दूसरे जोड़े हुए थीं।

मगर अब सोचने पर पता चलता है कि इंसान और पशु-पक्षी में क्या अंतर है! पेट तो पशु-पक्षी भी भरते हैं, अपने रहने की जगह बनाते हैं। कुछ निर्धारित समय तक परिवार के साथ भी रहते हैं। फर्क केवल इतना कि प्रकृति से इंसान को अच्छे-बुरे में फर्क करने, सोचने की शक्ति मिली हुई है। कई मायनों में पशु-पक्षी इंसान से अच्छे साबित होते हैं। अनेक लोग यह रोना रोते देखे जाते हैं कि आज के युवा अपने मां-बाप की भी नहीं सुनते। दरअसल, उन्हें जीवन की ऐसी सीख नहीं दी गई, जो वह किसी की सुने। सब धनपति बनने की चाह में दौड़ते रहे। बच्चों की ओर ध्यान कहां दिया गया? अपनी सुविधा और समय के अभाव की वजह से बच्चों को बचपन में ही छात्रावास में डाल दिया जाता है। महीने, दो महीने में मेहमान की तरह लोग अपने बच्चों से मिलने कुछ देर के लिए चले जाते हैं। स्कूलों में जीविका की शिक्षा के अलावा और क्या पढ़ाया जा रहा है!

दुनिया मेरे आगे

> सब धनपति बनने की चाह में दौड़ते रहे। बच्चों की ओर ध्यान कहां दिया गया? अपनी सुविधा और समय के अभाव की वजह से बच्चों को बचपन में ही छात्रावास में डाल दिया जाता है। महीने, दो महीने में मेहमान की तरह लोग अपने बच्चों से मिलने कुछ देर के लिए चले जाते हैं।

वोट और बदलाव

देश में इस समय चुनावी माहौल है। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, जबकि पिछला अनुभव यह है कि मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के बावजूद भी मत फीसद बहुत कम रहता है। उसकी वजह आम लोगों का यह मानना है कि हमारे वोट देने या न देने से हमारी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इन राजनीतिक दलों से इतना निराश है कि उसकी यह सोच बन गई है कि किसी भी दल की सरकार बने, हमें तो अपना परिवार पालना है, ये नेता हमें खाने-पहनने को नहीं देंगे। आम लोगों कि यह धारणा है कि नेता सिर्फ अपना हित साधेंगे। जब तक आम लोगों के जीवन स्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, जब तक वह राजनीतिक दलों से निराशा महसूस करेगा, तब तक वोट का फीसद बढ़ना मुश्किल है। जो लोग किसी विशेष दल से जुड़े हुए हैं, वे मतदान करने जाएंगे, लेकिन उसके अलावा साधारण लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस होगा तभी वह वोट देने के लिए अपने घर से नहीं निकलेगा।

– चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली

जल की फिक्र

भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी और बृहद मिशन 'जल जीवन मिशन' (हर घर नल से जल) का कारवां देश के दूर-सुदूर गांवों तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस योजना के आने से लोगों में प्रतिदिन स्वच्छ जल प्राप्त करने की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन इस योजना का एक कड़वा सच यह भी देखने में आ रहा है कि गांव-देहात में लगे नलों की टोंटी लोग निकाल कर ले जाते हैं और टोंटी के अभाव में पाइप से स्वच्छ जल बहता रहता है। एक तरफ जहां अप्रैल की शुरुआती दौर में ही नल जवाब देने लगे हैं, वहीं दिन-रात व्यर्थ बहते जल से भीषण जल संकट की समस्या देखने को मिल सकती है। धरती के गहरे तल से निकलने वाला साफ जल की बर्बादी से भू जलस्तर के और भी निम्न स्तर पर पहुंचने का खतरा है। अगर नीति-नियंता समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए जल संरक्षण के लिए सभी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

– महेंद्र नाथ चौरसिया, सिद्धार्थनगर

गरिमा के विरुद्ध

'बेलगाम बदजुबानी' (संपादकीय, 5 मार्च) पढ़ा। चुनावी मौसम में नेताओं की बदजुबानी का आक्रामक रूप अक्सर देखने को मिल जाता है। यह कैसी वाग्मिता है जो एक दूसरे पर व्यंग्य बाण चलाते वक्त न तो राजनीतिक मर्यादा की परवाह की जाती है और न ही किसी महिला उम्मीदवार की गरिमा का खयाल किया जाता है। अक्सर महिला उम्मीदवार इस बदजुबानी का शिकार ज्यादा होती हैं। उन पर व्यक्तिगत दोषारोपण किया जाता है। मुद्दों पर स्वस्थ बहस के इतर इस तरह की बदजुबानी से कुछ नेता सस्ती स्थानीय लोकप्रियता तो बटोर लेते हैं, मगर कई बार ये बिगड़े बोल उन पर भारी भी पड़ जाते हैं। ऐसा करने में सभी दलों के नेता शामिल हैं। पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए राजनीति की मर्यादा और महिलाओं गरिमा की खातिर अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने का काम करें।

– माम चंद, सागर, रजोकरी

कामयाबी की राह

बोर्ड परीक्षाओं में सबसे अव्वल रहने वाले छात्र-छात्राओं की तस्वीरें अखबारों में छपने लगती हैं। उनके स्कूल के अध्यापक और गली मोहल्ले के लोग उनका स्वागत फूल-मालाओं और गाजे-बाजे के साथ करते हैं। इस स्वागत को देखकर वे छात्र खुद को शर्मिंदगी और अफसोस की हालत में महसूस करते हैं, जो किसी भी कारण से बोर्ड परीक्षा में केवल औसत नंबर के साथ पास होते हैं। लेकिन एक कहावत है कि 'हर सफलता का रास्ता असफलता से होकर ही गुजरता है'। इसलिए समाज को चाहिए कि कामयाब छात्रों का स्वागत करे, लेकिन आज जो छात्र असफल हो गए हैं उनको आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं दें, ताकि परीक्षा में असफल होने वाले छात्र भी इस समाज में गर्व से कह सकें कि हम भी कल कुछ बेहतर कर सकते हैं। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

– रोहित यादव, रोहतक, हरियाणा

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AINewsPaperPdf

www.readwhere.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 46

न्यायिक सुधार जरूरी

भारत की अवरुद्ध न्याय प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बदनामी हासिल है जिसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश संबंधी निर्णयों में भी भूमिका रहती है। सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के फैसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति उच्च न्यायपालिका के लिए चेतावनी के समान है। न्यायाधीशों से ऐसे मामलों की जानकारी मांगते हुए जिनमें फैसला तीन महीनों से सुरक्षित है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने पाया है कि ऐसे भी मामले हैं जहां फैसले को 10 महीनों तक सुरक्षित रखा गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने पाया कि कई न्यायाधीशों ने मामलों की आंशिक सुनवाई के बाद उन्हें आगे बढ़ा दिया जिससे उन्हें नए सिरे से उनकी सुनवाई करनी पड़ी। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा किसी फैसले को 10 महीने तक रोके रखना न्यायिक समय की बरबादी है क्योंकि संबंधित न्यायाधीश को शायद ही मौखिक बहस इतने समय तक याद रहे। यह पहला मौका नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से गति बढ़ाने को कहा है। 2022 में एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे दो न्यायाधीशों के पीठ ने कहा था कि संबंधित उच्च न्यायालयों को सभी दलीलें पूरी होने के बाद जल्दी से जल्दी निर्णय सुनाने की सलाह दी जाती है।

फैसले आरक्षित रखने से अदालतों में मामलों का अंबार लगता जा रहा है। यह एक स्थापित संस्थागत समस्या है जो समूची न्याय व्यवस्था में अंतर्निहित है। सरकार का प्रदर्शन दिखाता है कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं जिनमें से एक लाख से अधिक मामले 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। ऐसी देरी की एक अहम वजह न्यायिक पीठों में बड़ी तादाद में रिक्तियों का होना है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय फिलहाल ऐसे दुर्लभ अवसर से गुजर रहा है जब वहां न्यायाधीशों का कोरम पूरा है। उच्च न्यायालयों में 329 रिक्तियां हैं। आश्चर्य नहीं कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की तादाद समय के साथ बढ़ती जा रही है। चूंकि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय मिलकर देश की व्यवस्था में न्याय की पहली पंक्ति तैयार करते हैं। ऐसे में देश के नागरिकों को बड़े पैमाने पर न्याय पाने में मुश्किल होती है। निश्चित तौर पर लंबे समय तक मामलों के अदालत में लंबित रहने से भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद के कारण भी हालात खराब हुए हैं। परंतु न्यायाधीशों की संख्या में कमी इस कहानी का एक हिस्सा है। समूचा न्याय तंत्र खराब हालत में है, खासकर उसका निचला स्तर। खुद सरकार का मानना है कि अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी और सहायक कर्मचारियों की तादाद में कमी और जांच एजेंसियों एवं वादियों-प्रतिवादियों की अदालती निर्देशों को समझने और उसका पालन करने की कमी ने भी न्यायपालिका की तस्वीर पर असर डाला है। बार-बार स्थगन और अपीलों ने भी अदालतों का बोझ बढ़ाया है जो केंद्र और राज्य सरकारों के विधानों में विस्तार के कारण पहले से दबाव में हैं।

इसके असर को भारत के प्रमुख आर्थिक साझेदारों द्वारा आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि दस्तावेज को पूरी तरह खारिज करने में देखा जा सकता है जिसका कहना है कि विदेशी निवेशकों को सभी न्यायिक उपचार भारतीय व्यवस्था में ही हासिल करने होंगे। उसके बाद ही वे मध्यस्थता का प्रयास कर सकते हैं। वोडाफोन को पिछली तारीख से लागू कर वाले मामले को भारतीय अदालतों में निपटाने में 13 वर्ष का समय लगा और यह एक चेतावनी की तरह है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के व्यवहार पर जो टिप्पणी की है वह समस्या के केवल एक पहलू की ओर इशारा करता है। परंतु यह हमें याद दिलाता है कि केंद्र और राज्य के स्तरों पर न्यायिक सुधारों को तत्काल तवज्जो देने की जरूरत है। भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसे मजबूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने के लिए विश्वस्तरीय न्याय व्यवस्था की जरूरत है।

बिनय सिन्हा

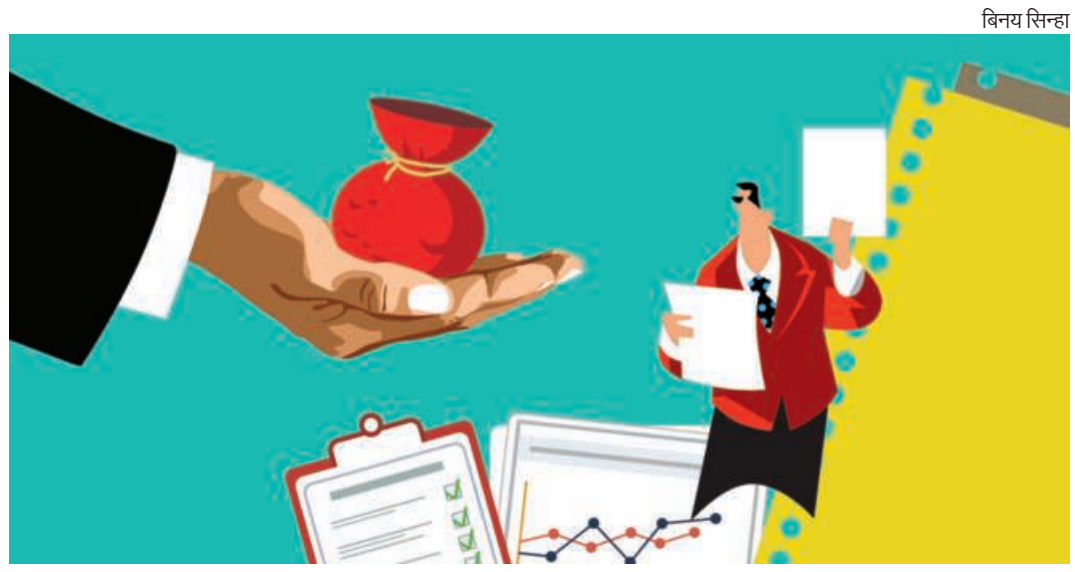

शेयरों की पुनर्खरीद और उसका महत्त्व

अंशधारकों को धनराशि वापस देने का यह अर्थ नहीं कि आप वृद्धि हासिल नहीं कर रहे या शायद आपको उस पूंजी की जरूरत नहीं हो जो आप मूल कारोबार से अर्जित करते हैं। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

विश्व भर में और खासकर अमेरिका में कंपनियों द्वारा निवेशकों को पूंजी लौटाने का एक तरीका शेयरों की बायबैक (पुनर्खरीद) भी है। आंशिक तौर पर ऐसा शेयर आधारित कर्मचारी मुआवजे के कारण आई कमी की भरपाई के लिए किया जाता है और आंशिक तौर पर ऐसा बेहतर कर कुशलता के कारण यह निवेशकों को पूंजी लौटाने का प्राथमिक माध्यम बन गया है। एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि सन 2000 से ही अमेरिका में 5.5 लाख करोड़ डॉलर के शेयरों की बायबैक हुई। वे अमेरिकी शेयरों की मांग का अकेला सबसे बड़ा माध्यम रहे। मांग का अगला बड़ा स्रोत रहा विदेशी निवेशकों से खरीद जो इस अवधि में 1.8 लाख करोड़ डॉलर रही।

सन 2000 के बाद से घरेलू खुदरा निवेशकों से कुल 100 अरब डॉलर की खरीद की गई। इसमें घरेलू बचत और म्युचुअल फंड शामिल हैं। शेयर बाजार के क्षेत्र में अमेरिका के निरपवाद प्रदर्शन की एक बड़ी वजह रही है अमेरिकी कंपनियों द्वारा अपने ही शेयरों की निरंतर इतनी बड़ी खरीद। किसी भी अन्य देश की तुलना में यह गति और परिमाण अप्रत्याशित है। फिलहाल हम अमेरिकी कंपनियों से वास्तविक रूप से सालाना एक लाख करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद देख रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शेयर आधारित मुआवजे को निष्प्रभावी करने की आवश्यकता से परे शेयरों की पुनर्खरीद अब अंशधारकों को पूंजी लौटाने के प्राथमिक माध्यम के रूप में स्वीकार्य है। सभी तकनीकी दिग्गज कंपनियों ने बड़े पैमाने पर शेयरों की पुनर्खरीद की है। यहां तक कि मूल्य वृद्धि वाले शेयरों में प्रमुख एनविडिया ने छह महीने पहले 25 अरब डॉलर के शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की।

अगर हम अधिक सूक्ष्म स्तर पर देखें तो ऐपल पुनर्खरीद की शक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हाल तक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रही ऐपल के लिए पुनर्खरीद अंशधारकों के मूल्य समीकरण का एक अहम हिस्सा रहा है। 2015 में आईफोन की बिक्री में कमी आनी शुरू हुई। तब से अब तक ऐपल की प्रति शेयर आय की समेकित सालाना वृद्धि औसतन 13 फीसदी रही है। इस अवधि में कंपनी की कुल बिक्री सालाना 6.4 फीसदी बढ़ी और कर पूर्व मुनाफा केवल 5.7 फीसदी बढ़ा। यह अंतर कम कर दर और शेयर पुनर्खरीद से पैदा हुआ जिन्होंने मिलकर सालाना 6.7 फीसदी की प्रति शेयर आय वृद्धि दी। प्रति शेयर आय में 13 फीसदी की वृद्धि में से 5 फीसदी शेयरों की शुद्ध पुनर्खरीद से हासिल हुई। इस अवधि में 550 अरब डॉलर मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद हुई और कंपनी ने अपने 30 फीसदी से अधिक शेयर हटाए। 2015 से 2019 के बीच शेयरों की पुनर्खरीद सबसे अहम थी। उस वक्त कर पूर्व मुनाफे में कमी आई और कंपनी ने हर वर्ष करीब 6 फीसदी शेयरों की पुनर्खरीद की। इसका सात फीसदी का उच्चतम स्तर 2019 में समाप्त हुआ।

आज भी कंपनी हर वर्ष 85 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद करता है। ऐपल लाभांश भी देती है लेकिन फ्री कैश फ्लो (एफसीएफ) का केवल 15 फीसदी ही इस मार्ग से चुकाती है। 85 फीसदी एफसीएफ पुनर्खरीद के जरिये लौटा दिया जाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की 2015 से 2023 के बीच की आय वृद्धि में 40 फीसदी शेयरों की पुनर्खरीद से आई। जब से ऐपल ने पूंजी की वापसी का यह मार्ग अपनाया, उसके मूल्यांकन में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। 2016 के आरंभ में कंपनी की सापेक्ष कीमत /अग्रिम आय 0.6 थी जो अब 1.25 हो चुकी है और डेढ़ गुना बढ़ चुकी है। मूल्यांकन विस्तार के एक हिस्से के लिए बाजार का वह व्यवहार उत्तरदायी है जिसके तहत वह कंपनी को उपभोक्ता फ्रैंचाइजी समझती है बजाय कि एक हार्डवेयर कंपनी के। परंतु थोड़ा श्रेय उस निर्णय को भी दिया जाना चाहिए जिसके तहत समस्त एफसीएफ शेयर धारकों को सौंपा गया। उच्च भुगतान अनुपात स्पष्ट रूप से उच्च मूल्यांकन और शेयरों पर बढ़ते प्रतिफल से संबद्ध है। निवेशक ऐसी कंपनियों को पसंद नहीं करते जो बेमतलब नकदी जमा करती हैं।

पूंजी की वापसी और पुनर्खरीद की यही शक्ति है। भारत के लिए इन बातों का क्या महत्त्व है? हमारे बाजारों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों और बजाज ऑटो जैसी इक्का-दुक्का कंपनियों के अलावा कोई पुनर्खरीद का इस्तेमाल नहीं करता। आंशिक तौर पर ऐसा करने के लिए बहुत सीमित कर प्रोत्साहन है और शेयर आधारित मुआवजे का भी चलन नहीं है। आज भी अधिकांश भारतीय कंपनियां पूंजी की वापसी को ऐसे देखती हैं मानो संबंधित शेयर उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका हो। कई प्रवर्तक अभी भी कंपनी की नकदी को अपना पैसा मानते हैं और इसे अल्पांश हिस्सेदारों के साथ बांटना नहीं चाहते।

यह जोखिम भी है कि देश की दीर्घावधि संभावनाओं को लेकर वर्तमान आशावाद के चलते निवेश करते रहने पर जोर हो, भले ही मूल कारोबारों को मुनाफे में आई समस्त राशि की आवश्यकता नहीं हो। आज भारत में वृद्धि का हर अवसर उत्साहवर्धक नजर आती है।

यह उच्च मुनाफे और नकदी प्रवाह का दौर है। कारोबारी जगत का उत्साह बढ़ रहा है। हर कोई आशावादी और उत्साहित है। सबसे अच्छे समय में सबसे बुरी गलतियां होती हैं। पूंजीगत अनुशासन से फिसलने की संभावना रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कंपनियां असंबद्ध कारोबारी निवेश का निकट से आकलन करेंगी और यह समझेंगी कि पूंजी प्रतिफल एक उपयुक्त विकल्प है। अंशधारकों को धन वापस देने का अर्थ यह नहीं है कि आप वृद्धि नहीं हासिल कर रहे हैं। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि आपको अपने मूल कारोबार के लिए तमाम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। उच्च कारोबारी मुनाफे वाले वर्तमान समय जैसे दौर निवेशकों के लिए अधिक खतरनाक होते हैं। यही वह स्थान है जहां पूंजीगत आवंटन की कला सामने आती है। कंपनियों को पूंजी पर प्रतिफल के अपने मानक को बरकरार रखना चाहिए।

अगली पीढ़ी कंपनियों के लिए यह और महत्त्वपूर्ण सबक है। इनमें से कई बहुत जल्दी बाजार में उतरेंगी। एक बार मुनाफा हासिल करने के बाद उनमें से कई कंपनियों के पास सीमित पूंजी होगी और वे भारी एफसीएफ तैयार करेंगी। निरंतर नए कारोबार में उतरने तथा नकदी का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पूंजी प्रतिफल और पुनर्खरीद की स्थिति पर विचार करना पड़ सकता है।

हर कंपनी की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां और वृद्धि विकल्प होते हैं। पूंजी प्रतिफल भी एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जिस पर प्रबंधन पूंजी आवंटन के समय विचार करते हैं। सभी नई वृद्धि परियोजनाएं और कारोबार हमेशा तार्किक नहीं होते। मौजूदा आकर्षण के बावजूद हमें पूंजी पर प्रतिफल की सीमा पर टिके रहना चाहिए। निवेशकों की तरह हमारा भी यह दायित्व है कि हम बाजार और मूल्यांकन के जरिये पूंजीगत अनुशासन कायम करें।

(लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं)

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विनिर्माण की चुनौतियां

कई देशों द्वारा स्थानीय सौर ऊर्जा और इसकी वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही अच्छी-खासी सब्सिडी शायद अपेक्षित परिणाम न दे पाए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में प्रोत्साहन केवल उच्च उत्पादन लागत की आंशिक भरपाई करते हैं।

ब्लूमबर्गएनईएफ के प्रमुख अमेरिकी सौर विश्लेषक पोल लेजकानो का कहना है, 'दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वश्रेष्ठ मॉड्यूल जल्द ही अमेरिकी डेवलपर के लिए काफी सस्ते हो जाएंगे। अधिकांश कारखाना योजनाओं के खत्म होने के कारण कुछ आपूर्तिकर्ता ही अमेरिका में मॉड्यूल बना पाएंगे।'

स्थानीय विनिर्माण के लिए विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और आयात को हतोत्साहित किया जा रहा है। अगर विदेश से सामान लाने की लागत कर शुल्क के बाद भी कम है तब ये दोनों तरीके कारगर नहीं होंगे। दरअसल संरक्षित बाजार की मूल्य साम्यता भी उसी स्तर पर चली जाती है जो बिना संरक्षण के होता है जैसा कि अमेरिका में होता है।

एक नये उद्योग में जब विनिर्माण की मात्रा बढ़ती है तब शुरुआत की ऊंची लागत लंबे समय में रणनीतिक तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में तब्दील हो सकती है जब तक कि उत्पाद की नकल आसानी से नहीं की जाती है। लेजकैनो का कहना है, 'सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योग में ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि ऐसे उत्पाद कोई भी बना सकता है।'

यूरोप भी स्थानीय पैनल निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। स्विटजरलैंड के सौर पैनल निर्माता कंपनी मेयर बर्गर ने जर्मनी में एक विनिर्माण इकाई बंद करने की घोषणा की और उन्होंने इसके बाद अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका कहना था कि यूरोप में व्यापारिक माहौल खराब हो रहा है। कंपनी ने पिछले महीने एक बयान जारी किया था जिसमें लिखा था, 'जर्मनी के फ्रीबर्ग (सैक्सोनी) साइट पर सोलर मॉड्यूल उत्पादन, मार्च 2024 के मध्य में ही बंद कर दिया गया जिससे अप्रैल से लागत में अच्छी बचत होगी। जर्मनी के थालहेम में सौर सेल उत्पादन के जरिये फिलहाल कुछ वक्त तक एरिजोना के गुडइयर में अमेरिकी सौर मॉड्यूल निर्माण के उत्पादन में तेजी के लिए समर्थन दिया जाएगा।'

ऊर्जा शक्ति
वंदना गोंबर

भारत में बने सौर पैनलों को बढ़ावा देने और साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के प्रयास के तहत में नीतिगत बदलावों की एक श्रृंखला के बाद भारत का सौर पैनल आयात पर फिर से रोक लगाने का फैसला वास्तव में निर्माताओं के लिए सकारात्मक है लेकिन इसका मतलब डेवलपर के लिए इसकी कीमत अधिक होगी और वह भी ऐसे वक्त में जब वैश्विक आपूर्ति की अधिकता कम कीमतों के संकेत दे रही है।

दुनिया की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियां ना सिर्फ चीजें बनाती हैं बल्कि वे सभी चीजों पर नियंत्रण भी करती हैं और साथ ही ये कंपनियां बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की जिंको सोलर ने 2023 में 78 गीगावॉट से अधिक का निर्यात किया। इस साल इसके 100-110 गीगावॉट तक बढ़ने की उम्मीद है। यह चीन के बाद चार सबसे बड़े बाजारों, अमेरिका, भारत, ब्राजील और जर्मनी के लिए संयुक्त रूप से नए निर्माण करने के पूर्वानुमान से अधिक है। चीन इस साल 300 गीगावॉट से अधिक की क्षमता स्थापित कर सकता है।

यूरोपीय आयोग ने इस सप्ताह, रोमानिया में एक सौर अनुबंध की विदेशी सब्सिडी विनियमन के तहत जांच शुरू की जिसका मकसद सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बोली लगाने वाले को दी गई विदेशी सब्सिडी की बाजार में संभावित विकृत भूमिका की जांच करना है। यूरोपीय संघ के आंतरिक बाजार आयुक्त थियरी ब्रेटन ने ब्लूमबर्ग न्यूज से कहा, 'यूरोप के लिए सौर पैनल रणनीतिक रूप से हमारे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, यूरोप में नौकरियों और आपूर्ति की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। जांच का उद्देश्य यूरोप की आर्थिक सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है।'

मीथेन नियंत्रण

हाल में कुछ घटनाक्रम से मीथेन उत्सर्जन की बेहतर निगरानी और नियंत्रण की जा सकेगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला से जुड़ा ऊर्जा क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों में से एक है जबकि दूसरा क्षेत्र कृषि है। आईईए ने कहा कि वर्ष 2023 में जीवाश्म ईंधन से अनुमानतः 12 करोड़ टन मीथेन उत्सर्जन में से दो-तिहाई उत्सर्जन 10 देशों, अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, चीन, अल्जीरिया, सऊदी अरब, कनाडा और इराक से हुए हैं।

ऐसा लगता है कि उत्सर्जन करने वाले इस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं क्योंकि यह 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक गर्मी को बांधे रख सकता है। दुबई में कॉप28 सम्मेलन में 50 से अधिक तेल और गैस कंपनियों ने तेल एवं गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर पर हस्ताक्षर कर दशक के अंत तक अपने मीथेन उत्सर्जन को सीमित करने का वादा किया था।

मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना और इसे मापना अब आसान हो गया है जैसे कि मीथेनसैट उपग्रह के माध्यम से यह संभव है। इंटरनैशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है और 2021 में जी20 की बैठक में इसकी शुरुआत होने के बाद से ही कई सफलताएं मिली हैं। विश्व बैंक की ग्लोबल फ्लेयरिंग ऐंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप विकासशील देशों पर केंद्रित है। अब तक 155 देश ग्लोबल मीथेन प्लेज के तहत उत्सर्जन कम करने पर सहमति जता चुके हैं और इसकी राष्ट्रीय नीतियों में भी झलक मिल रही है। नतीजतन, एसएलबी जैसी कंपनियां मीथेन उत्सर्जन प्रबंधन समाधानों में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखा रही हैं। हालांकि, इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बीएनईएफ के अपस्ट्रीम ऑयल विश्लेषण के प्रमुख इल्हान सवुत का कहना है, 'संयुक्त राष्ट्र और इससे संबंधित निकाय एवं उपग्रहों ने नीति निर्माताओं और निवेशकों की हाल की जांच को बढ़ा दिया है। यह शुरुआती दिलचस्पी वास्तव में कम मीथेन उत्सर्जन में तब्दील होगी या नहीं यह अभी तक निश्चित नहीं है।'

(लेखिका न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्गएनईएफ की वरिष्ठ संपादक, वैश्विक नीति हैं)

आपका पक्ष

मौसम की अति का नतीजा

किसी भी मौसम की अति जीवन के लिए त्रासदीदायक होती है। देश में औद्योगिक क्रांति के फायदे जरूर हुए मगर वायुमंडल में गर्मी रोकने वाली ग्रीन हाउस गैसों की उपेक्षा के कारण धरती का तापमान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। सर्वे बताते हैं कि देश में गर्म राज्यों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई है जो ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। मार्च से मई तक अलनीनो के दुष्प्रभाव का नतीजा 2024 के सबसे गर्म वर्ष के रूप में सामने आ सकता है। प्रकृति की प्रतिकूलता मानव जीवन के लिए त्रासदीदायक बनती जा रही है। हालांकि विषम होते हालात की वजह आम आदमी की करतूतें हैं जो पर्यावरण का नाश कर रही हैं। प्रकृति के स्वभाव में असहज बदलाव से ऋतु चक्र और मौसम की अवधि भी गड़बड़ा रही है। मौसम विज्ञान ने इस वर्ष मार्च से मई तक गर्मी के तेज प्रभाव की जो चेतावनी जारी की है उसके दुष्प्रभाव नजर आने लग गए हैं।

यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार दुनिया में वर्ष 2024 का मार्च महीना अब तक सबसे गर्म रहा

होली के पहले तेज गर्मी के एहसास से अलनीनो की परिस्थितियां बनने की गंभीर चेतावनी है। वैसे देखा जाए तो लोग साल में 10 माह गर्मी महसूस करते हैं। न बारिश नियमित है और न ही ठंड जरूरत के मुताबिक गिर रही है। इसकी एकमात्र वजह प्रकृति के दोहन की आदतें हैं। जब तक उनके संरक्षण के प्रयास नहीं होंगे, असंतुलन बना रहेगा।

अमृतलाल मारू, इंदौर

जल को सहेजना जरूरी

पानी को सहेजना जरूरी हो गया है। इसके लिए तालाबों और बांधों का ज्यादा संख्या में निर्माण हो। आजकल लोग बोतलबंद पानी खरीद कर पी रहे हैं। अगर पानी को सहेजा नहीं गया तो एक दिन पानी की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। पानी सहेजेंगे तो ही हम नदियों के पानी को समुद्र में व्यर्थ बहने से रोककर उसका उपयोग कर पाएंगे और जल ही जीवन की परिभाषा को सही तरीके से समझ पाएंगे।

संजय वर्मा, मनावर

इन्फ्लुएंसरों पर नियमन

सेलेब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए दिन विज्ञापनों और अलग-अलग उत्पादों का प्रचार करते दिखते हैं। इस दौरान जाने-अनजाने कई बार उनकी तरफ से भ्रामक यानी बहकाने वाले विज्ञापनों को बढ़ावा दिया जाता है, जिस पर उनके फॉलोअर आंख मूंदकर भरोसा भी कर लेते हैं। इससे उनका आर्थिक नुकसान भी होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों और सेलेब्रिटीज की ओर से किसी भी नकली प्रोडक्ट को सपोर्ट करने, गलत जानकारी देने या फिर बिना जांचे-परखे किसी भी ब्रांड को बढ़ावा देने के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह इसे रोकने के लिए जारी गाइडलाइन पर आवश्यक सख्ती बरते। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसरों और सेलिब्रिटी के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइड-लाइन में सबसे अहम निर्देश है कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और सेलेब्रिटी उन्हीं उत्पादों का प्रचार कर सकेंगे, जिनका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो या कर रहे हों।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

बेल्जियम के विदेश मंत्रालय की महासचिव थियोडोरा जेंटजिस ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों ने भारत, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 10 अप्रैल 2024

एकजुटता का संदेश

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) ने आखिर मंगलवार को गुड़ी पाड़वा के मौके पर सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। उसके लिए संतोष की अतिरिक्त बात यह भी है कि अन्य कुछ राज्यों में भले ही NDA खेमा ज्यादा व्यवस्थित और अनुशासित नजर आ रहा हो, कम से कम महाराष्ट्र में MVA ने उसे पीछे छोड़ दिया है। वहां महायुति के घटक दलों में अभी भी कई सीटों को लेकर मतभेद नहीं सुलझ पाए हैं।

बड़े भाई की भूमिका | सीटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ है, उसमें पहली नजर में शिवसेना (UBT) फायदे में नजर आती है जिसे सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली हैं। यानी कम से कम सीटों के बंटवारे के दौरान उसने प्रदेश राजनीति में बड़े भाई की अपनी भूमिका बरकरार रखने का दावा करने लायक स्थिति बना रखी है। कांग्रेस को जहां 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं NCP के हिस्से में महज 10 सीटें आई हैं। सांगली, भिवंडी और उत्तर पश्चिम मुंबई यानी जिन सीटों को लेकर विवाद सार्वजनिक हुआ था, उन सब पर कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि कांग्रेस इसे तानाशाही के खिलाफ जंग में दी गई आहुति करार दे रही है। लेकिन देखना होगा कि यह त्याग या समझदारी इन पार्टियों की सांसदों की संख्या में किस हद तक इजाफा कर पाती है।

महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमति

राज्य पर टिकीं नजरें | महाराष्ट्र पर इस बार पूरे देश की नजरें अगर विशेष रूप से टिकी हुई हैं तो उसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। यहां से कुल 48 सांसद चुने जाते हैं, जो यूपी (80) के बाद सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी बात यह कि विभिन्न पार्टियों में टूट-फूट के चलते न सिर्फ पार्टियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है बल्कि उसकी वजह से प्रत्याशियों और उनके वोटर बेस को लेकर भी ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनके जवाब इन चुनाव नतीजों से ही मिलेंगे।

राजनीति का स्वरूप | इस बार दांव पर महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति का स्वरूप भी है। जिन नेताओं और परिवारों की प्रदेश राजनीति में साख रही है, न केवल उनकी पार्टियां दो फाड़ हो चुकी हैं बल्कि वे परिवार के स्तर पर भी जूझते दिख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता इसका सारा दोष BJP पर मढ़ते हैं, जो इसे गलत बताती है। लेकिन इन नेताओं के परिवारवाद को निशाना बनाने में कोई गुरेज नहीं करती। स्वाभाविक ही, लोकसभा चुनाव के नतीजे यह फैसला करेंगे कि प्रदेश की राजनीति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का दबदबा कायम रहेगा या उसके अंत की शुरुआत हो जाएगी।

पांच चरणों में चुनाव | प्रदेश में चुनाव पांच चरणों में होना है। 19 अप्रैल को वहां पहले और 20 मई को आखिरी दौर का मतदान होना है। बहरहाल, सबसे बड़ी बात देखने वाली यह होगी कि इन पार्टियों के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर होते हैं या नहीं और होते हैं तो किस हद तक।

दो दूनी चार

सस्ता मतलब खराब?

रमेश तिवारी

हाल में सरकार ने भारत दाल, आटा और चावल की शुरुआत की। बाजार के मुकाबले बेहद सस्ते इन प्रॉडक्ट्स को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। इस तरह के दावे आए हैं कि इनकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन अपने इर्द-गिर्द कई लोगों से इसके बारे में पूछा। वे इससे उत्साहित नहीं दिखे। कुछ ने तो सीधे इन प्रॉडक्ट्स की क्वॉलिटी पर सवाल उठा दिए। मेरे लिए यह पहली बार नहीं था। इससे पहले जन औषधि स्टोर की जेनेरिक दवा के बारे में भी यही प्रतिक्रिया मिल चुकी थी। मेरी जान-पहचान के लोग यह सोचते हैं कि हेल्थ के मामले में रिस्क क्यों लिया जाए, इसलिए वे ब्रैंडेड दवाएं खरीदने में यकीन रखते हैं।

हमारे इलाके में एक चैरिटेबल अस्पताल है। वहां आंखों की जांच आज भी 10 रुपये में होती है। गाहे-बगाहे कुछ लोगों ने आंखों की तकलीफ होने पर मुझसे अस्पतालों के बारे में राय मांगी थी। मैंने उन्हें इसी अस्पताल के बारे में बताया। 10 रुपये की फीस के बारे में सुनने पर उनमें से ज्यादातर लोगों का यही सवाल था कि क्या वहां MBBS डॉक्टर बैठते हैं। मैंने कहा कि वहां MD डॉक्टर बैठते हैं। फिर सवाल आया कि वे क्यों बैठते हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जाए। एक वक्त था, जब लोग पैसे बचाने के लिए बाजार में सस्ते से सस्ती चीजों की तलाश करते थे। आज समय बदल गया है। अब सस्ती चीज हाथ में लेने का मतलब यह हो गया है कि आप क्वॉलिटी से समझौता कर रहे हैं। लोग मान बैठे हैं कि सेवा भाव, सरकारी समर्थन जैसी कोई चीज मौजूद नहीं रह गई है। लेकिन क्या महंगी चीज लेने का मतलब यह है कि उसमें निश्चित तौर पर क्वॉलिटी पाने जा रहे हैं? इस देश में जब लखटकिया कार के बारे में सोचा गया, तब खर्च के बारे में लोगों की सोच इसकी डिमांड पैदा कर रही थी। लेकिन जब यह कार बाजार में आई तो सोच में बड़ा बदलाव आ चुका था। तब कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा, जब बाजार में बिकने वाली कारों में आधी SUV कैटिगरी की होंगी। सस्ते मोबाइल फोन को कोई युवा हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा।

हमारे दिमाग में एक अंतर्निहित पूर्वाग्रह होता है। एक अनकहा विश्वास होता है कि प्रीमियम का टैग चीज के शानदार होने का प्रतीक है, कि भारी कीमत बेहतर परफॉर्मेंस की गारंटी देती है। इसके उलट बजट फ्रेंडली ऑप्शन मिलने पर संदेह पैदा हो जाता है। लेकिन सस्ती चीजें हमेशा खराब नहीं होतीं। वे आवश्यकताओं के आधार पर अच्छी भी हो सकती हैं। इनकी गुणवत्ता उपयोग के तरीके पर भी निर्भर करती है। हम वैल्यू की खोज करें, साथ में विवेक का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण है। किफायती विकल्पों को सिरे से खारिज करने के बजाय उनका निष्पक्ष मूल्यांकन करें। रिव्यू पढ़ें, तुलना करें और असल परफॉर्मेंस का आकलन करें। उस बैलेंस की तलाश करें, जहां क्वॉलिटी और कॉस्ट में एक तालमेल साफ साफ दिख रहा हो।

एकदा

भगत सिंह ने मांगी रबड़ी

साइमन कमिशन बहिष्कार के आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सुपरिंटेंडेंट सांडर्स की हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों फरार हो गए और एक वर्ष तक आगरा शहर में रहे। आगरे में नाई की मंडी से थोड़ी दूर नूई दूरी दरवाजे में इन्होंने एक कोठी किराए पर ली। वहीं उन्होंने वह बम बनाया था, जिससे अंग्रेजों की संसद बुरी तरह हिल गई थी। उस कोठी के ठीक सामने बेनी प्रसाद हलवाई की दुकान थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हर रोज बेनी प्रसाद की दुकान पर जाया करते थे। शहीद भगत सिंह को दूध पीना बहुत पसंद था। वह खाना कम खाते थे और दूध अधिक पीते थे। बेनी प्रसाद की दुकान पर मिलने वाली रबड़ी उन्हें खूब भाती थी। हर रोज तीनों बड़े चाव से रबड़ी खाते और बहुत देर तक वहां बैठकर बातचीत किया करते थे। भगत सिंह बेनी प्रसाद को 'बाबा' कहकर बुलाते थे। एक साल बाद तीनों को गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान बेनी प्रसाद को गवाही के लिए लाहौर बुलाया गया। बेनी प्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ जब लाहौर गवाही देने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि तीनों पूरे जोश के साथ गर्व से सीना चौड़ा करके खड़े थे। बेनी प्रसाद को देखकर भगत सिंह बोले, 'बाबा आज रबड़ी नहीं लाए क्या?' भगत सिंह के बोल सुनते ही बेनी प्रसाद की आंखों से आंसू झरने लगे। बेनी प्रसाद को रोता देख भगत सिंह ने कहा, 'बाबा रोते क्यों हो? आपकी गवाही चाहे कैसी भी हो, हम तीनों को फांसी तो होगी ही। आप बेकार चिंता मत करो। अगली बार जब आओ तो रबड़ी जरूर लेकर आना।' बेनी प्रसाद की रबड़ी की यह कहानी उन तीनों शहीदों की बहादुरी और देशभक्ति के साथ ही उनके मस्त स्वभाव की भी बानगी है।

Shital Verma

संकलन : रिंकल शर्मा

2008 की मंदी के वक्त ब्रिक्स देशों के पास 1,500 टन सोना था, जो आज करीब 6,600 टन है

ब्रिक्स की किस चाहत ने बढ़ाया सोने का भाव

चंद्रभूषण

सोना भारतीय बाजारों में फिलहाल 7000 रुपया प्रति ग्राम से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। ध्यान रहे, डॉलर और सोने के भाव के बीच उलटा अनुपात काम करता है। दुनिया में इन दोनों को सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा जाता है।

20% बढ़े दाम | पिछले दो साल में, खासकर इधर के छह महीनों में सोने की कीमतों का तेजी से बढ़ना समझ में आता है। दुनिया में दो लड़ाइयां चल रही हैं, जिनके फैलने का डर बना हुआ है। विश्व अर्थव्यवस्था में जब भी डर बढ़ता है, सोने की खरीद बढ़ जाती है। फिर भी महीने भर के अंदर सोने का 60 हजार रुपया प्रति तोले से सीधा 20% चढ़कर 72 हजार रुपया तोले पर पहुंच जाना समझ से परे है।

6,600 टन का रिजर्व | कोई बड़ी हलचल सतह के नीचे चल रही है, जिस पर ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। अलबत्ता, अमेरिकी वित्त सचिव जेनेट येलेन का बिना किसी गर्जन-तर्जन के तीन दिन चीन में जाकर बैठना कुछ संकेत जरूर दे रहा है। इधर, एक आंकड़ा चर्चा में है कि ब्रिक्स देशों के सरकारी खजाने में 2008 की मंदी के समय 1,500 टन सोना था, जो अभी 6,600 टन के आसपास पहुंच गया है।

238 टन की खरीदारी | ध्यान रहे, यह आंकड़ा इस साल की शुरुआत में ब्रिक्स में आए पांच नए देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया को जोड़कर नहीं निकाला गया है। पांचों पुराने ब्रिक्स देशों- भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का ही यह आंकड़ा है। 238 टन सोना तो चीन ने सरकारी इस्तेमाल के लिए अभी, जनवरी 2024 के सिर्फ एक महीने में खरीदा है।

रूस की मंशा | ब्रिक्स के खजाने में सोना बढ़ने की वजह यह बताई जा रही है कि आपसी कारोबार में डॉलर का इस्तेमाल अब वे बिल्कुल ही बंद करने वाले हैं। हालांकि यह सही है कि ब्रिक्स की समानांतर मुद्रा खड़ी करके डॉलर को सीधी टक्कर देने की बात अभी सिर्फ रूसी कर रहे हैं, जबकि बाकी ब्रिक्स देश ऐसे किसी अतिरेक से बचना चाहते हैं।

ब्रिक्स देशों का क्या है इरादा

- रूस चाहता है ब्रिक्स की मुद्रा हो
- डॉलर के दबदबे से चीन भी नाखुश
- दूसरे सदस्य देश शायद साथ न दें

अभी डॉलर को खतरा नहीं | कुछ तो इसलिए कि दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था से पंगा लेने में समझदारी नहीं है। कुछ इसलिए भी क्योंकि उनकी राष्ट्रीय संपदा का 10-20% हिस्सा डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड की शक्ल में ही है। उनकी किसी हरकत से डॉलर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक कमजोर होता है तो यह अपनी रकम अपने हाथ से जला देने जैसा होगा।

AI Image

अमेरिका की मनमानी | ब्रिक्स के अलावा कई और देश भी अभी गैर-डॉलर कारोबार में जाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनैंशल टेलिकम्युनिकेशन (SWIFT) देशों के आर-पार मुद्रा की आवाजाही की एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इसका नियंत्रण अमेरिका के हाथ में है, लेकिन इसका इस्तेमाल उसे दंड के औजार या दबदबे के हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए था।

स्विफ्ट का विकल्प | यह काम 2014 में रूस के खिलाफ बराक ओबामा ने किया। और जो बाइडन ने रूस को इससे बाहर ही कर दिया। इसका जवाब रूसियों ने SPFS और चीनियों ने CIPS के रूप में खोजा, जिसका इस्तेमाल कई देशों से व्यापार में हो रहा है।

ब्रिक्स में तनाव | रही बात ब्रिक्स मुद्रा की तो यह उतनी आसान नहीं है। ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी रूस के पास है और उसका प्रस्ताव बिटकॉइन आदि जैसी ब्रिक्स की एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का है। ध्यान रहे, अभी ब्रिक्स के दस देश मिलाकर दुनिया के 42% तेल का उत्पादन करते हैं। साढ़े तीन अरब, यानी दुनिया की लगभग आधी आबादी उनके पास है, जो तकरीबन 29% ग्लोबल GDP का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिक्स में भीतरी तनाव भी हैं। चीन के स्वाभाविक प्रभुत्व वाले इस खेमे का अभिन्न अंग बनकर रहना भारत के लिए संभव नहीं है, न ही ईरान से नजदीकी बनाए रखना सऊदी अरब और UAE के लिए बहुत आसान होने वाला है।

ठोस आधार नहीं | फिर भी मामला यह है कि ब्रिक्स का, और उसके पीछे दुनिया के कई देशों का एक अलग वित्तीय ढांचा समय की मांग है। एक ग्लोबल मुद्रा के रूप में डॉलर को 'फिएट मनी' यानी सिर्फ हुकुम पर चलने वाली मुद्रा कहा जाता है, जिसके पीछे अमेरिकी चमक-दमक की खबरों के अलावा स्थायी मूल्य वाला कोई ठोस आधार नहीं है।

डॉलर का स्वर्ण मूल्य | 1971 से पहले कम से कम कागजी तौर पर डॉलर का एक स्वर्ण मूल्य हुआ करता था, जबकि दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं डॉलर के साथ निश्चित विनिमय मूल्यों पर बंधी हुई थीं। यह व्यवस्था 1944 में द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका के न्यू हैंपशायर प्रांत के कैरल शहर की ब्रेटन-वुड्स नाम की बस्ती में हुई एक वित्तीय बैठक में बनाई गई थी और बाद में इसके तहत ही IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी।

सहमति टूटी | इस बैठक में तय किया गया था कि डॉलर की कीमत सोने के साथ 35 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से बंधी रहेगी और सम्मेलन में शामिल 44 देशों की मुद्राएं डॉलर के साथ इस तरह जुड़ी रहेंगी कि उनकी सापेक्ष कीमतों में 1% से ज्यादा उतार-चढ़ाव न आने पाए। वियतनाम युद्ध के चलते यह व्यवस्था 1971 में ध्वस्तप्राय दिखने लगी और 1976 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से दुनिया की सारी मुद्राएं आगे-पीछे 'फ्री-फ्लोट' कर रही हैं। यह व्यवस्था वैश्विक आम सहमति से ही चल सकती थी, जो काफी पहले भंग हो चुकी है।

हालत यह है कि अमेरिका और उसके करीबी मुल्कों के प्रतिबंधों से कई देश परेशान हैं। ब्रिक्स के रूप में इन देशों को इस दबदबे से मुक्त होने की गुंजाइश नजर आ रही है। चुनौती यही है कि ब्रिक्स की विनिमय प्रणाली बनाते हुए विश्व अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा झटका न लगने पाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जलती, पिघलती और हिलती धरती

अप्रैल शुरू ही हुआ है और मौसम का मिजाज समझ से बाहर होता जा रहा है। पर इसकी वजह भी है। रिपोर्ट आई है कि हर मिनट धरती से 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं। मई-जून की हीटवेव अभी आ गई है, आर्कटिक की बर्फ और तेज पिघल रही है। इन सब मुद्दों पर पिछले दिनों आई कई शोध रिपोर्टों के जरिए समझते हैं पूरा माजरा...

जलते-कटते जंगल

इंसान के साथ आग ने भी 2023 में वनों को जो नष्ट किया, उससे 24 करोड़ टन कार्बन निकला

37 करोड़ ha ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नष्ट 2023 में।

13.2 लाख ha प्राकृतिक जंगल नष्ट कांगो में

प्राथमिक वन नष्ट

- लाओस में 1.9%,
- निकारागुआ में 4.2%

(ha= हेक्टेयर)

बोलीविया में वनों के नष्ट होने की **स्पीड 27% बढ़ी।**

सबसे ज्यादा नुकसान ब्राजील, कांगो, इंडोनेशिया, पेरू, बोलीविया

भारत

21,672 ha प्राइमरी फॉरेस्ट नष्ट देश में।

2001-2023 के बीच 23.3 लाख ha ग्रीन शेड नष्ट।

6% गिरावट आई 2000 के बाद ग्रीन शेड में वृक्ष आवरण में।

95% ग्रीन शेड नुकसान 2013-2023 के बीच।

बढ़ती गरमी

20% धीमी हुई लू की गति 1979 से

ज्यादा समय तक रहती है लू गति कम होने से

67% बढ़ीं लू की घटनाएं

लू का तापमान और क्षेत्र 40 साल पहले की तुलना में बढ़ा।

यहां हीटवेव: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, झारखंड

प्रकृति में हस्तक्षेप

गरमी कम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश हुई

- इसके लिए बादलों में नमक ऐरोसेल छोड़ा गया।
- **नमक एरोसेल से बादल और चमकने लगते हैं।**
- बादलों के चमकने से सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती हैं।
- **प्रकृति में हस्तक्षेप की वैज्ञानिक कर रहे आलोचना।**

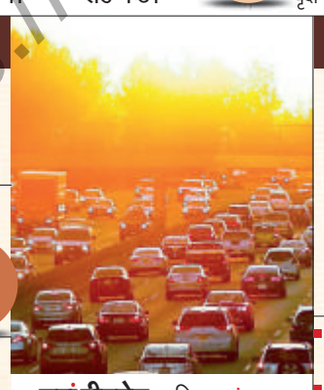

पिघलती बर्फ

12.2% प्रति दशक कम हो रही है आर्कटिक समुद्री बर्फ।

17% तक कम कर देती है आर्कटिक समुद्री बर्फ एल नीनो की तीव्रता को।

16 साल में पड़ने लगेगी आर्कटिक में गरमी।

- अल नीनो की विविधता में कमी हुई तो बढ़ सकती हैं चरम मौसम की घटनाएं
- **जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक शोधों को धक्का।**
- नीति निर्माताओं को नीति बनाने में दिक्कत।

इस साल भी गरमी बहुत तेजी से अप्रैल में बढ़ी है। कर्नाटक में तो गरमी से जंगलों में आग लगी हुई है। पानी का सूखा सबको मालूम है। ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्य का मुद्दा नहीं है, यह आज के जान-माल का मुद्दा है।

-चंद्रभूषण, CEO, iForest

(सोर्सः GFW, WRI, CWC, अल्बानी, नेचर, साइंस एडवांसेज)

कंटेंटः राहुल पाण्डेय, **ग्राफिकः** NBT

सूखती नदियां

महानदी और पेन्नार के बीच 13 नदियों में पानी खत्म।

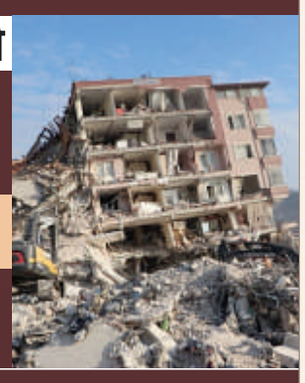

लगातार घटा गोदावरी बेसिन का भंडार।	12 नदी बेसिनों का भंडार 2023 से कम।

गंगा बेसिन में पानी का भंडारण **क्षमता का 41.2% है, 2023 से कम।**

36% गिरा देश के 150 प्रमुख जलाशयों का भंडार

नदियों में घटा पानी

- **46.2%** नर्मदा
- **56%** तापी
- **49.53%** महानदी
- **39.54%** साबरमती
- **34.76%** गोदावरी

डोलती धरती

7.5 तीव्रता का भूकंप बुधवार को ताइवान में आया।

ताइवान में 18 की मौत, 600 घायल।

पिछले हफ्ते ही US के न्यूयॉर्क-फिलाडेल्फिया तक झटके।

क्लाइमेट लिंक: जलवायु परिवर्तन भूकंपों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि सूखे की वजह से मौजूदा फॉल्ट लाइनें और खराब हो जाती हैं।

मद में चूर देशों के बीच छिड़ी है वर्चस्व की लड़ाई

साफ दिख रहा है कि दुनिया में आज ऐसे हिंसक युद्ध लड़े जा रहे हैं, जिनमें दोनों ही पक्ष खुद को पीड़ित बता रहे हैं। इतना ही नहीं दोनों अपने लिए न्याय भी मांग रहे हैं

देवदत्त पटनायक

15वीं शताब्दी से उपलब्ध पुर्तगाल की प्रसिद्ध मेडिरा वाइन का नाम संस्कृत शब्द मद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है नशा। यह इंडो-यूरोपीय शब्द 'मीड' से भी जुड़ा है, जिसका मतलब ऐसा पेय है जो देवताओं को प्रिय हो। खास तौर पर भारत में मद का मतलब उस तरल पदार्थ से होता है, जो यौन उत्तेजना की स्थिति में हाथी की कनपटी से निकलता है। ऐसा हाथी खतरनाक, अदम्य और हिंसक होता है। वह प्रतिद्वंद्वियों से लड़ता और उन्हें मारता है। यहां तक कि यह उन मादाओं को भी मार सकता है, जो सहमति नहीं देतीं। यह मिलन के बाद ही शांत होता है।

हिंदू संस्कृति में स्वीकार्य नहीं | इसी 'मद' से निकला है 'कामदेव' का एक नाम मदन। जब कोई व्यक्ति प्रेम, वासना या मोह के प्रभाव में होता है, तो उसकी हालत उत्तेजित हाथी की तरह होती है। यानी- बेकाबू, आक्रामक और जुनूनी। इस स्थिति में, इंद्रियां हावी हो जाती हैं। संवेदनशीलता के लिए कोई जगह नहीं बचती। जुनून तर्कशीलता को अवरुद्ध कर देता है। पारंपरिक हिंदू संस्कृति इस 'मद' को स्वीकार नहीं करती क्योंकि यह आत्मा पर ग्रहण और अहंकार के चरम को दर्शाता है।

वीर और महावीर | हिंदू मंदिरों में हम ऐसे जंगली हाथी की तस्वीरें पाते हैं, जिन्हें एक शक्तिशाली शेर कुचल रहा होता है। हाथी (गज) के ऊपर शेर का यह रूपांकन बहुत लोकप्रिय है। हाथी वीर है, हिंसक जुनूनी नायक, जो अपनी इंद्रियों से प्रेरित है। शेर महावीर है, एक वैरागी ऋषि की तरह, जो इंद्रियों को जीत चुका है। जहां अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही पुरानी लोक संस्कृतियों में वीर को पूजने का चलन था, लेकिन बाद की परिष्कृत और संपन्न संस्कृतियों में स्थिति बदल गई। इन संस्कृतियों में वीर के बजाय महावीर पूजे जाने लगे।

हाथी का संहार | बौद्धों के लिए बुद्ध महावीर हैं तो जैनियों के लिए तीर्थंकर। हिंदुओं के लिए शिव (हर) और विष्णु (हरि) दोनों महावीर हैं। इन सभी ने 'पागल हाथी' पर विजय पाई है। बुद्ध उस हाथी को शांत करते हैं, जो उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। तीर्थंकर के व्यक्तित्व से हाथी की आक्रामकता कम हो जाती है। कृष्ण ने कंस के उस शाही हाथी को मार डाला था, जिसे उन्हें कुचलने के लिए भेजा गया था। शिव गजासुर का संहार करते उसके सिर पर नृत्य करते हैं और उसकी खाल लपेट लेते हैं।

AI Image

कॉमन रूम

मद की बाढ़ | मौजूदा दुनिया में अपने आसपास हम मद यानी अहंकार की बाढ़ देख रहे हैं। इन दिनों युवाओं को बताया जा रहा है कि उन्हें इंस्टाग्राम पर उन लोगों की तरह व्यवहार करना है, जो खुद के प्रति जुनूनी होते हैं और जिन्हें लगता है कि दूसरे केवल उनकी प्रशंसा करने के लिए हैं। दुनिया में आज हिंसक युद्ध लड़े जा रहे हैं, जहां दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बताते हैं और अपने लिए न्याय मांगते नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में राक्षसी व्यवहार भी आत्मरक्षा का रूप ले लेते हैं।

वर्चस्व की लड़ाई | ये 'पागल हाथी' क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे कोई नहीं रोक सकता। पश्चिमी वर्चस्ववाद की यही तार्किक परिणति होनी है, जहां केवल दो ही विकल्प दिए जाते हैं: व्यक्तिवाद (केवल अपने बारे में सोचना) और सामूहिकतावाद (केवल अपने समूह के बारे में सोचना)। इस नजरिए में दूसरा या तो संसाधन होता है या प्रतिद्वंद्वी।

हिंसा से भरी ऐसी दुनिया तभी स्वीकार्य हो सकती है जब अस्तित्व का संघर्ष चल रहा हो। तब नहीं जब आप संपन्न हों और आपके पास आराम करने, विचार करने और पहले अंदरूनी, फिर बाहरी 'पागल हाथी' को रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

(बिजनेस सूत्र के लेखक का यह आलेख 30 मार्च को THE ECONOMIC TIMES में प्रकाशित हुआ था, जिसके हिंदी अनुवाद का यह संक्षिप्त और संपादित रूप है)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

धर्म वही है जो शरीर और मन को प्रकृति से जोड़े

आनंदमूर्ति गुरुमां

धर्म मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है। धर्म का अर्थ कोई विशिष्ट परंपरा, संप्रदाय या दर्शनशास्त्र बिल्कुल नहीं। जो जैसा है उसको वैसा ही खोजने, पहचानने और जानने को हम धर्मयात्रा कहेंगे। मेरी दृष्टि में धर्म एक विश्वास नहीं, धर्म एक खोज है। धर्म एक सीढ़ी है, जिस पर निरंतर चढ़ते हुए व्यक्ति वैचारिक रूप से ऊंचा उठता जाता है। धर्म आस्था नहीं है, क्योंकि आस्था कभी भी अनास्था में बदल सकती है। ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव मनुष्य की आस्था और अनास्था से परे है।

बहुत-से लोग धर्म को विश्वास का नाम भी दे देते हैं, लेकिन धर्म विश्वास नहीं हो सकता। वजह कि विश्वास हमेशा बदलते रहते हैं। विश्वास का संबंध मनुष्य की धारणाओं से होता है और धारणाओं का संबंध मान्यताओं से होता है। फिर मान्यताएं, धारणाएं जिस मन से निकलती हैं, वह मन सदैव बदलता रहता है। आस्था और विश्वास तो बदलते रहते हैं, पर सत्य हम उसी को कहते हैं जो अपरिवर्तनशील है। जो परिवर्तित हो जाए उसे हम सत्य नहीं कह सकते। जो सदैव एकरस, समरस रहे, उसी को हम सत्य कहते हैं। इसी सत्य की खोज को धर्म कहते हैं। आस्थाओं और अनास्थाओं से ऊपर विश्वास और अंधविश्वास से भी ऊपर, अपनी बुद्धि की क्षमताओं और अपनी बुद्धि की सीमाओं को समझते हुए जब मनुष्य का मन अपनी उस निजता की खोज करता है, तब इसी को हम धर्म कहते हैं।

जहां आप अपने मन के स्वभाव और मन की कार्यप्रणाली को समझते हैं, वहीं धर्म है। जीवन के शुरू और अंत होने के उस काल, उस क्रम को समझते हैं। प्रकृति किस प्रकार हमारे शरीर और मन पर अपने गहरे प्रभाव छोड़ती है और किस प्रकार हमारा मन प्रकृति के अधीन है, इसकी समझ होना धर्म है। एकाग्रचित्त मन ही ऐसी सोच ला सकता है और एकाग्र मन ही चिंतन कर सकता है। मंदिर में देवमूर्ति, देवदर्शन, इष्टदर्शन के माध्यम से मन को एकाग्र करने का अगर कोई साधन है, तो निश्चय ही वह भी बहुत लाभकारी हो सकता है।

एक वह मनुष्य है जो अपनी इंद्रियों और शरीर का दास है, पर एक वह मनुष्य है जो अपनी इंद्रियों और मन के दायरे से बाहर निकलकर अपने निज स्वभाव में आत्मनिष्ठ होता है। लेकिन हर यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आपके निजस्वरूप के अनुभव का ख्याल ही आपको धर्म के इस मार्ग पर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह धर्म की यात्रा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संसार क्या है? संसार क्यों है? मैं क्यों हूं? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं कहां जाऊंगा? अगर ये प्रश्न रात या दिन में कभी चित्त को नहीं खदेड़ते, तो जिसे यही नहीं पता कि वह आया कहां से है और जाएगा कहां और वह जी भी क्यों रहा है, तो ऐसे मनुष्य का जीवन भी क्या कोई जीवन होता है? वह अपनी ही अज्ञानता की जंजीरों में जकड़े हुए बंधनग्रस्त, व्यथित, पीड़ित, रोगी मन से जीवन जीता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं,जिनके चित्त में ये प्रश्न उठते हैं। वे निश्चय ही बेहद भाग्यशाली हैं।

जीवन जीने का एक नया पाठ सीखें। कौन हूं मैं? कौन है ईश्वर? कौन है वह परम शक्ति? इसे अपनी खोज बनाएं। इसे अपनी आस्था नहीं, इसे अपना अनुभव बनाएं। ऐसी एक शुभ शुरुआत आप सभी पाठकों के जीवन में हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपना प्रेम सबको भेजती हूं।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.

संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

बढ़ता पारिवारिक कर्ज

हमारे देश में हाल के वर्षों में पारिवारिक कर्ज में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है. वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2023 में घरेलू कर्ज अपने सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया. सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में पारिवारिक ऋण का अनुपात 40 प्रतिशत हो गया है. साथ ही, जीडीपी में पारिवारिक बचत का अनुपात लगभग पांच प्रतिशत रह गया है, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है. उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष सितंबर में बताया था कि परिवारों की बचत का अनुपात वित्त वर्ष 2022-23 में 5.1 प्रतिशत हो गया, जो 47 वर्षों में सबसे कम है. यह सही है कि बचत कम कर और कर्ज लेकर बहुत से लोग परिसंपत्तियां या उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते हैं. ऐसे लोग भविष्य में अपनी आमदनी को लेकर आश्वस्त रहते हैं या उन्हें अपने निवेश से लाभ होने की आशा रहती है. लेकिन विभिन्न आंकड़ों के साथ बचत में कमी और कर्ज बढ़ने के मसले को देखें, तो चिंताजनक तस्वीर उभरती है. वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू कर्ज जीडीपी के 38 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था. इससे अधिक आंकड़ा केवल 2020-21 में रहा था, जो कि महामारी की भयावह मार का साल था. हालिया रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि घरेलू कर्ज में वृद्धि में सबसे प्रमुख हिस्सा पर्सनल लोन का है. उल्लेखनीय है कि ऐसे लोन में ब्याज की दर भी बहुत अधिक होती है. माना जाता है कि पर्सनल लोन बहुत मजबूरी में ही लोग लेते हैं. क्रेडिट कार्ड से खर्च और डिफॉल्ट में भी वृद्धि हो रही है. रिजर्व बैंक पहले ही असुरक्षित कर्जों के बारे में बैंकों को सचेत रहने की सलाह दे चुका है. हालांकि वृद्धि दर उत्साहजनक है, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी अपेक्षा के अनुसार नहीं है. महंगाई की वजह से भी परिवारों पर दबाव बढ़ा है. मुद्रास्फीति के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है, पर रिजर्व बैंक ने बार-बार कहा है कि यह अभी भी चिंता का कारण बना हुआ है. इसी कारण से हालिया मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती नहीं की गयी है. चूंकि आमदनी में बढ़त धीमी है, तो उसका असर उपभोग पर पड़ना स्वाभाविक है. वित्त वर्ष 2023-24 में पारिवारिक निवेश और निजी उपभोग दोनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गयी है. यदि बचत बढ़ाने, असुरक्षित कर्ज घटाने तथा उपभोग बढ़ाने पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया, आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. आर्थिक विकास का लाभ आबादी के अधिकाधिक हिस्से तक पहुंचे. इस दिशा में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है. बचत और कर्ज में संतुलन बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

हालांकि वृद्धि दर उत्साहजनक है, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी अपेक्षा के अनुसार नहीं है. महंगाई की वजह से भी परिवारों पर दबाव बढ़ा है.

भारत की स्त्रीवादी विरासत है द्रौपदी

प्रो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित
कुलपति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली
santishreepandit@gmail.com

भारतीय इतिहास, समाज एवं चेतना में पैबस्त द्रौपदी में रहस्यात्मक जटिलता है. वह मानवीय अनुभव की द्वैध प्रतीक है- वह स्त्रैण, करुणामयी और उदार है, पर अपने साथ अनुचित होने पर वह प्रतिरोध की क्षमता भी रखती है. महाभारत में जो अपमान उसके साथ हुआ, वह हृदयविदारक है. उस परिघटना की गूंज पूरे महाभारत में और बाद में भारतीय समाज और इतिहास में बनी रही.

भारतीय संरचना में नारीवाद उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, जिसकी आयु आठ हजार वर्ष की है. मातृ देवी की अवधारणा प्रकृति-केंद्रित ब्रह्मांड में संतुलन एवं साहचर्य को स्थापित करने का लैंगिक विचार है, जो मानव-केंद्रित विश्व में परस्पर विरोध के द्वैध के विपरीत है. ऐसे आख्यानों को बार-बार कहने, उनकी पुनर्कल्पना और पुनर्रचना करने की आवश्यकता है. वे कथाएं और स्त्री चरित्र पितृसत्ता की पीड़िता बन गयीं और उन्हें परंपरा के सुविधाजनक आवरण तक सीमित कर दिया गया और अति प्रतिगामी बना दिया गया. प्रभावशाली व्यक्तिगत कथाओं के बावजूद हमारे पौराणिक आख्यानों के महिला चरित्रों को बहुत हद तक अनदेखा किया गया है. दुर्भाग्य से पौराणिक आख्यानों की पूर्वाग्रहयुक्त व्याख्या ने एक प्रकार से हमारे समाज की स्त्रियों के बारे में हमारी समझ को गढ़ा है. लेकिन हम उन्हीं कथाओं का उपयोग कर विस्मृत या बिगाड़े गये चरित्रों को पुनः गढ़ सकते हैं और पूर्ववर्ती समझ की आलोचना के लिए उनका रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं. दशकों से बहुत से भारतीयों ने पश्चिम से पहचान पाने की कोशिश में अपनी संस्कृति एवं अपने इतिहास को खारिज किया है. इससे ऐतिहासिक विस्मृति उत्पन्न हुई और जान-बूझकर उपेक्षा की स्थिति बनी, जिससे अपने सभ्यतागत अतीत की भारत की समझ पर असर पड़ा. लोगों का शासन होने का विचार या न्याय एवं लैंगिक समानता की अवधारणा केवल पश्चिम के खाते में नहीं है. यह समझ तो और भी दोषपूर्ण है कि पश्चिमी चिंतकों द्वारा इन्हें बताने के पहले दुनिया को इन अवधारणाओं का पता ही नहीं था. भारत एवं अन्य कई सभ्यताओं ने इन अवधारणाओं पर लंबे समय तक विचार किया है तथा इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

भारत के पास नारी शक्ति की समृद्ध परंपरा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मेधा एवं साहस तथा व्यवस्था में बुराई व दोष को चुनौती देने के माध्यम से हुई. महाभारत में द्रौपदी (पांचाली) भारतीय इतिहास में एक मौलिक नारीवादी उपस्थिति है, जो अपने सतत प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है. भारतीय संस्कृति में नारीवाद के और भी उदाहरण हैं. रामायण की सीता में भी स्त्रीवादी आदर्श हैं, जो अधिक महीन हैं. एकल माता के प्रारंभिक उदाहरणों में एक सीता ने पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी, हालांकि उनके चरित्र को अक्सर अधिक अनुवर्ती दृष्टि से देखा जाता है. प्राचीन भारत में स्त्रियों द्वारा सीमाओं को तोड़ना अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य परिघटना थी. इतिहास में स्त्रियों ने गणितज्ञ, दार्शनिक और वैदिक साहित्य की विदुषी के रूप में अपनी छाप छोड़ी है. यह बात इस समझ को चुनौती देती है कि नारीवाद एवं लैंगिक समानता पश्चिम से आयातित हैं. यह कहना निहायत अनुचित है कि भारत ने इन अवधारणाओं को पश्चिम से ग्रहण किया है. सच तो यह है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में सशक्त महिलाओं की सुदीर्घ परंपरा है, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

भारतीय इतिहास, समाज एवं चेतना में पैबस्त द्रौपदी में रहस्यात्मक जटिलता है. वह मानवीय अनुभव की द्वैध प्रतीक है- वह स्त्रैण, करुणामयी और उदार है, पर अपने साथ अनुचित होने पर वह प्रतिरोध की क्षमता भी रखती है. महाभारत में जो अपमान उसके साथ हुआ, वह हृदयविदारक है. उस परिघटना की गूंज पूरे महाभारत में और बाद में भारतीय समाज और इतिहास में बनी रही. वैसी स्थिति में उसके प्रतिरोध से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं. पहला, अपने साथ हुए अन्याय की जो निंदा उन्होंने शब्दों में की है, वह अभूतपूर्व है. राजदरबार में, जहां उसके साथ अन्याय हुआ था, द्रौपदी ने बड़ों एवं दरबारियों के सामने निर्भय होकर उनके उत्तरदायित्व को याद दिलाया, जो चुपचाप बैठे हुए थे. अपने शब्द कौशल से उसने दरबार के लोगों के राजा धृतराष्ट्र और राजकुमार दुर्योधन के प्रति समर्पण को रेखांकित किया तथा उसके बरक्स उनके नैतिक व नीतिगत कर्तव्य को सामने रखा. उनके अनुचित समर्पण पर द्रौपदी का साहस के साथ प्रश्न उठाना अंधानुकरण पर नैतिकता के महत्व का समयातीत स्मारिका है. दूसरी बात यह कि द्रौपदी के शब्द और कार्य भारतीय संस्कृति एवं समाज का मार्मिक प्रतिबिंब हैं, विशेषकर तब जब समाज अन्यायपूर्ण आचरण के गलत रास्ते पर भटक जाता है. सामाजिक उथल-पुथल के बीच वह अनुचित का साहसी प्रतिकार कर और न्याय की पैरोकारी कर शोधन का प्रतीक बनकर उभरती है. इस प्रकार, केवल पुरुष चरित्र ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयासरत नहीं थे, बल्कि स्त्रियों ने भी अमूल्य योगदान दिया है. द्रौपदी का अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार करना समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है, जो अपने समुदाय को सही राह पर अग्रसर करने के लिए समर्पित थी.

तीसरा निष्कर्ष यह है कि द्रौपदी का प्रतिकार व्यक्तिगत परिवेश से परे जाकर व्यापक लैंगिक अनुक्रम को चुनौती देता है. उसका क्रोध, साहस और दृढ़ निश्चय स्त्री के वस्तुकरण के विरुद्ध शक्तिशाली प्रतिरोध हैं. उसने अपनी त्रासदी को नारी शक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तित कर दिया. अंतिम बात, द्रौपदी की कथा इतिहास और समाज को गढ़ने में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका का एक उदाहरण है. उसकी त्रासदी बेहद गंभीर है, उससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले व्यापक अन्यायों पर प्रकाश पड़ता है. अपनी नियति को स्वीकार करने से उसका इनकार लैंगिक समानता का ठोस आह्वान है, जो अन्यों को भी अधिकारों एवं न्याय के लिए प्रेरित करता है. भगवान कृष्ण ने रेखांकित किया है कि द्रौपदी के साथ जो हुआ, उसका दायरा पांडवों की चिंता से कहीं अधिक है. यह स्त्रियों की व्यापक चिंता और समाज में धर्म को बनाये रखने से जुड़ा हुआ था. समकालीन समाज में द्रौपदी के संघर्ष की गूंज बनी हुई है. द्रौपदी की वास्तविक विरासत का सामना करने से बचने की कोशिश घरेलू हिंसा, अत्याचार और लैंगिक विषमता के गंभीर मुद्दों के समाधान से हिचक को प्रतिबिंबित करता है. यह एक स्त्रीवादी सभ्यता है, जहां स्त्रैण की विजय का उत्सव दशहरे में मनाया जाता है. सबसे शक्तिशाली देवियां ही हैं और पुरुष देवों के नाम उनकी अर्द्धांगिनियों के नाम पर हैं- सीतापति, उमापति और लक्ष्मीपति. द्रौपदी के साहस को रेखांकित कर हम उसकी विरासत का सम्मान कर रहे हैं तथा अधिक समावेशी एवं समतामूलक समाज का रास्ता बेहतर कर रहे हैं. **(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)**

कच्चातिवु समझौते की शर्तों पर जोर दिया जाए

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
pc7001010@gmail.com

भारत एवं श्रीलंका के बीच अच्छे संबंधों की सलामती के लिए कच्चातिवु द्वीप और मछुआरों का विवाद बड़ी चुनौती हैं. हालांकि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के अनुसार जल सीमा निर्धारण और उस द्वीप को वापस लेना सरल नहीं है, लेकिन समझौते की शर्तों पर जोर दिया जाए, तो हमारे मछुआरों के लिए बढ़िया होगा.

यह कड़वा सच है कि हमारे मछुआरे आये दिन श्रीलंका की सीमा में घुस जाते हैं और फिर उनके नारकीय दिन शुरू हो जाते हैं. जैसे तैसे छूट भी आते हैं, तो उनके जीवनयापन का जरिया नावें वहीं रह जाती हैं. इस त्रासदी के निदान के लिए कच्चातिवु द्वीप एक भूमिका निभा सकता है. उसे वापस लेने के बजाय निर्धारित शर्तों के कड़ाई से पालन की बात हो, तो भारतीय मछुआरों के लिए उचित ही होगा. लेकिन यह समझना होगा कि यह चुनावी मुद्दा नहीं है क्योंकि भारत ने भी श्रीलंका से इसके एवज में बेशकीमती जमीन ली है. कच्चातिवु द्वीप 285 एकड़ का हरित क्षेत्र है, जो एक नैसर्गिक निर्माण है और ज्वालामुखी विस्फोट से 14वीं सदी में उभरा था. इसका अधिकार 17वीं सदी में मदुरै के राजा के पास होने के दस्तावेज हैं. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यह द्वीप मद्रास प्रेसीडेंसी में था. इस पर मछुआरों के दावों को लेकर 1921 में भी सीलोन यानी श्रीलंका और भारत के बीच विवाद हुआ था. साल 1947 में इसे भारत का हिस्सा माना गया, पर श्रीलंका इस पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था. इंदिरा गांधी के दौर में भारत के श्रीलंका से घनिष्ठ संबंध थे. कोलंबो में 26 जून 1974 और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों ने एक समझौता किया, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया.

समझौते के मुताबिक, दोनों देशों के मछुआरे कच्चातिवु का उपयोग आराम करने और अपने जाल सुखाने के साथ-साथ वहां सेंट एंथोनी चर्च में पूजा कर सकते थे. साल 1983 तक ऐसा होता भी रहा. तब भारतीय मछुआरों की संख्या कम थी और जाफना में अशांति भी नहीं थी. अब श्रीलंका की सेना भारतीय मछुआरों को उधर फटकने नहीं देती. यह सच है कि भाजपा से जुड़े मछुआरों के संगठन की लंबे समय से मांग रही है कि इस टापू को यदि वापस लिया जाता है, तो भारतीय मछुआरों को जाल डालने के लिए अधिक स्थान मिलेगा और वे श्रीलंका की सीमा में गलती से भी नहीं जायेंगे. लेकिन यह भी सच है कि आज जिस द्रमुक को इसके लिए जिम्मेदार कहा जा रहा है, वह 1974 के बाद कई बार भाजपा के साथ सत्ता में हिस्सेदार रहा है. यह भी सच है कि तमिलनाडु के मछुआरों का एक वर्ग कच्चातिवु के समझौते से खुश नहीं था. फिर भारत और श्रीलंका के बीच 1976 में एक और करार हुआ, जिसके तहत श्रीलंका ने हमें कन्याकुमारी के करीब वेज बैंक सौंप दिया, जो 3,000 वर्ग किलोमीटर में फैला द्वीप है. इस संधि से भारतीय मछुआरों को इलाके में मछली पकड़ने का अधिकार मिला. इसके तीन साल बाद श्रीलंकाई मछुआरों के वहां जाने पर रोक भी लगा दी गयी. वेज बैंक कच्चातिवु जैसे निर्जन द्वीप के मुकाबले अधिक सामरिक महत्व का और कीमती है. यहां तेल एवं गैस के बड़े भंडार भी मिले हैं.

मछुआरों की समस्या को समझे बगैर कच्चातिवु के महत्व को नहीं समझा जा सकता. रामेश्वरम के बाद भारतीय मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा लगभग 12 समुद्री मील मिली है. इसमें भी छोटी नावों के लिए पहले पांच समुद्री मील छोड़े गये हैं. गत एक दशक के दौरान हमारे तीन हजार से ज्यादा मछुआरे श्रीलंका सेना द्वारा पकड़े गये, जिनमें से कई को गोली लगी और जान भी गयी. सैंकड़ों लोग सालों तक जेल में भी रहे. भारत और श्रीलंका में साझा बंगाल की खाड़ी के किनारे रहने वाले लाखों परिवार सदियों से समुद्री मछलियों से अपना पेट पालते आये हैं. जैसे मछली को नहीं पता कि वह किस मुल्क की सीमा में घुस रही है, वैसे भारत और श्रीलंका भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि समुद्र के असीम जल पर सीमा कैसे खींची जाए. यह भी कड़वा सच है कि जब से शहरी बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, तब से गोदी के कई-कई किलोमीटर तक तेल रिसने, शहरी सीवर डालने व अन्य प्रदूषणों के कारण समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है. अब मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए काफी दूर निकलना पड़ता है. खुले सागर में सीमाओं को तलाशना लगभग असंभव होता है.

दोनों देशों के बीच मछुआरा विवाद की एक बड़ी वजह हमारे मछुआरों द्वारा इस्तेमाल नावें और तरीके भी हैं. हमारे लोग बॉटम ट्रॉलिंग के जरिये मछली पकड़ते हैं. इसमें नाव की तली से वजन बांध कर जाल फेंका जाता है. इस तरीके को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदेह माना जाता है. श्रीलंका में ऐसी नावों पर पाबंदी हैं. तभी श्रीलंका सीमा में हमारे मछुआरे अवैध तरीके से मछली पकड़ने के दोषी बन जाते हैं. श्रीलंका के सुरक्षा बल भारतीय तमिलों को संदिग्ध नजर से भी देखते हैं. भारत एवं श्रीलंका के बीच अच्छे संबंधों की सलामती के लिए कच्चातिवु द्वीप और मछुआरों का विवाद बड़ी चुनौती हैं. हालांकि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के अनुसार जल सीमा निर्धारण और उस द्वीप को वापस लेना सरल नहीं है, लेकिन समझौते की शर्तों पर जोर दिया जाए, तो हमारे मछुआरों के लिए बढ़िया होगा. साल 2015 में ही हमने बांग्लादेश के साथ भूमि लेन-देन का बड़ा समझौता किया था. यदि पूर्ववर्ती सरकारों के समझौतों को चुनावी मुद्दा बनाया जायेगा, तो हमारी साख गिरेगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

साझा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए रूस की पेशकश

विगत वर्षों में चंद्रमा मिशन फिर से अन्वेषण के केंद्र में है. कई राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ-साथ निजी कंपनियां पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पड़ोसी के लिए मिशन शुरू कर रही हैं और इसकी सतह पर मानव बस्तियों से लेकर जल खनन कार्यों और दूरबीनों तक सब कुछ बनाने की योजना बना रही हैं. रूस ब्रिक्स ढांचे के भीतर चंद्रमा पर संयुक्त खोज अभियान आयोजित करने की योजना बना रहा है. रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के चंद्रमा कार्यक्रम के पहले चरण के वैज्ञानिक निदेशक लेव ज़ेलेनी ने कहा है कि ब्रिक्स के ढांचे के भीतर चंद्रमा की खोज पर व्यापक सहयोग आयोजित करने पर विचार चल रहा है, जिसमें भारत, चीन और अन्य देश हों. ये अभी भी केवल योजनाएं हैं, शायद हम निकट भविष्य में ब्रिक्स देशों की बैठक में इन पर चर्चा करेंगे.' अंतरिक्ष गतिविधियां मनुष्य जीवन के लगभग हर पहलू में गहराई से अंतर्निहित हैं. दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, वैश्विक वित्तीय लेन-देन को रेखांकित करना, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान को बढ़ावा देना और सैन्य क्षेत्र में असीमित लाभ को सक्षम करना, ये सभी चीजें अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी हुई हैं. अगले दशक में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन एक चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, एक साहसिक कदम के रूप में रूस और चीन 2033 और 2035 के बीच चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना भी बना रहे हैं. रूस नियमित रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को अंतरिक्ष संबंधी सहयोग की पेशकश करता है तथा भागीदारों के साथ राजनीतिक तालमेल पर जोर देता है.

-सत्येंद्र प्रताप सिंह

बोधि वृक्ष

सफलता का शिखर

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलता का शिखर छूना चाहता है, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है. इसका सबसे बड़ा कारण है, उचित मार्गदर्शन का अभाव. प्राचीन भारत में लगभग साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व एक योगी राजा हुए थे- युधिष्ठिर. उनके मार्गदर्शक भगवान कृष्ण थे. कृष्ण महान योगी थे. उनके नाम का अर्थ हुआ, जो युद्ध के मैदान में भी अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखता है, वह युधिष्ठिर है. वे योगी भी थे. योगी का अर्थ है व्यवहारिक मनुष्य. एक योगी को सिद्धांत से कुछ लेना-देना नहीं है. उनसे एक प्रश्न पूछा गया- 'उचित पथ क्या है, यानी उचित मार्ग क्या है?' राजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया- 'व्यावहारिक मनुष्य का ही अनुसरण करना चाहिए, सिद्धांतवादी का नहीं. सिद्धांत व्यवहार के क्षेत्र में सफल नहीं भी हो सकता है, पर व्यावहारिक जीवन में यह उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी. इसलिए योगी को, आध्यात्मिक साधक को व्यावहारिक मनुष्य का ही अनुसरण करना चाहिए और योगी को महायोगी का अनुसरण करना चाहिए. लेकिन शास्त्र एक-दूसरे से अलग मत रखते हैं. सभी शास्त्रों के समर्थक कहते हैं, 'हमारा संदेश ईश्वर का है, यही अंतिम शब्द है.' यदि सभी शास्त्र एक ही परमात्मा के संदेश हैं, तब वे एक-दूसरे से भिन्न राय क्यों रखते हैं? परमात्मा एक है और यदि सभी शास्त्र उनके ही संदेश हैं, तब उनमें कोई मतांतर नहीं होना चाहिए. जैसा कि योगी राजा युधिष्ठिर ने कहा, 'जीवन का परम लक्ष्य, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी का एक है.' वह परम लक्ष्य कहां है? आध्यात्मिकता का सार प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपा है. तुम अनेक लोगों को जानने की कोशिश करते हो, पर तुम स्वयं को नहीं जानते हो. यदि तुम सभी को जानना चाहते हो, एक को जानो और वह एक तुम्हारा अपना 'मैं' है. सबसे पहले तुम्हें अपनी सारी अभिलाषाओं के साथ तुम्हारे स्वयं के 'मैं' के संपर्क में आना चाहिए. प्रयोगशाला में किसी सिद्धांतवादी से तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी, तुम्हारे अनुसंधान में कुछ सहायता नहीं कर सकेगा.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

नयी शुरुआत का माह

कविता विकास
लेखिका
kavitavikas28@gmail.com

अप्रैल यानी वसंत के आगमन का पहला महीना, जब पेड़-पौधों में नयी कोपलें और नये पत्तों का आगमन होता है. साल का सबसे संतुलित माह है यह, जब न तो गर्मी होती है और न सर्दी. वसंत के समय खिलने वाले सारे फूल सुख और खुशी के प्रतीक हैं. नयी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का उपयुक्त समय है यह. मन में संवेगात्मक तरंगों की प्रचुरता होती है, इसलिए ध्यान, भक्ति और योग की दिशा में आगे बढ़ने का उत्तम समय है यह. चरमराते सूखे पत्तों की सेज पर खड़ा लंबी-लंबी टहनियों वाला साल हो या अमलतास, जब झूम-झूम कर हवा से बातें करता है, तो मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है. बर्फ बनी हिमालयी नदियां अपनी जकड़न खोलने लगती हैं. कवियों की कल्पना में अप्रैल ठूंठ पड़े वृक्षों में पल्लव आने का महीना है. प्रेम का अंकुर फूटने का माह है. पहला प्रेम, पहला बीज-स्फुटन कोई नहीं भूलता है. इनके पनपने के लिए जो वक्त चाहिए, वही तो अप्रैल है. जो फसलें कट कर आ जाती हैं, उनसे भरे-पूरे भंडार गृह को देख-देख कर किसान फूले नहीं समाते हैं. अब पुनः उसी माटी को जोतने का समय आ जाता है- फिर एक नयी शुरुआत. व्यावसायिक व वित्तीय क्षेत्रों में पुरानी उपलब्धियों का आकलन कर नयी रूप रेखा बनायी जाती है. स्कूल-कॉलेजों में नये सत्र का आरंभ होता है. छोटे बच्चों में नये बैग, नये यूनिफॉर्म और नयी कक्षा का खिंचाव होता है. किशोरवय में चेहरे की चमक बढ़ जाती है. अप्रैल प्यार का प्रतीक है, जो हर साल समय के भागते क्रम में आता है और हमें पुनर्जीवित कर चला जाता है. जीवन की आपाधापी, एकरसता और शिथिलता को भगाने के लिए, प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताने के लिए तथा सूर्य की उन नेह किरणों को आत्मसात करने के लिए इससे बढ़िया अवधि शायद ही हो. वड्र्सवर्थ ने इसी महीने खिलने वाले डेजी के फूल की सुंदरता से वशीभूत होकर कई कविताएं लिखीं. कई मोटिवेशनल लेखकों ने अप्रैल की शुष्कता और बसंत की मोहकता से जीवन के राग और लय को जोड़ा है.

यह माह अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर देता है. देवी की आराधना की जाती है. नयी चुनौतियों के लिए तैयार होना मनुष्य के हाथ में है, इसलिए उसे प्रकृति के रहस्यों से भी परिचित होना चाहिए. हर अच्छा अनुभव जीवन का वसंत काल होता है. वसंत के लिए पलकें बिछी हों, तो शरद के लिए भी आतुरता हो. हेमंत की रूमानियत बनी रहे, तो शिशिर का भी इंतजार हो. चित्त से नकारात्मकता, अवसाद और घुटन निकाल कर ऐसा रिक्त कर दें कि केवल उमंग, उत्साह और जोश के लिए जगह हो, चाहे मौसम मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल.

आपके पत्र

यात्री शेड व पानी की हो व्यवस्था

बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, लेकिन हॉल्ट पर सुविधा नहीं के बराबर है. यात्रियों की सुविधा के लिए शेड बनाने के साथ पेयजल का इंतजाम करना चाहिए. चिलचिलाती धूप में यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है. छोटे हॉल्टों पर ग्रामीण इलाकों के यात्री अधिक होते हैं. पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं व बच्चों को फजीहत उठानी पड़ती है. भीषण गर्मी को देखते हुए रेल प्रशासन जल्द यात्री शेड बनाने पर विचार करें.

एस कुमार, वैशाली

ऑनलाइन जुआ पर रोक जरूरी

अभी आइपीएल चल रहा है. इस दौरान ऑनलाइन सट्टा का बाजार काफी गर्म है. कानून की नजर में जुआ खेलना और सट्टा लगाना अपराध की श्रेणी में आता है. लेकिन, जुआ खेलाने के लिए कई ऑनलाइन एप आ गये हैं. ड्रीम11, माइ 11 सर्कल ,एमपीएल, रमी जैसे बड़े-बड़े एप पर सरकार खामोश है. इसका नतीजा यह है कि युवाओं को कंपनियां लूट रही हैं. इतना ही नहीं बड़े-बड़े स्टार इन एप का प्रमोशन करते हैं. सरकार को इन एप को भी एक सीमा में बांधना चाहिए. इससे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है.

अल्पना कुमारी, नालंदा

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

शेयर बाजार की छलांग

मंगलवार को जब देश हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष में कदम रख रहा था, और चैत्र नवरात्रि की प्रथम पूजा में जगह-जगह देशवासियों की सुख-समृद्धि की कामनाएं की जा रही थीं, लगभग उसी समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी। बीएसई के तीस शेयरों वाले सेंसेक्स ने पहली बार 75 हजार की मोहक ऊंचाई को लांघा। हालांकि, बाद में वह 74,683 अंक पर आकर बंद हुआ, फिर भी निवेशकों की इस उम्मीद को आधार तो दे ही गया कि वह दिन दूर नहीं, जब सेंसेक्स एक लाख की जादुई सीमा पर खड़ा होगा। चर्चित निवेशक मार्क मोबियस की मानें, तो यह कामयाबी अगले पांच वर्ष में ही मिल सकती है और यह अस्वाभाविक आकलन भी नहीं है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में ही शेयर बाजार ने 70 हजार अंक की छलांग लगाई है। सुखद बात यह है कि शेयर बाजार के साथ-साथ मंगलवार को सर्राफा बाजार में भी रौनक का आलम था। सोने-चांदी जैसी धातुएं भी नई ऊंचाई को छू रही थीं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, जब रिकॉर्ड जीएसटी वसूली के आंकड़े सामने आए थे।

निस्संदेह, ये सारी बातें देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के ठोस संकेत देती हैं। मगर इन आंकड़ों के बरक्स कुछ ऐसे ब्योरे भी सामने आए हैं, जिनकी ओर नीति-नियंताओं का ध्यान खींचे जाने की जरूरत है। जिस समय हम अपने पूंजी बाजार की ऊंची उड़ान पर लहालोट हैं, लगभग उसी समय वित्तीय सेवाओं से ही जुड़ी कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि भारतीय परिवारों पर कर्ज बढ़कर जीडीपी का 40 प्रतिशत हो गया है, जबकि उनकी बचत जीडीपी की करीब पांच फीसदी रह बची है। खुद आरबीआई ने पिछले साल सितंबर में भारतीय परिवारों पर बढ़ते कर्ज को लेकर आगाह किया था। वैसे, बढ़ती आर्थिक विषमता सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर के अर्थशास्त्री इसे लेकर लगातार अपनी चिंताएं जता रहे हैं।

आर्थिक मजबूती का लाभ पूंजी बाजार के आगे यदि संस्थागत विकास को मिलता है, तो अगले कुछ सालों में देश एक बड़े सामाजिक बदलाव का गवाह बन सकेगा।

हमारी समस्या यह है कि एक बड़ी भारतीय आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव इस आबादी को अतिरिक्त संवेदनशील बना देता है। बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना-काल ने इस सामाजिक हकीकत से हमें अच्छी तरह रूबरू करा दिया है। यकीनन, सरकार ने महामारी का अपने तईं अच्छा मुकाबला किया, मगर हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश की एक विशाल आबादी को मुफ्त राशन मुहैया कराने की योजना आज तक जारी है। हमने विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के जरिये हाशिये के लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, मगर कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास जैसी सामाजिक तरक्की की विभिन्न कसौटियों पर उन्हें ऊपर लाने के लिए अभी भी काफी कोशिश करने की आवश्यकता है। निस्संदेह, जब अगली जनगणना होगी, तब हमारी सामाजिक तरक्की की मुकम्मल तस्वीर सामने आ पाएगी। इस वक्त दुनिया के निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यदि इसका लाभ पूंजी बाजारों के आगे संस्थागत विकास को मिलता है, तो यकीनन अगले पांच साल में बीएसई के लखटकिया होने के साथ-साथ देश एक बड़े सामाजिक बदलाव का गवाह बन सकेगा, वरना अरबपतियों की तादाद में कुछ हजार नाम और जुड़ जाएंगे और करोड़ों की आबादी बुनियादी जरूरतों लायक आय के लिए संघर्ष करती मिलेगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 10 अप्रैल, 1949

यह शांति का मार्ग नहीं

आजकल संसार में शांति के लिए जितना अधिक प्रयत्न किया जा रहा है, उतना ही संघर्ष का भय भी बढ़ता जा रहा है। यह एक अप्रिय किंतु नग्न सत्य है जिसका समर्थन अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर घटने वाली आज की एक-एक घटना करती है।

अभी कुछ ही दिन हुए आठ पश्चिमी राष्ट्रों ने मिलकर एटलांटिक रक्षा-संधि की योजना स्वीकार की थी और चार अन्य राष्ट्रों से भी उसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की थी। विगत सोमवार को उक्त बारह देशों के परराष्ट्र मंत्रियों ने अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में एकत्र हो संधि पर नियमित रूप से हस्ताक्षर कर दिये। कहने के लिए तो यह एक रक्षा-संधि है, जिसका उद्देश्य किसी भी संभावित आक्रमणकारी का विरोध करना, या यों कहिए कि विश्व में शांति-स्थापना के निमित्त प्रयास करना है। किंतु वास्तविकता यह है कि महासमर की ज्वाला को प्रकुपित करने के लिए जितना घृत इस संधि में है, उतना कदाचित् ही अब तक की किसी अन्य घटना में रहा हो। रक्षा-संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की यह गर्वोक्ति है कि उनके संगठन के समक्ष रूस बौना बन गया है। एटलांटिक रक्षा-संधि पर बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, हालैंड, नार्वे, पुर्तगाल और आइसलैंड के अतिरिक्त फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्रिटेन और अमरीका ने भी हस्ताक्षर किये हैं। इनकी सम्मिलित जन-शक्ति ३३ करोड़ २४ लाख और ३९ हजार है, जो कि रूस तथा उसके ६ साथी देशों- पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, हंगरी, रूमानिया, बल्गेरिया और अल्बानिया की संयुक्त जन-शक्ति से १५ प्रतिशत अधिक है। पश्चिमी राष्ट्रों का यह भी दावा है कि उनके पास रूस और उसके समर्थकों की तुलना में तिगुना अधिक इस्पात, दोगुना अधिक कोयला, आठ गुना अधिक तेल, ३४ गुना अधिक व्यापारिक जहाज और तिगुना से अधिक यातायात-यंत्र है। बड़ा ऊंचा दावा है यह। द्वितीय महासमर से पहले भी ऐसी ही डींगें हांकी जाती थीं और रूस को गाजर-मूली समझा जाता था। किंतु समय ने सत्य का उद्घाटन किया और आज भी किसी एक समूह के बल को दूसरे समूह के बल से भारी आंकना कोरे मन के मोदक खाने के समान है। समय आने पर कौन देश किसका साथ देगा यह भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता।

क्या राजस्थान में करवट बदलेगा ऊंट

साल 2014 के बाद से पहली बार भाजपा नेता भी मान रहे हैं कि चार-पांच सीटों पर टक्कर मिल रही है। एक दशक बाद भाजपा ने यहां अपने लगभग आधे उम्मीदवार बदल दिए हैं।

यहां स्कैन करें

विजय विद्रोही | वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान के इस लोकसभा चुनाव में तीन बातें साफ-साफ दिखाई देती हैं। एक, यह एक लहर विहीन चुनाव है, हालांकि माहौलबंदी जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दूसरी बात, सन् 1980 से लेकर 2019 तक राज्य में हुए ग्यारह लोकसभा चुनावों में बिना लहर वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटें करीब आधी-आधी बंटती रही हैं। तीसरी, बिना लहर के चुनाव में जिस दल के पक्ष में ज्यादा माहौलबंदी होती है, वह करीब 70-80 फीसदी सीटें निकाल लेता है। मगर दूसरे दल के हिस्से में भी 20 से 30 फीसदी सीटें आ ही जाती हैं।

राज्य में सन् 1991 और 1996 के आम चुनाव बिना किसी लहर के थे। 1991 में राज्य की 25 सीटों में कांग्रेस को 13 और भाजपा को 12 सीटें मिली थीं। 1996 में दोनों दलों को 12-12 सीटें मिलीं। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। मगर साल 1999 में कारगिल युद्ध में भाजपा के पक्ष में माहौल बना, तो उसने 16 सीटें निकाल लीं। कांग्रेस को नौ सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसी तरह, 2009 में तत्कालीन मनमोहन सरकार के आर्थिक मोर्चे पर अच्छे दिन से बने माहौल का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने 20 सीटें जीत लीं, तो बीजेपी को पांच मिली इस बार भी बिना लहर का ऐसा चुनाव है, जिसमें भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन साल 2014 और 2019 की तरह कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की संभावना या आशंका (अपनी-अपनी नजर में) कम नजर आती है।

जाहिर है, इस बार के आम चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। साल 2014 के बाद पहली बार भाजपा नेता भी मान रहे हैं कि चार-पांच सीटों पर उन्हें टक्कर मिल रही है। एक दशक बाद भाजपा ने राज्य में अपने आधे उम्मीदवार बदले हैं। पहली बार उसने कांग्रेस से आए दो-दो नेताओं को टिकट दिया है। साल 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने छह लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनावों में उतारा था। तीन जीते-तीन हारे। इससे यह साफ जाहिर हुआ था कि सांसदों के खिलाफ सत्ता-विरोधी रुझान है, लिहाजा 25 में से 11 नए चेहरे उतारे गए हैं।

बाहर से लाए गए नेताओं और थोक में भर-भरकर शहर और जिला स्तरीय नेताओं को पार्टी में शामिल करने से कुछ जगह पुराने कार्यकर्ताओं में रोष भी देखने को मिल रहा है। 2014 के बाद से पहली बार हुआ है कि भाजपा के एक सांसद राहुल कस्वां कांग्रेस के टिकट पर चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़े गुर्जर नेता प्रह्लाद गुंजल कांग्रेस के टिकट पर कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टक्कर दे रहे हैं। दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार अपने बेटे दुष्यंत सिंह की झालावाड़ सीट तक सिमट गई हैं।

जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो 2014 के बाद पहली बार इसने तीन सीटों पर गठबंधन किया है। नागौर की सीट आरएलपी के हनुमान बेनिवाल के लिए और सीकर की सीट सीपीएम के अमरा राम के लिए छोड़ी गई है। इस बार पार्टी के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने में आनाकानी दिखाई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी अदावत में ऐसा पहली बार हुआ है कि टिकट वितरण में पायलट की अधिक चली और कम से कम पांच सीटों पर वह अपने नेताओं को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं।

इधर, प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस के घोषणापत्र से लेकर अन्य मुद्दों पर जो भी बोलते हैं, दूसरे नेता उसे दोहरा भर रहे हैं। जहां तक राज्य के मुद्दों की बात है, तो भाजपा पूर्वी राजस्थान में चंबल और यमुना के पानी को पहुंचाने की योजना को आधार बना रही है। राम मंदिर को भी भुनाने की कोशिश हो रही है। उधर कांग्रेस ने चुनाव कमेटी जरूर बनाई है और उसका घोषणापत्र भी सामने आ चुका है, लेकिन मतदाताओं तक घोषणापत्र की खास-खास बातों को सरल-सहज भाषा में पहुंचाने के गंभीर प्रयास दिख नहीं रहे। कांग्रेस को राहुल गांधी का इंतजार है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरे चुनाव को सीट-दर-सीट के हिसाब से लड़ रही है। सचिन पायलट की मांग ज्यादा है और वह मोदी सरकार के दस सालों का हिसाब सामने रखकर वोट मांग रहे हैं।

सबसे रोचक मुकाबला शेखावाटी और बाड़मेर में है। बाड़मेर जैसलमेर की सीट क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लोकसभा कहलाती है। यहां 26 साल के युवा रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय लड़ रहे हैं और कांग्रेस की जीत का आधार बन सकते हैं। उधर, शेखावाटी की तीनों सीटों चूरू, झुंझुनूं और सीकर में इस बार भारी उलटफेर हो सकता है। चूरू में बीजेपी ने दो बार के सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटा, जिनके पिता भी यहां से चार बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे। अब कस्वां कांग्रेस से लड़ रहे हैं। बगल की झुंझुनूं सीट से कद्दावर जाट नेता शीशराम ओला के बेटे बृजेंद्र ओला कांग्रेस की कमान संभाले हैं और मुकाबले में भाजपा के शुभकरण चौधरी हैं, जो यहां की उदयपुरवाटी सीट से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। सीकर की सीट सीपीएम को दी गई है। इन तीन लोकसभा सीटों के तहत विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 16 जीती थीं, तो बीजेपी इसकी आधी सीटें ही जीत पाई थी।

बहरहाल, पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 16 सीटें दो लाख से ज्यादा अंतर से जीती थीं। इनमें से चार सीटें तो चार लाख के ज्यादा अंतर से जीती गई थीं। इसीलिए भाजपा कुछ आश्वस्त दिख रही है। उसे लगता है, कांग्रेस भले ही कुछ सीटों पर टक्कर दे रही हो, पर हार का अंतर पाटना आसान नहीं होगा। सांसदों के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी उनके टिकट काटकर काफी हद तक दूर की जा चुकी है। धनबल में भाजपा बहुत आगे है। बूथ स्तर पर उसकी तैयारी कांग्रेस से कई गुना अच्छी है। चुनाव के समय पारा 42 डिग्री पार रहने का अनुमान है और भाजपा को उम्मीद है कि उसके समर्थक मोदी की हैट्रिक के लिए सुबह दस साढ़े दस बजे तक वोट डाल चुके होंगे, वैसे भी पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। फिर भी, लोगों का यही कहना है कि इस बार ऊंट को भी पता नहीं है कि किस लोकसभा सीट में वह किस करवट बैठेगा? ऐसी सीटों की संख्या चार से छह के बीच बताई जा रही है, पर कांग्रेस आठ-नौ सीटों पर चर्चा में है। इनमें से पांच-छह में तगड़ी टक्कर भी दे रही है, लेकिन जो दल अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने में कामयाब रहा, ऊंट उसी करवट बैठ जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सद्भाव से संपन्न समाज का पैगाम देता ईद-उल-फितर

यहां स्कैन करें

सरताज अहमद | प्रोफेसर व शिक्षाविद्

ईद-उल-फितर का त्योहार आमतौर पर हिजरी (इस्लामी चंद्र कैलेंडर) के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है, जो रमजान के ठीक बाद आता है। ईद शब्द का अर्थ अरबी, उर्दू और फारसी में खुशी या हर्षोल्लास से है, यानी वह खुशी, जो बार-बार आए। ईद-उल-फितर एक महीने तक रखे गए सामूहिक उपवासों की समाप्ति का दिन है।

पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मदीना आने के दो साल बाद सन् 624 ईस्वी में रमजान के पूरे महीने में रोजे रखने का आदेश हुआ था। एक महीने के रोजे रखने के बाद इसी वर्ष पहली बार ईद मनाई गई थी। इसी दिन पैगंबर हजरत मुहम्मद ने बद्र के युद्ध में विजय हासिल की थी। तब लोगों ने खुशी में ईद का त्योहार मनाया था। तब से अभी तक ईद का त्योहार विश्व भर में पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है।

यह रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को मिलने वाले इनाम का दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर के नौवें महीने में पूरे माह के रोजे नमाज, तरावीह, तहज्जुद की नमाज, लैलेतुल कद्र की इबादत तथा एहतकाफ (एकांतवास) को पूरा कर लेते हैं, तो अल्लाह इस दिन अपनी इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश व इनाम से नवाजता है। इसी दिन को ईद-उल-फितर का नाम दिया गया है। पवित्र रमजान के महीने की समाप्ति पर मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें पूरे महीने के उपवास रखने की शक्ति दी, मन-मस्तिष्क को शांति दी और पवित्र महीने में इबादत का भागीदार बनाया। अतः इस दिन लोग जश्न मनाने और अल्लाह के हुक्म को साझा करने के लिए खुले आसमान के नीचे दिन के उजाले में इकट्ठा होते हैं। ईद के दिन भोर में सामूहिक रूप से अल्लाह की इबादत करते हैं। खास बात यह भी है कि ईद के दिन रोजा रखना हराम है।

यह रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को मिलने वाले इनाम का दिन माना जाता है।

ईद पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए खुशी का समय है। यह सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद-उल-फितर मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। ईद पर हर मुसलमान चाहे वह आर्थिक रूप से संपन्न हो या न हो, सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं। यह पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। यह प्रेम, करुणा व स्नेह की भावनाओं के विस्तार का त्योहार है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए हमें यह प्रेरित करता है।

हालांकि, इस्लामी परंपराओं में सर्वमान्य ईद के दौरान तीन बार गले मिलने का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी मुसलमानों के लिए स्नेह, भाईचारे और सद्भावना के संकेत के रूप में ईद-उल-फितर जैसे समारोहों के दौरान एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई देना आम बात है। रमजान के पवित्र महीने में ईद से पहले हर संपन्न व्यक्ति को एक किलो 633 ग्राम गेहूं या उसकी बाजार के मौजूदा भाव के आधार पर तय कीमत के बराबर राशि गरीबों में वितरित करनी होती है। इसे फितरा कहते हैं। चिंतन और खुशी के बीच ईद-उल-फितर को फितरा के नाम दान का पर्व भी कहा जाता है। गरीबों को दान देना इस्लाम में अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि गरीबों, अनाथों और बंदियों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन दो। जकात इस्लाम में एक प्रकार का दान है, जिसको धार्मिक रूप से जरूरी और कर के रूप में देखा-माना जाता है।

कुरान में नमाज के बाद जकात का ही स्थान है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक, हरेक समृद्ध मुसलमान को 52.5 तोला चांदी (612.36 ग्राम) या 7.5 तोला (87.48 ग्राम) सोना या इसके बराबर रकम या व्यवसाय के इरादे से खरीदी हुई वस्तु, माल, जमीन वगैरह-वगैरह पर इस तरह मालिक होने की सूरत में कि एक हिजरी साल गुजर जाए, तो उसको अपनी कुल सालाना बचत का 2.5 प्रतिशत हिस्सा गरीबों को दान में देना दीनी फर्ज है, इस दान को ही जकात कहते हैं। हमें अपने परिजनों, दोस्तों, पड़ोसियों, गरीबों, रोगियों और जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करके ईद का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

हम सब क्या खोज रहे

इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, खुशी या कोई आश्रय पाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में, हम आखिर क्या ढूंढ़ रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। संभवतः हममें से ज्यादातर लोग अशांति, युद्ध, संघर्ष, कलह से भरे इस संसार में एक ऐसा आश्रय चाहते हैं, जहां कुछ शांति हो। इसीलिए हम खोज में लगे हैं। हम एक के बाद दूसरे नेता के पीछे, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन की ओर या एक गुरु से दूसरे गुरु की तरफ दौड़ते रहते हैं।

मगर क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं या किसी प्रकार की तुष्टि, मौज-मजे की तलाश कर रहे हैं, जिससे खुशी पा लेने की उम्मीद रखते हैं? खुशी और तुष्टि में अंतर है। क्या खुशी को खोजा जा सकता है? आप संभवतः तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, पर खुशी नहीं। खुशी आनुषंगिक है। वह किसी और चीज के साथ अनायास चली आती है। यहां तीव्र जिज्ञासा, ध्यान, सोच, ख्याल की जरूरत है। ऐसी किसी चीज की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना होगा कि हम पाना क्या चाहते हैं- खुशी या तुष्टि? मुझे लगता है, अधिकतर व्यक्ति तुष्टि की तलाश में हैं। वे संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के अंत में पूर्णता का एहसास करना चाहते हैं।

यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है, तो वह उसे बड़ी आसानी से पा सकता है। वह आंखें मूंदकर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर सकता है और उसमें आश्रय ले सकता है। निस्संदेह, ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होता है। किसी विचार के घेरे में अपने को अलग-थलग कर लेने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलती। अतः हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वह क्या है, जिसे हममें से हर कोई चाहता है? यदि हम इसके बारे में स्पष्ट हैं, तो हमें कहीं किसी गुरु के पास, किसी उपासना-गृह या संगठन में जाने की जरूरत नहीं है। अतः हमारी कठिनाई अपनी मंशा में साफ होने की है। क्या इस बारे में हम स्पष्ट हो सकते हैं?

किसी विचार के घेरे में अपने को अलग-थलग कर लेने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलती। अतः हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वह क्या है, जिसे हममें से हर कोई चाहता है?

हम पुस्तकें पढ़ते हैं, अनेक धार्मिक-आध्यात्मिक सभाओं में जाते हैं और चर्चा करते हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार उस द्वंद्व का, अपने जीवन के क्लेशों का हल ढूंढ़ते हैं; और यदि हम यह सब नहीं भी कर रहे हों, तो सोचने लगते हैं कि हमने पा लिया है; यानी हम कहते हैं कि कोई विशेष संगठन ऐसा है, कोई विशेष आचार्य या कोई विशेष ग्रंथ ऐसा है, जो हमें संतुष्ट करता है; हम जो कुछ चाहते हैं, हमने उसमें पा लिया है। और हम उसमें जड़ होकर, कैद होकर रह जाते हैं।

जे कृष्णमूर्ति

न्यायमूर्ति जे आर मिधा | पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय

इंसाफ की अदालत में सच्चाई दोनों पक्षों को पहले से मालूम रहती है, आजमाइश तो दर-हकीकत उस जज की होती है, जो उनका मुकदमा सुन रहा होता है।

अनुलोम-विलोम

हाईटेक चुनाव प्रचार

आज हाईटेक चुनाव प्रचार ज्यादा प्रभावी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि देश की 1.2 अरब आबादी के हाथों में फोन है, जिनमें से करीब 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि देश में 60 करोड़ लोग संचार के अत्याधुनिक साधन से जुड़े हुए हैं और वे निस्संदेह सोशल मीडिया भी देखते होंगे या इससे प्रभावित होते होंगे। ऐसे में, किसी राजनीतिक दल के लिए हाईटेक चुनाव प्रचार करना उनकी बाध्यता भी है और आवश्यकता भी, खासतौर से इसकी प्रभावशीलता को देखते हुए। यही कारण है कि आज सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर अपना अधिकाधिक अभियान चला रहे हैं और मतदाताओं के दिलों तक उतरने की कोशिश कर रहे हैं।

एक तर्क और है। देश में नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसी बार पौने दो करोड़ से ज्यादा वोटर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है, ये वे लोग हैं, जो संभवतः 18-19 साल के होंगे। नई पीढ़ी के बच्चे अन्य आबादी-वर्ग की तुलना में कहीं ज्यादा इंटरनेट पर रहते हैं और सोशल मीडिया में विचरते हैं। ऐसे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भी सियासी पार्टियों को हाईटेक चुनाव प्रचार करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा, तो वे नए वोटरों को शायद ही प्रभावित कर सकेंगी। इसीलिए चुनाव में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर विरोधी दलों को निशाने पर लिया जा रहा है, तो कहीं रील्स वगैरह बनाकर जन-सहानुभूति बटोरी जा रही है। वाट्सएप के तमाम ग्रुप तो इन दिनों राजनीतिक प्रचार-माध्यम बने हुए हैं।

पर्यावरण सुधार की दिशा में भी हाईटेक प्रचार जरूरी है। पहले पंपलेट, पोस्टर आदि छपवाए जाते थे और उनको खूब बांटा जाता था। मगर हाईटेक चुनाव प्रचार ने पंपलेट-पोस्टर को मानो इतिहास बना दिया है। अब उस तरह पोस्टर नहीं दिखते, जैसे पहले दिखा करते थे। इससे प्रचार-सामग्री की गंदगी भी कम होती है। पहले चुनाव खत्म होते-होते चुनाव प्रचार-सामग्रियां इतनी वितरित हो जाती थीं कि चुनाव के बाद उसका निस्तारण भी किसी समस्या से कम नहीं होता था। मगर अब तकनीक ने इस कचरे को खत्म कर दिया है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ता है। स्पष्ट है, हाईटेक चुनाव प्रचार ने कई चीजों को आसान बना दिया है। इससे एक साथ कई लोगों तक पहुंचा जा सकता है और पर्यावरण को भी चोट नहीं पहुंचती, इसलिए हमें इसे अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। अच्छी बात है कि राजनीतिक दल इसे समझने भी लगे हैं।

गोलू, मेल बॉक्स

क्षेत्र भ्रमण से हर मतदाता तक बनती पहुंच

भले ही कुछ लोग हाईटेक चुनाव प्रचार को कहीं बेहतर मानते हों, लेकिन आज भी यदि मतदाताओं के दिलों में जगह बनानी है, तो उनके बीच ही जाना पड़ता है। उनके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है। उनके गले मिलने होते हैं। उनके साथ उनका सुख-दुख साझा करना पड़ता है और यह सब काम कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। कोई तकनीक भी इसका विकल्प नहीं हो सकती। रोबोटिक विज्ञान में भी इसका कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में, जमीन पर उतरकर ही लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में अपनी जगह बनानी पड़ती है। मतलब साफ है, आज भी राजनेताओं को मतदाताओं के बीच ही जाना होगा। वहीं से उन्हें जीत का आशीर्वाद मिलेगा।

स्मार्टफोन के आंकड़े दिखाकर इन दिनों यह भी साबित करने की मानो मुहिम चल रही है कि अब भौतिक प्रचार-प्रसार के दिन लद गए हैं। कहा जा रहा है, तकनीक ने चुनाव प्रचार को पूरी तरह से बदल दिया है और अब नेताओं को उस तरह मतदाताओं के घरों तक जाने की जरूरत नहीं, जिस तरह से वे पहले जाया करते थे। मगर ऐसा कहते हुए वे भूल जाते हैं कि स्मार्टफोन के प्रति देश में एक विरक्ति का भाव भी पैदा हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में 44 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में 2019 से 2023 के दरम्यान भले ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या नौ प्रतिशत से बढ़कर 13 प्रतिशत हो गई है, लेकिन शहरों में इसी दौरान इसी आयु-समूह के उपयोगकर्ताओं की संख्या 19 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत रह गई। इसका अर्थ है कि शहरी आबादी यह समझने लगी है कि स्मार्टफोन के क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं। वे अब इससे दूरी भी बनाने लगी है।

हां, यह सही है कि कागजी प्रचार-सामग्री से कचरा पैदा होता है, इसलिए इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि नेताओं को जमीन पर नहीं उतरना चाहिए और आभासी दुनिया से ही लोगों को संबोधित करना चाहिए। यह स्थिति अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भले न्यायसंगत ठहरा दी जाए, लेकिन भारत में कम से कम अभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि सिर्फ हाईटेक चुनाव-प्रचार से ही किसी नेता को जीत मिल जाए।

अगर कोई नेता वास्तविक दुनिया को छोड़कर सिर्फ आभासी दुनिया में ही विचरता रह जाएगा, तो यकीन मानिए, वह आभासी दुनिया में ही सिमटकर रह जाएगा, वास्तविक दुनिया की किसी विधानसभा या संसद की दहलीज नहीं पार कर सकेगा।

मोहित चौहान, टिप्पणीकार

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 10 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

ईश्वर की अनुभूति के लिए आस्था आवश्यक है

मनी लांड्रिंग के मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिलती तो फिर उन्हें और अधिक समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि शराब नीति के जरिये घोटाले को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को करीब छह माह बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया एक वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। भ्रष्टाचार के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से गिरफ्तार लोगों को लंबे समय तक इसलिए जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि मनी लांड्रिंग संबंधी कानून में जमानत के प्रविधान अत्यंत कठोर हैं। चूंकि ऐसे मामलों का ट्रायल शुरू होने में अन्य अनेक मामलों की ही तरह समय लगता है, इसलिए कई बार मनी लांड्रिंग के आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यदि ट्रायल शुरू होने में देर होती है तो मनी लांड्रिंग के आरोपित को जमानत दी जा सकती है, लेकिन प्रायः ईडी की ऐसी दलीलें जमानत में बाधक बन जाती हैं कि यदि आरोपित बाहर आया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फिर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। कई बार तो आरोप पत्र दायर होने के बाद भी ईडी की यही दलील आरोपित की जमानत में बाधक बन जाती है और उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। बतौर उदाहरण महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल मनी लांड्रिंग मामले में 26 माह बाद जमानत पर जेल से बाहर आ पाए थे। आम तौर पर जब किसी आरोपित को उच्चतर अदालतों से भी जमानत नहीं मिलती तो यह धारणा कायम होती है कि उस पर लगे आरोप सही हैं और यदि कहीं उसे जमानत मिल जाती है तो यह प्रचारित किया जाता है कि ईडी के आरोपों में दम नहीं और उसे गलत फंसाया गया है। दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं। कौन दोषी है और कौन नहीं, यह तो ट्रायल कोर्ट और फिर ऊपरी अदालतों के फैसलों से ही तय हो सकता है। चूंकि कई नेता मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिलने या न मिलने के आधार पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। यह सिलसिला तभी बंद हो सकता है, जब कठोर प्रविधानों वाले मनी लांड्रिंग कानून के तहत दर्ज मामलों का निपटारा तेजी से हो। जितना जरूरी यह है कि मनी लांड्रिंग के अपराध पर लगाम लगे, उतना ही यह भी कि इससे जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण हो।

बायो मेडिकल वेस्ट

उत्तराखंड में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सिस्टम की सुस्ती चिंताजनक है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है कि सख्त कानून के बावजूद इस समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार तंत्र सक्रिय नहीं दिख रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इस तरह के अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण न करने वालों पर एक लाख तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा का प्रविधान है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन प्रविधानों को लागू करने के प्रति बोर्ड की इच्छाशक्ति नहीं दिखी। राज्य के अधिकांश शहरों में जहां-तहां बायो मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है। अस्पतालों के आसपास सड़कों के किनारे पड़ा कचरा यह बताने के लिए काफी है कि हालात क्या हैं। कहने में संकोच नहीं कि बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए जिस गति से काम होना चाहिए, वह नजर नहीं आता है। देहरादून का हाल ही ले लीजिए, यहां नगर निगम ने बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए डीपीआर तैयार की थी, मगर चार वर्ष बाद भी यह सरकारी फाइलों में धूल फांक रही है। बायो मेडिकल वेस्ट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए इसे न तो खुले में डाला जा सकता है और न ही पानी में बहाया जाता है। देहरादून की बात करें तो यहां प्रतिदिन लगभग ढाई हजार किलो बायो मेडिकल वेस्ट निकलता है, जिसमें से आधे का ही निस्तारण हो पाता है। निजी अस्पतालों की स्थिति ज्यादा खराब है। इससे तमाम तरह की बीमारियों की आशंका बनी रहती है। यह देखने की जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, पर वह अपने दायित्व के प्रति कम ही सजग नजर आता है। समस्या के प्रति तंत्र की उदासीनता जल्द से जल्द टूटनी जरूरी है।

> बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण चुनौती बनता जा रहा है, इसके समाधान के प्रति जवाबदेही तय करना जरूरी है

समाधान की मांग करता जल संकट

विवेक देवराय

जल संकट से निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र को एकीकृत रणनीति बनानी चाहिए

आदित्य सिन्हा

अवधेश राजपूत

एक वक्त 'झीलों की नगरी' के रूप में विख्यात बेंगलुरु शहर बीते दिनों पानी की भारी किल्लत के चलते सुर्खियों में रहा। यह शहर पारंपरिक रूप से जल संपदा से संपन्न रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान कहानी उसके समृद्ध अतीत से मेल नहीं खाती। भारत की आइटी राजधानी के रूप में स्थापित हुए इस महानगर में अब बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि यह केवल बेंगलुरु की ही कहानी नहीं है। हैदराबाद में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। देश के तमाम शहर पानी के इसी प्रकार के अभाव से दो-चार हैं। निरंतर बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से दुनिया भर के शहर पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 'नेचर' में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (करीब 93.3 करोड़ लोग) पानी की किल्लत से जूझ रहा था। यह आंकड़ा वर्ष 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब तक पहुंच सकता है। यानी विश्व की करीब आधी जनसंख्या को पानी की कमी की समस्या का सामना करना होगा। चूंकि भारत में शहरीकरण का दायरा और गति तेजी से बढ़ने पर है तो भारतीय शहर भी पानी के गहराते संकट के लिहाज से खासे संवेदनशील हैं।

जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर पर रुझानों को रेखांकित किया गया। इस सूचकांक के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जहां गुजरात जैसा राज्य करीब 76 अंकों के साथ जल प्रबंधन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था तो मेघालय जैसा राज्य 26 अंकों के साथ इस सूचकांक की तलहटी पर था। यह विषमता देश भर में जल प्रबंधन को सुधारने के लिए तात्कालिक कदम उठाने का संकेत करती है। भारत में जल प्रबंधन वैसे तो मूल रूप से राज्यों का दायित्व है, लेकिन जिस प्रकार का विकराल जल संकट आकार ले रहा है, उससे निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र और स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर एकीकृत रणनीति बनाना आवश्यक है। प्रभावी एवं टिकाऊ समाधानों के लिए बहुस्तरीय रणनीति की भारत के विविधतापूर्ण भौगोलिक, जलवायविक एवं सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से सुसंगति भी आवश्यक है।

राज्यों के स्तर पर सरकारों को कानूनी एवं नियामकीय मोर्चे पर प्रभावी ढांचा स्थापित करना होगा, जो लचीला होने के साथ ही अपने प्रविधानों को लागू करने की दृष्टि से सक्षम हो और जो पानी के आवंटन का काम तार्किक रूप से कर सके। इस दिशा में आस्ट्रेलिया से सीख ली जा सकती है, जहां तात्कालिक डाटा और मानसून के रुझान के हिसाब से पानी का आवंटन होता है। भारत में जल अधिकारों और उसके व्यापार को लेकर एक राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाया जाए। इसमें ब्लाकचेन तकनीक की मदद ली जा सकती है, जो प्रभावी जल प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और राज्यों के बीच नदियों के जल से जुड़े विवादों के निपटारे में भी मददगार होगी। पानी के मूल्य को लेकर भी कोई प्रगतिशील व्यवस्था बनाना बेहद अहम हो गया है, ताकि उसका मोल समझ आए। इससे जल संरक्षण और उसके किफायती उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिजिटल तकनीक से बड़ी सहायता मिल सकती है, जिसमें पानी की उपलब्धता, मांग और उपभोक्ता के व्यवहार से उसकी दरें निर्धारित करने के विभिन्न आधार तय हो सकेंगे। इसके आधार पर उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संरक्षण की नीतियों को आकार देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

शहरों में स्थापित जल अवसंरचना में इंटरनेट आफ थिंग्स सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता, वितरण में अक्षमता और रिसाव आदि की तात्कालिक जानकारी जुटाई जा सकती है। इससे जुटाए गए डाटा का एआइ के साथ जुड़ाव पानी से संबंधित ढांचे के बेहतर रखरखाव, पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति के मोर्चे पर कोई सार्थक राह दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में रिसाव पर अंकुश लगाकर व्यापक स्तर पर पानी को बचाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाकर भी जल संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। मैनेज्ड एक्विफर रीचार्ज जैसी तकनीक की मदद से खासतौर से उन इलाकों की सूरत संवारी जा सकती है, जहां बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेन गार्डेंस और कुछ विशेष संरचनाओं के माध्यम से भूजल को रीचार्ज करने के साथ ही बाढ़ की समस्या पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की क्षमताओं को और बेहतर बनाना होगा, ताकि अपशिष्ट जल से अधिक से अधिक साफ पानी मिल सके। इस पूरे अभियान में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही नियामकीय सुदृढ़ता और जनजागरूकता बेहद जरूरी होगी। स्थानीय निकायों को भी इसमें अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा, क्योंकि कई शहर इस मोर्चे पर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार 78 प्रतिशत शहरी निकाय ऐसी स्थिति में पाए गए, जिनके लिए पानी के मामले में अपने गवर्नेंस माडल को सुधारना आवश्यक है। करीब आधे नगर निकायों को जल के प्रबंधन से जुड़े अपने डाटा और सूचनाओं तक पहुंच को प्राथमिकता के स्तर पर देखना होगा।

अगर राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य उपयोग किए गए जल के प्रबंधन के मामले में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी हैं। इसके उलट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र जैसे राज्य काफी पीछे हैं। जल संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को अपने प्रयास बेहतर करने होंगे, क्योंकि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन जैसी पहल के माध्यम से केंद्र सरकार इस मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। इन प्रयासों के साथ ही अमृत 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम उस बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं, जो बढ़ती मांग और जलवायु अनिश्चितताओं के बीच निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)
response@jagran.com

कपड़ों की तरह बदली जाती विचारधारा

मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह पत्नी प्रेमलता सिंह के साथ फिर से कांग्रेस में लौट गए। प्रेमलता भी हरियाणा से भाजपा की विधायक रह चुकी हैं। इसके एक महीने पहले 2019 में भाजपा से लोकसभा सदस्य चुने गए उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। बीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के चाहे जो कारण गिनाए, माना यही जाता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में न तो बृजेंद्र सिंह को भाजपा का टिकट मिलने की संभावना थी और न ही विधानसभा चुनाव में प्रेमलता को। बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बेटे भाजपा छोड़ने वाले इकलौते नेता नहीं हैं। कई अन्य नेताओं ने भी भाजपा छोड़ी है और इसका एक बड़ा कारण उन्हें या उनके स्वजनों को लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलना रहा। भाजपा छोड़ने वालों की तुलना में कांग्रेस और दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या कहीं अधिक है। कुछ समय पहले तक तो यह स्थिति थी कि करीब-करीब हर दिन कांग्रेस या फिर अन्य किसी दल का कोई न कोई नेता भाजपा में शामिल हो रहा था। अब यह सिलसिला थोड़ा धीमा हुआ है। इससे अन्य दलों से अधिक राहत की सांस भाजपा नेताओं ने ली होगी, क्योंकि दूसरे दलों से आए कई नेता भाजपा में शामिल होते ही लोकसभा के प्रत्याशी बन जा रहे थे। ऐसे नेता भले ही यह कहते हों कि उन्हें भाजपा की विचारधारा भा गई, लेकिन सच यह है कि अधिकतर नेता कोई पद पाने या प्रत्याशी बनने या फिर अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति की चाह में भाजपा में आ रहे हैं।

भाजपा ने अभी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जितने किए हैं, उनमें से 30 से अधिक वे हैं, जिन्होंने दो साल और कुछ ने तो दो सप्ताह पहले ही उसका दामन थामा है। इसके चलते कई जगह भाजपा को असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा उन दलों में है, जिसमें ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, जो विचारधारा के कारण उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। यदि ये निराश- हताश हुए तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी तय है कि जैसे ही प्रतिकूल स्थितियां उभरीं या फिर दूसरे दलों से आए नेताओं के वांछित स्वार्थ पूरे नहीं हुए, वैसे ही वे अन्यत्र कूच करने में न तो देर करेंगे और न ही संकोच। निःसंदेह ऐसा भी नहीं है कि अन्य दलों से भाजपा में आया हर नेता उसका प्रत्याशी बन जा रहा है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि उनका सचमुच अचानक हृदय परिवर्तन हो जा रहा है और इसलिए वे भाजपाई होना पसंद कर रहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ एवं तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए और फिर तृणमूल कांग्रेस में जाकर पुनः भाजपा में लौटे अर्जुन सिंह ने विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपाई होने का फैसला किया होगा? जो आसानी से कहा जा सकता है, वह यह कि उनकी न तो पहले कोई विचारधारा रही होगी और न ही अब। राजनीति में ऐसे नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं। उनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। चुनावों के अवसर पर विशेष तौर पर ऐसा होता है। देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं, जो कपड़ों की तरह अपनी विचारधारा बदलकर करीब-करीब सभी राजनीतिक दलों की यात्रा कर चुके हैं।

राजीव सचान

ऐसे नेता निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं और जिनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जा रहा है

भाजपा में शामिल होते कांग्रेस नेता। प्रेट्र

विचारों में बदलाव कोई बुरी बात नहीं है। देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से लोगों के विचार बदलते हैं और बदलने भी चाहिए, लेकिन विचार बदल जाने या फिर हृदय परिवर्तित होने का ढोंग भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल ऐसा हो रहा है। यह गजब ही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह पिछले पांच महीने में तीन दल बदल चुके हैं। फिलहाल वह भाजपा में हैं। इसी तरह इसी राज्य में सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा कांग्रेस से भाजपा में आईं और 48 घंटे के अंदर फिर कांग्रेस में चली गईं। यह समझ आता है कि कोई दल विस्तार के क्रम में उन राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाए, जहां वह कमजोर है, जैसे भाजपा के मामले में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, लेकिन आखिर वह अपने मजबूत गढ़ समझे जाने वाले राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं को क्यों महत्व दे रही है? आखिर ऐसा करके वह पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नेताओं को क्या संदेश दे रही है?

एक समय था, जब हर दल की विचारधारा होती थी, लेकिन धीरे-धीरे विचाराधाराहीन दलों की संख्या बढ़ने लगी और अब गिनती के दल ऐसे हैं, जिनकी अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा है। राष्ट्रीय दलों में भाजपा और वाम दल ऐसे दलों में गिने जाते हैं, जिनकी अपनी विचारधारा है। एक वक्त कांग्रेस की भी विचाराधारा होती थी, लेकिन आज शायद कांग्रेसजन भी यह न समझा पाएं कि उनके दल की विचारधारा क्या है, क्योंकि आज की कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सेक्युलर दल है और विभाजन के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के बचे-खुचे नेताओं की ओर से बनाई गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी। बदलते समय और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विचारधाराओं में बदलाव आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उनका हाल वामपंथ की विचारधारा जैसा होता है, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं के पालाबदल को जनता की आकांक्षाओं का परिणाम बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यह तो शुद्ध अवसरवाद है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

आत्म-जागरण

हमारे शास्त्रों में उल्लेख है-कलैव ब्रह्म अर्थात कला ही ब्रह्म है। यह कला ही है, जो पत्थरों में छिपी मूर्तियों को निखारती है। कला ही शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती है। वीणा में सोए संगीत को जगाती है, लेकिन इन सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला वह है जो सोए आत्मा को जगाती है। आत्मा को जगाने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आत्मा हमारा ही है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं कोई और नहीं। वर्तमान में हम आत्म-जागरण की कला भूल दूसरों की पसंद या नापसंद के दास बन गए हैं। जिसकी लगाम हाथ में न हो, उस पर बैठना खतरे से खाली नहीं है।

अपने जीवन की लगाम यदि हमारे हाथ में है तो हम स्वयं के मालिक हैं और स्वतंत्र हैं। न जाने क्यों अपना बुद्धि, विवेक त्याग कर हमने बाहर वालों को हमारी गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। वस्तुतः, हम स्वभाव से नहीं, अपितु दूसरों के प्रभाव से जी रहे हैं। किसी की प्रशंसा से मंत्रमुग्ध होकर उसके मुरीद बन गए। कोई हमारे ऊपर लांछन लगा गया तो उससे शत्रुता पाल ली। हम दूसरों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि स्वयं के भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। हमारी प्रसन्नता और नाराजगी दूसरों पर आधारित हो गई है, क्योंकि जीवन में सब कुछ दूसरे तय कर रहे हैं। हम भी अपनी समस्त क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करने के लिए और उनकी कसौटी पर खरे उतरने के लिए कर रहे हैं।

हम अपनी समस्त मौलिकता खो बैठे हैं। जबकि हमारा हित इसी में है कि अपने मालिक बनें। अपने मालिक बनते ही भीतर की संपदाओं से परिचय हो जाएगा। फिर संसार का सारा शोर और विकार लुप्त हो जाएंगे। इन सबसे परे होकर स्वयं का अन्वेषण करना ही सच्ची साधना है। यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है।

डा. निर्मल जैन

शहरों में जाम की समस्या

सुधीर कुमार

डच कंपनी टामटाम द्वारा छह महादेश के 55 देशों के 387 शहरों के सर्वेक्षण पर आधारित ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट-2023 से पता चलता है कि 2022 की तुलना में 2023 में 387 शहरों में से 228 में सड़कों पर वाहनों की औसत गति में कमी आई है। 60 प्रतिशत से अधिक शहरों में 2021-23 के बीच ईंधन की औसत बजट में 15 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट बताती है कि लंदन दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी औसतन 37 मिनट 20 सेकेंड में तय की जाती है। वहीं इस मामले में बेंगलुरु और पुणे क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं, जहां उतनी ही दूरी क्रमशः 28 मिनट 10 सेकेंड तथा 27 मिनट 50 सेकेंड में पूरी होती है। डबलिन, टोरंटो, मिलान तथा दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहर भी ट्रैफिक जाम की चपेट में हैं।

भारत की 'सिलिकान सिटी' बेंगलुरु दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में शामिल होती जा रही है। बेंगलुरु में सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना कठिनाई भरा सबक साबित हो रहा है। गौरतलब है कि बेंगलुरु के इतिहास में 27 सितंबर, 2023 का दिन सबसे व्यस्ततम रहा, जब शहर के आउटर रिंग रोड इलाके में भीषण जाम देखने को मिला था। उस दिन जाम में लगभग साढ़े तीन लाख वाहन फंसे थे। नतीजतन वाहनों ने एक किलोमीटर का सफर दो घंटे में तय किए थे। आलम यह था कि स्कूल से छूटे बच्चे रात में अपने घर पहुंचे थे। आज देश के कमोबेश छोटे-बड़े सभी शहर जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं। जाम मानव स्वास्थ और पर्यावरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। जाम वक्त ही बर्बादी के साथ-साथ मानव की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। परिवहन व्यवस्था अकुशल होने पर उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक है। ट्रैफिक जाम ड्राइवरों, यात्रियों और प्रमुख सड़क मार्गों के पास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न बीमारी और परेशानियां उत्पन्न करता है। यह लोगों में तनाव और चिड़चिड़ापन को जन्म देता है और श्वसन संबंधी अनेक बीमारियों को जन्म देता है। मोटर वाहन को दुनियाभर में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक माना जाता है। वाहनों से निकलने वाला नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर डाईआक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड और ओजोन जैसे गैस वायु को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।

> शहरी यातायात में जाम मानव स्वास्थ और पर्यावरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है

बहरहाल यातायात की भीड़ को कम करके, शहर रहने और काम करने के लिए अधिक कुशल और सुखद स्थान बन सकते हैं। जाम को कम किए बिना सतत विकास लक्ष्यों का हासिल करना भी मुमकिन नहीं होगा।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अपने अहित पर आमादा कांग्रेस

'कांग्रेस के न्याय पत्र पर वामपंथ की छाप' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में उमेश चतुर्वेदी ने कांग्रेस की दिशाहीनता से परिचय कराया गया है। लेखक ने उचित ही लिखा है कि कांग्रेस इस समय वामपंथ की ओर मुड़ रही है। जबकि देश-दुनिया से वामपंथी विचारधारा का निरंतर संकुचन होने पर है। केरल को छोड़कर कहीं उसकी मुखर मौजूदगी नहीं रही। यहां तक कि एक समय उसके गढ़ रहे बंगाल और त्रिपुरा भी उसके हाथ से निकल गए हैं। एक समय कांग्रेस में वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी सभी प्रकार की वैचारिकी से प्रेरित नेता मौजूद थे और व्यापक रूप से पार्टी की पहचान भी मध्यमार्गी दल की रही जिसका अन्य धाराओं को साधकर चलने में विश्वास रहा, लेकिन राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद से पार्टी पर वामपंथ का प्रभाव बढ़ा है। फिर चाहे उद्यमियों या औद्योगिक घरानों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप हो या फिर पुरानी पेंशन का शिगूफा या फिर सरकारी नौकरियों का मोह दिखाना। वर्तमान में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर कर रही हैं, उनमें कांग्रेस की नीतियां आर्थिकी को पीछे ले जाने वाली ही अधिक लगती हैं। कांग्रेस वक्त की दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पाने का प्रयास नहीं कर रही। वह खुद ही अपने कायाकल्प में अवरोध बन रही है।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

लोकतंत्र का वास्तविक अहसास

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश का एक आम नागरिक अपने रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को सही से नहीं जान पाता है, लेकिन अब समय बदल रहा है। पहले हमारे पास जानने के साधन सीमित थे। अब इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा है। अब कहीं भी, किसी भी समय हम अपने सभी अधिकारों को जान सकते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अपने सभी अधिकारों को जानकर हम जैसे आम नागरिक उनकी रक्षा खुद कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव रूपी लोकतंत्र के त्योहार में अच्छा होगा कि निष्पक्ष होकर अपना मतदान करें। यह मतदाता के लिए भी हित में है और देश हित में भी। ऐसे व्यक्ति को मतदान करें, जो वास्तविक सेवक बनकर देश के लोगों और देश के लिए कुछ नया करे, जिससे नागरिकों और देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके। आप सिर्फ मतदाता न बनकर रह जाएं, देश के लोकतंत्र में खुद को सामने लाएं और नेतृत्व की क्षमता विकसित कर देश की बागडोर संभालने में भी अपना सीधा योगदान दें। यह व्यवस्था पर आरोप लगाने से कई गुना अच्छा होगा। तब जाकर देश के एक आम नागरिक को लोकतंत्र का अहसास होगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

बुजुर्गों की दयनीय दशा

'समस्याओं से घिरते बुजुर्ग' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में बुजुर्गों की दयनीय दशा को चित्रित करने के लिए आभार। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बदले माहौल में बच्चों द्वारा उनकी जिम्मेदारी भी नहीं उठाई जा रही है और वे धन के अभाव में स्वयं को धरती पर भार मानकर जीते हैं। सरकार को इसी संदर्भ में ईपीएस पेंशनधारकों को मिल रही पेंशन को समुचित स्तर तक बढ़ाना चाहिए। चाहे इसके लिए कुछ अंशदान पेंशनधारकों से भी ले लिया जाए तो भी कुछ बुराई नहीं है। ईपीएस पेंशन में 1,250 रुपये प्रति माह का अंशदान करने वाले व्यक्ति को केवल 4,127 रुपये मासिक पेंशल मिलती है, जो आज के दौर में कितना गुजारा करती होगी, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी इसे बढ़ाने पर न तो आज तक अमल हुआ है और न ही सरकार की ओर से इन्हें कोई राहत दी गई है। 1995 में लागू हुई इस ईपीएस योजना को अपनाना और उसमें आजीवन योगदान करना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य था। अनुरोध है कि सरकार इसे एकमुश्त बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह करे तथा इसके लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी जारी कर दे तो बहुत अच्छा होगा।

सुरेश चंद शर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी- 210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

ईश्वर की अनुभूति के लिए आस्था आवश्यक है

मनी लांड्रिंग के मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिलती तो फिर उन्हें और अधिक समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि शराब नीति के जरिये घोटाले को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को करीब छह माह बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया एक वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। भ्रष्टाचार के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से गिरफ्तार लोगों को लंबे समय तक इसलिए जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि मनी लांड्रिंग संबंधी कानून में जमानत के प्रविधान अत्यंत कठोर हैं। चूंकि ऐसे मामलों का ट्रायल शुरू होने में अन्य अनेक मामलों की ही तरह समय लगता है, इसलिए कई बार मनी लांड्रिंग के आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यदि ट्रायल शुरू होने में देर होती है तो मनी लांड्रिंग के आरोपित को जमानत दी जा सकती है, लेकिन प्रायः ईडी की ऐसी दलीलें जमानत में बाधक बन जाती हैं कि यदि आरोपित बाहर आया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फिर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। कई बार तो आरोप पत्र दायर होने के बाद भी ईडी की यही दलील आरोपित की जमानत में बाधक बन जाती है और उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। बतौर उदाहरण महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल मनी लांड्रिंग मामले में 26 माह बाद जमानत पर जेल से बाहर आ पाए थे। आम तौर पर जब किसी आरोपित को उच्चतर अदालतों से भी जमानत नहीं मिलती तो यह धारणा कायम होती है कि उस पर लगे आरोप सही हैं और यदि कहीं उसे जमानत मिल जाती है तो यह प्रचारित किया जाता है कि ईडी के आरोपों में दम नहीं और उसे गलत फंसाया गया है। दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं। कौन दोषी है और कौन नहीं, यह तो ट्रायल कोर्ट और फिर ऊपरी अदालतों के फैसलों से ही तय हो सकता है। चूंकि कई नेता मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिलने या न मिलने के आधार पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। यह सिलसिला तभी बंद हो सकता है, जब कठोर प्रविधानों वाले मनी लांड्रिंग कानून के तहत दर्ज मामलों का निपटारा तेजी से हो। जितना जरूरी यह है कि मनी लांड्रिंग के अपराध पर लगाम लगे, उतना ही यह भी कि इससे जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण हो।

फैसले का हो मूल्यांकन

राज्य के सरकारी स्कूलों में आठवीं पास कई बच्चों के लिए शिक्षा विभाग का नया नियम परेशानी की वजह बन गया है। नए नियम के अनुसार आठवीं पास बच्चों को अपनी ही पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में नौवीं में दाखिला लेना होगा। पंचायत और निगम क्षेत्र से इतर नजदीकी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अब नाम कटाना पड़ रहा है। अपने क्षेत्र के स्कूल में दाखिले की कवायद शुरू हो गई है। कई जगहों पर इसका असर यह हुआ है कि बच्चों को अब पूर्व के मुकाबले स्कूल जाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। बच्चों और अभिभावकों ने इसका कुछ जगहों पर विरोध भी किया है। भागलपुर के सुलतानगंज, पीरपैंती समेत कई जगहों पर बच्चों व अभिभावकों ने इस व्यवस्था का विरोध किया। नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले जहां हमें स्कूल जाने के लिए 250 से 300 मीटर चलना पड़ता था, वहीं अब दो-दो किमी की दूरी तय करनी होगी। यह कष्टप्रद है। राज्य के दूसरे जिलों से भी ऐसी खबरें हैं। ऐसी आशंका है कि अधिक दूरी के कारण स्कूल जाने में बच्चों की रुचि घटेगी।

अपनी ही पंचायत या निगम के स्कूल में नौवीं में दाखिले के फैसले का मूल्यांकन करने की जरूरत है।

चूंकि, सरकारी स्कूलों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए निजी वाहनों का खर्च वहन कर पाएं, ऐसे में ड्रापआउट के मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि, इस फैसले के पीछे विभाग की सोच है कि अब जब सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है तो छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो। इससे बेहतर नतीजे की उम्मीद है, लेकिन अगर अधिक बच्चों की परेशानी बढ़ रही है तो इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हाल ही में जारी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम से साबित हुआ है कि हमारी पढ़ाई ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। पांच साल में सबसे बेहतर परिणाम हासिल हुआ है। बच्चे समय पर स्कूल आ रहे हैं, शिक्षक भी मन लगाकर पढ़ा रहे। ऐसे में यह ध्यान देना होगा कि इस फैसले से बच्चे स्कूल से विमुख न हों।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अखिलेश यादव वोट बैंक के लालच में माफिया मुख्तार अंसारी के घर गए?

आज का सवाल

क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है?

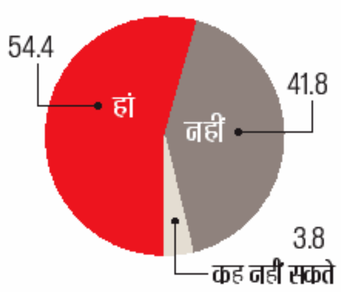

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

समाधान की मांग करता जल संकट

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

जल संकट से निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र को एकीकृत रणनीति बनानी चाहिए

एक वक्त 'झीलों की नगरी' के रूप में विख्यात बेंगलुरु शहर बीते दिनों पानी की भारी किल्लत के चलते सुर्खियों में रहा। यह शहर पारंपरिक रूप से जल संपदा से संपन्न रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान कहानी उसके समृद्ध अतीत से मेल नहीं खाती। भारत की आइटी राजधानी के रूप में स्थापित हुए इस महानगर में अब बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि यह केवल बेंगलुरु की ही कहानी नहीं है। हैदराबाद में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। देश के तमाम शहर पानी के इसी प्रकार के अभाव से दो-चार हैं। निरंतर बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से दुनिया भर के शहर पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 'नेचर' में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (करीब 93.3 करोड़ लोग) पानी की किल्लत से जूझ रहा था। यह आंकड़ा वर्ष 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब तक पहुंच सकता है। यानी विश्व की करीब आधी जनसंख्या को पानी की कमी की समस्या का सामना करना होगा। चूंकि भारत में शहरीकरण का दायरा और गति तेजी से बढ़ने पर है तो भारतीय शहर भी पानी के गहराते संकट के लिहाज से खासे संवेदनशील हैं।

जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर पर रुझानों को रेखांकित किया गया। इस सूचकांक के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जहां गुजरात जैसा राज्य करीब 76 अंकों के साथ जल प्रबंधन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था तो मेघालय जैसा राज्य 26 अंकों के साथ इस सूचकांक की तलहटी पर था। यह विषमता देश भर में जल प्रबंधन को सुधारने के लिए तात्कालिक कदम उठाने का संकेत करती है। भारत में जल प्रबंधन वैसे तो मूल रूप से राज्यों का दायित्व है, लेकिन जिस प्रकार का विकराल जल संकट आकार ले रहा है, उससे निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र और स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर एकीकृत रणनीति बनाना आवश्यक है। प्रभावी एवं टिकाऊ समाधानों के लिए बहुस्तरीय रणनीति की भारत के विविधतापूर्ण भौगोलिक, जलवायविक एवं सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से सुसंगति भी आवश्यक है।

राज्यों के स्तर पर सरकारों को कानूनी एवं नियामकीय मोर्चे पर प्रभावी ढांचा स्थापित करना होगा, जो लचीला होने के साथ ही अपने प्रविधानों को लागू करने की दृष्टि से सक्षम हो और जो पानी के आवंटन का काम तार्किक रूप से कर सके। इस दिशा में आस्ट्रेलिया से सीख ली जा सकती है, जहां तात्कालिक

अवधेश राजपूत

डाटा और मानसून के रुझान के हिसाब से पानी का आवंटन होता है। भारत में जल अधिकारों और उसके व्यापार को लेकर एक राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाया जाए। इसमें ब्लाकचेन तकनीक की मदद ली जा सकती है, जो प्रभावी जल प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और राज्यों के बीच नदियों के जल से जुड़े विवादों के निपटारे में भी मददगार होगी। पानी के मूल्य को लेकर भी कोई प्रगतिशील व्यवस्था बनाना बेहद अहम हो गया है, ताकि उसका मोल समझ आए। इससे जल संरक्षण और उसके किफायती उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिजिटल तकनीक से बड़ी सहायता मिल सकती है, जिसमें पानी की उपलब्धता, मांग और उपभोक्ता के व्यवहार से उसकी दरें निर्धारित करने के विभिन्न आधार तय हो सकेंगे। इसके आधार पर उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संरक्षण की नीतियों को आकार देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

शहरों में स्थापित जल अवसंरचना में इंटरनेट आफ थिंग्स सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता, वितरण में अक्षमता और रिसाव आदि की तात्कालिक जानकारी जुटाई जा सकती है। इससे जुटाए गए डाटा का एआइ के साथ जुड़ाव पानी से संबंधित ढांचे के बेहतर रखरखाव, पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति के मोर्चे पर कोई सार्थक राह दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में रिसाव पर अंकुश लगाकर व्यापक स्तर पर पानी को बचाया जा सकता है। वर्ष जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाकर भी जल संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। मैनेज्ड एक्विफर रीचार्ज जैसी तकनीक की मदद से खासतौर से उन इलाकों की सूरत संवारी जा सकती है, जहां बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेन गार्डेंस और कुछ विशेष संरचनाओं के माध्यम से भूजल को रीचार्ज करने के साथ ही बाढ़ की समस्या पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की क्षमताओं को और बेहतर बनाना होगा, ताकि अपशिष्ट जल से अधिक से अधिक साफ पानी मिल सके। इस पूरे अभियान में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही नियामकीय सुदृढ़ता और जनजागरूकता बेहद जरूरी होगी। स्थानीय निकायों को भी इसमें अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा, क्योंकि कई शहर इस मोर्चे पर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार 78 प्रतिशत शहरी निकाय ऐसी स्थिति में पाए गए, जिनके लिए पानी के मामले में अपने गवर्नेंस माडल को सुधारना आवश्यक है। करीब आधे नगर निकायों को जल के प्रबंधन से जुड़े अपने डाटा और सूचनाओं तक पहुंच को प्राथमिकता के स्तर पर देखना होगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 90 प्रतिशत नगर निकायों को इस क्षेत्र में लक्षित वित्तीय नियोजन एवं निवेश करना होगा।

अगर राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य उपयोग किए गए जल के प्रबंधन के मामले में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी हैं। इसके उलट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र जैसे राज्य काफी पीछे हैं। जल संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को अपने प्रयास बेहतर करने होंगे, क्योंकि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन जैसी पहल के माध्यम से केंद्र सरकार इस मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। इन प्रयासों के साथ ही अमृत 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम उस बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं, जो बढ़ती मांग और जलवायु अनिश्चितताओं के बीच निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

कपड़ों की तरह बदली जाती विचारधारा

मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह पत्नी प्रेमलता सिंह के साथ फिर से कांग्रेस में लौट गए। प्रेमलता भी हरियाणा से भाजपा की विधायक रह चुकी हैं। इसके एक महीने पहले 2019 में भाजपा से लोकसभा सदस्य चुने गए उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। बीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के चाहे जो कारण गिनाए, माना यही जाता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में न तो बृजेंद्र सिंह को भाजपा का टिकट मिलने की संभावना थी और न ही विधानसभा चुनाव में प्रेमलता को। बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बेटे भाजपा छोड़ने वाले इकलौते नेता नहीं हैं। कई अन्य नेताओं ने भी भाजपा छोड़ी है और इसका एक बड़ा कारण उन्हें या उनके स्वजनों को लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलना रहा। भाजपा छोड़ने वालों की तुलना में कांग्रेस और दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या कहीं अधिक है। कुछ समय पहले तक तो यह स्थिति थी कि करीब-करीब हर दिन कांग्रेस या फिर अन्य किसी दल का कोई न कोई नेता भाजपा में शामिल हो रहा था। अब यह सिलसिला थोड़ा धीमा हुआ है। इससे अन्य दलों से अधिक राहत की सांस भाजपा नेताओं ने ली होगी, क्योंकि दूसरे दलों से आए कई नेता भाजपा में शामिल होते ही लोकसभा के प्रत्याशी बन जा रहे थे। ऐसे नेता भले ही यह कहते हों कि उन्हें भाजपा की विचारधारा भा गई, लेकिन सच यह है कि अधिकतर नेता कोई पद पाने या प्रत्याशी बनने या फिर अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति की चाह में भाजपा में आ रहे हैं।

भाजपा ने अभी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जितने किए हैं, उनमें से 30 से अधिक वे हैं, जिन्होंने दो साल और कुछ ने तो दो सप्ताह पहले ही उसका दामन थामा है। इसके चलते कई जगह भाजपा को असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा उन दलों में है, जिसमें ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, जो विचारधारा के कारण उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। यदि ये निराश-हताश हुए तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी तय है कि जैसे ही प्रतिकूल

राजीव सचान

ऐसे नेता निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं और जिनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जा रहा है

भाजपा में शामिल होते कांग्रेस नेता ● प्रेट

स्थितियां उभरीं या फिर दूसरे दलों से आए नेताओं के वांछित स्वार्थ पूरे नहीं हुए, वैसे ही वे अन्यत्र कूच करने में न तो देर करेंगे और न ही संकोच। निःसंदेह ऐसा भी नहीं है कि अन्य दलों से भाजपा में आया हर नेता उसका प्रत्याशी बन जा रहा है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि उनका सचमुच अचानक हृदय परिवर्तन हो जा रहा है और इसलिए वे भाजपाई होना पसंद कर रहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ एवं तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए और फिर तृणमूल कांग्रेस में जाकर पुनः भाजपा में लौटे अर्जुन सिंह ने विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपाई होने का फैसला किया होगा? जो आसानी से कहा जा सकता है, वह यह कि उनकी न तो पहले कोई विचारधारा रही होगी और न ही अब। राजनीति में ऐसे नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं। उनका कभी भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। चुनावों के अवसर पर विशेष तौर पर ऐसा होता है। देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं, जो कपड़ों की तरह अपनी विचारधारा बदलकर करीब-करीब सभी राजनीतिक दलों की यात्रा कर चुके हैं।

विचारों में बदलाव कोई बुरी बात नहीं है। देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से लोगों के विचार बदलते हैं और बदलने भी चाहिए, लेकिन विचार बदल जाने या फिर हृदय परिवर्तित होने का ढोंग भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल ऐसा हो रहा है। यह गजब ही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह पिछले पांच महीने में तीन दल बदल चुके हैं। फिलहाल वह भाजपा में हैं। इसी तरह इसी राज्य में सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा कांग्रेस से भाजपा में आईं और 48 घंटे के अंदर फिर कांग्रेस में चली गईं। यह समझ आता है कि कोई दल विस्तार के क्रम में उन राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाए, जहां वह कमजोर है, जैसे भाजपा के मामले में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, लेकिन आखिर वह अपने मजबूत गढ़ समझे जाने वाले राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं को क्यों महत्व दे रही है? आखिर ऐसा करके वह पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नेताओं को क्या संदेश दे रही है?

एक समय था, जब हर दल की विचारधारा होती थी, लेकिन धीरे-धीरे विचाराधाराहीन दलों की संख्या बढ़ने लगी और अब गिनती के दल ऐसे हैं, जिनकी अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा है। राष्ट्रीय दलों में भाजपा और वाम दल ऐसे दलों में गिने जाते हैं, जिनकी अपनी विचारधारा है। एक वक्त कांग्रेस की भी विचाराधारा होती थी, लेकिन आज शायद कांग्रेसजन भी यह न समझा पाएं कि उनके दल की विचारधारा क्या है, क्योंकि आज की कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सेक्युलर दल है और विभाजन के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के बचे-खुचे नेताओं की ओर से बनाई गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी। बदलते समय और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विचारधाराओं में बदलाव आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उनका हाल वामपंथ की विचारधारा जैसा होता है, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं के पालाबदल को जनता की आकांक्षाओं का परिणाम बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यह तो शुद्ध अवसरवाद है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्म-जागरण

हमारे शास्त्रों में उल्लेख है-कलैव ब्रह्म अर्थात कला ही ब्रह्म है। यह कला ही है, जो पत्थरों में छिपी मूर्तियों को निखारती है। कला ही शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती है। वीणा में सोए संगीत को जगाती है, लेकिन इन सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला वह है जो सोए आत्मा को जगाती है। आत्मा को जगाने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आत्मा हमारा ही है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं कोई और नहीं। वर्तमान में हम आत्म-जागरण की कला भूल दूसरों की पसंद या नापसंद के दास बन गए हैं। नादिरशाह ने हाथी पर बैठने से यह कह कर इन्कार कर दिया था कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में न हो, उस पर बैठना खतरे से खाली नहीं है।

अपने जीवन की लगाम यदि हमारे हाथ में है तो हम स्वयं के मालिक हैं और स्वतंत्र हैं। न जाने क्यों अपना बुद्धि, विवेक त्याग कर हमने बाहर वालों को हमारी गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। वस्तुतः, हम स्वभाव से नहीं, अपितु दूसरों के प्रभाव से जी रहे हैं। किसी की प्रशंसा से मंत्रमुग्ध होकर उसके मुरीद बन गए। कोई हमारे ऊपर लांछन लगा गया तो उससे शत्रुता पाल ली। हम दूसरों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि स्वयं के भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। हमारी प्रसन्नता और नाराजगी दूसरों पर आधारित हो गई है, क्योंकि जीवन में सब कुछ दूसरे तय कर रहे हैं। हम भी अपनी समस्त क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करने के लिए और उनकी कसौटी पर खरे उतरने के लिए कर रहे हैं।

हम अपनी समस्त मौलिकता खो बैठे हैं। जबकि हमारा हित इसी में है कि अपने मालिक बनें। अपने मालिक बनते ही भीतर की संपदाओं से परिचय हो जाएगा। फिर संसार का सारा शोर, विसंगतियां और विकार लुप्त हो जाएंगे। इन सबसे परे होकर स्वयं का अन्वेषण करना ही सच्ची साधना है। यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अपने अहित पर आमादा कांग्रेस

'कांग्रेस के न्याय पत्र पर वामपंथ की छाप' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में उमेश चतुर्वेदी ने कांग्रेस की दिशाहीनता से परिचय कराया गया है। लेखक ने उचित ही लिखा है कि कांग्रेस इस समय वामपंथ की ओर मुड़ रही है। जबकि देश-दुनिया से वामपंथी विचारधारा का निरंतर संकुचन होने पर है। केरल को छोड़कर कहीं उसकी मुखर मौजूदगी नहीं रही। यहां तक कि एक समय उसके गढ़ रहे बंगाल और त्रिपुरा भी उसके हाथ से निकल गए हैं। एक समय कांग्रेस में वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी सभी प्रकार की वैचारिकी से प्रेरित नेता मौजूद थे और व्यापक रूप से पार्टी की पहचान भी मध्यमार्गी दल की रही जिसका अन्य धाराओं को साधकर चलने में विश्वास रहा, लेकिन राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद से पार्टी पर वामपंथ का प्रभाव बढ़ा है। फिर चाहे उद्यमियों या औद्योगिक घरानों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप हो या फिर पुरानी पेंशन का शिगूफा या फिर सरकारी नौकरियों का मोह दिखाना। वर्तमान में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर कर रही हैं, उनमें कांग्रेस की नीतियां आर्थिकी को पीछे ले जाने वाली ही अधिक लगती हैं। कांग्रेस वक्त की दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पाने का प्रयास नहीं कर रही। वह खुद ही अपने कायाकल्प में अवरोध बन रही है।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

बुजुर्गों की देखभाल में एआइ का प्रयोग

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख 'समस्याओं से घिरते बुजुर्ग' में युवाओं के देश में बढ़ रहे बुजुर्गों की आबादी को सम्मान जनक जीने की चिंता समाज के साथ सरकारों को भी करने की सलाह दी गई है। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा लगभग समाप्त हो चली है। घर के बुजुर्ग एकाकी जीवन जी रहे हैं। बुढ़ापे में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या रहती है। भारत में एकल परिवार की वृद्धि को लेकर नीति आयोग ने भारत में बुजुर्गों की देखभाल बढ़ाने के लिए कर व कानूनी सुधार, आवास क्षेत्र में सुधार, एक मजबूत पेंशन एवं बीमा प्रणाली का आह्वान किया है। आयोग ने कहा भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नीति आयोग ने शुक्रवार को 'भारत में वरिष्ठ देखभाल सुधारः वरिष्ठ देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना' शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया। विकसित भारत 2047 के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया प्रतिबद्धतापूर्ण कदम है। उच्च स्तर की देखभाल के लिए व्यापक स्तर पर तकनीक को प्राथमिकता देना हम सभी के लिए जरूरी हो जाता है। अब समय आ गया है कि चिकित्सा एवं सामाजिक आयामों के अलावा वरिष्ठों की देखभाल के विशेष आयामों के बारे में भी सोचा जाए। स्थिति पत्र की सिफारिशें सशक्तिकरण, सेवा वितरण एवं चार मुख्य क्षेत्रों के तहत उनके समावेशन के संदर्भ में आवश्यक विशिष्ट हस्तक्षेपों को वर्गीकृत करती हैं। यह वह समय है, जब उम्र बढ़ने को गरिमा से प्रेरित, सुरक्षित एवं उत्पादक बनाने पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हर परिवार के युवकों का दायित्व बनता है कि वे बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, भलाई एवं देखभाल पर अधिक ध्यान दें। यह क्रमिक प्रक्रिया है। आपकी देखा-देखी आपका पुत्र भी बुढ़ापे में आपके लिए तैयार रहेगा।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

कर्ज माफी निदान नहीं

उमेश चतुर्वेदी द्वारा लिखित आलेख 'कांग्रेस के न्याय पत्र पर वामपंथ की छाप' पढ़ा। लेखक के मंतव्य से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी में वामपंथी विचारधारा हावी हो रही है, इस कारण उसके न्याय पत्र में मुस्लिम लीग एवं वामपंथ की छाप दिख रही है। इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने पर जातीय जनगणना एवं आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने का वादा किया है। सदियों से वंचित एवं उपेक्षित समाज को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए दस वर्षों के लिए आरक्षण का प्रविधान किया गया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की खातिर कभी इसकी समीक्षा नहीं की गई, केवल समय सीमा बढ़ाई गई, नई जातियों को जोड़ा गया एवं आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया जाता रहा है। आज भी कुछ जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, एवं कुछ विशेष वर्ग बार-बार आरक्षण का लाभ उठा रहा है। यदि शत प्रतिशत भी आरक्षण प्रदान किया जाए, तब भी देश की बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। कांग्रेस ने रेवड़ी संस्कृति का कार्ड खेलते हुए किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं हो सकता है। कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके एवं उन्हें कर्ज लेने की नौबत नहीं आए। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं देश की मजबूती की रूपरेखा रखनी चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

खराब नेता पैदा नहीं होते। बल्कि वे तो बनाए जाते हैं, वह भी उन लोगों द्वारा, जो मतदान के दिन पिकनिक मनाने चले जाते हैं। परेश रावल @SirPareshRawal

किसी साधु-संत की कोई जाति नहीं होती, अपितु वे तो सभी समाजों के साझा होते हैं। उन्हें जाति के बंधन में बांधना सनातन संस्कृति का अपमान है।

अंकेश भाटी @AnkeshBhatii

अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ हाई कोर्ट से झटका लगा है, बल्कि अदालत ने जो टिप्पणी की है, वह उनके लिए आगे की कानूनी डगर मुश्किल करने वाली है।

रोमाना ईसार खान @romanaisarkhan

बसपा पर तमाम लोग भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बहनजी के राजनीतिक वारिस आकाश आनंद सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को निशाने पर ले रहे हैं। सौरभ त्रिपाठी @Saurabh_LT

कृपया मेरी पोस्ट को अन्यथा न लें, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि मीडिया में भले ही दिखाया जा रहा हो कि देश अपना मन बना रहा है, मगर मुझे लगता है कि देश अपना मन पहले ही बना चुका हूं। मेरे हिसाब से इस चुनाव का फैसला लगभग हो चुका है।

शेखर कपूर @shekharkapur

जनपथ

झटके पर झटका लगे किंतु न सुधरें 'आप',
दिल्ली वाले देखते बंधु 'आप' का पाप।
बंधु 'आप' का पाप कोर्ट कहता सच्चाई,
किंतु सुनें ना आप कान में रुई लगाई!
गलत किया है काम तभी तो हो यूं लटके,
तुम्हें दे रहा कोर्ट मियां झटके पर झटके!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर वी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 355

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बुधवार, 10 अप्रैल 2024

प्रेम और करुणा से भरा हृदय आंतरिक शक्ति, खुशी, शांति और इच्छाशक्ति का मुख्य स्रोत है।
-दलाई लामा

एनारॉक और नरेडको की संयुक्त रिपोर्ट लोकसभा चुनाव से पहले देश में रियल एस्टेट क्षेत्र की सुखद तस्वीर पेश करती है, जिसका श्रेय पिछले दस वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों को जाता है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए इस गति का बने रहना जरूरी है।

रियल एस्टेट की चमक

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक और नेशनल रियल एस्टेट डेवलेपमेंट काउंसिल (नरेडको) की संयुक्त रिपोर्ट का यह कहना कि पिछले दस वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, इस क्षेत्र की सुखद तस्वीर पेश करता है, जिसका श्रेय हालिया संरचनात्मक सुधारों को जाता है। इस क्षेत्र में 2013 में कुल चार करोड़ रोजगार उपलब्ध थे, जो 2023 में बढ़कर 7.1 करोड़ हो गए, तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल, इस दौरान यानी 2014 से 2023 के बीच शीर्ष सात शहरों में करीब 29 लाख मकान बिके, तो करीबन इतने ही नए लॉन्च भी हुए, जिससे स्वाभाविक ही नई नौकरियां पैदा हुईं। हालांकि, करीब 24 लाख करोड़ रुपये के भारतीय रियल एस्टेट बाजार का, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः 80 और 20 फीसदी है, 2017 से पहले कोई नियामक न होना हैरत में डालता है। लेकिन, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाई), किफायती और मध्य-आय आवास (स्वामी) फंड के लिए स्पेशल विंडो और वस्तु व सेवा कर जैसी पहलों ने रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदली है। कई राज्यों में रेरा लागू होने के बाद इस क्षेत्र में पारदर्शिता आई है और परियोजनाएं भी समय से पूरी हो रही हैं। गौरतलब है कि रेरा की स्थापना के बाद से आज तक राज्यों में करीब सवा लाख परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं और ग्राहकों की करीब इतनी ही शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। लेकिन, लोगों की सोच में क्रांतिकारी बदलाव कोविड काल के दौरान आया, जब उन्हें अपना घर होने की अहमियत का अहसास हुआ। इन सुधारों से देश के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े बदलाव तो आए, लेकिन देश के कुल रोजगार में 18 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब सात फीसदी का योगदान देने वाले इस क्षेत्र को अब तक पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा न मिल

पाना एक प्रमुख बाधा है, जिसके चलते डेवलेपर्स को कर्ज मिलने में परेशानी होती है। इसके बावजूद, रिपोर्ट का यह कहना महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र का आकार 2030 तक दस खरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह शीर्ष पांच में पहुंची है और पिछले लगातार तीन वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि यह क्षेत्र अपनी यही गति बनाए रखे।

चुनावी अर्थशास्त्र की चुनौतियां

भारत सरकार के कुल व्यय बजट, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपये है, में चुनावी खर्च बहुत छोटी-सी रकम है। लिहाजा, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या चुनाव पर सार्वजनिक खर्च वास्तव में कोई मुद्दा है।

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में पहले चरण का मतदान भी होने वाला है। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जोर-शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। अक्सर चुनाव के दिनों में चुनावी खर्च की चिंता जताई जाती है और बढ़ते चुनावी खर्च का तर्क देकर 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर भी विचार किया जाने लगा है।

जहां तक चुनावों में होने वाले खर्च की बात है, तो वैश्विक स्तर पर चुनाव कराने की प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तीय लागत काफी भिन्न होती है और विभिन्न देशों के बीच और देश के भीतर भी चुनावी लागत अलग-अलग होती है। सामान्य अर्थों में देखें तो, अपने देश में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न चुनावों पर सार्वजनिक खर्च में प्रति वर्ष 19.98 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017-18 में चुनाव पर केंद्र सरकार के सार्वजनिक व्यय की लागत 1322.22 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में बढ़कर 2724.26 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक चुनावों पर सार्वजनिक लागत का सबसे उच्चतम स्तर वर्ष 2022-23 में दर्ज किया गया है, जो 3775.42 करोड़ रुपये था।

पिनाकी चक्रवर्ती
एनआईपीएफपी के पूर्व निदेशक

इस चुनावी खर्च में छह प्रमुख मदें शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं -निर्वाचन अधिकारियों पर किया जाने वाला खर्च, मतदाता सूची तैयार करने और उसकी छपाई पर खर्च, लोकसभा और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव के संचालन के लिए किया जाने वाला खर्च, पंचायतों/स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए किया जाने वाला खर्च, आदि और चुनाव संबंधी अन्य खर्च। जैसा कि सार्वजनिक व्यय की इन व्यापक मदों से स्पष्ट है, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा चुनाव कराने के लिए किए जाने वाले प्रशासनिक खर्च हैं।

भारत सरकार के कुल व्यय बजट, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपये है, में चुनावी खर्च बहुत छोटी-सी रकम है। लिहाजा, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या चुनाव पर सार्वजनिक खर्च वास्तव में कोई मुद्दा है।

आइए, अब जरा चुनावों के अर्थशास्त्र पर भी विचार कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव संबंधी खर्च में बढ़ोतरी को अक्सर अल्पावधि में उपभोग खर्च को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। अल्पावधि में उपभोक्ता बाजार पर चुनावी खर्च के लाभ अलग-अलग होते हैं और इसका आर्थिक प्रभाव विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा की चुनावी प्रकृति समेत कई कारकों पर निर्भर करता है।

हालांकि चुनावी प्रतिस्पर्धा की प्रकृति का सार्वजनिक वित्त पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल जीत हासिल कर सरकार का गठन करता है, उस सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक नीतियों का सार्वजनिक खर्च पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे खर्चों का विकास, राजकोषीय संतुलन और मानव विकास पर दीर्घकालीन असर पड़ता है। हाल के वर्षों में चुनाव पूर्व किए गए वादे के बड़े सार्वजनिक खर्च प्रतिबद्धता में तब्दील होने का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम है। हमें चुनाव पूर्व किए गए इस तरह के वादे के ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, जिन्होंने सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के साथ नई सार्वजनिक नीतियों का भी निर्माण किया है।

भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार, विभिन्न राज्यों का एक संघ है। लिहाजा, एक संघीय देश में राष्ट्रीय निर्वाचन और राज्यों के निर्वाचन की चुनावी प्रतिस्पर्धा अलग-अलग होनी चाहिए, खासकर तब, जब राष्ट्रीय सरकार की भूमिका राज्यों की सरकारों से बहुत अलग हो। हालांकि हमारे अपने देश भारत में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वादे यह अंतर करने में विफल रहते हैं। राजनीतिक वादों से इस अंतर को समझना भी मुश्किल होता है।

केंद्र और राज्यों, दोनों के चुनाव में किए जाने वाले वादे बड़े पैमाने पर परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए पुनर्वितरण खर्च पर केंद्रित होते हैं। पुनर्वितरण खर्च उसे कहते हैं, जो संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित होते हैं, इसलिए इस मामले में राज्य कुछ हद तक केंद्र पर भी निर्भर होते हैं। इसके परिणामस्वरूप समस्या यह पैदा होती है कि चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों में कार्यात्मक टकराव पैदा होता है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें एक ही तरह की सेवा या सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों और जिम्मेदारियों का विभाजन स्पष्ट है।

संसाधनों के सांविधानिक विभाजन को देखते हुए स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि जैसे ज्यादातर पुनर्वितरण खर्च राज्य स्तर के होते हैं। आदर्श रूप में राज्यों के चुनाव इस तरह के पुनर्वितरण के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। कानून-व्यवस्था की बहाली भी राज्य का विषय है। इसलिए राज्यों के चुनाव कानून-व्यवस्था और शासन (गवर्नेंस) के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। जबकि राष्ट्रीय चुनाव आदर्श रूप में अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी संरचनाओं के विकास, रेलवे, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। लेकिन अपने देश में वास्तविकता बिल्कुल अलग है।

हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रमुख पुनर्वितरण संबंधी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय चुनावी वादों की कोई भूमिका नहीं है। कहने का मूल तात्पर्य यह है कि यदि संविधान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणापत्र में मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्थान दिया जाता है, तो चुनाव के बाद सरकार का गठन होने पर चुनावी वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऐसे वादों को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी।

-साथ में कौशिक भद्रा।
edit@amarujala.com

जीवन धारा

सत्यानंद महाराज

दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है। इसके विपरीत भीरुता, क्रोध एवं विवेकहीनता पाशविक वृत्ति हैं। बालक झूठ बोलने की आदत तब तक नहीं छोड़ सकता, जब तक कि उसमें सच बोलने की निर्भयता नहीं आएगी।

चरित्र निर्माण के बिना जीवन सार्थक नहीं

मनुष्य के जीवन को चरित्रवान एवं प्रभावशाली बनाने के लिए श्रीभगवद्गीता में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। इसमें मनुष्य जीवन को सुंदर और उच्च बनाने का जो विचार सुझाया गया है, वह अनुकरणीय है। यद्यपि बहुत से लोगों ने उसे बहुत बार और अनेक तरह से पढ़ा है, लेकिन सही तरीके से उसे कुछ ही गिने-चुने महात्माओं ने समझा और अपने जीवन में अपनाया है। जिस तरह बच्चा अपने बड़ों से कुछ सीखकर या सिखाए जाने पर बहुत कुछ सीख जाता है, उसी तरह हमें भी गीता से बहुत कुछ सीखकर जीवन में अपनाना चाहिए। चरित्र निर्माण के बिना जीवन सार्थक नहीं है। मानव, माया-मोह के झंझटों में तो पशुओं-पक्षियों से ही मिलता-जुलता है। शेर के मुंह से अपने बछड़े की जान बचाने के लिए गाय उसके सामने आ जाती है। ममता का यह उच्च स्तर मनुष्य में भी पाया जाता है। मनुष्य की तरह पशु-पक्षी दूसरे की निंदा में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दूसरों की निंदा, चुगली में मानव बहुत दिलचस्पी लेता है। परंतु वह जीवन प्राणमय जीवन के दुर्गुण हैं। इस जीवन में झगड़े भी बहुत हैं। संतान की रक्षा एवं पालन का मोह स्वाभाविक है। पशु-पक्षियों में भी यह भावना कम नहीं। लेकिन बुद्धि और विवेक सिर्फ मानव में ही है। यही मानव जीवन की क्रीड़ा है। लेकिन इसमें पाशविक वृत्ति भी जरूरत से ज्यादा है।

इंसान के जीवन में ज्ञान और विचार ही अधिक होना चाहिए। जो अच्छे विचार वाले मनुष्य हैं, वे ही दैवी संपत्ति के अधिकारी हैं।

दैवी विचारों में निर्भयता प्रथम गुण है। इसके विपरीत भीरुता, क्रोध एवं विवेकहीनता पाशविक वृत्ति है। जब तक आत्मज्ञान न हो, तब तक मनुष्य और पशु में भेद ही क्या? क्रोध, मोह, ममता, लालच जैसे विकार ही तो मानव को गंदे कीचड़ से निकलने नहीं देते। बालक झूठ बोलने की आदत किसी के डर से तब तक नहीं छोड़ सकता, जब तक कि उसमें सच बोलने की निर्भयता नहीं आएगी। दैवी संपत्ति के लिए सच बोलना आवश्यक है। यही कारण है कि निर्भयता के बलबूते पर भारत ऊंचे स्तर पर उठ गया। हमारे महापुरुषों ने निर्भयता का प्रचार किया। फलस्वरूप गोले-बारूद से नहीं, बल्कि निर्भयता के कारण ही भारत स्वतंत्र हुआ। तप करना, सत्याग्रह करना और व्रत रखना आसान है, लेकिन मन की निर्मलता बनाए रखना कठिन है। वस्त्रों की उज्ज्वलता और बाहरी आडंबर से मानव को क्षणिक मान मिलता है। इसलिए निंदा रूपी कीचड़ को अपने अंतःकरण में न उभरने दें। मित्र द्रोह, जाति द्रोह और देश द्रोह बहुत बुरा है। दूसरों को मजबूर करके अपने प्रयोजन सिद्ध करना बुरी बात है। मन का मैल धोने के लिए सत्याग्रह करना घोर तप है। सबके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। वैर-विरोध रूपी वैतरणी में गोते लगाने के बजाय परहित के लिए अपना तन-मन-धन बलिदान कर देना ही प्रत्यक्ष यज्ञ है। मानव अपने जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित करे, तो बेहतर।

सदाचार ही मूल...

सूत्र

सदाचार का जीवन ही वास्तव में मूल है। ऐसा वचन बोलना चाहिए, जो सत्य हो, प्यारा हो, मधुरता से भरा हो। दैवत्व गुण में आडंबर और दिखावा नहीं है। चुप रहने से सत्य बोलना अच्छी बात है। अपना पुरुषार्थ दूसरों के जीवन के लिए समर्थवान बनाएं-यही देवत्व जीवन है। श्रीभगवद्गीता के चरित्र निर्माण का यह भी एक अंग है। दूसरे को पीड़ा देने वाला अच्छा नहीं माना जाता।

दूसरा पहलू

मौलाना आजाद रोड स्थित बंगले को 1962 में उपराष्ट्रपति आवास बनाया गया था। पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इसी बंगले में रहे।

इतिहास बन जाएगा पहला उपराष्ट्रपति आवास

करीब 62 वर्षों तक देश के उपराष्ट्रपति का आवास रहने के बाद 6, मौलाना आजाद रोड स्थित बंगला इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति आवास में रहने चले गए हैं, जो 15 एकड़ में फैला हुआ है। अब 6, मौलाना आजाद रोड का बंगला जल्द ही जमींदोज होगा। सरकार यहां दस मंजिला इमारत बनाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के दफ्तर होंगे। 6, मौलाना आजाद रोड स्थित बंगले को 1962 में उपराष्ट्रपति आवास बनाया गया था। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसी बंगले में रहे। उनके बाद डॉ. जाकिर हुसैन, वी.वी.गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी. डी. जत्ती, एम हिदायतउल्ला, आर. वेंकटमण, शंकर दयाल शर्मा, डॉ. के. आर. नारायणन, कृष्णकांत, भैरोसिंह शेखावत, हामिद अंसारी और वैंकया नायडू इसी बंगले में रहे। कृष्णकांत का इसी बंगले में निधन हो गया था।

विवेक शुक्ला

दरअसल किंग एडवर्ड रोड (अब मौलाना आजाद रोड) के चार नंबर के बंगले में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद रहते थे। उनके निधन के बाद इस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया।

अब जब यहां गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी, तो यहां के तमाम छायादार पेड़ कट जाएंगे। इनमें नीम और पीपल के भी पेड़ हैं। पेड़ों के कटने से यहां के परिंदे भी बेघर होंगे।

दरअसल किंग एडवर्ड रोड (अब मौलाना आजाद रोड) के चार नंबर के बंगले में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद रहते थे। उनके निधन के बाद इस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया। कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन के महान डिजाइनर रोबर्ट टोर रसेल ने ही इस बंगले का डिजाइन तैयार किया था। इस बंगले में एक मस्जिद भी है। यह कब बनी, कोई नहीं बता पाता। यह सिर्फ रमजान के महीने में खुलती है। हालांकि इसकी साफ-सफाई नियमित होती है। 6, मौलाना आजाद रोड के भीतर जाकर लगता है, मानो आप किसी हरे-भरे टापू में हो। यहां अनार और जामुन के काफी पेड़ हैं। यहां के बुजुर्ग पेड़ों पर शाम के वक्त सैकड़ों तोते और दूसरे पक्षी आकर बैठ जाते हैं। भैरो सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति थे, तो इस बंगले के द्वार सबके लिए खुले रहते थे। शेखावत जी खुद यारबाश और किस्सागो इंसान थे। उनके पास मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उनके विरोधी तो थे, मगर शत्रु कोई नहीं। जब तक हामिद अंसारी इस बंगले में रहे, यहां अनेक लेखकों की किताबों के विमोचन होते रहे। उन्हें लेखकों और विद्वानों से मिलना पसंद था। उन्होंने खुद भी कई किताबें लिखी थीं। वैंकेया नायडू भी उपराष्ट्रपति आवास में लेखकों, नौजवानों, कलाकारों वगैरह से मिला करते थे।

अब जब यहां गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी, तो यहां के तमाम छायादार पेड़ कट जाएंगे। इनमें नीम और पीपल के भी पेड़ हैं। पेड़ों के कटने से यहां के परिंदे भी बेघर होंगे। बस बची रह जाएंगी सिर्फ यादें और किस्से।

आंकड़े

फलों के उत्पादन में वृद्धि

वित्त वर्ष 2012-22 (दस वर्षों में) के बीच फलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है।

स्रोत :TII; GOI Horticulture Status

सेठ ने प्रसन्न होकर दूसरी बहुओं से कहा, जिस प्रकार धान बोने से बढ़े हैं, उसी प्रकार सेवा-परोपकार से पुण्य बढ़ते हैं।

परोपकार से पुण्य

राजगृह में एक बुद्धिमान सेठ रहता था। उसकी पत्नी का निधन हो गया था। चार पुत्रवधुएं थीं। सेठ ने सोचा, क्यों न इन चारों को परखकर किसी एक को घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। एक दिन उसने चारों बहुओं को बुलाकर कहा, तुम चारों को मैं धान के पांच-पांच दाने देता हूं। इन्हें रखना और जब मैं मांगू, उन्हें लौटा देना।

बड़ी बहू ने सोचा कि कोठार में धान भरा है, जब ससुर जी मांगेंगे, तो वहीं से पांच दाने लाकर दे दूंगी। उसने दाने फेंक दिए। दूसरी ने भी यही किया। तीसरी कुछ समझदार थी। उसने दानों को रेशमी कपड़े में बांधकर रत्नों से भरी पेटिका में रख दिया। चौथी बहू ने सत्संग में सुना था कि कोई भी सद्कर्म करने से बढ़ते हैं, इसलिए उसने दानों को खेत में बो दिया। उससे जो फसल पैदा हुई, उसने उन्हें फिर से बो दिया। इस तरह कुछ ही वर्षों में उसके पास काफी धान हो गया। पांच वर्ष बाद सेठ ने बहुओं से दाने मांगे। शुरू की तीन बहुओं ने दाने वापस कर दिए, पर चौथी ने कहा, पिताजी, वे पांच दाने कोठार में बंद हैं और मैं उसे लाने में असमर्थ हूं। सेठ ने प्रसन्न होकर दूसरी बहुओं से कहा, जिस प्रकार धान बोने से बढ़े हैं, उसी प्रकार सेवा-परोपकार से पुण्य बढ़ते हैं। उसने छोटी बहू को घर की मालकिन बना दिया।

अंतर्यात्रा
संकलित

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 8 अप्रैल, 1955

टूंडला में हिंदू-मुस्लिम एकता का अपूर्व मेला

टूण्डले में हिन्दू-मुसलिम का अपूर्व मेला एकता

कस्बा टूण्डला में पीर फादर साहब का उर्स सदा की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाहर के आये हुए कव्वालों में से श्री शौरस साहब मुजफ्फर नगरवाले की कव्वालियां तथा गाने जनता ने बहुत पसंद किये। हिन्दू-मुसलिम जनता हर रोज काफी तादाद में उपस्थित रही।

टूंडला में पीर फादर साहब का उर्स सदा की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह जलसा हिंदू-मुस्लिम एकता का अपूर्व मेला बन गया, क्योंकि हर रोज काफी तादाद में लोग उपस्थित रहे।

'प्राकृतिक बॉन्ड' पर भी चर्चा हो

जलवायु परिवर्तन के मौजूदा संकट के दौर में प्रकृति के साथ हमारा जो बॉन्ड है, उसके प्रति हम कब प्रतिबद्ध होंगे?

गुंजन मिश्र

मुद्दा

अपने देश की जनसंख्या के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी है। हमारे देश में दुनिया की 18 फीसदी आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास वैश्विक भूमि का 2.4 फीसदी, वन का दो फीसदी, स्वच्छ जल का मात्र चार फीसदी ही उपलब्ध है। भविष्य में जैसे-जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाएगा, ये संसाधन और कम होते जाएंगे। अभी जिस दर से हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ष 2030 तक हमें 25 गुना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होगी।

पारिस्थितिकी के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स ऐंड पीस के अनुसार, अगर खाद्य सुरक्षा पर 25 फीसदी खतरा होगा, तो देश में टकराव/ संघर्ष की आशंका 36 फीसदी तक बढ़ जाएगी और इतने ही पानी की कमी होगी, तो संघर्ष की घटनाएं 18 फीसदी बढ़ जाएंगी। जैव विविधता की दृष्टि से हमारे देश में चार हॉटस्पॉट हैं, लेकिन

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन स्थानों का भी 90 प्रतिशत क्षेत्र कम हो चुका है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण भारत को हर साल औसतन सात अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। यही कारण है कि पिछले पांच वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वर्ष 2022 में भारत 121वें स्थान पर था। इन सब घटनाओं को देखते हुए आज प्राकृतिक बॉन्ड के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

यह प्राकृतिक बॉन्ड है क्या? हमने अब तक प्रकृति से जो लिया है या ले रहे हैं, उसे उसी अनुपात में प्रकृति को हम लौटा सकें, यह प्रतिबद्धता ही प्राकृतिक बॉन्ड है। अगर हम नहीं लौटा पाते हैं, तो हम इस प्रकृति के कर्जदार हैं। प्रकृति कोई वित्तीय संस्था नहीं है, जो पूरी जांच-पड़ताल के साथ हमें कर्ज देती है। इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन सह अस्तित्व के सिद्धांत के तहत होता है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, पर उसका ऋण चुकाना भूलकर हम सुख-साधनों की तरफ भाग रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आखिर कैसी पृथ्वी सौंप कर जाएंगे? कोरोना महामारी के संकट ने हमें सिखा दिया है कि वास्तविक धन क्या है। प्रकृति की उपेक्षा करके मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता।

जलवायु परिवर्तन और उसके कारण होने वाले विस्थापन का मुकाबला करने तथा पीड़ित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब तक देश में कोई ठोस नीति या कार्य योजना नहीं है। यही कारण है कि एक अनुमान के मुताबिक, अकेले भारत में जलवायु आपदाओं के कारण 2050 तक 4.5 करोड़ लोगों को अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में चरम मौसमी घटनाओं के परिणामस्वरूप पलायन करने वाले लोगों की संख्या वर्तमान संख्या से तीन गुना हो जाएगी।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, 2021, अनुसंधान समूह जर्मनवॉच की वार्षिक रैंकिंग, भारत को जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में रखती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते 2035 तक खाद्य कीमतों में सालाना 3.2 फीसदी की वृद्धि होने का अंदेशा है। यही नहीं, इससे फसलों की उपज पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु में आ रहे बदलावों के कारण आम आदमी के खाने की थाली कहीं ज्यादा महंगी हो सकती है।

इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। लेकिन बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, और उससे निपटने के लिए राजनीतिक दलों के पास क्या कार्ययोजना है, यह इस चुनावी बहस का मुद्दा नहीं है। अगर सही में देखा जाए तो यह चुनाव भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए हम अपने देश की लोकतांत्रिक संरचना को हरित लोकतंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। मौजूदा जलवायु परिवर्तन के दौर में यह आवश्यक है कि देश को एक हरित लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की पहल की जाए, और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोका जाए। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर किया जाने वाला विकास अंततः हमें विनाश के रास्ते पर ही ले जाएगा। इसलिए समय रहते सचेत होने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है।

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

ताकि समस्या का समाधान खुद न बन पाए समस्या

सच है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर समूचा विश्व चिंतित है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन पर्यावरण की अनदेखी इस कदर होने लगी है कि सरकारी तंत्र पर भी ग्रीन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक लक्ष्यों को पूरा करने में शिथिलता बरतने का आरोप लगता रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए हो रहे तमाम प्रयासों के बीच यह शंका भी लगातार व्यक्त की जाती रही है कि क्या सारे प्रयास पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि इन प्रयासों और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सही संतुलन साधा नहीं जा रहा।

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण पक्षी के संरक्षण से जुड़े एक फैसले में इस बिन्दु को बेहतर ढंग से समझा है। शीर्ष कोर्ट ने सौर ऊर्जा और पन बिजली के उत्पादन और लुप्त हो रहे गोडावण पक्षी की रक्षा के बीच संतुलन बनाया है। यह सच है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में तीव्र सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता जैसी बातें शामिल हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य , भोजन उगाने की क्षमता, आवास, सुरक्षा और कार्य क्षमता तक प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर भारत समेत कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने-अपने लक्ष्य तय किए हैं। हमारे यहां इन प्रयासों के तहत जैव ईंधन पर आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता घटाने के लिए सौर ऊर्जा और पन बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। एक तथ्य यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच गोडावण की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में राजस्थान और गुजरात में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सौर ऊर्जा से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों पर रोक लगाई थी, क्योंकि यह माना गया कि ये लाइनें गोडावण की मौत का कारण बन रही हैं। बाद में सरकार व प्रभावित पक्षों का तर्क स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण के मुख्य रहवास को छोड़कर शेष में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगी रोक हटा दी। यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, क्योंकि दोनों लक्ष्य ही जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने किए जा रहे उपायों पर सावधानी से काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। सरकारी तंत्र को यह समझने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए जो भी लक्ष्य तय किए जाएं, उनमें बारीकी से इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन्हें पूरा करने में कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को तो नुकसान नहीं हो रहा है।

भाजपा को 51.61 प्रतिशत मत मिले

झारखंड में लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को 15.83 प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी को 51.61 प्रतिशत और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11.66 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

लोकसभा चुनाव 2024

कांग्रेस को 1.14 प्रतिशत मत मिले

लोकसभा चुनाव 2019 सिक्किम में भाजपा को 4.74 प्रतिशत, कांग्रेस को 1.14 प्रतिशत, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 44.21 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 47.76 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। यहां की एक सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने चुनाव जीता था।

गुजरात चुनाव प्रचार पर विवाद की छाया बनी भाजपा का सिर दर्द

कांग्रेस और आप जीरो से उबरने के लिए लगा रहे पूरा दम

पत्रिका LIVE चुनाव मैदान से

अहमदाबाद
उदय पटेल

गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। 12 अप्रेल से इसके लिए नामांकन भरे जाने हैं। फिलहाल चुनाव का वह माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुस्ती के साथ ही चुनाव प्रचार आरंभ हो गया है। भाजपा ने जहां सभी 26 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक 20 प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी को चार सीटों पर अब भी उम्मीदवार घोषित करने बाकी हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटील लगातार बूथ प्रमुख के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसमें अपने प्रत्याशियों की सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि 5 लाख की लीड से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी चुनाव प्रचार का आगाज किया है। अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। उधर कांग्रेस के प्रभारी व राज्य सभा सांसद मुकुल वासनिक ने भी गुजरात का दौरा किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रह चुके अशोक गहलोत दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बनासकांठा में एक चुनाव सभा भी आयोजित की। राजस्थान में जोधपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं।

वडोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस महल।

रुक नहीं रहा विवाद

गुजरात में धीरे-धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। हालांकि इन दिनों सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री और राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला की चर्चा और विवाद के घेरे में हैं। गत 22 मार्च को दिए गए बयान को लेकर क्षत्रिय समाज की ओर से लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। राज्य के अलग-अलग जगह रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगहों पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है। यह स्थिति तब है जब रूपाला दो बार माफ़ी भी मांग चुके हैं। क्षत्रिय समाज को पाटीदार समाज व मालधारी समाज सहित अन्य समाज का भी समर्थन मिल रहा है। राज्य के मंत्रीगण और भाजपा के वरिष्ठ क्षत्रिय नेता भी लगातार क्षत्रिय समाज को मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल सका है। क्षत्रिय समाज रूपाला की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है।

लगाया पूरा दमखम

भाजपा जहां पर लगातार तीसरी बार राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत के लिए पूरे दमखम लगा रही है, वहीं पिछले दो लोकसभा चुनावों से एक भी सीट नहीं जीतने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं।

चुनावी चटकारा

सुलझ गई टिकट मिलने की गुत्थी

हाल ही में विधानसभा चुनाव में पराजित हुए सांसद गणेश सिंह को मध्यप्रदेश की सतना सीट से फिर टिकट मिल गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ और भाजपा में सबकी भौंहें तन गईं। सबके जेहन में यही सवाल आया कि क्या लोकप्रियता खो चुके सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर बचा पाएगी । पार्टी नेताओं को यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी का तो नहीं लगा। खबरियों ने इधर-उधर झांका तो पता चला कि सांसद पुत्र पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के पुत्र का पार्टनर है एक लॉ फर्म में। सारी गुत्थी सुलझ गई।

इस बार दीवार पर लिखी इबारत

राजनीतिक पंडित कितना भी गुणा-भाग कर लें, नियति ने तो इस बार दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में लोकसभा चुनाव का नतीजा लिख दिया है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने इन सभी पंडितों को भी राष्ट्र निर्माण के नाम पर एकजुट कर दिया है। असल में इन लोगों के बाकायदा प्रशिक्षण वर्ग तक लग चुके हैं और उन्हें समझाया गया है कि अपने विश्लेषण किस तरह प्रस्तुत किए जाने हैं ताकि विश्वसनीय लगें, एकतरफा नहीं। लेकिन, राज को समर्पित कुछ 'पुरोहित' इन सीमाओं को लांघ ही जाते हैं। किरकिरी होती है आकाओं की। कुछ कुंठित लोग इधर-उधर मुंह मार रहे हैं, लेकिन दीवार पर लिखी इबारत को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे।

पश्चिम बंगाल लाभार्थी महिलाओं से सम्पर्क के लिए अभियान

योजनाओं के लाभ दिखा डोरे डाल रही तृणमूल कांग्रेस

पत्रिका LIVE चुनाव मैदान से

कोलकाता
रवीन्द्र राय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब लोककल्याणकारी योजनाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा लोककल्याणकारी योजनाओं तथा महिलाओं के पक्ष में खड़े होने को मुद्दा बना रही है। हाल के कुछ चुनावों में इनसे सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल को मदद भी मिली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस राज्य में लगभग 2.13 करोड़ लक्ष्मी भंडार लाभार्थियों तक सीधे सम्पर्क साध रही है। योजना के तहत इस माह से सामान्य वर्ग की महिलाओं को अब दोगुना भत्ता मिलेगा। पार्टी महिलाओं को बता रही है कि तृणमूल प्रमुख तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल से ही भत्ते में इजाफा हुआ है। चुनावी रणनीति के तहत हर इलाके में लक्ष्मी भंडार समेत अन्य योजनाओं से तहत मिलने वाली सहायता राशि का उल्लेख किया जा रहा है। व्यापक रूप से इसका प्रचार किया जा रहा है। तृणमूल नेता और कार्यकर्ता विशेषकर घर-घर दस्तक देकर महिलाओं को योजना के लाभ के बारे में बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पार्टी लोगों के हित में इस तरह की योजनाएं जारी रखेंगी। तृणमूल लोगों के बीच यह दर्शाना चाहती है कि एक तरफ ममता बनर्जी राज्य की महिलाओं के भत्ते बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र में मोदी सरकार बंगाल के लोगों के उचित लाभों को रोक रही है। पार्टी का दावा है कि लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है।

कोलकाता के सबसे दूरस्थ हिल स्टेशनों में से एक है मोंगपु।

लक्ष्मी भंडार योजना

तृणमूल कांग्रेस महिलाओं को संदेश देना चाहती है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत भत्ते में बढ़ोतरी बांग्ला नववर्ष (15 अप्रेल) पर ममता दीदी की ओर से एक उपहार है। महिलाओं के एक समूह के साथ खड़ी ममता बनर्जी की तस्वीर वाले नीले रंग के पोस्टर पर दोनों तरफ बांग्ला में संदेश है। इसमें लिखा है कि यह आपके लिए नए साल का उपहार है, दीदी ने लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ा दी है। अब सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति के लिए 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दिया गया है। बढ़ी हुई रकम लाभार्थियों के बैंक खातों में मिलनी शुरू हो गई है। पहले चरण में पार्टी जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और दार्जिलिंग में महिलाओं से पार्टी जुड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि लक्ष्मी भंडार योजना संदेशखाली का तोड़ साबित हो सकती है। राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस अभियान की कमान संभाली है।

संदेशखाली बना मुद्दा

पश्चिम बंगाल में करीब 7.59 करोड़ मतदाताओं में से 49.19 फीसदी महिलाएं हैं। भाजपा ने इस बार चुनाव में संदेशखाली में महिलाओं पर कथित अत्याचार को मुख्य मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

पोलीटून

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवार तय होना बाकी, प्रचार में भाजपा आगे

ठंडे पहाड़ों में नेताओं के सियासी बयानों से आने लगी गरमाहट

शादाब अहमद

बर्फीले पहाड़ों वाले हिमाचल प्रदेश में यों तो एक जून को मतदान होना है लेकिन नेताओं के सियासी बयानों ने पहाड़ों में 'गर्माहट' ला दी है। बयानों की इस गर्मी से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी संघर्ष भी रोचक होने वाला है। हिमाचल में लोकसभा की चार सीटें, हैं। पिछली बार इनमें से तीन पर भाजपा और एक पर कांग्रेस ने कब्जा किया था।

केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। दीगर बात यह है कि हिमाचल की मंडी सीट पर देश भर की निगाहें लगी हैं जहां से भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। पिछली बार यहां से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनावी जीती थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में जो माहौल बना उसमें पार्टी की काफी फजीहत भी हुई है। इस उठापटक का नतीजा यह हुआ कि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी का यहां राज्यसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। यह बात दूसरी है कि पार्टी आलाकमान के दखल के बाद यहां खेमों में बंटी पार्टी में मेलमिलाप हुआ है। यह मेलमिलाप कितना कारगर हो पाएगा यह चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। वैसे कांग्रेस एकजुट होती दिख रही है। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह व हिमाचल सरकार में मंत्री उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंडी सीट पर कंगना रनौत के मुकाबले में विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं ऐसी चर्चा है। विक्रमादित्य बीफ, सुभाष चन्द्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताने, व 2014 में देश की आजादी वाले बयानों को लेकर रनौत को घेरना शुरू कर दिया है।

रनौत ने भी पलटवार कर विक्रमादित्य पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि कंगना ने सफाई दी है कि वे गोमांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करतीं। अपने खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को कंगना ने शर्मनाक बताया है। साथ ही कहा है कि वे दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही है। कांग्रेस अभी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में प्रचार की रंगत दोनों ही दलों के उम्मीदवार सामने आने पर ही सामने आएगी।

दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे टनल है रोहतांग की अटल सुरंग। इसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पूरा किया गया था।

भाजपा ने चारों सीटों पर उम्मीदवार तय किए

भाजपा ने चारों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं। चारों ही सीट पर भाजपा का प्रचार तेजी से चल रहा है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में प्रचार के मामले में कांग्रेस पिछड़ी हुई है।

बिहार : जातीय गणित साधते हुए उम्मीदवार खड़े किए, मुस्लिम आबादी का भी रखा ध्यान

लालू यादव जीत सुनिश्चित करने के लिए फूंक-फूंक कर रख रहे कदम

प्रियरंजन भारती

लोकसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान में अब करीब सप्ताह भर का समय ही शेष बचा है। पहले दौर के मतदान वाली बिहार की चार संसदीय सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो चुनावी रैलियां हो चुकी हैं। उधर चुनाव के अगले चरणों के लिए इंडिया गठबंधन अभी उम्मीदवार चयन की माथापच्ची में ही उलझा हुआ है। जिन चार संसदीय सीटों पर पहले दौर में 19अप्रेल को मतदान होना है, उनमें एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार मुकाबले में डटे हैं। लालू यादव ने जातीय आधार पर चुनाव के लिए चर्चित बिहार में जातीय गणित साधते हुए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें से जमुई और गया सीट से क्रमशः लोकजनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार हैं जबकि कांग्रेस की परंपरागत औरंगाबाद सीट लालू यादव ने कांग्रेस से अपने पास ले ली।जमुई में चिराग पासवान के बदले इस बार उनके बहनोई मैदान में हैं।

गया में स्थित विष्णुपद मंदिर। यहां भगवान विष्णु के पदचिह्न भी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत यहीं से करके यह संदेश दे दिया कि उनकी नज़र बिहार पर है और वह पिछड़ा , अतिपिछड़ा और वंचित वर्ग के वोटों को एनडीए से जुड़े रखने में कोई कमी नहीं करना चाहते।यह भी स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान की अहमियत उनके लिए कम नहीं है।

गया में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी मैदान में हैं। राजद नेता लालू यादव ने औरंगाबाद सीट से भाजपा के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह के खिलाफ जदयू से आए नेता को मैदान में उतार दिया है। यहां आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के जरिए लालू यादव भाजपा-जदयू के आधार वोट में बिखराव की कोशिश करते हुए उसे मात देने की उम्मीद पाले हुए हैं। ऐसे ही लोजपा की सीट नवादा को अपने हिस्से में लेकर भाजपा ने सवर्ण भूमिहार जाति के विवेक ठाकुर पर दांव लगाया है तो आरजेडी ने कुशवाहा समाज के नेता को चुनाव में उतारकर यह गणित बिठाने की जुगत लगाई है कि एनडीए के ओबीसी वोटबैंक में सेंधमारी कर उसकी बढ़त रोक दें। इसका असर देखना होगा।

आरजेडी एमवाइ के भरोसे

इंडिया गठबंधन का बिहार में अग्रणी घटक राष्ट्रीय जनता दल 2019 की पराजय नहीं दुहराना चाहता। लिहाजा लालू यादव फूंककर कदम-दर-कदम चल रहे हैं। चुनाव परिणामों को पक्ष में लाने के लिए आरजेडी बहुजन,अगड़ा,आधी आबादी और पुअर यानी 'बाप' के आधार वाली गरीबों की पार्टी होने का दावा बेशक कर रही है मगर नजरें अपने कोर वोटर मुस्लिम और यादव (एमवाइ)की ओर ही लगी हैं। पार्टी की नजर उन क्षेत्रों पर अधिक लगी हैं जहां मुस्लिम आबादी 12 से सत्तर फीसदी तक है। ऐसे लगभग दर्जन भर से अधिक संसदीय क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त यादव बहुल संसदीय क्षेत्रों पर पार्टी की नजर टिकी हुई है। जातीय सर्वेक्षण के अनुसार यादव जाति की कुल आबादी 14.26 फीसदी और मुस्लिम आबादी 17.7 फीसदी के करीब है। दोनों जातियों की कुल आबादी 31फीसदी से अधिक हो जाती है। आरजेडी जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहा है, वहां मुस्लिम व यादव समाज का दबदबा है।

मुस्लिम मतदाताओं का साथ महत्त्वपूर्ण

अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी,शिवहर,सुपौल, मधेपुरा,सिवान, औरंगाबाद जैसी अनेक सीटें ऐसी हैं जहां जीतने के लिए मुस्लिम मतदाताओं का साथ होना जरूरी है।इन क्षेत्रों में कम से कम 21और अधिकतम 32फीसदी मुस्लिम आबादी है। लिहाजा आरजेडी मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखकर उम्मीदवार का चयन कर रही है। इसके अलावा यादव आबादी का प्रतिशत भी चुनाव में विजय दिलाने का मादा रखता है। दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मधेपुरा, सहरसा, बांका जैसे क्षेत्रों पर नजर दौड़ाएं तो यादव और मुसलमान एकजुट होकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आज का सवाल

राजनीतिक दल टिकट किस आधार पर देते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

जनता आगे आए

राजनीति में सुधार के लिए आम जनता को ही आगे आना होगा। यह तय करना होगा कि जो कोई नेता स्वच्छ राजनीति करेगा मतदाता उसी को वोट देगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो।

-शंकर गिरि, रावतसर, हनुमानगढ़

आवाज बुलंद करें

राजनीति में सुधार के लिए भ्रष्ट और दोहरे चरित्र के नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। राष्ट्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले और निष्ठावान नेताओं को समर्थन दिया जाना चाहिए।

-सतीश उपाध्याय, मनेंद्रगढ़ एमसीबी, छत्तीसगढ़

मौकापरस्त नेताओं से दूर रहें

ऐसे मौकापरस्त नेताओं पर लगाम लगाना जरूरी है, जो जिस दल के जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो, उसी दल में शामिल हो जाते हैं। लोकतंत्र में ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

-डॉ. गोविन्द कुमार मीना, सवाई माधोपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'राजनीति में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/kggs67

https://t.me/epaperpdf

चिंतन

विकासशील से विकसित की ओर तेजी से बढ़ रहा देश

नए वर्ष पर देश को आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक अनेक शुभ संकेत मिले हैं। शेयर मार्केट नए शिखर पर पहुंच गया, सोना भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड पर और भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है और जल्दी ही हम जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। आईटी और ऑटो शेयरों में भारी खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक के पार पहुंच गया जबकि निफ्टी भी 22,765 अंक के नए स्तर को छू गया। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले सोमवार को भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। पिछले नौ महीने में इसमें 100 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। पिछले साल पांच जुलाई को भारत का मार्केट कैप 300 लाख करोड़ रुपये पहुंचा था। उसके बाद से निफ्टी में 16 प्रतिशत तेजी आई है। भारत का मार्केट कैप 2007 में 50 लाख करोड़ पहुंचा था जबकि 2014 में यह पहली बार 100 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा था। इसमें 200 लाख करोड़ रुपये का स्तर फरवरी 2021 में छुआ था। देसी बाजार का अब अगला बड़ा पड़ाव 5 लाख करोड़ डॉलर बाजार पूंजीकरण हासिल करना होगा, जिससे अभी वह करीब 4 फीसदी पीछे है। बाजार के भागीदारों ने कहा कि घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक मजबूती और विदेशी निवेश के निरंतर प्रवाह से शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला बना हुआ है। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मापने का पैमाना होता है। यही बताता है कि देश के उद्योग किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, आम आदमी किस तरह निवेश और खर्च कर रहा है। बाजार को देखने का एक और मानक होता है सोना। वह भी नव वर्ष के दिन नई बुलंदी पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 71,150 रुपये हो गई। सोमवार को इसमें करीब 1400 रुपये की तेजी आई थी और मंगलवार को 240 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत में भारी तेजी देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में यह 75,000 रुपये तक जा सकता है। अर्थव्यवस्था को देखने के लिए किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी परखा जाता है। इस क्षेत्र में भी भारत नित नए सोपान छू रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 29 मार्च 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.951 अरब डॉलर की शानदार बढ़ोतरी हुई और यह 645.583 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। पिछले कई महीनों से भारत अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा रहा है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह 817 टन पहुंच गया है। ये सारे संकेत बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत न केवल ठीक है बल्कि नई बुलंदी की ओर बढ़ रही है। भारत बड़ी इकॉनमीज में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के मुताबिक अगले दो साल तक भारत सबसे तेज इकॉनमी बना रहेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट के थिंक टैंक एक्सपर्ट का कहना है कि भारत की इकॉनमी चीन से ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है और आगे भी यही स्थिति रहेगी। 2023 में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.5 फीसदी से ऊपर रहने की संभावना है, जबकि चीन के मामले में 5.2 फीसदी रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि भारत जल्दी ही जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। सारे संकेत बताते हैं कि हम विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनमें बहुत कुछ किया जाना शेष है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स को देखे तो हम पड़ोसी पाकिस्तान से भी पीछे हैं। हमें वो उपाय करने होंगे, जिससे हर देशवासी में उल्लास का संचार हो। उसे अपने भविष्य का सुखद अहसास हो। ऐसी ही हालात हंगर इंडेक्स की है। यह बताता है कि देश तो बुलंदी छू रहा है, लेकिन एक तबका आज भी दो रोटी की जंग लड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सेहत, शिक्षा और रोजगार तीन ऐसे पैमाने हैं, जो विकसित होने की गारंटी कहे जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जल्द से जल्द आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। तभी हम दुनिया में अव्वल राष्ट्र कहला पाएंगे।

दिवस विशेष
योगेश कुमार गोयल

गैर विषैले और दुष्प्रभावों से मुक्त हैं होम्योपैथिक उपचार

प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को 'होम्योपैथी' के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के चिकित्सक, महान विद्वान, शोधकर्ता, भाषाविद् और उत्कृष्ट वैज्ञानिक डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर 'विश्व होम्योपैथी दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच की सफलता दर को बेहतर बनाना है। 10 अप्रैल 1755 को जन्मे डा. हैनीमैन के पास एमडी की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने बाद में अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतालवी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि कई भाषाओं में चिकित्सा, वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तकों को सीखा। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो औषधियों तथा उनके अनुप्रयोग पर आधारित है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष यह दिवस 'होम्योपैथीः अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना' थीम के साथ मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि वैकल्पिक और परम्परागत औषधियों को बढ़ावा दिए बगैर सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में विश्व में होम्योपैथी का प्रमुख स्थान है। होम्योपैथी ग्रीक शब्द 'होमियो' से बना है, जिसका अर्थ है 'समान' और 'पाथोस', जिसका अर्थ है पीड़ा या बीमारी। होम्योपैथी को चिंता, अवसाद, एडीएचडी और ओसीडी सहित कई प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों, एलर्जी और पुराने दर्द सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में प्रभावी पाया गया है। होम्योपैथिक उपचार सुरक्षित, गैर विषैले और दुष्प्रभावों से मुक्त हैं, जो उन्हें ऐसी पारम्परिक मनोरोग चिकित्सा का आकर्षक विकल्प बनाते हैं, जो प्रायः कई अप्रिय दुष्प्रभावों को साथ लाती है। होम्योपैथी अत्यधिक तनुकृत पदार्थों के उपयोग पर आधारित ऐसा उपचार है, जिसके बारे में चिकित्सकों का दावा है कि यह शरीर को स्वस्थ रख सकता है। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसार चिकित्सा का ही एक वैकल्पिक रूप है होम्योपैथी, जो 'समः समम शमयति' अथवा 'समरूपता' दवा सिद्धांत पर आधारित है, जो दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।

दिखने में भले ही होम्योपैथी दवाएं एक जैसी लगती हैं, किन्तु वास्तव में विश्वभर में होम्योपैथी की चार हजार से भी ज्यादा तरह की दवाएं हैं। होम्योपैथी के संस्थापक माने जाने वाले सैमुअल हैनीमैन का कहना था कि इलाज का उच्चतम आदर्श सबसे भरोसेमंद और कम से कम हानिकारक तरीके से स्वास्थ्य की तेज, कोमल और स्थायी बहाली है। चूंकि बहुत सारी होम्योपैथी दवाओं का असर रोगी पर कुछ धीमी गति से होता है, जबकि एलोपैथी दवाएं रोगी पर तुरंत असर दिखाती हैं, इसीलिए हाम्योपैथी भले ही एलोपैथी जितनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन दुनियाभर में यह उपचार के सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक रूप में मौजूद हैं। दरअसल होम्योपैथिक उपचार सबसे सरल उपचार है, जो शरीर को अधिक प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया की अनुमति देता है। होम्योपैथी दवाएं चिकित्सा का एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प प्रदान करती हैं, जो बिना किसी दुष्प्रभाव अथवा दवा के परस्पर क्रिया का कारण बनता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

देश के लिए संकट बनते खर्चीले चुनाव

विश्लेषण
प्रमोद भार्गव

चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवार को 95 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि करीब आठ विधानसभाओं में लड़े जाने वाले इस चुनाव में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वास्तविक खर्च इससे कई गुना अधिक होता है। प्रत्याशी और दल तो चुनाव में धन खर्च करते ही हैं, सरकार को भी चुनाव कराने में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए खर्च के इस छुटकारे का उपाय एक साथ चुनाव बनाम संयुक्त चुनाव में देखे जा रहे हैं। यदि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छा जाती है, वह दूर होगी।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 'उनके पास चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं है।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'मुझे इस बात को लेकर भी मलाल है कि चुनाव में समुदाय व धर्म जैसी चीजों को जीत तय करने का आधार बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है।' सीतारमण कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के अनुभव से गुजर चुकी हैं, इसलिए वे जो कह रही हैं उसमें निश्चित सच्चाई है। हम देख भी रहे हैं कि अनैतिक रूप से कमाए गए धन और आवारा पूंजी ने चुनावी खर्च इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी तो छोड़िए मध्यमवर्गीय व्यक्ति का भी चुनाव लड़ना मुश्किल है। वैसे चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवार को 95 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि करीब आठ विधानसभाओं में लड़े जाने वाले इस चुनाव में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वास्तविक खर्च इससे कई गुना अधिक होता है। प्रत्याशी और दल तो चुनाव में धन खर्च करते ही हैं, सरकार को भी चुनाव कराने में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए खर्च के इस छुटकारे का उपाय एक साथ चुनाव बनाम संयुक्त चुनाव में देखे जा रहे हैं। संभव है 2029 का चुनाव इसी प्रणाली से हो?

यदि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छा जाती है, वह दूर होगी। एक साथ चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता को एक ही बार घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा, अतएव मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि यह स्थिति बनती है तो चुनाव में होने वाले सरकारी खर्च कम होगा। 2019 के आम चुनाव में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुए थे, जबकि 2014 में इसके आधे 30 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2024 के चुनाव में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। गैर-लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के अध्ययन के अनुसार 2019 का आम चुनाव दुनिया में सबसे महंगा चुनाव रहा है। इस चुनाव में औसतन प्रति लोकसभा क्षेत्र 100 करोड़ रुपये खर्च हुए। एक तरह से यह खर्च एक मत के लिए 700 रुपये बैठता है। यह खर्च केवल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद का है। कई उम्मीदवार जिनका लड़ना तय होता है, वह साल-छह माह पहले से ही चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। इस खर्च को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। यदि लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 75 से 80 सीटें ऐसी थीं, जहां प्रत्याशी विशेष ने 40 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किए। यह चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशी के लिए तय खर्च की अधिकतम सीमा से 50 गुना से भी अधिक है। 2019 में खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये थी।

यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल और प्रत्याशी को भी कम धन खर्च करना होगा। दरअसल अलग-अलग चुनाव होने पर हारने वाले कई प्रत्याशी एक बार फिर किस्मत आजमाने के मूड में आ जाते हैं,

वहीं विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीट खाली होती है, उसे फिर से छह माह के भीतर भरने की संवैधानिक बाध्यता के चलते चुनाव कराना पड़ता है। नतीजतन जनता के साथ-साथ प्रत्याशी को भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी उदासीनता झेलनी पड़ती है। इस कारण सरकारी मशीनरी की जहां कार्य संस्कृति प्रभावित होती है, वहीं मानव संसाधन का भी ह्रास होता है।

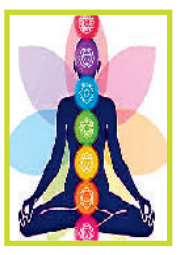

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सात चरणों में करीब ढाई माह चुनाव प्रक्रिया चलेगी। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप चुनाव को देखें तो उत्तर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में सुंदर वन के मैंग्रोव जंगल के इलाके भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। इनमें अनेक मतदान केंद्र ऐसे होते हैं, जहां मतदानकर्मियों को पालतू मवेशियों और नावों में चुनाव सामग्री लादकर ले जानी पड़ती है। ऐसे में प्रति मतदाता चुनाव का औसत खर्च 700 रुपये तक बैठता है। जबकि देश की साठ फीसदी आबादी बमुश्किल औसतन 250 रुपये प्रतिदिन कमा पाती है। ऐसे में बार-बार चुनाव में खर्च निश्चित ही एक चिंता का विषय है। सरकारी खर्च के अलावा प्रत्याशियों को टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों में विज्ञापन पर बड़ा खर्च करना होता है। वाहन, भोजन, पोस्टर-बैनर और नेताओं के लिए जुलूस व आम सभाओं पर भी बड़ा खर्च होता है। यदि इन प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा अप्रत्यक्ष खर्चों को देखें तो शराब, वोट के बदले नोट और उपहार के रूप में कोई वस्तु देने पर भी बड़ा खर्च प्रत्याशियों को उठाना पड़ता है। चुनाव में होने वाली खर्च की बड़ी राशि को सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादा खर्च दिखाना तय राशि का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उम्मीदवार और दल बेहिसाब धन खर्च करते हैं। निर्वाचन आयोग में पंजीबद्ध दलों के प्रत्याशी चुनावी सुविधाओं के लिए डमी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े करते हैं। इन पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। प्रत्येक चुनाव में जातीय और धर्म आधारित समुदायों के ध्रुवीकरण पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। अब धनी उम्मीदवार जातिवार सभाएं करके उनके भोजन-पानी का भी इंजमाम करते हैं। हालांकि राजनीतिक दल के लिए खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसी तरह विधानससभा चुनाव के लिए प्रत्याशी अधिकतम चालीस लाख रुपये खर्च कर सकता है। वहीं छोटे राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में लोकसभा उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 75 लाख रुपये और विधानसभा उम्मीदवार के लिए 28 लाख रुपये है।

ऐसे में एक साथ सभी चुनावों को संयुक्त रूप में करा दिया जाए तो एक प्रत्याशी को कई सीटों से या बार-बार चुनाव लड़ने के विकल्प समाप्त हो जाएंगे और धन की बर्बादी नहीं होगी। चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

आध्यात्मिक चेतना आखिर क्या है?

संकलित
दर्शन

आज मनुष्य अत्यधिक भौतिकवादी तथा लालची हो गया है। बलिदान, त्याग, संतोष, प्रज्ञा, चिंतन-मनन, मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक मूल्यों के द्योतक रहे हैं। व्यापक उपभोगवादी संस्कृति तथा भोग-विलास से पोषित भौतिकवाद की नई उभरी संस्कृति ने आध्यात्मिक चेतना पर पर्दा डाल दिया है। धन-अर्जन, सत्ता तथा प्रसिद्धि की लालसा और सुखवादी जीवन-प्रणाली आज जीवन का परम लक्ष्य है। सभी धर्मों ने लालच को महापाप कहा है, परंतु आज लालच ही मुख्य प्रेरणा-द्वार है। ऋषि-मुनि आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देते हैं। हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों का अनुक्रम है-धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। अर्थ तथा काम संसारिक मूल्य हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य हैं, परंतु धर्म का स्थान सर्वदा प्रथम है। यह अर्थ तथा काम दोनों का प्रेरक तथा नियंत्रक है। जीवन के हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, सात्विक सर्वाधिक ऊंचा आदर्श है। इसके बाद राजसी का स्थान है, जो एक आदर्श नहीं, परंतु सामाजिक आवश्यकता है। तामसिक सबसे अधिक अपमानजनक वृत्ति है, जिससे सभी बुद्धिमान दूर रहते हैं। मनु की पद्धति में सतत्व को न्याय की संज्ञा दी गई है, राजस को आकांक्षा की तथा तमस को इच्छाओं की। महापुरुषों ने चिंतन-मनन को मनुष्य के परम आनंद के रूप में देखा। आंतरिक शांति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित जीवन ही मानव गतिविधियों का सवरेत्तम रूप है।

मूर्ख साधू और ठग

संकलित
प्रेरणा

किसी गाँव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधू रहता था। उसे अपने भक्तों से दान में तरह- तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधू ने काफी धन जमा कर लिया था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गाँव में एक ठग रहता था। ठग हमेशा साधू का पीछा किया करता था, लेकिन साधू उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। उसने साधू से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधू तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधू के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था। एक दिन साधू को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया, साधू ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधू अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधू ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कम्बल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतज़ार था। जैसे ही साधू नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चम्पत हो गया। शिक्षाः किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।

गुड़ी पड़वा

मुंबई के गिरगांव में मंगलवार को गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्रीयन नव वर्ष के अवसर पर पारंपरिक पोशाक पहने लोग एक रैली में भाग लेते हुए।

आज की पाती

इजरायल पर हमला हमास को महंगा पड़ा

हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला कर निर्दोष लोगों की जान ही नही ली,बल्कि अनेक लोगों को बन्दक बना कर ले गए। आज का मंजर भयानक है। गाज़ा पट्टी को तहस नहस करने की ठान चुके इजराइल ने अब तक 33 हजार से ज्यादा लोगो को मौत की नींद सुला दिया। आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने का दृढ़ संकल्प ले चुके इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की भी नही सुन रहे है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इजराइल को धमकाने की जगह अमेरिका हमास पर दबाव क्यो नही बनाता। खंडहर में तब्दील गाजापट्टी वीरान दिखाई दे रही है। – **कांतिलाल मांडोत**, सूरत

करंट अफेयर

इंपीरियल कॉलेज लंदन ने 'यूनिवर्सिटी चैलेंज' जीता

ब्रिटेन में इंपीरियल कॉलेज लंदन की क्विज़ टीम ने 'यूनिवर्सिटी चैलेंज' की चैंपियन ट्रॉफी जीती है। इस टीम में कोलकाता के कम्प्यूटेशनल विज्ञान स्नातक सौरजीत देबनाथ शामिल हैं। ब्रिटेन के टेलीविज़न का सबसे कठिन 'क्विज़ टूर्नामेंट' बताए जाने वाले कार्यक्रम में 31 वर्षीय देबनाथ ने अंतिम दौर में कई मुश्किल सवालों का जवाब दिया और पिछली टीम के 'अद्वितीय मार्गदर्शन' ने इस साल प्रभावशाली अंतर से जीत दर्ज करने में योगदान दिया। यह कार्यक्रम सोमवार रात को बीबीसी पर प्रसारित किया गया जिसमें लंदन स्थित विश्वविद्यालय, कार्यक्रम के इतिहास में सबसे कामयाब विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। देबनाथ ने कहा, 'मैं ब्रिटिश क्विज़ का हिस्सा बनकर काफी खुश हूं और आभारी हूं कि हमारी टीम को इंपीरियल का प्रतिनिधित्व करते हुए खिताब जीतने का अवसर मिला।' ब्रिटिश-भारतीय प्रस्तोता अमोल राजन ने बीबीसी के लोकप्रिय कार्यक्रम की मेज़बानी की। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज की जीत को उल्लेखनीय बताया। टीम को इंपीरियल कॉलेज लंदन के साउथ केन्सिंग्टन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में राजन और जाने माने नाटककार सर टॉम स्टॉपर्ड ने 'यूनिवर्सिटी चैलेंज' ट्रॉफी से सम्मानित किया।

ऑफ बीट

अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने न्यूनतम स्तर पर

दक्षिणी गर्मियों के अंत में, अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने वार्षिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। कम से कम एक माप से, जो समुद्र के उस क्षेत्र को ट्रैक करता है जिसमें कम से कम 15% समुद्री बर्फ है, यह 2023 के रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ा ऊपर था। उस समय, मैं इतालवी आइसब्रेकर लौरा बस्सी पर सवार था, विडंबना यह है कि केप हैलेट से लगभग 10 किमी दूर समुद्री बर्फ से घिरा हुआ था और अभियान के नमूना स्थलों में से एक तक जाने में असमर्थ था। यहां तक कि सिर्फ एक दशक पहले तक, समुद्री बर्फ हर सर्दियों में मज़बूती से खुद को फिर से बना लेती थी। लेकिन दक्षिणी महासागर के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया है और समुद्री बर्फ से ढका क्षेत्र नाटकीय रूप से कम हो गया है। हमारा उद्देश्य अंटार्कटिका के आसपास समुद्र में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करना और उन कुछ प्रक्रियाओं का पता लगाना था जिनके बारे में हमें लगता है कि वे समुद्री बर्फ के इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक संभावना है, यह महासागरों के गर्म होने का परिणाम है और इसलिए हमने उन रास्तों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके जरिए गर्म समुद्री जल और बर्फ को पिघलाने निकल सकता है।

ट्रेंड

युद्ध के आघात को बढ़ाया

सूचना युद्ध ने गाजा में युद्ध के आघात को और बढ़ा दिया है-तथ्यों को छिपाना और दोषारोपण करना। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में प्रवेश से वंचित करना दुष्प्रचार और झूठी कहानियों को पनपने की इजाजत दे रहा है।

-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

सम्मानजनक अंत्येष्टि

डब्ल्यूएचओ नेअल-शिफा अस्पताल परिसर में अज्ञात शवों के लिए सम्मानजनक अंत्येष्टि के आयोजन में आज गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का समर्थन किया। शव पहले गंदगी या प्लास्टिक की चादर के नीचे पड़े रहते थे।

-टेड्रोस, डब्ल्यूउचओ महानिदेशक

हिंदू-मुस्लिम करने में लगे

10 साल सरकार चलाने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो पीएम मोदी अपनी घिसी-पिटी स्क्रिप्ट पर आ गए हैं, बजाए अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के हिंदू-मुस्लिम करने में लगे हैं। पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं, उनके सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी का 180 पार नहीं हो रहा।

-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

अच्छा लगता है

मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई दूसरा मैदान है जहां भीड़ लगभग मैच के बाद की प्रस्तुति का हिस्सा बन जाती है। मुझे इसे यहां करना अच्छा लगता है।

-हर्षा भोगले, क्रिकेट एक्सपर्ट

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid